हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(पटना से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

विश्वविद्यालय अपने संसाधन खुद जुटाएं

जब हर चीज और हर सेवा को कारोबार मान लिया गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासनों का यह सोचना बेजा नहीं है कि संपत्तियों का अधिक से अधिक मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जाए। उन संपत्तियों को भी जो मुफ्त में विश्वविद्यालयों को दी गई थीं। अमेरिका में मशहूर विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी जमीन या अन्य संपत्तियों को बेचने की खबरें कई वर्षों से चर्चित हैं। आज की कारोबारी भाषा में इन्हें संपत्ति को मोनेटाइज करना कहा जाता है। नव-उदारवादी दौर में जब हर चीज और हर सेवा को कारोबार मान लिया गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासनों का यह सोचना बेजा नहीं है कि संपत्तियों का अधिक से अधिक मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जाए। यह दीगर बात है कि कभी जब शिक्षा को सामाजिक जरूरत माना जाता था, तब सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्तियां मुफ्त में या बेहद रियायती दरों पर विश्वविद्यालय को दी गई थीं। बहरहाल, अब यह ट्रेंड भारत पहुंच गया है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) अपनी दो संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है। तर्क है कि विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट में है। इसलिए विश्वविद्यालय ने अपनी दो संपत्तियों- गोमती गेस्ट हाउस और 35, फिरोज शाह रोड को बेचने की योजना बनाई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिख कर जेएनयू ने अपनी संपत्तियों पर चल रहे 12 राष्ट्रीय संस्थानों का किराया मांगने का इरादा भी जताया है। शिक्षक संगठनों ने उचित ही इस कथित वित्तीय संकट के लिए सरकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक जब मुद्रास्फीति के अनुपात में सरकार उच्च शिक्षा का बजट नहीं बढ़ा रही है, तो ऐसी स्थिति आनी ही है। गौरतलब है कि केंद्र पहले ही शोध अनुदान, लाइब्रेरी फंड आदि में कटौती कर चुका है। सवाल है कि इस नीति का क्या परिणाम होगा? जाहिर है, धीरे-धीरे यह सोच लागू कर दी जाएगी कि विश्वविद्यालय अपने संसाधन खुद जुटाएं। नतीजतन शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि वह आम परिवारों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा के मामले में ऐसा पहले ही हो चुका है। अब सामान्य शिक्षा को भी सुविधा-संपन्न तबकों का विशेषाधिकार बनाया जा रहा है। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि देश सामान्य परिवारों से आने वाली प्रतिभाओं की सेवा से वंचित हो जाएगा। इस सिलसिले में यह तथ्य सबको याद रखना चाहिए कि शिक्षा, शोध और विज्ञान में बिना सार्वजनिक बड़े निवेश के कोई समाज आगे नहीं बढ़ा है।

जितनी आबादी उतना हक ?

कई विपक्षी दल जातिगत जनगणना की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो जिस जाति का है उसे उतना हक मिलना चाहिए। परन्तु ये दल यह नहीं बतलाते कि यह हक किन क्षेत्रों में मिलेगा। समतावादी समाज में सभी को पढ़ने का या सीखने का, या कौशल प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद ओपन कंप्टीशन में योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। 'हक़' किस क्षेत्र में? शायद मुख्य मुद्दा सरकारी नौकरियों में है। परन्तु वहां तो पहले से ही एस.सी., एस.टी., पिछड़ों, गरीब सवर्ण सवर्णों और शारीरिक रूप से अक्षम को आरक्षण है। फिर क्या व्यापार में हक की बात की जा रही है। एक बाजार में कितनी दुकानें सवर्णों की होंगी, कितनी एस.टी. वालों की? सरकारी नौकरियों में पहले से ही आरक्षण है। इसका एक दुष्परिणाम यह भी देखने को मिलता है कि आरक्षण के कारण जूनियर अपने पहले के सीनियर से उसका बॉस बन जाता है। यह सरकारी काम क्षमता में एक रोड़ा है। असल में अभी केन्द्र ने कुछ पदों के लिए ओपिन कंप्टीशन से विशेषज्ञों की नियुक्तियों के लिए यू.पी.एस.सी. के मार्फत विज्ञापन निकाला है। डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए है। असल में देश संचालन में कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यू.पी. एस.सी. ने मात्र 35 या 40 पदों के लिए विज्ञापन दिया था जो डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए था। विपक्षी महज विरोध के लिए विरोध कर रहा है। इनको चिराग पासवान। नीतीश कुमार का भी समर्थन है, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी कहे जाते थे। वे कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे और भाजपा की सरकार में भी। कोई सरकारी कर्मचारी यदि दूसरी शादी करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। परन्तु रामविलास पासवान को दोनों शादियों से बच्चे हैं। चिराग पासवान के पास मात्र पांच सांसद हैं। बिहार में उनको कोई बहुत समर्थन नहीं है। उनके चाचा, जे.डी.यू. और लालू यादव का विरोध उन्हें सहना पड़ेगा। नीतीश कुमार पल्लू राम के नाम से प्रसिद्ध है। मोदी जी देश में केवल चार जाति मानते हैं। उन्होंने ज्ञान के अनुसार गरीब युवा, अन्नदाता और नारी ये चार जातियां बतलाई हैं। बिहार की पार्टियां लोहिया जी का नाम लेती हैं जो जाति तोड़ो के पुरोधा थे। इन पार्टियों को जरा लोहिया साहित्य ठीक से पढ़ लेना चाहिए। मोदी जी को किसी से भी डर नहीं होना चाहिए। वे निर्भीक होकर शासन करें।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद

आरती कुमारी

जम्मू एवं कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने के साथ क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर के द्वार खोलने का माध्यम बनेगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की सीटें हैं, इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर ऐसी सरकार बनाये जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान चुनावी सरगर्मियों एवं भविष्य के गर्भ में ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर लगी हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। इस बार के चुनाव अब तक हुए चुनावों से अलग है और खास है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ हद तक इस तरह की अनिश्चितता हर चुनाव में होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में हालात सामान्य से ज्यादा जटिल हैं और इस असमंजस के पीछे उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी खेमे में माने जाने वाले राज्य के तीनों प्रमुख दलों में सहयोग और संघर्ष दोनों का दिलचस्प घालमेल दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आलम यह है कि पहले चरण की 24 सीटों का भी बंटवारा मुश्किल साबित हो रहा। पीडीपी इस गठबंधन से बाहर है। फिर भी मुद्दों की एकरूपता के चलते न सिर्फ उमर अब्दुल्ला उससे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा करने को कह रहे हैं बल्कि खुद महबूबा भी कह चुकी हैं कि अगर उनके अजेंडे को स्वीकार किया गया तो गठबंधन का समर्थन करेंगी। भाजपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वहां इस तरह की गफलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करना वहां भी जटिल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसे जिस तरह वापस लेना पड़ा, उससे उसकी छिछालेदार तो हुई ही है, अनुशासित दल की उसकी छवि को धक्का भी लगा। स्थिति यह है कि पार्टी ने सोमवार को 44 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के थोड़ी ही देर बाद व्यापक विरोध के कारण उसे वापस ले लिया। इसके बाद जो सूची जारी की गई, उसमें 15 ही प्रत्याशियों के नाम थे। यह आलम तब है, जब पहली सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर की गई थी। यदि भाजपा औरों से अलग तथा अनुशासित दल की अपनी छवि के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अपनी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले जारी सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना पड़ा था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकी है, जिससे असंतोष, विरोध और भितरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या केवल भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। यह कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं। चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्याएं मिटा देने तथा सब रोगों की दवा बन जाने की नैतिकता की बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि "अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।" इसलिये प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना होगा। इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है। भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षेत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहां होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहां से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है। जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है। ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब राज्य लम्बे दौर की विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद शांति एवं विकास की राह पर अग्रसर है।

क्या झारखंड में भी सफल होगा भाजपा का "ऑपरेशन लोटस" ?

अशोक भाटिया , मुंबई

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। वह 30 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीएम हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरों के बीच चंपई सोरेन सोमवार को दिल्ली पहुंचे और देर रात उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इसी मुलाकात में उनके भाजपा में शामिल होने का रास्ता भी साफ हो गया।झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को भाजपा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड प्रदेश के चुनाव सह-प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चंपई सोरेन और अपनी मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर बताया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने थोड़ी देर पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे।इसी के साथ मीडिया में चल रही यह खबर भी गलत साबित हो गई कि झारखण्ड में भाजपा का "ऑपरेशन लोटस " असफल हो गया । अब पाठक गण यह सोचेंगे कि " ऑपरेशन लोटस" क्या है । " ऑपरेशन लोटस" 2008 में बनाया गया एक शब्द है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए जब कर्नाटक राज्य के पूर्व मंत्री जी। जनार्दन रेड्डी ने दलबदल विरोधी कानून को दरकिनार कर विधायकों से समर्थन हासिल करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल किया, तब इस तरीके को ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया। तब से जहाँ भी भाजपा के लिए दलबदल होता है उसे राजनीतिक हलकों में ऑपरेशन लोटस की संज्ञा देने का रिवाज बन गया है । ज्ञात हो कि राज्यसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान के वक्त हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। ऊपरी सदन के लिए सांसद चुने जाने के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसके कारण कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हार गए।लेकिन बात सिर्फ एक राज्यसभा सीट की नहीं थी। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खतरे आ गई थी। ऐसा लगने लगा था कि बागी विधायकों का गुट भाजपा में जा मिलेगा और कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जाहिर है पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में बिना चुनाव जीते सरकार बना चुकी है। आइए ऐसी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं: 2014 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 11 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 42, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 5 और निर्दलीयों के हिस्से दो सीटें गईं। लेकिन दो वर्षों में यह संख्या बदल गई। भाजपा के सीटों की संख्या 48 और कांग्रेस के सीटों की संख्या एक हो गई। पीपीए के पास नौ सीटें हो गईं और निर्दलीय दो ही रहे। थोक दलबदल, राष्ट्रपति शासन, एक पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और तमाम अन्य घटनाओं के बाद अंततः भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली ! 2014 में ही झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 35 सीटें और उसकी सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 5 सीटें जीतीं। जाहिर है उनके पास बहुतम नहीं था। ऐसे में उन्होंने कुछ निर्दलीय सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया। साथ ही झारखंड विकास मोर्चा के 8 में से 6 विधायकों को अपने पाले में किया। बिहार की 2015 की घटना है 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने 2015 का चुनाव राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। दो साल तक महागठबंधन में सरकार चलाई। लेकिन 2017 में भाजपा ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर लिया सरकार में आ गयी। बाद में नीतीश फिर राजद से जुड़े। लेकिन 2024 के पहले महीने से वह एक बार फिर भाजपा के साथ मिल गए। 2017 में गोवा की कुल 40 सीटों में से भाजपा सिर्फ 13 सीटें जीती थी। नतीजों की घोषणा के बाद उन्होंने उन छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन किया, जिन्होंने खुले तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस तरह वह सबसे बड़ी पार्टी बन गए और सरकार बना ली। कांग्रेस को 17 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। मणिपुर में 2017 में भाजपा ने 60 में से 21 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिलीं। लेकिन भाजपा ने दो स्थानीय पार्टियों नेशनल पीपुल्स पार्टी और नागा पीपुल्स फ्रंट और अपनी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के एक अकेले विधायक को अपने पाले में कर सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने पहले भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि हेपतुल्ला पहले भाजपा सांसद थीं। 2018-19 में कर्नाटक में सत्ता हथियाने के लिए दो भाजपा को दो बार कोशिश करनी पड़ी। पहली कोशिश 2018 में की, जो असफल रही। 224 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 104 विधायक जीते थे। यानी पार्टी बहुमत से चूक गई थी। लेकिन गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक वजुभाई वाला ने राज्यपाल के रूप में कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन को नजरअंदाज करते हुए, भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अगले दिन फ्लोर टेस्ट की घोषणा हुई। येदियुरप्पा ने सदन में हार का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया और राज्य में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार बनी। हालांकि एक साल बाद ही खेल पलट गया। अचानक कांग्रेस के 13, जेडीएस के 3 और कर्नाटक प्रज्ञवंता जनता पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। सरकार अल्पमत में आ गई और इस तरह भाजपा बहुमत करने में सफल रही। राज्य में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई और येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सत्ता में वापस आ गई। वर्तमान में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और आज भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा "ऑपरेशन लोटस " के तहत हमारे विधायकों को बरगला रही है । हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनावों में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था। भाजपा को 90 सदस्यीय सदन में 40 सीटें ही प्राप्त थीं। ऐसे में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी को चुनाव के बाद गठबंधन का ऑफर दिया, जबकि जेजेपी ने अपने चुनाव अभियान में भाजपा पर गंभीर हमला किया था। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन दो साल के भीतर ही कांग्रेस के विधायकों के एक वर्ग को लुभाकर, भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में चली और मार्च 2020 में कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ गया। इसके बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में 2019 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी। तब विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना ने बहुमत हासिल किया लेकिन मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा इस पर दोनों में मतभेद हो गया। हफ्तों की उथल-पुथल और विधायकों को होटलों में छुपाने के बाद 22 नवंबर की रात को शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच अजीब गठबंधन हुआ। लेकिन अगली सुबह भाजपा ने राकांपा के अजीत पवार को विपक्षी गठबंधन छोड़ने और कथित तौर पर 54 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने के लिए मना लिया। एक गोपनीय समारोह में राज्यपाल बीएस कोश्यारी (उत्तराखंड के पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री) ने दो सदस्यीय सरकार को शपथ दिला दी। लेकिन कुछ ही घंटों में ये सरकार गिर गई क्योंकि अजित पवार के साथ कोई नहीं था। वह राकांपा में वापस चले गए और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। हालांकि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद अजित पवार फिर एनडीए में चले गए। जून 2022 में शिवसेना के 16 विधायकों के बगावत करने के बाद महा विकास अघाड़ी अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए भाजपा से गठबंधन कर लिया और राज्य में एनडीए की सरकार बन गई। अब यह तो लगभग तय हो गया है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे है पर अब तक यह नहीं मालूम पड़ा है कि उनके साथ अन्य विधायकों का कितना बल है उसके बाद ही तय होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनी रहती है या नहीं ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशिःआज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आप माता-पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जायेंगे। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जायेगा। किसी काम में की गई मेहनत जरूर सफल होगी। आज व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आज फायदेमंद रहेगी। अगर आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आग बढ़ेंगे, तो आपको अधिक मुनाफा होगा।

वृष राशिःआज का दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे, आपको ऐसा कर के अच्छा लगेगा। आज किसी बचपन के मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है,आप पुरानी बातों पर चर्चा करेंगे। आज कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशिःआज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटों का रास्ता आज ढूंढ लेंगे। आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगायेंगे। आज आपको परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। उनकी सेहत और परिवार का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चो के लिए आज का दिन बढिया है। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे।

कर्क राशिःआज आपका दिन आपके लिए खुशियों की नई सौगात लाया है। जीवनसाथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। आज अपनी काबिलियत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेगे तो भविष्य में आपकी सफलता के अवसर बढ़ जायेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने में सहजता रहेगी। आज दोपहर बाद थोड़ा समय आराम करने और कलात्मक कामों में बीतेगा। खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए आपको योगा करना चाहिए।

सिंह राशिःआज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के दिन आपके लिए कमियों से सीख लेकर आगे बढऩे का है। ऐसा करने से आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों से फायदेमंद मुलाकात रहेगी। आज अपने निजी मामलों में किसी की दखलअंदाजी न होने दें।

कन्या राशिःआज का दिन आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है। आज यात्रा से आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आज आपकी परिस्थितियों में बदलाव होगा। थोड़ा समय परिवार वालों के साथ बीताने और बातचीत करने से किसी खास मुद्दे का समाधान निकलेगा। भाइयों और रिश्तेदारों के बीच चल रहे विवाद किसी से निपट सकते हैं। समझ पूर्ण व्यवहार से आप परिवार की एकता को बरकार रखने में कामयाब होंगे।

तुला राशिःआज आपका दिन बहुत बढिय़ा रहने वाला हैं। समय का पूरा सदुपयोग करें। आज दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। आज पुश्तैनी जमीन-जायदाद से जुड़ा काम सुलझ सकता है। आज आपके घर में मांगलिक कामों की योजनाएं बनेंगी। संबंधों में मजबूती आएगी। आपका रुका हुआ सरकारी काम आज पूरा हो सकता है। आज आप अपने घर को नए तरीके से सजायेंगे।

वृश्चिक राशिःआज आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है। माताएं अपने बच्चों को कुछ नया सिखाएंगी, जिससे बच्चों में नए विचार आएंगे। आज परिवार के कुछ जरूरी काम होंगे। आज किसी से फोन पर लम्बी बात हो सकती है। इससे रिश्ते और मजबूत होंगे। रूटीन में सुधार करने की जरूरत है। व्यवस्थित रहेंगे तो आज काम समय पर पूरे हो जाएंगे। शाम का समय आपका खुशी व उमंग से भरा रहेगा।

धनु राशिःआज आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। आज आप वर्किंग प्लेस पर खूब मेहनत करेंगे। आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिन्हें आप अच्छी तरह से निभायेंगे। इस राशि के मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा।

मकर राशिःआज आपका दिन खुशनुमा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, ऐसे ही आपको आगे बढऩे के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस में अच्छे से काम को करने पर आपको फायदा होगा। कारोबार में कुछ नया करने के लिए चल रहे प्रयास सफल होंगे। दूसरों की मदद करने से आपको फायदा होगा। जमीन जायजाद के मामले में लाभ मिलेगा।

कुंभ राशिःआज आपका दिन बढिय़ा गुजरेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए शार्टकट तरीके अपनाने से बचें। निश्चित ही काम थोड़े विलम्ब से ही लेकिन पूरे हो जाएंगे। इस राशि के बिजनेसमैन के बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। माताएं बच्चो को मोरल स्टोरी सुनाएंगी। काम को पूरा करने में मन लगायेंगे और कुछ क्रिएटिव 2शहह्म करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए आज का दिन अच्छा है।

मीन राशिःआज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में आज का दिन ठीक रहेगा। साथ ही कोई कलीग आपके काम में हेल्प करेंगे। आज किसी के बहकावे में न आये और अपने काम के प्रति सतर्क रहें। आपके परिवार में कोई नन्हा मेहमान आने के योग बन रहे हैं। आज आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा।

शब्द सामर्थ्य -160

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवाद, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (उ.) 11. किरण 12. छौंक, तड़का 13. दुखदायी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समूह, दल, समुदाय 19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध सफेद पक्षी, वक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।

ऊपर से नीचे

1. विचित्र, अद्भुत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुलायम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यावली, करस्तानी, प्रशंसनीय कार्य 13. दासी, नौकरानी, बांदी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (उ.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 159 का हल

दि	क्क	त	■	आ	सा	न	■	आ
ल	■	मी	■	खि	■	सी	ख	ना
■	म	ज	बू	र	■	ह	■	जा
स	र्द	■	■	का	■	त	रा	ना
र	■	■	■	र	वि	■	ह	■
प	ह	ना	ना	■	ना	रा	ज	■
ट	■	■	क	शि	श	■	नी	ला
■	र	■	■	का	■	रा	■	य
खा	ति	र	दा	री	■	त	क्ष	क

सूडोकु नवताल- 7171

★★★☆☆ मध्यम

		8				1	5	
2					1	8		
3			4		6	7		9
5					9			
	9		2	3	4		7	
			1					8
4		7	6		5			1
		6	7					4
	5	3				2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7170 का हल

3	9	7	5	2	1	4	8	6
5	4	2	9	6	8	7	1	3
8	6	1	3	7	4	9	5	2
2	8	9	1	5	3	6	4	7
4	7	3	2	8	6	5	9	1
6	1	5	4	9	7	2	3	8
9	3	4	7	1	2	8	6	5
7	5	6	8	3	9	1	2	4
1	2	8	6	4	5	3	7	9

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 28 अगस्त 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

प.बंगाल में छात्रों की आड़ में राजनीति

कोलकाता के आर जी कर सरकारी अस्पताल में हुए जघन्य अपराध को लेकर सियासत दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मंगलवार को नबन्ना अभियान की शक्ल में सियासत का एक और रूप देखने मिला। नबन्ना भवन में प.बंगाल सरकार का सचिवालय है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है। प.बंगाल छात्र समाज ने इसी भवन तक बलात्कार कांड के विरोध में रैली निकालने का आह्वान किया था, जिसे नबन्ना मार्च या नबन्ना अभियान नाम दिया गया। प्रत्यक्ष तौर पर इस अभियान में कोई राजनैतिक चेहरा नहीं था, लेकिन इसमें जिस तरह भाजपा ने समर्थन दिया और स्वयं राज्यपाल की तरफ से वीडियो संदेश जारी हुआ। उससे समझा जा सकता है कि यह सारा अभियान बलात्कार जैसे खौफनाक अपराध में पीड़िता और उसके परिजन को मिलने वाले इंसाफ से कहीं अधिक राजनैतिक लाभ हासिल करने की नीयत से छेड़ा गया था।

नबन्ना मार्च रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय के छात्र प्रबीर दास, कल्याणी विश्वविद्यालय के शुभंकर हलदर और सयान लाहिड़ी नामक छात्रों द्वारा बुलाया गया था, इन छात्रों का कहना है कि उनका राजनीति से लेना-देना नहीं है। हालांकि शुभंकर हलदर ने खुद ही कहा है कि वे आरएसएस से जुड़े हैं और उन्हें इस पर गर्व है। इस मार्च को पहले विपक्ष का समर्थन भी मिला था, लेकिन बाद में संघ के तार इससे जुड़ते देख कांग्रेस और वाममोर्चा दोनों ही इससे पीछे हट गए। छात्रों ने इस अभियान के लिए तीन मांगों को सामने रखा था, अभया के लिए न्याय, अपराधी के लिए मौत की सजा और ममता बनर्जी का इस्तीफा। यह अजीब बात है कि जब मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी शुरु कर दी है, तब इस तरह की मांग को लेकर रैली निकालने का औचित्य क्या है। जहां तक सवाल ममता बनर्जी के इस्तीफे का है, तो फिर इसकी शुरुआत मणिपुर से होते हुए उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां की बेटियों के साथ भी इसी तरह के अक्षम्य अपराध हुए हैं।

महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में 24 तारीख को महाविकास अघाड़ी ने भी प्रदर्शन का आह्वान किया था, हालांकि अदालत में इसे रोकने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल हुई और उसके बाद अदालत ने इस पर रोक लगाई तो फिर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने काली पट्टी मुंह पर बांध कर मौन प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। ऐसा ही काम कोलकाता में भी हो सकता था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसके पास खुफिया जानकारी थी कि कुछ उपद्रवी रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच घुसने और बड़े पैमाने पर हिंसा व अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। सरकार ने पहले ही बीएनएसएस की धारा 163 के तहत नबन्ना के निकट निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, जिसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगती है। सोमवार को पुलिस ने एक संवाददाता सम्मेलन कर आंदोलन को गैरकानूनी करार देते हुए इसे अशांति फैलाने की साजिश करार दिया था। लेकिन सोमवार देर शाम राजभवन की ओर से जारी एक वीडियो संदेश में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह छात्रों को रैली रोकने के लिए बल प्रयोग न करे।

राज्यपाल पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के संदेश जारी करना कहां तक उचित है, यह भी विचारणीय है। इस अभियान को लेकर पुलिस की आपत्तियों पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस को इसे वैध या अवैध कहने का क्या अधिकार है ? लोकतांत्रिक देश में कोई भी विरोध कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध या मार्च निकाला जाता है तो पुलिस उसमें बाधा नहीं डाल सकती। काश दिलीप घोष यही बात तब कहते जब संसद की ओर अपनी मांगों को लेकर निकली महिला पहलवानों को पुलिस ने बलप्रयोग करते हुए ही रोका था और जेल में डाला था। इससे पहले किसानों के साथ भी यही सलूक किया गया।

बहरहाल, पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद जब नबन्ना मार्च निकाला गया, तब हालात संभालने के लिए करीब 5 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। फिर भी विरोध भड़कते देख प्रदर्शनकारियों को काबू में लेने के लिए पुलिस को पानी की बौछार जैसे तरीके इस्तेमाल करने पड़े। इसके बाद सियासत और तेज हो चुकी है, अब भाजपा ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। जाहिर है यह सब ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

आर जी कर अस्पताल की घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। एक स्वस्थ और जागरुक समाज को इस तरह के अपराध और नाइंसाफी पर नाराज होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही इस बात के लिए सचेत भी रहना चाहिए कि कोई उसकी नाराजगी का राजनैतिक फायदा तो नहीं उठा रहा। क्योंकि देश में कई जगह कोलकाता की घटना पर विरोध की रैलियां निकाली गईं, फिर भी लड़कियों के लिए माहौल पहले से ज्यादा असुरक्षित बना हुआ है, तो सोचना होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है।

देश में नैतिक पतन जारी है : इसे कैसे रोका जाए ?

पश्चिम बंगाल और केरल सांस्कृतिक दृष्टि से देश के सर्वोपरि राज्य हैं। दोनों राज्यों को देश के महान संस्कृतिकर्मियों ने योगदान दिया है। बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सुभाषचन्द्र बोस, ज्योति बसु, आदि शामिल हैं। अनेक कवि, सत्यजीत रे समेत अनेक फिल्मकर्मियों ने जन्म लिया है, ऐसे महान राज्य में एक महिला डाक्टर के साथ जो कुछ हुआ वह बंगाल के चेहरे पर कालिख है। इस महिला डाक्टर के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया वरन उसकी हत्या भी की गई। घटना के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे लगता है कि वह अनेक गुप्त बातों की जानकार थी जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होना थी। वह इन बातों को उजागर करे उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई।

केरल देश की संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रों में देश का ही नहीं वरन् दुनिया में भी सर्वोपरि है। अभी हाल में जाहिर किए गए आंकड़े से पता लगा है कि एक लाख में से 19 माताएं या तो बच्चे के जन्म देने के तुरंत बाद या गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं। यह आंकड़ा अमेरिका से भी आगे है। उसके विपरीत उत्तरप्रदेश में 1 लाख में से 167, मध्यप्रदेश में 173 असम में 195 महिलाएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 100 प्रतिशत आबादी शिक्षित हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी तरह पूरे देश में वह सर्वोच्च शिखर पर है। ऐसे प्रदेश में वहां के फिल्म जगत में काम करने वाली महिलाओं ने अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत की। उनकी शिकायत के चलते वहां की सरकार ने एक अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने वहां की सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों की शिकायत को सुना और यह आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों की शिकायत सही है। इस आयोग की रिपोर्ट 2019 में मुख्यमंत्री को भेजी गई। परंतु किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। इस बीच उन पर दबाव बढ़ता रहा और इस माह में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट सार्वजनिक करने में इतनी देर क्यों हुई ? इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अनेक प्रकार के स्पष्टीकरण दिये हैं जिनमें एक स्पष्टकीरण के अनुसार उनका कहना था कि देरी के लिए आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का सुझाव दिया था।

कारण जो भी हो परंतु मलियालम में बनी फिल्में अद्भुत समझी जाती हैं। इन फिल्मों को बनाने में जिन अभिनेत्रियों का योगदान रहता है उनके साथ इस तरह का व्यवहार केरल को शर्मसार करने वाली घटना है।

हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतवर्ष शीघ्र ही विश्वगुरू बनेगा। परंतु जो विश्वगुरू बनने वाला है उसके 150 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कुछ दुष्कर्म के भी मामले हैं। जिस देश के 150 जनप्रतिनिधि अपराधों में शामिल हों वह कैसे विश्वगुरू बन पायेगा ?

एल.एस. हरदेनिया

> केरल देश की संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रों में देश का ही नहीं वरन् दुनिया में भी सर्वोपरि है। अभी हाल में जाहिर किए गए आंकड़े से पता लगा है कि एक लाख में से 19 माताएं या तो बच्चे के जन्म देने के तुरंत बाद या गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं। यह आंकड़ा अमेरिका से भी आगे है। उसके विपरीत उत्तरप्रदेश में 1 लाख में से 167, मध्यप्रदेश में 173 असम में 195 महिलाएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं।

हमारे देश में इस समय महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अनेक अपराधों की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में अभी हाल में जो घटना हुई उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। एक स्कूल की 4 साल की दो बच्चियों के साथ उसी स्कूल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। उसी महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की खबर सामने आई। असम में भी ट्यूशन से घर वापिस आ रही एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इसके विरोध में असम में पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए। परंतु इस घटना को लेकर वहां के मुख्यमंत्री ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की वह चौंकाने वाली है। इस बच्ची के साथ अपराध करने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यक पाया गया। इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में यहां के मूल निवासी अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। शायद उनका इशारा किसकी ओर है यह वही बता सकते हैं।

समाज में आए दिन सभी रिश्तों को तोड़ते हुए घटनाएं हो रही हैं। एक समाचार के अनुसार एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या में तकिये का उपयोग किया गया। हत्या इसलिए की गई क्योंकि अपने पति की इस दूसरी पत्नी की निगाह अपने पति के रिटायर होने पर मिली भारी रकम पर नज़र थी। उसको डर था कि उसका पति उनकी पहली पत्नी की संतानों को रकम का भारी हिस्सा दे देंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो इसके पहले ही उसने अपने पति की हत्या कर दी। जिस पत्नी ने हत्या की वह स्वयं अपने पहले पति को तलाक देकर दूसरी शादी की थी।

एक और मामले में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके स्वयं थाने को सूचित कर दिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। कारण उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पति-पत्नी का रिश्ता अत्यधिक विश्वास का रिश्ता होता है। परंतु उसमें भी कभी भी खटाई पड़ जाती है और हत्या के समान जघन्य अपराध हो जाते हैं। एक अखबार में खबर छपी है कि कुछ लोग महिलाओं के या बच्चियों के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाते हैं और फिर उस वीडियो को भारी कीमत पर बेचते हैं। इस अखबार के अनुसार यह एक बड़ा धंधा हो गया है। इसलिए इस तरह की खबरे पढ़ने को मिलती हैं कि महिला या बच्ची अपने को दुष्कर्म से मुक्त करने के लिए अपील करती हैं परंतु उसे बचाने के स्थान पर लोग उसका वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। इस तरह की घटनाएं ही इस बात का सबूत है कि इंसान की संवेदनशीलता को क्या हो गया है ? हम लाखों की संख्या में प्रवचन सुनने जाते हैं परंतु उस प्रवचन से हमारी आत्मा पर क्या असर हुआ यह ज्ञात नहीं होता है।

अभी हाल में महाराष्ट्र में एक हिन्दू संत ने इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक बातें की। उसकी प्रतिक्रिया में मध्यप्रदेश के छतरपुर नाम के स्थान पर मुसलमानों ने रोष प्रकट किया। थाने का घेराव किया और पुलिसकर्मियों को घायल किया। इस घटना के विरोध में पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई के फलस्वरूप एक धनी मुस्लिम के मकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। न सिर्फ मकान को नेस्तनाबूद किया बल्कि जो वाहन वहां थे उनको भी तोड़ डाला। क्या वाहन भी प्रदर्शन में शामिल थे ? फिर मकान को नेस्तनाबूद करने के पहले इस बात की भी जानकारी नहीं ली गई उसकी कानूनी स्थिति क्या है। यह भी बताया गया कि इस विशाल मकान के भीतर जो मूल्यवान वस्तुएं थीं जैसे गहने, टीवी, फ्रिज उनका क्या हुआ ? यदि मकान गैरकानूनी था तो जब वह बन रहा था तब उसका निर्माण क्यों नहीं रोका गया ? इस तरह की घटनाएं मध्यप्रदेश के और स्थानों पर भी हुई हैं और उत्तरप्रदेश में तो बड़े पैमाने पर हो रही हैं।

ऐसी घटनाओं के बारे में क्या रवैया अपनाया जाए ? यह कहना मुश्किल है क्योंकि उसके पीछे बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ है ऐसा आरोप लगाया जाता है। कुल मिलाकर समाज में चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो या अन्य अपराध हों लगभग कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है ?

इस समय बुलडोजर ऐसे मकान पर भी चला दिया जाता है जिसमें रहने वाले परिवार के केवल एक सदस्य ने अपराध किया हो। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की सज़ा पूरे परिवार को क्यों दी जाती है ? फिर हमारे देश के कानून के अनुसार अपराधी को सज़ा देने का अधिकार न्यायपालिका का है न कि पुलिस का। परन्तु आये दिन बुलडोजर चलाकर सज़ा पुलिस वाले दे रहे हैं जो सरासर गैरकानूनी है।

मुद्रास्फीति पर रिजर्व बैंक की बढ़ती जा रही दुविधा

■ अंजन रॉय

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल, व्योमिंग से स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दर उलट चक्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फेडरल रिजर्व आखिरकार कम नीतिगत दरों की व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

वित्तीय बाजारों ने इसे तुरंत उठाया और हाल के दिनों में गिरावट के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में एक बार फिर उछाल आया है। एक बार फेडरल रिजर्व अपनी नीति उलटने की पहल करता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वित्तीय बाजार आगे समायोजन करना शुरू कर देंगे।

जब अमेरिकी फेड बोलता है, तो दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंकरों को सुनना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार गतिशीलता के एक नये चरण में प्रवेश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपना एंटीना उठायेगा और भारतीय बाजारों में होने वाले बदलावों पर नज़र रखेगा।

यह उम्मीद भी की जा सकती है कि वैश्विक बाजारों के साथ तालमेल बिठाते हुए भारतीय शेयर भी बढ़ेंगे, जैसा कि व्यापक स्पेक्ट्रम ब्याज दरों में कमी आने पर होता है। आने वाले दिनों में शेयर बाजारों में और उछाल आना चाहिए। इसके साथ ही, बॉन्ड बाजार भी नये स्तरों की तलाश करेंगे। इस उछाल का लाभ उठाने के लिए विदेशी बाजारों से धन प्रवाह की भी उम्मीद की जा सकती है।

> जब अमेरिकी फेड बोलता है, तो दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंकरों को सुनना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार गतिशीलता के एक नये चरण में प्रवेश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपना एंटीना उठायेगा और भारतीय बाजारों में होने वाले बदलावों पर नज़र रखेगा।

इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक को अपने व्यापक नीति उपायों को कैसे फिर से निर्धारित करना चाहिए ? जाहिर है, मार्गदर्शक कारक भारत में समग्र मूल्य स्थिरता के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता और प्रदर्शन होना चाहिए।

6 और 8 अगस्त के बीच रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठकों में नीति मापदंडों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। समिति की कार्रवाई की नवीनतम रपट के अनुसार, नीति दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था, हालांकि समिति के दो सदस्यों ने इस निर्णय के खिलाफ जोरदार तर्क दिया।

आरबीआई के लिए जिन कारकों पर विचार करना वांछनीय हैं, वे हैं मुद्रास्फीति के रुझान और मूल्य प्रवृत्तियों में वृद्धि की संभावना। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में नरम रुझान दिखाई दिये हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मासिक आर्थिक रिपोर्ट में इस सप्ताह काफी आरामदायक तस्वीर दिखाई गई।

कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति धीमी होकर 4.6प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5.3 प्रतिशत थी। विशेष रूप से महीने-दर-महीने जुलाई में कीमतों में तेज गिरावट देखी गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2024 में 5.1 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2024 में 3.5 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने इसका श्रेय खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट को दिया।

खाद्य मुद्रास्फीति जून 2024 में 9.4प्रतिशत से घटकर जुलाई 2024 में 5.4प्रतिशत हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति में देखी गई पर्याप्त गिरावट को मुख्य रूप से जून 2024 में 29.3प्रतिशत से जुलाई 2024 में 6.8प्रतिशत तक सब्जी मुद्रास्फीति में गिरावट से मदद मिली। हालांकि, यह देश भर के बाजारों में कीमतों के स्तर, खासकर सब्जियों की कीमतों के बारे में वास्तविक अनुभवों के विपरीत है।

अब सवाल यह है कि क्या कीमतों में यह नरमी क्षणिक है या फिर लंबे समय तक चलने वाले रुझान का संकेत है ? अगर यह अचानक मासिक गिरावट अल्पावधि में उलट जाती है, तो आरबीआई को अपने मुद्रास्फीति विरोधी रुख से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और कीमतें निचले स्तरों की ओर बढ़ती हैं, तो आरबीआई के पास अपनी नीतिगत दरों को फिर से निर्धारित करने की गुंजाइश है। अभी तक, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आने वाले महीनों में कीमतों का रुझान कैसा रहेगा।

इस तरह के किसी भी आकलन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, ऐतिहासिक रुझान। आम तौर पर देखा गया है कि खाद्य कीमतें, खास तौर पर दो प्रमुख अनाज और फलों और सब्जियों की कीमतें गर्मियों के महीनों से लेकर मानसून अवधि तक बढ़ती हैं। फिर अक्टूबर से खरीफ की कटाई के बाद के मौसम में इनमें गिरावट आती है।

अनुभव के आधार पर, शायद हम कीमतों में उछाल से उबर चुके हैं और अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को छोड़कर आने वाले महीनों में रुझान और भी सहज होते जायेंगे। दूसरा अनुकूल कारक यह है कि मानसून अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और पूर्वानुमान है कि इस वर्ष यह सामान्य स्तर पर रहेगा।

इसलिए, इस मौसम में खराब मानसून और खाद्य उत्पादन पर संभावित प्रभाव की आशंकाओं को दरकिनार किया जा सकता है। मूल्य स्थिति, विशेष रूप से, खाद्य मुद्रास्फीति अभी स्थिर रह सकती है।

वित्त मंत्रालय ने इसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया: 'मध्यम कोर मुद्रास्फीति और मानसून में सकारात्मक प्रगति के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सकारात्मक है। सामान्य मानसून को मानते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति 4.5प्रतिशत और दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति4.4प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।' दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट अन्यथा अनुकूल आर्थिक आंकड़ों के बीच प्रतिकूल उपभोक्ता अपेक्षाओं पर ध्यान देती है।

वित्त मंत्रालय ने नोट किया कि 'अनुकूल विकास के बीच, वर्तमान आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर और आय में उपभोक्ता विश्वास में गिरावट आई है, जैसा कि आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के वर्तमान स्थिति सूचकांक में परिलक्षित होता है।'

पिछले सर्वेक्षण दौर की तुलना में आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक स्थितियों के बारे में हाऊसहोल्ड आशावादिता में कमी आई है। इसके अलावा, 'सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और कीमतों पर कम आशावाद के कारण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के भविष्य की उम्मीदों के सूचकांक में भी कमी आई है।' आमतौर पर, आर्थिक मॉडल भविष्य की मुद्रास्फीति के लिए एक मार्गदर्शक संकेतक के रूप में उपभोक्ता की मुद्रास्फीति की उम्मीद को एक बड़ा महत्व देते हैं। एक बार जब मुद्रास्फीति की उम्मीदें स्थिर हो जाती हैं, तो कीमतों का भविष्य इससे प्रभावित होता है।

स्पष्ट विरोधाभास को देखें। उपभोक्ता और बुनियादी आर्थिक इकाइयां भविष्य के बारे में निराशावादी हैं, हालांकि वर्तमान स्थिति का आकलन करना बुरा नहीं है। यह विरोधाभासी मूल्यांकन कैसे हुआ ? हो सकता है, लोगों को शासन संरचनाओं में पर्याप्त विश्वास न हो। यह उन लोगों में विश्वास की कमी है जो ड्राइवर की सीट पर हैं। लेकिन, फिर, नीति निर्माण में रिजर्व बैंक की समस्या पर विचार करें। यह एक 'पहेली' का सामना कर रहा है। यदि आप उदार नीति अपनाते हैं तो आप मुद्रास्फीति की आग को भड़काते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप विकास को पूरी गति से आगे बढ़ाने का अवसर खो देते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपके पत्र

अनावश्यक बयान देकर सांसद कंगना रनौत मुश्किल में

चलचित्र अदाकारा एवं हिमाचल के मंडी लोकसभा की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में आ जाती हैं. कंगना रनौत का ताजा वक्तव्य बीजेपी को नागवार गुजारा है और सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी बातें न करें। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'जो किसान आंदोलन हुआ, वहां लाश लटक रही थी एवं वहां रेप हो रहे थे और आशंका जताई कि इन 'उपद्रवियों' की बहुत बड़ी प्लान थी. आज किसानों का मुद्दा इतना गर्म नहीं रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है लेकिन कंगना रनौत ने बयान देकर अनावश्यक चर्चा को बढ़ावा दिया है, जिसको विपक्ष और किसान संगठनों ने हाथों-हाथ लपका है और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन चुनाव में हमेशा बड़ी भूमिका रही है। ऐसी अनावश्यक चर्चा के कारण बीजेपी को एक बड़ी चुनौती कांग्रेस से मिलेगी। केंद्र सरकार को इस मुद्दे को जितना जल्दी हल कर सके कर लेना चाहिए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी दखल देते हुए इस मुद्दे पर एक कमेटी का गठन करने का आदेश पारित हुआ है और सरकार से लगातार वार्ता जारी करने का निर्देश भी दिया है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

बेतुके बयानबाजी करने से बचें

भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल से मंडी की सांसद महोदया और अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसानी आंदोलन पर दिए गए बेहद दुखद और शर्मनाक बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम जानते हैं कि किसानी आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चला था। किसानों द्वारा किए गए प्रयासों के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। एक साल से अधिक चले आंदोलन में लगभग 700 किसानों की मौत हुई थी। उस समय भी कंगना रनौत द्वारा बेहद घटिया बयान दिए गए। किसान आंदोलन में बैठी माताओं के बारे में बहुत गलत बोला था। उनके इन निम्न स्तर के बयानों के कारण ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडी लोकसभा सीट से टिकट दी गई और वे सांसद बन गई। लेकिन अभी इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कंगना से किनारा किया वो बिल्कुल सही है। अक्सर देखने को मिलता है कि इस पार्टी में जो ज्यादा बेतुके बयान दे उसको आगे किया जाता है। लेकिन इस बार पार्टी ने जो कार्रवाई की है वो अगर 2024 के चुनावों के पहले बेतुके बयान देने वालों के खिलाफ की होती तो यह पार्टी बहुमत से दूर कभी नहीं जाती। कंगना रनौत अब लोगों की प्रतिनिधि है ? उनको ऐसे बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं ने पहले ही इनका बहुत नुकसान किया है भविष्य में इनको सम्भल कर चलना चाहिए।

- सिमरन रंधावा, वेरका

ललित सुरजन की कलम से

कश्मीर : समाधान के लिए प्रतीक्षा

'भारत में बड़ी हद तक जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही जम्मू-कश्मीर का प्रशासन चलने की गुंजाइश शुरू से बना रखी है। इसके अपवाद गिनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर अपवाद निर्मित होने की स्थितियां क्यों बनीं, उन कारणों में भी जाने की आवश्यकता होगी और हम मौजूदा चर्चा से भटक जाएंगे। मुख्य बात यह लिखने की है कि प्रदेश में अब तक चार-पांच पार्टियों और गठबंधनों का अलग-अलग समय में शासन रह चुका है। याने जनतंत्र के रास्ते चलने में सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। इसके बावजूद अगर घाटी में अविश्वास का वातावरण बना हुआ है तो उसका एक प्रमुख कारण शायद यह भी है कि हिन्दू-बहुल शेष भारत मुस्लिम-बहुल कश्मीर पर विश्वास नहीं करता तथा हिन्दूत्ववादी ताकतें उसकी देशभक्ति पर निरंतर संदेह की उंगली उठाती रहीं हैं। वे बहुत आसानी से 1947 के पहले नागरिक शहीद मकबूल शेरवानी और पहले सैनिक शहीद बिग्रेडियर उस्मान के सर्वोच्च बलिदान को भुला देते हैं। मेरी तो यह जानने की भी इच्छा है कि हाशिम कुरैशी ने 1971 में विमान अपहरण क्यों किया, पाकिस्तान ने उसका सत्कार करने के बजाय उसे जेल में क्यों डाला, उसे नार्वे में किसके कहने से शरण मिली तथा प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने उसे भारत वापस क्यों बुलाया ?'

(देशबन्धु में 21 जुलाई 2016 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/07/blog-post_20.html

पावन प्रसंग

चिंता से मानसिक शांति का क्षरण

चिंता सभी को होती है। ऐसा कोई नहीं जिसे चिंता न घेरती हो। कोई कम चिंता करते हैं, तो कोई अधिक, लेकिन करते सभी हैं। जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो दिमाग में स्वतः ही तरह-तरह की आशंकाएं आ जाती हैं, जो चिंता का रूप ले लेती हैं। जब हमें चिंता घेरती है तो हम उससे निकलने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा करके हम और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक द्वंद्व को और बढ़ा लेते हैं क्योंकि विचार करने मात्र से चिंता का समाधान नहीं हो पाता, विचार तो खुद एक तरह की चिंता है।

यदि चिंता पर बहुत ध्यान दिया जाए तो उससे चिंता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। विचार करके केवल चिंता निवारण का उपाय खोजा जा सकता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। चिंता एक तरह से मन की कल्पना है, जो वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं होती। इसीलिए इसे दूर करने के लिए सजग होने, कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। बिना कुछ किए केवल सोचने मात्र से चिंता कम होने के बजाय बढ़ेगी ही। इसीलिए यदि सजग रहा जाए तो चिंता नहीं घेरेगी।

एक झेन फकीर बोकोजू एक गुफा में रहते थे। दिन में या कभी-कभी रात में भी वह जोरों से कहते थे-'बोकोजू !' और फिर वह खुद कहते-'हां, मैं मौजूद हूं।' वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे- आप इस तरह से अपना ही नाम क्यों पुकारते हैं ? बोकोजू ने जवाब दिया-'जब भी मैं अचेतन में डूबने लगता हूं, तो मुझे सजग होना पड़ता है और इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। जिस क्षण मैं 'बोकोजू' कहता हं और कहता हूं कि हां, मैं मौजूद हूं। उसी क्षण अचेतन से उपजती शंकरएं विलीन हो जाती है' अपने अंतिम दिनों में उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा तो शिष्यों ने पूछा- गुरुदेव, अब आप वैसा क्यों नहीं करते ? तब बोकोजू ने कहा-अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं रहती। पहले मैं खो जाता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था।

यही सच है कि हम अपने वर्तमान में होते हुए भी भूत या भविष्य में खो जाते हैं और तब चिंता हमें घेर लेती है। इसीलिए यदि हम अपने वर्तमान में रहते हुए सजग रह सकें तो चिंताएं आएंगी जरूर, लेकिन हमें अपनी कैद में नहीं ले पाएंगी। वर्तमान में रहकर जीवन-जीने के बहुत सारे उपाय हैं, जिन्हें लोगों ने अपनाया है और इनसे चिंताएं दूर भगाई हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहते थे-'काम करो, चिंता अपने आप नहीं आएगी।' चर्चिल द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 18 घंटे काम करते थे और अक्सर कहते-'मेरे पास इतना काम है कि मुझे चिंता करने की फुर्सत ही नहीं मिलती।' उन्होंने चिंता से बचने के लिए काम में जुटे रहने को अनिवार्य माना। जो सदा अपने कार्य में संलग्न रहते हैं चिंता भी उनसे दूर ही रहना पसंद करती है।

चिंता के विषय में जार्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था- खाली समय में अपने सुख-दुख पर विचार करना ही दुखी होने का कारण है। इसलिए व्यर्थ बातें न कीजिए और न ही उन्हें सोचिए, तभी आप चिंता मुक्त रह सकते हैं।

युग निर्माण योजना

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

सुभाषित

जब मनुष्य अपनी वासनाओंपर नियंत्रण कर लेता है तो आत्माकी ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। ❐ **महर्षि वाल्मिकी**

खाद्य कीमतोंपर सतर्कता जरूरी

रिजर्व बैंकने अपनी ताजा रिपोर्टमें कहा कि यद्यपि देशमें बेहतर मानसून, अच्छे मौद्रिक प्रबंधन और सरकार द्वारा तत्परतासे महंगी नियंत्रणके बावजूद अब भी खाद्य कीमतोंपर सतर्कता जरूरी है। महंगीपर सरकारकी चिंता है और अब सरकारने संकेत दिया है कि महंगी नियंत्रणके लिए बहुआयामी रणनीतिपर फोकस होगा।

❐ **डा.जयंतीलाल भंडारी**

पहालमें २२ अगस्तको वित्त मंत्रालयके द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्टमें कहा गया है कि जुलाई २०२४ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनमें प्रगतिके कारण खरीफकी बोआई अच्छी हुई है और खाद्य पदार्थोंकी महंगी दरमें और कमी आ सकती है। इसी तरह पिछले दिनों १९ अगस्तको रिजर्व बैंकने अपनी ताजा रिपोर्टमें कहा कि यद्यपि देशमें बेहतर मानसून, अच्छे मौद्रिक प्रबंधन और सरकारके द्वारा तत्परतासे महंगी नियंत्रणके उपायोंसे महंगी घटनेका सुकूनदेह परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी खाद्य कीमतोंपर सतर्कता जरूरी है। केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानने कहा है कि वर्ष २०२४-२५ के बजटके तहत शीघ्र खराब होनेवाले सामानकी बाजारमें समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करनेके लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं। बजटके तहत उपभोक्ता मामलोंके विभागको दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए दस हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। जहां इस कोषका उपयोग दाल, प्याज और आलूके बफर स्टॉकको रखनेके लिए किया जायगा, वहीं जरूरी होनेपर इन अन्य खाद्य वस्तुओंके बढ़े दामोंको नियंत्रित करनेके लिए भी इस कोषका इस्तेमाल किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि १४ अगस्तको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा प्रकाशित आंकड़ोंके मुताबिक थोक महंगी जुलाई २०२४ में घटकर तीन महीनेके निचले स्तर २.०४ प्रतिशतपर आ गयी। यह जूनमें ३.३६ प्रतिशत थी। खास बात यह भी है कि १२ अगस्तको जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगीके आंकड़ोंके अनुसार जुलाई २०२४ में खुदरा महंगी दर घटकर ३.५४ फीसदी रह गयी है, जबकि जून २०२४ में खुदरा महंगी दर ५.०८ प्रतिशत थी। सुकूनदेह स्थिति यह है कि खुदरा महंगी दर पिछले पांच वर्षोंके सबसे कम और रिजर्व बैंकके द्वारा निर्धारित चार प्रतिशतके लक्ष्यसे भी नीचे आ जानेसे अर्थव्यवस्थाको मजबूती मिलते हुए दिखाई देगी। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि बेहतर मानसूनसे खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों विशेषतया आलू, प्याज और टमाटर आदिकी कीमतोंमें बड़ी कमी आनेसे खुदरा महंगी दरमें कमी आयी है। पिछले दिनों ८ अगस्तको आरबीआईने देशमें बढ़ती हुई महंगीको देखते हुए मौद्रिक नीति समीक्षाके तहत रेपो रेटको पहलेकी तरह ६.५ प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह लगातार नौवीं बार है जब मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकमें रेपो रेटको यथावत रखनेका फैसला किया गया है। आखिरी बार रेपो रेटमें फरवरी २०२३ में बदलाव किया गया था। इस मौद्रिक नीति समीक्षाके तहत तेज विकास दरकी बजाय महंगी नियंत्रणको प्राथमिकता दी है। भारतीय रिजर्व बैंकके गवर्नर शक्तिकांत दासने कहा कि निरन्तर आर्थिक विकासको ध्यानमें रखते हुए अब भी महंगीपर स्पष्ट तरीकेसे ध्यान केंद्रित करनेकी जरूरत है। रिजर्व बैंक और सरकारके समन्वित प्रयासोंसे महंगी नियंत्रणके लगातार रणनीतिक कदम जरूरी हैं। केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानके मुताबिक वर्ष २०२४-२५ के बजटके तहत उपभोक्ता मामलोंके विभागको दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए जो धनराशि सुनिश्चित की गयी है, उससे खाद्य भंडारणसे जुड़ी एजेंसियोंको धन मुहैया कराया जायगा, ताकि वे उपयुक्त भंडारण बनानेके लिए किसानोंके खेत या मंडीसे सीधे खरीददारी कर सकें। इसके अलावा नये बजटके तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभागके लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंगके लिए ऋणोंकी राशि दोगुनी करके ५०,००० करोड़ रुपये सुनिश्चित की गयी है। नि:संदेह नये बजटके तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे अधिक खाद्यान्न उत्पाद और महंगी नियंत्रणको प्रोत्साहन मिलेगा। प्राकृतिक खेतीपर भारी प्रोत्साहन सुनिश्चित किये गये हैं और आगामी दो वर्षोंमें एक करोड़ किसानोंको प्राकृतिक खेती अपनानेके लिए प्रोत्साहित किया जायगा। देशभरमें दस हजार बायो इनपुट सेंटर बनाये जायंगे, जहांसे प्राकृतिक खेतीकी गतिविधियां संचालित होंगी। मौसमकी मारके कारण खराब होनेवाली फसलोंके लिए समर्थन राशि बढ़ाई जानेसे कृषिको नया प्रोत्साहन मिलेगा। नये बजटमें जलवायु परिवर्तनकी चुनौतियोंसे निबटने, दलहन-तिलहनकी पैदावार बढ़ाकर और किसानोंकी आय बढ़ाने, बीजकी समस्याके निराकरण और मुख्य फसलोंकी उत्पादकता प्रभावित होने जैसे मामलोंकी चुनौतियोंको कम करनेके साथ-साथ कृषि शोधके विकासके लिए ज्यादा प्रावधान किये हैं। गौरतलब है कि ११ अगस्तको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने नयी दिल्लीमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसरके खेतोंमें जाकर ६१ फसलोंकी १०९ नयी एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देशमें कम जमीनमें अधिक पैदावार लेने और किसानोंकी आय बढ़ानेमें मदद मिल सकेगी। इससे महंगीसे भी बचाव होगा। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकारको इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासतमें मिला है, उससे भी महंगीमें और कमी आयगी। पूरे देशके कोने-कोनेमें बेहतर मानसूनके लाभ दिखाई देने लगे है। कृषि मंत्रालयने १२ अगस्तको खरीफ फसलोंका रकबा बढ़ने संबंधी रिपोर्टमें कहा है कि चालू खरीफ सीजनमें अबतक खरीफ फसलोंकी बोआई ९८० लाख हेक्टेयरके स्तरपर पहुंच गयी है, जो पिछले सालकी समान अवधिमें ९६६ लाख हेक्टेयर ही थी। इस साल अच्छे मानसूनसे दाल, तिलहन और अनाजका उत्पादन बढ़ेगा और इनकी सप्लाई बढ़नेसे इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसूनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाकेमें खपत बढ़ेगी। निश्चित रूपसे रिजर्व बैंककी मौद्रिक नीति, सरकारके वित्तीय नियंत्रण और बेहतर मानसूनसे जिस तरह महंगीमें कमी आयी है, अब इसे नियंत्रित रखनेके साथ-साथ ग्रामीण भारतकी आर्थिक ताकतमें इजाफा करनेके लिए कुछ अहम बातोंपर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा। इस समय ग्रामीण भारतमें जल्द खराब होनेवाले ऐसे कृषि उत्पादोंकी आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करनेपर प्राथमिकतासे काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगीके उतार-चढ़ावमें ज्यादा भूमिका होती है। ऐसेमें सरकारको खाद्य उत्पादनमें वृद्धिके साथ-साथ कृषि उपजकी बर्बादीको रोकनेके बहुआयामी प्रयासोंकी कारगर रणनीतिपर आगे बढ़ना होगा। हम उम्मीद करें कि अगस्त २०२४ में जिस तरह खुदरा उपभोक्ता महंगी रिजर्व बैंकके द्वारा निर्धारित चार फीसदीके लक्ष्यसे भी कम है, उसी तरह सरकार भविष्यमें भी खुदरा महंगी दरको पूर्णतया नियंत्रित रखनेके लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार नये दाम स्थिरीकरण कोष तथा खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंगके लिए किये गये प्रभावी बजट आवंटनोंके कारगर उपयोगपर शुरुआतसे ध्यान देगी। साथ ही सरकार कृषि प्रौद्योगिकीके इस्तेमाल, खाद्य पदार्थोंकी बरबादीको कम करने, कृषिमें मशीनीकरणको बढ़ाये जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाये जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कोंको मंडियोंसे जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओंके साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलामें सुधारसे खाद्य वस्तुओंकी महंगीको नियंत्रित रखनेके कारगर प्रयासोंकी डगरपर लगातार आगे बढ़ेगी।

बेहतर मानसूनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाकेमें खपत बढ़ेगी। निश्चित रूपसे रिजर्व बैंककी मौद्रिक नीति, सरकारके वित्तीय नियंत्रण और बेहतर मानसूनसे जिस तरह महंगीमें कमी आयी है, अब इसे नियंत्रित रखनेके साथ ग्रामीण भारतकी आर्थिक ताकतमें इजाफा करनेके लिए कुछ अहम बातोंपर ध्यान देना जरूरी है। जल्द खराब होनेवाले कृषि उत्पादोंकी आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करनेपर प्राथमिकतासे काम करना होगा। ऐसेमें सरकारको खाद्य उत्पादनमें वृद्धिके साथ कृषि उपजकी बर्बादीको रोकनेके बहुआयामी प्रयासोंकी रणनीति अपनानी होगी।

छोटे कर्जकी सुगम योजना

छोटे कारोबारियोंके समक्ष पूंजीका संकट सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण उनके कारोबारपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे कारोबारी बाजारसे महंगा कर्ज लेनेको विवश हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव उनकी लागतपर पड़ता है। लागत बढ़नेसे उनका लाभ भी कम हो जाता है, क्योंकि कर्जकी अदायगीमें उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे कारोबारियोंकी समस्याओंको ध्यानमें रखते हुए उनके लिए एक राहतकारी योजना तैयार की है। इससे उनकी पूंजीकी समस्या काफी हदतक कम हो सकती है। रिजर्व बैंकके गवर्नर शक्तिकांत दासने बेंगलुरुमें आयोजित एक वैश्विक सम्मेलनमें घोषणा की है कि देशमें छोटे कारोबारियोंको आसानीसे कर्ज मिल सके इसके लिए एक नया प्लेटफार्म शीघ्र ही लांच किया जायगा, जहांसे उन्हें बाधारहित कर्ज आसानीसे मिल सके। इससे किसान, एमएसएमई और खुदरा कारोबारी आसनीसे छोटे कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। यह कार्य यूनीफाइड लैण्डिंग इण्टरफेस (यूएलआई) प्लेटफार्मके माध्यमसे सम्पन्न हो सकेगा। रिजर्व बैंकने पिछले वर्ष बाधारहित कर्ज वितरणके लिए पायलट प्रोजेक्टके आधारपर एक टेक्नालाजी प्लेटफार्मकी शुरुआत की थी। अब इसे यूएलआई प्लेटफार्मसे देशव्यापी स्तरपर लांच किया जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और उभरती टेक्नालाजी विश्वमें लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओंको भविष्यकी यात्राको आकार देगी। केन्द्रीय बैंक लगातार ऐसी नीतियां, प्रणालियां और प्लेटफार्म तैयार करनेकी दिशामें कार्य कर रहा है। इससे वित्तीय क्षेत्र मजबूत होनेके साथ ही यह ग्राहक केन्द्रित होगा। उनका यह भी कहना है कि सभी संकेतोंसे पता चलता है कि आनेवाले वर्षोंमें यह प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। यूएलआईसे क्रेडिट मूल्यांकनमें लगनेवाला समय कम होगा। इसका एक कारण यह भी है कि नये प्लेटफार्मसे तकनीकी एकीकरण जटिलता कम होगी और कर्जके लिए ज्यादातर दस्तावेजोंकी आवश्यकता नहीं होगी। शक्तिकांत दासने यह भी भरोसा दिया है कि जिस तरह यूपीआईने पेमेण्ट इकोसिस्टमको बदला है उसी प्रकार यूएलआई ऋण क्षेत्रको बदलनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। निश्चित रूपसे रिजर्व बैंका नया प्लेटफार्म छोटे कर्जोंके लिए राहतकारी है। यह हर दृष्टिसे सुगम और उपयुक्त है। छोटे कर्जकी मांग भी बढ़ेगी और इससे कारोबारी गतिविधियोंको गति मिलेगी तथा कारोबारियोंकी समृद्धि भी बढ़ेगी।

बलूच विद्रोहियोंका हमला

पाकिस्तानके बलूचिस्तान प्रान्तमें सोमवारको बलोच विद्रोहियोंके हाईवे, रेलवे ब्रिज और पुलिस थानेपर किये गये हमलों और सुरक्षाबलोंकी जवाबी काररवाईमें दोनों ओरसे लगभग ७३ लोगोंकी मौत हो गयी। पाकिस्तान सरकारकी माने तो इस संघर्षमें ३८ नागरिक एवं १४ सैनिक, पुलिसके जवान मारे गये, जबकि २१ हमलावरोंके मारे जानेका दावा किया गया है। विद्रोहियोंने अपने सबसे बड़े हमलेमें बस यात्रियोंको उतारकर उनका पहचान-पत्र देखनेके २३ लोगोंको गोलियोंसे भून डाला। इस घटनाओंकी जिम्मेदारी चरमपंथी संघटन बलूच लिबरेशन आर्मीने ली है। संसाधन सम्पन्न प्रान्तपर नियंत्रणके लिए दशकोंसे चल रहे विद्रोहके तहत यह पिछले कई वर्षोंसे किया जा रहा सबसे बड़ा हमला है। दरअसल १९४८ में पाकिस्तानमें जबरन शामिल करनेके बादसे बलूचिस्तान प्रान्त अशान्त और विद्रोह क्षेत्र बना हुआ है। पाकिस्तानकी बलूचिस्तानमें शोषण, उपेक्षा और दमनके खिलाफ बलोच विद्रोही संघर्ष कर रहे हैं। यह क्षेत्र काफी लम्बे समयसे अपने प्राकृतिक संसाधनोंके बड़े पैमानेपर हो रहे दोहनसे भी जूझ रहा है। चरमपंथी बलूच विद्रोही प्रान्तके संसाधनोंपर यहांके लोगोंका अधिकार जताते हुए दशकोंसे संघीय सरकारका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगोंका सरकारोंपर बलूचिस्तानके संसाधनोंका दोहन कर मुनाफा कमाने और इलाकेके विकासकी उपेक्षा करनेका आरोप लगाते रहे हैं। ये दक्षिणी बलूचिस्तानमें चीनके विकसित किये जा रहे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ग्वादर बंदरगाह, सोने और तांबेकी खानोंके दोहनका भी विरोध कर रहे हैं। यह भी सच है कि बलूचिस्तान एशियामें सोना, तांबा, कोयला और गैसके सबसे बड़े भण्डारोंमें एक है और चीनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओंको अंजामतक पहुंचानेके लिए खास जगह है, जो भारतके लिए खतरेकी घण्टी है। ऐसेमें यह समूह बूलचिस्तानको विदेशी प्रभाव, विशेष रूपसे चीन और पाकिस्तानी सरकारसे लोगोंको निजाद दिलाना चाहता है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सत्तामें बैठे लोगोंका भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और चरमपंथियोंकी निर्णायक भूमिकामें होनेसे स्थितियां बदतर हुई है। पाकिस्तानको इन सभी चीजोंसे निजात पाना होगा, तभी इस समस्याका समाधान हो सकता है।

लोक संवाद

पेंशनर होंगे लाभान्वित

महोदय,-केन्द्र सरकारने यूपीएस लागू करनेका फैसला किया है। चुनावोंमें विपक्षका पुरानी पेंशन योजना लागू करनेकी घोषणाके बाद केन्द्र सरकारने काट निकाल दी है। यूपीएसके तहत कर्मचारियोंको २५ साल काम करनेपर पूरी पेंशन मिलेगी। पेंशनरोंको बड़ी राहत देते हुए मोदीकी अध्यक्षतामें यूपीएस लागू करनेका निर्णय किया गया। योगी आदित्यनाथ और उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्यने मोदीका आभार व्यक्त किया है। मूल वेतनका ५० प्रतिशत रकम पेंशनके रूपमें दी जायगी। केन्द्र सरकारने यूनीफाइड पेंशन स्कीमको मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियोंने २५ साल सेवा दी है। उनके अंतिम कार्यवर्षके १२ महीनोंमें ५० प्रतिशत बतौर राशि पेंशन दी जायगी। केन्द्र सरकारका यह महत्वपूर्ण फैसला बुजुर्गोंके चेहरे खिलनेके निमित्त बना दिया है। सुनिश्चित पेंशन परिवारको पेंशन न्यूनतम पेंशन और पेंशनकी राशिको महंगी दरके साथ जोड़ने और सेवानिवृत्तके साथ ग्रेच्युटीके अलावा एक सुनिश्चित राशिके अलावा एक सुनिश्चित राशिके भुगतानकी व्यवस्था सरकारका मकसद है। सरकारकी तरफसे पेंशन फंड १४ प्रतिशतसे १८.५ प्रतिशत कर दिया है। केन्द्र सरकारका ६२५० करोड़का बोझ २०२६ तक बढ़ेगा। २०२५ से लागू होनेवाली योजनामें २३ लाख कर्मचारियोंके लिए यूपीएस महत्वपूर्ण है और एनपीएससे बढ़िया योजना लागू की जा रही है। धीरे-धीरे फायदा दिलानेवाली योजनाओंपर सरकार फैसला दे रही है, जिसमें अनेक योजनाएं गरीबोंके लिए फायदेमंद होगी। विपक्षी दलोंपर जिम्मेदारी बढ़ गयी है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे पेंशनर्सको लुभानेकी कोशिश की जाय। हरियाणा और जम्मू-कश्मीरमें घोषणा हो चुकी है और झारखंड और महाराष्ट्रमें चुनावकी घोषणा बाकी है। सेवानिवृत्त कर्मचारीकी मृत्यु होनेपर दस हजारकी पेंशन दी जायगी। खुदरा महंगी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। छह माहका वेतन एक मुश्त मिलेगा। केन्द्र सरकारकी इस योजनासे पेंशनरोंके चेहरे खिल गये हैं। **- कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

देशमें खेलका भ्रामक परिदृश्य

पाकिस्तान २०२४ पेरिस ओलंपिकमें पदक तालिकामें आगे रहकर भारतको शर्मिन्दा कर गया। देशमें खिलाड़ियोंपर चार अरब ७० करोड़ रुपये खर्च करनेके बावजूद भारत एक स्वर्ण पदकतक हासिल नहीं कर सका।

❐ **योगेंद्र**

ओलंपिक खेलोंमें भारतका बेहद निराशाजनक प्रदर्शन बताता है कि सिर्फ जीडीपीमें पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बननेसे इस दिशामें कुछ हासिल होनेवाला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तरपर बेहतर प्रदर्शनके लिए खेलोंमें संसाधनोंके साथ खेल संस्कृतिका जज्बा जरूरी है। पाकिस्तान ही नहीं, अफ्रीकाके ऐसे देश, जो दशकोंसे घरेलू युद्धका बेहद गरीबीमें सामना कर रहे हैं, वे भी ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेलोंके आयोजनमें भारतको पछाड़ गये। भारतीय टीमसे उम्मीद की गयी थी कि वह टोक्यो ओलंपिकसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पेरिस ओलंपिकमें भारतीय टीम पिछले ओलंपिकसे एक मेडल कम रह गयी। टोक्यो ओलंपिकमें एक मेडलके मुकाबले पेरिसमें छह मेडल आये हैं। इसमें पांच ब्रांज और एक सिल्वर है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ाने जीता। केन्द्र सरकारने ओलंपिकमें अच्छा प्रदर्शन करनेके लिए खिलाड़ियोंपर अरबोंपर रुपये खर्च किये थे, लेकिन उसका परिणाम सुखद नहीं रहा है। पेरिस ओलंपिकमें भारतकी तरफसे १६ खेलोंमें ११७ एथलीट गये थे। इसपर भारत सरकारने कुल ४७० करोड़ रुपए खर्च किये थे। एथलेटिक्सके अलग-अलग खेलोंके लिए कुल ९६.०८ करोड़ रुपये जारी किये गये थे। बैडमिंटनपर ७२.०३ करोड़, बॉक्सिंगपर ६०.९३ करोड़, शूटिंग ६०.४२ करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हॉकीपर ४१.३ करोड़ और रेसलिंगपर ३७.०८ करोड़, आर्चरीमें ३९.१८ करोड़ खर्च हुए थे। इसके अलावा वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, नौकायन जैसे खेलोंपर भी करोड़ों खर्च हुए थे। औसतन एक मेडलके लिए सरकारको ७८ करोड़ खर्च करने पड़े। भारतके लिए नीरज चोपड़ाने जैवलिनमें सिल्वर, मनु भाकर और सरबजीत सिंहने शूटिंगमें ब्रांज, भारतीय हॉकी टीमने ब्रांज, अमन सहरावतने कुश्तीमें ब्रांज जीता। मनु भाकरने दो ब्रांज मेडल जीते थे। दूसरी तरफ भारतके पड़ोसी पाकिस्तानने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन वह भारतसे मेडल टैलीमें आगे निकल गया है, क्योंकि मेडल टैलीमें उसे ऊपर रखा जाता है, जो स्वर्ण पदक जीतता है। भारतने पेरिस ओलंपिकमें कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, जबकि पाकिस्तानके एक गोल्ड जीतते ही लॉटरी लग गयी है। पेरिस ओलंपिक २०२४ की मेडल टैलीमें भारत ७१वें नंबरपर है तो वहीं पाकिस्तान ६२वें नंबरपर मौजूद है। हर विश्व चैंपियनशिपके दौरान भारतके निराशाजनक प्रदर्शनके बाद कई सवाल पूछे जाते हैं। हमारी टीमें अकसर गुस्साये और निराश दर्शकोंके सामने लौटती हैं और हम अपने मेहनती खिलाड़ियोंपर भी अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। खेलोंमें भारतकी दुर्दशाका आलम यह है कि हॉकीके अलावा अन्य टीमवाले खेलोंमें भारतका विश्व स्तरपर अता-पतातक नहीं है। इसमें महिला टीमके खेलोंकी हालत और भी ज्यादा शोचनीय है। देशमें खेलके लिए पर्याप्त वातावरण नहीं होनेके अलावा लैंगिक भेदभाव भी खेलोंमें भारतीय महिलाओंके पिछड़नेकी प्रमुख वजह है। भारतके ओलंपिकमें निराशाजनक प्रदर्शनका कारण भारतकी विश्व स्तरपर खराब रैंकिंग भी है। भारतीय टेनिस टीम विश्वमें २३वें स्थानपर है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम १२७ देशोंमेंसे ३४वें स्थानपर है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ११३ खेलनेवाले देशोंमेंसे सौवें स्थानपर है। भारतीय बास्केटबॉल टीम ८५ देशोंमेंसे ६१वें स्थानपर है। नवीनतम फीबा रैंकिंग रिपोर्टमें हमारी रग्बी टीम १०२ खेलनेवाले देशोंमेंसे ७४वें स्थानपर है। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी आबादी, क्षेत्रफल और अर्थव्यवस्थावाले देशकी हालत खेलोंके प्रदर्शनमें इतनी खराब कैसे है। खेलोंकी सुविधाओंमें निवेश करनेकी भी जरूरत है। चीनने ऐसा किया और कमालका प्रदर्शन किया। ब्रिटेनने ऐसा किया और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान आदिने भी यही किया। जाहिर है कि अमेरिकाके पास निवेश और एक बड़ी आबादी है जो कई ओलंपिक खेलोंके लिए जुनूनी है, इसलिए उनका सामान्य प्रभुत्व है। लेकिन केन्या और इथियोपिया या जमैका जैसे देशोंको देखें और जिस तरहसे वे आर्थिक रूपसे शक्तिशाली न होते हुए भी लगातार विशेष खेलोंमें विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करनेमें सक्षम रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास उन प्रतियोगिताओंमें भाग लेनेकी परम्परा है और उन देशोंके बच्चे शायद वहांके लोगोंको अपना आदर्श मानते हुए बड़े होते हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेलोंमें भाग लिया है और जीत हासिल की है। चीनी टेनिस खिलाड़ी झेंग किनवेन, जिसने हालमें ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, ने टेनिस खेलना शुरू करनेके बादसे अबतक २.८ मिलियन अमेरिकी डालरसे अधिक खर्च कर दिये हैं। २.८ मिलियन डालर एक चीनी परिवारके लिए कोई छोटी रकम नहीं है, भारतीय परिवारकी तो बात ही छोड़िये। यहांतक कि अनुभवी एथलीटोंके लिए भी प्रतियोगितामें पुरस्कार राशि जीतनेकी सौ प्रतिशत गारंटी नहीं होती। चीनी मीडियाका दावा है कि भारतमें लड़कोंको खेलोंके बजाय डाक्टर और इंजीनियर बनानेपर अधिक ध्यान दिया जाता है। वहीं चीनमें तीनसे ज्यादाकी उम्रके बच्चे बेहद कड़ी ट्रेनिंगसे गुजरते हैं। इस तकलीफको सहकर ही वे चैम्पियन बननेकी कला सीखते हैं। चीनके पास एक तय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलोंका माडल है जिसके जरिये उसका पैसा ट्रेनिंगपर ही खर्च होता है और चूंकि चीन खेलोंपर अपने खर्चेके हिसाबसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओंमें पदक ले आता है तो वह अपने माडलको तुलनात्मक रूपसे सफल मानता है। चीन ओलंपिक खेलोंकी मेडल टैलीमें लगातार अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिकाको पछाड़ कर नंबर वन होनेकी कोशिश करता रहा है। चीनने अपने देशके अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलोंका मॉडल खड़ा कर रखा है, जिसके जरिये वह अच्छे एथलीट्स तैयार करता है। भारतमें हर बच्चा किसी पॉप स्टार, किसी फिल्म स्टार या किसी अन्य सेलिब्रिटीको अपना आदर्श मानता है। इस सूचीमें खेलोंमें सिर्फ क्रिकेट शामिल है, जो कि बेहद महंगा होनेके साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल नहीं है। क्रिकेट एशियाई और ओलंपिकमें शामिल नहीं है। युवा यदि थोड़ा-बहुत खेलोंके प्रति आकर्षित हैं भी तो क्रिकेटकी तरफ। ऐसा क्रिकेटमें ग्लैमर और पैसा होनेके कारण है। ओलंपिक या किसी भी विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगितामें भारतको सफल होनेके लिए कड़ी मेहनत और दूरगामी नीतिकी जरूरत है। भारतमें खेलोंकी स्थिति रातों-रात नहीं बदलेगी। हालांकि हममेंसे प्रत्येक द्वारा उठाये गये छोटे-छोटे कदम हमें उस बिन्दुतक ले जायंगे जहां हम अंतत: सुधार देखना शुरू कर देंगे। भारतमें खेलोंकी संस्कृतिका निर्माण करना और भारतके नवजात खेल परिदृश्यको ऊपर उठानेकी जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा महान खिलाड़ी ही बने। फिर भी यह उनके मनमें खेलके बारेमें सकारात्मक धारणा बनानेमें काफी मददगार साबित होगा।

आत्मबोध

धूपम्का महत्व

❐ **जग्गी वासुदेव**

कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो जलनेपर सुगंध देते हैं और सुखद अनुभव मिलता है। वास्तवमें धूपम् वातावरणको शुद्ध करनेके लिए है, हमें सुगंध देनेके लिए नहीं। एक पहलू ये है कि इसकी गंध फैलती है। अलग-अलग जगहोंपर अलग-अलग ढंगकी ऊर्जा संरचनाएं होती हैं और यही वजह है कि भारतीय संस्कृतिमें, हमारे रहनेके कमरोंके आकार और नापपर खास ध्यान दिया जाता है। अलग-अलग तरहके आकारों और नापकी वजहसे अलग-अलग तरहकी ऊर्जा संरचनाएं बनती हैं। यदि ये संरचनाएं बहुत शक्तिशाली हों तो इनका असर आपकी भावनात्मक और मानसिक दशापर भी होता है। ये असर फायदेमंद भी हो सकता है या आप जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें बाधा भी दे सकता है। एक पदार्थ होता है, जिसे संब्रानी (लोबान) कहते हैं और ये एक बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ होता है। लोग शुभ कार्योंमें लोबान जलाते हैं, बीमार पड़नेपर इसे जलाते हैं। यह देखा गया है कि लोबान जलानेसे वहांकी हवामें, जमीन या फर्श और दूसरी सतहोंपर रहनेवाले कीटाणु मर जाते हैं। संब्रानी कुछ खास पेड़ोंसे टपकने वाला द्रव पदार्थ होता है। आप जंगलोंमें ऐसे बड़े-बड़े पेड़ देखेंगे जहां लोग इस संब्रानीको इकट्ठा करनेके लिए पेड़ोंके तनोंमें ही काट कर जगह बना लेते हैं। बाहरसे पेड़ ठोस दिखते हैं परन्तु उनके अंदर खोखली जगहें होती हैं जिनमें ये द्रव टपकता है। इस द्रवके टपकनेके प्राकृतिक कारण क्या हैं ये मैं नहीं जानता, परन्तु लोग इसे इकट्ठा करते हैं। ये मिलता कम मात्रामें है और कीमती होता है। इसे अच्छी मात्रामें पानेके लिए लोगोंको मीलोंतक चलना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ोंका लंबी उम्र वाला, पूरी तरहसे विकसित होना जरूरी है। ये कमसे कम ३० से ५० सालकी उम्रके होने चाहिए नहीं तो ये पदार्थ नहीं मिलता। वातावरणपर संब्रानीका शक्तिशाली असर होता है। इसमें सुगंध होना जरूरी नहीं है, परन्तु ये हवाको शुद्ध कर देता है और वातावरणको खुशनुमा बनाता है। यदि आप घरके अन्दर हल्का संब्रानी भी जलायें तो ये आपको बाहरकी खुली हवामें होनेका अहसास करायेगा, किसी एकदम खुली जगह जैसा, जहां कोई भवन निर्माण न हो।

दागी जनप्रतिनिधियोंपर काररवाई अति आवश्यक

❐ **अरविंद जयतिलक**

हालमें एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स) द्वारा अपनी रिपोर्टमें खुलासा किया गया है कि १५१ मौजूदा सांसदों और विधायकोंने अपने चुनावी हलफनामोंमें महिलाओंके खिलाफ अपराधसे संबंधित मामलोंकी जानकारी दी है। इनमें १६ मौजूदा सांसद और १३५ विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिताकी धारा ३७६ के तहत बलात्कारसे संबंधित मामलोंकी जानकारी दी है। ऐसे मामलोंमें दस सालकी सजाका प्रावधान है और इसे आजीवन कारावासतक बढ़ाया जा सकता है। इन माननीयोंमें भाजपाके ५४, कांग्रेसके २३, तेलुगु देशमके १७ सांसद-विधायकोंके अलावा कई अन्य दलोंके भी माननीयगण शामिल हैं। रिपोर्टके मुताबिक २५ सांसदों और विधायकोंके साथ पश्चिम बंगाल शीर्षपर है। अर्थात राज्यके तौरपर सर्वाधिक दागी इसी राज्यसे हैं। उल्लेखनीय है कि चुनाव सुधारके लिए काम करने वाली संस्था एडीआरने २०१९ और २०२४ के बीच चुनावोंके दौरान निर्वाचन आयोगको सौंपें गये मौजूदा सांसदों और विधायकोंके ४८०९ हलफनामोंमेंसे ४६९३ की जांच की, जिसमें यह तथ्य सामने आया है। विडंबना है कि दागी जन-प्रतिनिधियोंको लेकर सर्वोच्च अदालत लगातार चेतावनी दे रहा है इसके बावजूद भी संसद और विधानसभाओंमें पहुंचनेवाले दागी जन-प्रतिनिधियोंकी संख्यामें कमी नहीं आ रही। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलोंका ऐसे लोगोंसे परहेज नहीं है और न ही निर्वाचित करते समय जनता इसे तवज्जो दे रही है। यह स्थिति किसी भी संसदीय लोकतंत्रकी जीवंतताके लिए भयावह और खतरनाक है। याद होगा गत वर्ष पहले सर्वोच्च अदालतने पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकोंके खिलाफ उन लंबित आपराधिक मामलोंका निबटारा दो महीनेके दरम्यान करनेको कहा था जिनके ट्रायलपर रोक लगी हुई थी। तब जस्टिस एनवी रमनाकी अध्यक्षता वाली पीठने दो-टूक कहा था कि इस मामलेमें सुनवाई रोजाना हो और इसे बेवजह न टाला जाय। पीठने सभी उच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीशोंको भी ताकीद किया था कि इन निर्देशोंके पालनमें किसी तरहकी बाधा नहीं होनी चाहिए। वे इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके जरिये भी निबटायें। सर्वोच्च अदालतने यह भी निर्देश दिया था कि यदि किसी मुकदमेंमें उच्च न्यायालयने रोक लगा रखी हो तो उसे जल्दसे जल्द हटाया जाय। अच्छी बात है कि देशकी सभी अदालतें ऐसे मामलोंमें तेजीसे सुनवाई करते हुए निर्णय सुना रही हैं। देखा भी जा रहा है कि तमाम माननीयोंको संसद और विधानसभाओंकी सदस्यतासे हाथ धोना पड़ रहा है। सदनकी शोभा बढ़ानेवाले जेलकी सलाखोंके भीतर जा रहे हैं। दागियोंको लेकर सर्वोच्च अदालत कितना गम्भीर है वह इसीसे समझा जा सकता है कि वह प्रधान मंत्री एवं राज्यके मुख्य मंत्रियोंको भी ताकीद किया कर चुका है कि आपराधिक पृष्ठभूमिवाले दागी लोगोंको मंत्री पद न दिया जाय, क्योंकि इससे लोकतंत्रको क्षति पहुंचती है। सर्वोच्च अदालत यह भी कह चुका है कि भ्रष्टाचार देशका दुश्मन है और संविधानकी संरक्षककी हैसियतसे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियोंसे अपेक्षा की जाती है कि वे आपराधिक पृष्ठभूमिवाले लोगोंको मंत्री नहीं चुनेंगे। लेकिन विडंबना है कि अदालतके इस नसीहतका सियासी दलोंपर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। इसका प्रमुख कारण है कि सर्वोच्च अदालतने दागी सांसदों और विधायकोंको मंत्री पदके अयोग्य माननेमें सीधे हस्तक्षेपके बजाय इसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियोंके विवेकपर छोड़ दिया है। उसने व्यवस्थापिका और कार्यपालिकामें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। यहां ध्यान देना होगा कि दागी माननीयोंको लेकर सर्वोच्च अदालत एक-दो बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। लेकिन हर बार देखा जाता है कि राजनीतिक दल अपने दागी जन-प्रतिनिधियोंको बचाने और उन्हें टिकट देनेके लिए कुतर्क गढ़ते नजर आते हैं। याद होगा गत वर्ष पहले जब सर्वोच्च अदालतने जन-प्रतिनिधित्व कानूनमें संशोधनके जरिये दोषी सांसदों एवं विधायकोंकी सदस्यता समाप्त करने और जेलसे चुनाव लड़नेपर रोक लगायी तो राजनीतिक दलोंने किस तरह बखेडा खड़ा किया। अकसर राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक मंचोंसे मुनादी पीटा जाता है कि राजनीतिका अपराधीकरण लोकतंत्रके लिए घातक है। वे इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने और चुनावमें दागियोंको टिकट न देनेकी हामी भरते हैं। लेकिन जब उम्मीदवार घोषित करनेका मौका आता है तो दागी ही उनकी पहली पसंद बनते हैं। याद होगा गत वर्ष पहले सर्वोच्च अदालतने राजनीतिमें आपराधीकरणको रोकनेके लिए आदेश दिया था कि उम्मीदवार कमसे कम तीन बार अखबार और टीवी चैनलमें प्रचार कर अपनी अपराधिक पृष्ठभूमिको सामने लायें। न्यायालयके आदेशके बाद चुनाव आयोगने इस बारेमें एक अधिसूचना भी जारी की। लेकिन राजनीतिका अपराधीकरण नहीं रुका। देखा जाता है कि उम्मीदवार किसी भी छोटे-छोटे अखबारमें ब्यौरा देकर खानापूर्ति करनेमें सफल रहते हैं और यह जनताके संज्ञानमें नहीं आता है। यही नहीं वे टीवी चैनलोंमें समय तय न होनेके कारण देर रात इस बारेमें प्रचार करते हैं और उसे जनता देख नहीं पाती है। नतीजा दागियोंका असली चेहरा जनताके सामने नहीं आता है। उसका नतीजा यह होता है कि भारतीय जनमानसमें दागियोंके साखको तनिक भी बट्टा नहीं लगता। मजेदार बात यह भी कि राजनीतिक दल भी इसे संज्ञान लेनेमें रुचि नहीं दिखाते हैं। उल्टे चुनावी समयमें दागी उम्मीदवारोंपर ही भरोसा जताते नजर आते हैं। दरअसल राजनीतिक दलोंको विश्वास हो चुका है कि जो जितना बड़ा दागी है उसके चुनाव जीतनेकी उतनी ही बड़ी गारंटी है। गौर करें तो पिछले कुछ दशकमें ऐसी राजनीतिक मनोवृत्तिको जबरदस्त बढ़ावा मिला है। लेकिन विचार करें तो इस स्थितिके लिए सिर्फ राजनीतिक दल और उनके नियंता ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके लिए देशकी जनता भी बराबरकी गुनाहगार है। जब देशकी जनता ही साफ-सुथरे प्रतिनिधियोंको चुननेके बजाय जाति-पांति और मजहबके आधारपर बाहुबलियों और दागियोंको चुनेगी तो स्वाभाविक रूपसे राजनीतिक दल उन्हें टिकट देंगे ही। नागरिक और मतदाता होनेके नाते जनताकी भी जिम्मेदारी है कि वह ईमानदार, चरित्रवान, विवेकशील और कर्मठ उम्मीदवारोंको अपना जन-प्रतिनिधि चुने। यह तर्क देना उचित नहीं कि कोई भी दल साफ-सुथरे लोगोंको चुनावी मैदानमें नहीं उतारता है इसलिए दागियोंको चुनना हमारी मजबूरी है। यह एक खतरनाक और शुतुर्गमुर्गी सोच है। देशकी जनताको समझना होगा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्थामें नेताओंके आचरणका बदलते रहना स्वाभावगत प्रक्रिया है। लेकिन उनपर निगरानी रखना और यह देखना कि बदलावके दौरान नेतृत्वके आवश्यक और स्वाभाविक गुणोंकी क्षति न होने पाये यह जनताकी जिम्मेदारी है। देशकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्कीके लिए जितनी सत्यनिष्ठा एवं समर्पण राजनेताओंकी होनी चाहिए उतना ही जनताकी भी। लोकतंत्रमें जनता ही संप्रभु होती है। समझना होगा कि दागियोंको राजनीतिसे बाहर खदेड़नेकी सिर्फ जिम्मेदारी राजनीतिक दलोंके कंधेपर डालकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। जनताकी भी जिम्मेदारी है कि वह दागियोंको चुननेके बजाय साफ-सुथरे लोगोंको चुनें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

नया परिदृश्य और नई आकांक्षाएं

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों की लंबे समय से प्रतीक्षित तिथियों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान, जिसमें 24 सीटें शामिल हैं, 18 सितंबर को होगा। दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा, और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिये थे। यह जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन/निरस्तीकरण के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा. निरस्तीकरण 5 अगस्त, 2019 को हुआ था।

पहले, जम्मू और कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46, और लद्दाख में 4 सीटें थीं। इसके अलावा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिए 24 सीटें निर्धारित थीं। हाल ही में हुई परिसीमन प्रक्रिया के फलस्वरूप सीटों की संख्या परिवर्धित हुयी हैं। अब जम्मू में 43 सीटें होंगी, जबकि कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए यथावत 24 सीटें आरक्षित रहेंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें आरक्षित की गई हैं और उन्हें कश्मीरी प्रवासी/विस्थापित कहा जायगा। इसके अलावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में तीन सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा, जिनमें से दो कश्मीरी प्रवासी/विस्थापित और एक पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। दो कश्मीरी प्रवासी नामितों में से एक महिला होनी चाहिए। कश्मीरी विस्थापित को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर, 1989 के बाद घाटी या जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से प्रवास कर गया हो और राहत आयुक्त के यहाँ पंजीकृत हो। जो लोग 1947-48, 1965, या 1971 की घटनाओं के बाद पीओके से प्रवास कर गए, उन्हें विस्थापित व्यक्ति माना जाएगा। प्रवासियों के लिए विशेष रूप से दो सीटों को आरक्षित या नामित करने की पहल के साथ, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए नई आशा जगी है। इस निर्णय से उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपनी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के निवारण की मांग करने के लिए एक मंच मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 7 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आवंटित की गई हैं, जबकि 9 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अनुच्छेद 370 के अवसान के बाद पहला चुनाव है और यह चुनाव केंद्र-शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिसीमन प्रक्रिया से भी, जिसने जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी है, क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी प्रभाव डालने की संभावना है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें जम्मू और कश्मीर के इन चुनाओं पर केन्द्रित हो रही हैं राज्य गहन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जहां नेता और पार्टी कार्यकर्ता समर्थन जुटाने के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामाकंन भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ हद तक इस तरह की अनिश्चितता हर चुनाव में होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में हालात सामान्य से ज्यादा जटिल हैं और इस असमंजस के पीछे उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी खेमे में माने जाने वाले राज्य के तीनों प्रमुख दलों में सहयोग और संघर्ष दोनों का दिलचस्प घालमेल दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आलम यह है कि पहले चरण की 24 सीटों का भी बंटवारा मुश्किल साबित हो रहा। पीडीपी इस गठबंधन से बाहर है। फिर भी मुद्दों की एकरूपता के चलते न सिर्फ उमर अब्दुल्ला उससे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा करने को कह रहे हैं बल्कि खुद महबूबा भी कह चुकी हैं कि अगर उनके अजेंडे को स्वीकार किया गया तो गठबंधन का समर्थन करेंगी।

ललित गर्ग।

जम्मू एवं कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने के साथ क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर के द्वार खोलने का माध्यम बनेगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की सीटें हैं, इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर ऐसी सरकार बनाये जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान चुनावी सरगर्मियों एवं भविष्य के गर्भ में ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर लगी हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। इस बार के चुनाव अब तक हुए चुनावों से अलग है और खास है। भाजपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वहां इस तरह की गफलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करना वहां भी जटिल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसे जिस तरह वापस लेना पड़ा, उससे उसकी छिछालेदार तो हुई ही है, अनुशासित दल की उसकी छवि को धक्का भी लगा। स्थिति यह है कि पार्टी ने सोमवार को 44 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के थोड़ी ही देर बाद व्यापक विरोध के कारण उसे वापस ले लिया। इसके बाद जो सूची जारी की गई, उसमें 15 ही प्रत्याशियों के नाम थे। यह आलम तब है, जब पहली सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर की गई थी। यदि भाजपा औरों से अलग तथा अनुशासित दल की अपनी छवि के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अपनी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले जारी सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना पड़ा था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकी है, जिससे असंतोष, विरोध और भितरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या केवल भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। यह कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं। चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्याएं मिटा देने तथा सब रोगों की दवा बन जाने की नैतिकता की बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे। इसलिये प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना होगा। इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है। भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षेत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहां होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहां से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है। जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है।

शख्सियत

इम्तियाज हुसैन
(पीसीसी सचिव)

एक हंसता मुस्कराता हुआ चेहरा, आखों में गजब का आत्मविश्वास, कुछ अच्छा करने का जज्बा और सबका आदर करने का भाव कुछ ऐसी ही हमारी आज की शख्सियत है। जी हां मित्रों चौधरी इम्तियाज हुसैन वर्तमान में प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी में सचिव हैं। कॉंग्रेसी खेमे के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों में भी इनकी चर्चा होती है। वो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं 2008 में क्रश्च करने के बाद भिवाड़ी एक एमएनसी कंपनी में नौकरी करने लगे इसी दोरान कंपनी के द्वारा विभिन्न राज्यों वो देशों में कंपनी के कार्यों से जाना हुआ क्योंकि राजनीति में शुरू से ही रुचि थी तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम किया उसके पाश्चात्य भँवर जितेन्द्र जी नें इनसे कहा आप पूर्णतः राजनीति में आओ क्योंकि मेवात में पढ़े लिखे नवजवानों की राजनीति में कमी है आप चुनाव की राजनीति करो उसके बाद उन्होंने सीधा ही जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 41 से कॉंग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना दिया इन्होंने शानदार चुनाव लड़ा उसके बाद जिला युवा कॉंग्रेस में महासचिव बना दिया फिर उन्होंने जिला कॉंग्रेस में सचिव बना दिया,पूर्व में छात्र राजनीति में राजस्थान इंजीनियरिंग स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहे हैं दो बार । भारत सरकार के डेलीगेट के रूप में विदेश यात्रा भी की जिनमें चाइना व कतर देश शामिल रहे,ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से भी जुड़े हुए हैं जो स्वच्छ राजनीति के उपर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम चलाती है जो कि दिल्ली में स्थित है,वर्तमान में प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पूर्व में रामगढ़ और तिजारा विधानसभा से कॉंग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी भी की। मिलनसारिता की जब कहीं कोई बात होती है तो वहाँ इम्तियाज हुसैन का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इनके चाहने वाले भी सच मे बेशुमार हैं जो हमेशा इनके सुनहरे भविष्य की बात करते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

जय हिंद

आज का इतिहास

28 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा किया।
- मुगलों ने 1600 को अहमदनगर पर कब्जा किया।
- फ्रांस में 28 जुलाई 1794 को मैक्सीमिलियन रोबेस्पियर और उसके साथियों को मृत्युदंड दिए जाने के बाद भय और आतंक का काल समाप्त हुआ। उसके अवधि में में 1 लाख 20 हजार लोग बिना मुकदमा चलाए मार दिए गए।
- स्पेन से पेरु को स्वतंत्रता मिली और 28 अगस्त 1821 को आज के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। यह देश दक्षिणी अमरीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है और एक्केडोर कोलम्बिया, चिली, ब्राजील और बोलीविया इसके पड़ोसी देश हैं।
- प्रसिद्ध पत्रिका साइंटेफिक अमरीकन का पहला संस्करण 1845 में छपा।
- कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन 1904 में हुआ।
- जापान साइबेरिया से अपने सैनिकों को 1922 में वापस बुलाने पर सहमत हुआ।
- जॉर्जिया में 1924 को सोवियत संघ के खिलाफ हुआ विद्रोह असफल रहा। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई।
- इंग्लैण्ड ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज पर कब्जा जमाया।
- साधारण बीमा कारोबार राष्ट्री यकरण बिल 1972 में पारित किया गया।
- सोवियत संघ ने 1984 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- भाग्यश्री साठे शतरंज में 1986 को ग्रैंडमास्टकर बनने वाली प्रथम महिला बनी।
- ईराक ने 1990 में कुवैत को अपना 19वाँ प्रान्त घोषित किया।
- श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट कॅरिअर की शुरूआत की।
- इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने 1996 में औपचारिक तौर पर तलाक लिया।
- मेजर समीर कोतवाल आसाम में 1999 को उग्रवादियों के एक गुट के साथ लडाई में शहीद हो गये।
- ताइवान के राष्ट्रपति चुने शुई बियान द्वारा चीन के साथ एकीकरण के विकल्प को स्वीकार करने का संकेत, संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दि विश्व धार्मिक शिखर सम्मेलन 2000 में शुरू हुआ।
- भारत-पाक सीमा पर 2001 में गोलीबारी, पाकिस्तान के 8 सैनिक मरे।
- आइरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी आईआरए ने 28 अगस्त 2005 में आधिकारिक तौर पर अपने सशस्त्र अभियान को रोकने की घोषणा की।
- बाराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरीकी बने जिनका नाम अमरीका की एक बड़ी पार्टी ने 2008 में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटो को प्रचलन से हटाने का निर्णय 2008 में किया।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने 2008 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया।
- लोकपाल आंदोलनः अन्ना हजारे ने 2011 में भारतीय संसद द्वारा 3 मांगों के समर्थन का प्रस्ताव पारित करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिनों से जारी अनशन को स्थगित करने की घोषणा की।
- माओवादी नेता डॉ बाबूराम भट्टराई तराई के मधेसी गठबंधन के समर्थन से नेपाल के नए प्रधानमंत्री 2011 में निर्वाचित हुए।

विशेष आलेख

फिराक गोरखपुरी पर विशेष

फिराक गोरखपुरी में बसी थी भारत की सांझी संस्कृति

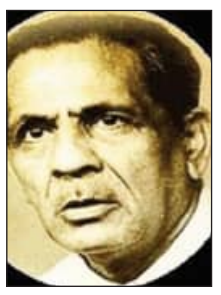

ललित गर्ग

'शायर-ए-जमाल'-सौन्दर्य का कवि कहलाने वाले फिराक गोरखपुरी उर्दू शायरी का देश एवं दुनिया का एक फनकार हैं जिसका रचना-संसार जीते-जी ही नहीं, मरकर भी गूंज रहा है। गोरखपुर को जिन वजहों से दुनिया भर में पहचान मिली, फिराक गोरखपुरी को हमें उनमें आगे की पंक्ति में रखना ही होगा। नाम के आगे गोरखपुरी लगाकर उन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में गोरखपुर को जो ऊंचाई दी, गोरखपुर ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल के लोग इसके लिए गौरव का अनुभव करते हैं। शायरी कहने के अपने अलमस्त और बेलौस अंदाज को लेकर वह शायरों में ही नहीं, आमजन के बीच भी हमेशा चर्चा का विषय रहे। रघुपति सहाय से फिराक गोरखपुरी बने, वे भारत के एक प्रसिद्ध उर्दू शायर, कवि, लेखक और आलोचक थे। उनकी साहित्यिक प्रतिभा कविता, गजल और निबंध सहित विभिन्न शैलियों में फैली हुई है। प्रगतिशील लेखक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व, गोरखपुरी की रचनाओं में मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ झलकती है। उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति ने शास्त्रीय लालित्य को आधुनिक संवेदनाओं के साथ जोड़ा, जिन्होंने शायरी को लोक बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच, नई रंगत, नई ऊर्जा उत्पन्न की। उन्हें फारसी, हिन्दी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ थी, इन्हीं कारणों से उनकी शायरी में भारत की विविधताओं युक्त सांझी रची-बसी हुई है। वे जन-कवि और सौन्दर्य के परम उपासक के रूप में असंख्य लोगों के दिल और दिमाग में रचे-बसे हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। वे एक अमीर परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, वे पेशे से वकील थे, किन्तु शायरी में उनका बहुत नाम था। इसी कारण फिराक को शायरी की प्रेरणा पिता से भी मिली। बचपन के चमकते-दमकते वैभव के बावजूद उनकी नजरें हमेशा जमीन की ओर देखती रही। उनकी जिन्दगी और रचनाओं का सफर न केवल रोचक रहा, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी रहा। उर्दू कविता के प्रति उनके मन मे छोटी आयु में ही रुझान था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने उर्दू में कविताएं लिखना आरंभ कर दी। वे साहिर, इकबाल, फैज, तथा कैफी आजमी से अत्यधिक प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस की कहानियों से आरंभ करने के बाद उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई में वे बड़े ही योग्य एवं होनहार विद्यार्थी थे। सन् 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए परंतु महात्मा गांधी के स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 1918 में पद से त्यागपत्र दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको डेढ़ वर्ष की जेल की यात्रा सहन करनी पड़ी। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। उनका कहना था कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है बल्कि आम भारतवासियों की भाषा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी इस सोच से अत्यधिक प्रभावित हुए, उन्होंने फिराक को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। नेहरू ने फिराक को जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में अन्डर सेक्रेटरी बना दिया। लगभग 50 वर्षों तक वे सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द के लिए काम करते रहे। फिराक की कविता में कुछ स्थानों पर रूमानियत देखी जा सकती है उन्होंने वियोग, श्रृंगार के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इलहाबाद बीता। और यहीं से वे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। इलाहाबाद में फिराक, महादेवी वर्मा और निराला को मिलाकर उस दौर के साहित्य की दुनिया की त्रिवेणी बनती थी। उनकी अनौपचारिक संगोष्ठियों में अंग्रेजी के विद्वानों के साथ-साथ तुलसी, कालिदास और मीर के पाठ भी समानांतर चलते थे। गहरी-गहरी और गोल-गोल डस लेने वाली आंखों में उनके व्यक्तित्व का फक्कड़पन खूब जाहिर होता था। फिराक के पिता भी अच्छे शायर थे, इसलिए उनके आवास लक्ष्मी निवास पर साहित्यकारों की खूब महफिल सजती थी। महफिल सजाने वालों में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द भी शामिल थे। कई बार प्रेमचंद वहां रुक भी जाते थे, जब फिराक की पत्नी को उनके लिए परहेजी खाना बनाना पड़ता था। इस दौरान फिराक का प्रेमचंद से एक खास रिश्ता बन गया था। फिराक की बेटी प्रेमा देवी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि लक्ष्मी निवास पर पंडित नेहरू भी कई बार आए थे क्योंकि नेहरू के वे काफी नजदीक थे। फिराक भरी-पूरी संभावनाओं का नाम रहा है, जहां साहित्य की अनेक सरिताएं प्रवहमान रही हैं। फिराक तबीयत से भले ही हर किसी को बागी नजर आए लेकिन उनकी शायरी सहज थी। उनके शेरों में संवेदनाएं, नेकदिली और जिंदादिली का अहसास कोई भी कर सकता है। उर्दू गजल के पारंपरिक अंदाज में बिना किसी छेड़छाड़ के नए लहजे की शायरी की जो अद्भुत मिसाल उन्होंने पेश की, उससे शायरी के कद्रदानों के अलावा मशहूर शायर भी उनके कायल हो गए। निदा फाजली जैसे शायर ने तो शायरी की दुनिया में गालिब और मीर के बाद फिराक को तीसरे पायदान पर रखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों के सान्निध्य में उन्होंने अपनी शायरी को ऊंचाई दी। पद्मश्री अली सरदार जाफरी ने फिराक को उर्दू शायरी की नई आवाज करार दिया। जोश मलीहाबादी ने कहा कि फिराक उर्दू के उस्ताद शायरों में एक बड़े नामवर गोशे के मालिक हैं। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विश्वनाथ तिवारी ने फक्कड़, मूडी, गुस्सैल आदि अनेक परिचय के धनी फिराक को शायरी के दुनिया का बेताज बादशाह कहा है। यही कारण है कि मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो की तरह ही फिराक गोरखपुरी के जीवन पर भी कई फिल्में बन चुकी हैं। एक फिर फिल्म गवर्नमेंट आफ इंडिया के फिल्म डिविजन ने भी बनाई है। फिराक के जीवन पर कई किताबें भी लिखी गईं हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आप मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे। वाणी पर संयम रखें अन्यथा मतभेद हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज अत्यधिक खर्च हो सकता है। मानहानि हो सकती है, अतः सावधान रहें। आज व्यापार में लाभ और आय में वृद्धि होगी।

वृष
जीवनसाथी के साथ भी अच्छा वक्त बीतेगा। व्यावसायिक कार्य से बाहर जाना हो सकता है। आज आप नए काम के शुरुआत की कोशिश करेंगे। बौद्धिक कामों और साहित्य लेखन में सक्रिय रहेंगे। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा।

मिथुन
शारीरिक और मानसिक रूप से आप ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। स्वादिष्ट भोजन और अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मित्रों तथा परिजनों के साथ आज का दिन आनंदपूर्वक गुजारेंगे। उनकी तरफ से आपको भेंट-उपहार मिल सकता है।

कर्क
साहित्य लेखन के लिए अच्छा दिन होने के कारण आप लेखन में प्रतिभा दिखा सकते हैं। आज आपको पूरी तरह से स्थिर होकर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर अच्छे अवसर भी हाथ से जा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा।

सिंह
उत्तम भोजन प्राप्त होगा। मित्रों के साथ रमणीय स्थान पर जा सकते हैं। महिला मित्र आज विशेष सहायक होंगी। बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा। बुजुर्गों तथा बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।

कन्या
वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए आज का दिन उत्तम है। आज नए काम की योजना बनेगी। व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला होगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। कोई शुभ प्रसंग हो सकता है।

तुला
मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से दूर ही रहें। आज दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज आप मन में खिन्नता और भय का अनुभव करेंगे। परिवार में मतभेद होने से पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। मन में किसी बात की दुविधा रहेगी

वृश्चिक
भाई-बंधुओं से प्रेम तथा सहयोग मिलेगा। कलाकारों, कारीगरों और लेखकों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विरोधी परास्त होंगे। आपका आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है।

धनु
आज आपका मन काफी चंचल रहेगा, इस कारण आपको निर्णय लेने में काफी परेशानी होगी। विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नए काम को करने की प्रेरणा मिलेगी। आप किसी बौद्धिक या तार्किक चर्चा में भाग लेंगे।

मकर
तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। विदेश में रहने वाले मित्रों और सगे-संबंधियों के समाचार प्राप्त होंगे, जिससे काफी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपके सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। संतान की चिंता सताएगी।

कुंभ
आपका आज का दिन सुख- शांति में व्यतीत होगा। मित्रों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा। स्वादिष्ट भोजन तथा नए कपड़े प्राप्त होंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ मुलाकात रोमांचक रहेगी। आज आपके विचार स्थिर नहीं रहेंगे।

मीन
कफ, सांस या पेट की परेशानी हो सकती है। आज शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी अनैतिक और सरकार विरोधी कामों से दूर रहें अन्यथा आप मुसीबत में आ सकते हैं। भागीदारी में लाभ होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

संपादकीय

"सोशल मीडिया भेड़चाल की तरह है। एक व्यक्ति शोर मचाता है, तो हर कोई उसमें शामिल हो जाता है। -अर्ल स्वेटशर्ट

डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या के विरोध में छात्रों के सड़कों पर उतरने और पुलिस से झड़प के दृश्य बताते हैं कि बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक महिला के साथ हुई बर्बरता पर मुख्यमंत्री, नैतिक आधार पर त्यागपत्र भले न दें, मगर कम से कम इतना तो करें कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।

बंगाल में कुछ ठीक नहीं

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या के विरोधस्वरूप मंगलवार को छात्रों व राज्य कर्मचारी संगठनों के लोगों की भीड़ के सड़कों पर उतरने और उनकी पुलिस से झड़प के दृश्य यही जाहिर करते हैं कि दीदी के बंगाल में चीजें ठीक नहीं चल रहीं। दरअसल, बीती आठ अगस्त की रात प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई और नौ अगस्त की सुबह शव मिलने के बाद से ही देश भर में डॉक्टरों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच 13 अगस्त को अपने हाथ में ली थी। उससे पहले दस अगस्त को राज्य पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस बर्बर हत्याकांड में शुरुआत से ही एक से ज्यादा लोगों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। शीर्ष अदालत की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने बेशक जनहित में अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही हैं और चौदह दिन बाद भी यह गुत्थी सुलझ नहीं सकी है, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना उतना ही स्वाभाविक है, जितनी कि लोगों की नाराजगी। एक महिला के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर भी उठते हैं, जो खुद एक महिला हैं और राज्य के स्वास्थ्य व गृह विभाग भी उन्हीं के पास हैं। उतना ही क्षोभकारी एक तृणमूल सांसद का प्रदर्शनकारियों की तुलना पिकनिक मनाने वालों से करना भी है। ममता बनर्जी ने देश में दुष्कर्मों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खत जरूर लिखा है, लेकिन अपने ही राज्य में हुई पूरे देश की चेतना को झकझोर देने वाली वारदात पर उनकी चिर-परिचित आक्रामकता के नदारद होने पर भी सवाल हैं। तथ्य बंगाल की कहानी आप बयां करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून (पॉक्सो) के 48 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनके त्वरित निपटान के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना पर विचार करने का आग्रह भी किया है। लेकिन, नहीं भूलना चाहिए कि अक्तूबर, 2019 में स्थापित केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पश्चिम बंगाल को जो 123 फास्ट ट्रैक अदालतें आवंटित की गई थीं, उनमें से कोई भी जून, 2023 तक शुरू नहीं हो सकी थी। इस बर्बर घटना पर मुख्यमंत्री नैतिक आधार पर त्यागपत्र भले न दें, लेकिन कम से कम दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाती तो दिखें।

रूस के 'जुकरबर्ग' और टेलीग्राम के रहस्य

टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव की प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं, लेकिन सत्ता विरोधी रवैये के चलते वह एक बार फिर मुश्किल में हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार बेशक उनके बचाव में हैं, लेकिन जब उनके एक्स से भी ज्यादा उपयोगकर्ता हों, तो वह कंटेंट पर नियंत्रण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

पॉल मोजुर
द न्यूयॉर्क टाइम्स

एक दशक से भी अधिक समय पहले, जब रूस ने पावेल डुरोव द्वारा बनाई गई फेसबुक जैसी साइट पर से विपक्षी राजनेताओं के पेज बंद करने का दबाव डाला, तो इस तकनीकी उद्यमी ने ऑनलाइन जवाब देते हुए एक हुडी पहने हुए कुत्ते की जीभ बाहर निकाले हुए एक चुटीली तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने बिना किसी खेद के लिखा, 'समूहों को ब्लॉक करने के अनुरोध पर खुफिया सेवाओं को आधिकारिक प्रतिक्रिया।'

तेरह साल बाद, डुरोव की सत्ता-विरोधी प्रवृत्ति ने उन्हें अधिकारियों के साथ मुसीबतों के एक नए दौर में पहुंचा दिया है। बीते दिनों उन्हें टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। टेलीग्राम एक ऑनलाइन संचार मंच है, जिसकी स्थापना उन्होंने 2013 में की थी, जो अब वैश्विक पहुंच बना चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डुरोव की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है' लेकिन 'कानून का पालन करने वाले मुल्क में, सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन, दोनों में स्वतंत्रता को कानूनी ढांचे के भीतर बरकरार रखा जाता है।'

डुरोव की गिरफ्तारी ने एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सेंसरशिप के बारे में चिंतित लोगों के बीच नायक बन गए हैं, खासकर तब, जब वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सामग्री की निगरानी बढ़ गई है। एक्स के मालिक एलन मस्क और एडवर्ड स्नोडेन उन लोगों में शामिल थे, जो डुरोव का बचाव करने के लिए आगे आए। इस दौरान एक्स पर हैशटैग फ्री पावेल #FreePavel छा गया। टेलीग्राम ने एक बयान में कहा कि वह यूरोपीय संघ के कानूनों का पालन करता है। कंपनी ने कहा, 'यह दावा बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है।' टेलीग्राम लंबे समय से डुरोव के सत्ता-विरोधी लोकाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कायम है। इसने टेलीग्राम को रूस, ईरान और सत्तावादी सरकारों के अधीन रहने वाले अन्य लोगों के लिए एक लोकप्रिय चैट एप बनाने में मदद की। लेकिन प्लेटफॉर्म पर निगरानी नहीं करने के डुरोव के दृष्टिकोण ने आतंकवादियों, चरमपंथियों, बंदूक तस्करों, घोटालेबाजों और ड्रग डीलरों को भी आकर्षित किया है। उनका कहना है कि गोपनीयता ऑनलाइन अभिव्यक्ति की कड़ी निगरानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक पोस्ट में, उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने शुक्राणु दाता के रूप में 12 देशों में 100 से अधिक जैविक बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन डुरोव की सबसे बड़ी प्राथमिकता टेलीग्राम है। वर्ष 2014 में उन्होंने रूस की सुरक्षा सेवाओं की बढ़ती निगरानी के बीच रूस छोड़ दिया और दुबई का रुख किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब से उन्होंने कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर एप्पल और प्रमुख सरकारों के साथ लड़ाई लड़ी है।

टेलीग्राम को 31 देशों में अस्थायी या स्थायी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। डुरोव ने एफबीआई पर एक टेलीग्राम प्रोग्रामर को काम पर रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया, ताकि अमेरिकी सरकार उपयोगकर्ताओं के डाटा तक पहुंच बना सके। एफबीआई ने इस पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। वर्ष 1984 में सोवियत संघ में जन्मे डुरोव चार साल की उम्र में ही अपने परिवार के साथ उत्तरी इटली चले गए। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद वह सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। कॉलेज में एक दोस्त ने डुरोव को फेसबुक का शुरुआती संस्करण दिखाया, जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इससे प्रेरित होकर डुरोव ने अपना खुद का संस्करण बनाने का फैसला किया। उन्होंने वीके (Vkontakte) की शुरुआत 2006 में की थी, जो कुछ ही वर्षों में रूस में छा गया। इसने क्रेमलिन का भी ध्यान आकर्षित किया, जिसने इसके उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगी।

डुरोव ने कहा कि उन्होंने 2011 के आसपास रूसी सुरक्षा बलों को अपने अपार्टमेंट के आसपास देखने के बाद टेलीग्राम का निर्माण शुरू किया था। सरकार ने अंततः उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो वे वीके के उपयोगकर्ताओं से संबंधित डाटा सौंप दें या देश छोड़कर चले जाएं। रूस से नाता तोड़ने के बाद से डुरोव टेलीग्राम इंजीनियरों से घिरे हुए घुमक्कड़ जीवन जीने लगे। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि वह हर कुछ महीनों में अपनी जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने बार्सिलोना, बाली, बर्लिन, हेलसिंकी और सैन फ्रांसिस्को में समय बिताया है, जबकि दुबई को टेलीग्राम का औपचारिक मुख्यालय बनाया है। डुरोव के पास संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की नागरिकता है। हालांकि वह निजी जेट से यात्रा करते हैं, लेकिन चीजें खरीदने से बचते हैं। वह अपने बैंक खाते में करोड़ों डॉलर और बिटकॉइन रखते हैं, ताकि आजाद रह सकें। ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया है कि उनकी कुल संपत्ति नौ अरब डॉलर से ज्यादा है।

टेलीग्राम अब दुनिया भर में एक अरब उपयोगकर्ताओं के करीब पहुंच रहा है, जो इसे एक्स से बड़ा बनाता है। जैसे-जैसे टेलीग्राम का इस्तेमाल बढ़ता गया, डुरोव द्वारा कंटेंट की निगरानी के लिए अपनाए गए हल्के-फुल्के तरीके की आलोचना होने लगी। नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कहा कि यह एप गलत सूचना, आतंकवाद के प्रचार, दक्षिणपंथी उग्रवाद, ड्रग डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हथियारों की बिक्री का अड्डा बन गया है। वर्षों तक डुरोव ने सिलिकॉन वैली के अपने साथियों की तरह सार्वजनिक जांच से काफी हद तक परहेज किया, जबकि जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई और टिकटॉक के शू च्यू को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया गया है, डुरोव और उनके इंजीनियरों ने चलते-फिरते टेलीग्राम को बनाए रखा और अपडेट करते रहे। एक बार तो उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट के बारे में अपडेट तब जारी किया, जब वे दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र में एक नाव पर सवार थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम ने कुछ सामग्री हटाई है, जैसे कि बाल यौन शोषण सामग्री या हिंसा भड़काने के उद्देश्य से किए गए पोस्ट। लेकिन अधिकारी हमेशा ही डुरोव के सहयोग की कमी से निराश रहे, जिसका खामियाजा डुरोव अब भुगत रहे हैं।

जीवन धारा

जेम्स एलन

शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो पहले मन की रक्षा करें। शरीर को नया बनाना चाहते हैं, तो मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं।

सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे

मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है, उसके पीछे जाने-अनजाने में बोया गया विचार का बीज छिपा होता है। हम जैसा कार्य करते हैं, वैसा ही उसका परिणाम आता है। परिस्थितियों के अनुसार, हम दुख या सुख महसूस करते हैं, वह हमारे विचारों का फल ही होता है। कई बार हम निराश होते हैं और पता ही नहीं होता है कि हम क्यों निराश हैं? हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि कहीं न कहीं हमने कोई न कोई विचार जरूर बोया है। उसी के फल के परिणामस्वरूप हमें निराशा महसूस होती है। इसलिए अब हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे। साथ ही उसके परिणाम के लिए धैर्यवान रहना होगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें रोजी-रोटी के लिए हर दिन काम करना पड़ता है और वे खुश हैं। इसका मतलब है कि खुशी बाहर के रंगीन दिखावे से नहीं मिलती है। अगर किसी इन्सान के दिमाग में बुरे विचार आते हैं, तो उसके जीवन में पीड़ा आना स्वाभाविक है। वहीं, अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा सकारात्मक विचारों में लगा देते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी परछाईं की तरह आगे-पीछे घूमेगी।

विचारहीन, अज्ञानी और आलसी लोग चीज के बजाय केवल प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हैं। साथ ही वे कानून, भाग्य और संयोग की बातें करते हैं। किसी व्यक्ति को अमीर या बुद्धिजीवी बनते देखकर वे कहते हैं, 'कितने भाग्यशाली हैं।' और किसी दूसरे के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को देखकर कहते हैं कि संयोग हर मोड़ पर उसकी सहायता करता है। ऐसा कहने वाले उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं, जिनका सामना इन लोगों ने अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया है। उन्हें उन बलिदानों का कोई ज्ञान नहीं है, जो उन्होंने किए हैं, उन निडर प्रयासों का, जो उन्होंने किए हैं। वे अंधकार और हृदय के दर्द को नहीं जानते हैं। वे केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं, और इसे 'भाग्य' कहते हैं। वे कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं, बल्कि केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं, और इसे 'सौभाग्य' कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखते हैं, और उसे 'संयोग' कहते हैं। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर को नया बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच के अभ्यास द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है।

संदेह और भय पर विजय पाएं

सूत्र

मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जिसने संदेह और भय पर विजय पा ली है, उसने असफलता पर विजय पा ली है। आज अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन पानी में एक पत्थर फेंककर कई लहरें पैदा कर सकते हैं।

दूसरा पहलू

न्यूयॉर्क शहर से पांच गुना आकार का एक हिमखंड गोल-गोल घूम रहा है। यह कब रुकेगा, कोई नहीं जानता।

अंटार्कटिक के विशाल हिमखंड की गुत्थी

तीस वर्षों से भी अधिक समय तक दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिक में फंसा रहा। न्यूयॉर्क शहर से पांच गुना बड़ा व एक हजार फुट से भी अधिक गहरा यह विशाल हिमखंड अंततः वर्ष 2020 में पिघलने लगा और दक्षिण महासागर की ओर धीमी गति से बहने लगा। अब ए23ए नाम का यह हिमखंड अपनी जगह पर घूम रहा है।

रेमी तुमिन

अंटार्कटिक के पानी से निकलकर यह हिमखंड पानी के नीचे पहाड़ पर एक भंवर में फंस गया है और वहीं पर 24 दिनों में एक चक्कर घूमता है।

अंटार्कटिक जल से निकलकर यह हिमखंड पानी के नीचे एक पहाड़ यानी समुद्री पर्वत पर एक भंवर में फंस गया है। कल्पना कीजिए कि करीब 1,500 वर्ग मील क्षेत्रफल और एंपायर स्टेट बिल्डिंग जितनी गहराई वाला हिमखंड धीरे-धीरे, परंतु इतनी तेजी से घूम रहा है कि लगभग 24 दिनों में यह पूरी तरह से अपने सिर पर घूम सके। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण, ब्रिटेन के ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिमखंड अंटार्कटिक प्रायद्वीप से लगभग 375 मील उत्तर-पूर्व में दक्षिण ऑर्कनी द्वीप समूह के पास घूम रहा है, जो प्रतिदिन 15 डिग्री परिक्रमा के साथ ठंड बनाए रखता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में ओपन ओशन्स रिसर्च ग्रुप के प्रमुख और भौतिक महासागर विज्ञानी एलेक्स ब्रियरली ने कहा, 'यह मूल रूप से बस वहीं घूम रहा है और जब तक यह वहां रहेगा, बहुत धीरे-धीरे पिघलेगा। हम नहीं जानते कि यह वास्तव में कब इससे बाहर निकलेगा।'

ए23ए 1986 के अंत में टूट गया और वेडेल सागर में नीचे चला गया, जहां यह अगले 34 वर्षों तक रहा। वर्ष 2020 में इसने खुद को मुक्त किया।

ए23ए शुरू से ही इस नाटक में उलझा हुआ है, यह विशेषता इसे अपने मूल हिमखंड से मिली है। ए23ए मूलतः बेहद विशाल ए 23 हिमखंड से निकला है, जो उन तीन हिमखंडों में से एक था, जो 1986 में फिल्चनर आइस शेल्फ से टूट गए थे। टूटने के समय ए23 सोवियत संघ के अनुसंधान केंद्र का घर था, नतीजतन शोधकर्ताओं को उसे छोड़ना पड़ा। उसी वर्ष बाद में ए23ए टूटा और वेडेल सागर में नीचे चला गया, जहां यह अगले 34 वर्षों तक फंसा रहा। वर्ष 2020 में अंततः ए23ए ने खुद को मुक्त किया। यह इतना बड़ा है कि पिछले दिसंबर में डॉ. ब्रियरली और एक शोध पोत को इस हिमखंड का चक्कर लगाने में पूरा दिन लग गया। वह इसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह जमीन की तरह दिखता है। वसंत ऋतु तक ए23ए ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हुए ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने पहली बार अप्रैल में हिमखंड को घूमते हुए देखा। उन्होंने कहा कि यह हिमखंड पिघलेगा नहीं और इससे समुद्र का जलस्तर भी नहीं बढ़ेगा। डॉ. ब्रियरली ने कहा कि चाहे कुछ भी हो अंटार्कटिका के किनारे और रहस्य हमें आकर्षित करते रहेंगे।

आंकड़े

कोयला उत्पादन

भारत में बिजली उत्पादन में करीब 50 फीसदी कोयले का इस्तेमाल होता है। झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है।

झारखंड	26.4%
ओडिशा	25.1%
छत्तीसगढ़	18.1%
पश्चिम बंगाल	10.8%
मध्य प्रदेश	9.8%

7.3 फीसदी के साथ तेलंगाना छठे स्थान पर है। | स्रोत : cco

अंतर्यात्रा

सत्यवती को दिए वचन की खातिर पितामह भीष्म ने परशुराम के काफी समझाने पर भी अंबा से विवाह नहीं किया, तो गुरु-शिष्य के बीच तेईस दिन भीषण युद्ध हुआ।

भीष्म ने किया गुरु परशुराम से युद्ध

अंतर्यात्रा
संकलित

पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से आठों वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें सात तो गंगा जी ने पैदा होते ही जल में बहाकर शाप से मुक्त कराए।

वसु के अंशावतार भीष्म को शांतनु ने रख लिया। एक बार भगवान परशुराम ने भीष्म से यह आग्रह किया कि तुम काशिराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो। परशुराम जी भीष्म के गुरु थे। उन्होंने कहा कि गुरुवर! 'मैंने राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है। इसलिए आपकी आज्ञा पूरी करने में असमर्थ हूं।' भीष्म ने कहा, 'मैं त्रिलोक का राज्य छोड़ सकता हूं, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता।' बहुत समझाने पर भी भीष्म नहीं माने, तो परशुराम क्रोध करने लगे। इस पर भीष्म ने कहा-आप कहते हैं, 'मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को इक्कीस बार जीत लिया था, उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या मेरे समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था।' यह सुनते ही परशुराम जी कुपित हो गए और युद्ध छिड़ गया। गुरु-शिष्य के बीच तेईस दिन तक भयानक युद्ध हुआ, तो देवताओं को बीच में आना पड़ा। देवताओं के समझाने पर युद्ध रुका। उल्लेखनीय है कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए सत्यवती को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे।

आज का इतिहास

फोर्ब्स ने मायावती को 100 शक्तिशाली महिलाओं में किया शुमार

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को 28 अगस्त का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यही वह दिन है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार 'फोर्ब्स' ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। 1858 में उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटेन के विलियम जेम्स हर्शेल का जन्म। 1956 में इंग्लैंड ने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हटाकर एशेज श्रृंखला पर कब्जा जमाया। 1972 में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण विधेयक पारित। 1986 में भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंडमास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला बनीं। 1992 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। 1996 में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया। 1999 में मेजर समीर कोतवाल असम में उग्रवादियों के एक गुट के साथ मुठभेड़ में शहीद। 2018 में भारत के मंजीत सिंह ने जकार्ता एशियाई खेलों की पुरुष 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

पेंशन, चिंताएं और बीच का रास्ता

पेंशन योजनाओं में हमेशा विवाद रहा है। ऐसे में पहले की दोनों योजनाओं की अच्छी बातों को शामिल करती यूपीएस आशा की किरण दिखाती है।

केएस तोमर | मुद्दा

करीब दो वर्ष पहले प्रख्यात अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कुछ पार्टियों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की ओर बहाली के वादे को 'नैतिक रूप से गलत' और 'पाप' बताते हुए कहा था कि इससे केंद्र और राज्यों की अगली सरकारों पर देनदारी का दबाव बढ़ेगा।

पनगढ़िया के इस दृढ़ दृष्टिकोण को पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और पूर्व सीएजी राजीव महर्षि ने भी राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 में ओपीएस की ओर लौटने का फैसला करने पर कहा था कि यह वित्तीय रूप से आत्मघाती कदम होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी ओपीएस चुनने वाले राज्यों को चेतावनी दी थी कि यह भविष्य में अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा।

इसी पृष्ठभूमि में हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लेकर आई है। राज्यों के कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए भाजपा शासित राज्य इसे तत्काल या निकट भविष्य में अपना सकते हैं। 2003 में वाजपेयी सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस लागू की थी, जिसे तत्कालीन भाजपा सरकारों ने लागू किया था, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को लेकर कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यूपीएस कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे मोदी सरकार का यूटर्न बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब दबाव में हो रहा है। साथ ही मूल वेतन के 50 फीसदी के बजाय 100 फीसदी पेंशन देनी चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं ने कहा कि अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण न कर राज्यों को भी यूपीएस लागू करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ओपीएस का विकल्प अच्छा है, लेकिन हमें व्यावहारिक होना चाहिए।

यूपीएस एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी और इसे लागू करने वाला एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) शासित महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। एनडीए के शीर्ष पदाधिकारियों के अनुसार, ओपीएस और एनपीएस का मिश्रित स्वरूप है यूपीएस, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय जिम्मेदारी और सुरक्षा, दोनों प्रदान करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 से मार्च 2023 तक तीन वर्षों में 28 राज्यों की बकाया पेंशन देनदारियां 43 फीसदी से अधिक बढ़ गईं, जो चिंताजनक है, क्योंकि इससे भविष्य में आर्थिक संकट हो सकता है।

राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सराकर ने ओपीएस लागू की है, लेकिन इससे राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो गया है और वह केंद्र से आर्थिक सहायता मांग रहा है। ऐसा ही राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने किया था और केंद्र सरकार से 37,000 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था। यूपीए सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी राज्यों द्वारा ओपीएस लागू करने को बेतुका बताया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन की देनदारियां बढ़ी हैं। केंद्र सरकार का अनुमानित पेंशन बिल 2024-25 के लिए लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य सरकारों के लिए संयुक्त अनुमानित पेंशन बिल 2024-25 में लगभग 5.73 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 195 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

प्रेरणा

उनके लिए फूल हमेशा उपलब्ध हैं, जो उन्हें देखना चाहते हैं। - हेनरी मातीस

संपादकीय

नीतिगत दृढ़ता गुड गवर्नेंस की पूर्व शर्त होती है

न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस), जिसे पिछले दस वर्षों में सरकार की दृढ़ और सुविचारित नीति माना गया था, अब अचानक सरकार ने विकल्प के रूप में एक नई स्कीम 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (यूपीएस) को घोषित कर दिया है। कह सकते हैं कि कुछ बदलाव के साथ फिर से पुरानी पेंशन योजना लौट आई है। हालांकि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में कोई एक योजना चुन सकते हैं। माना जा रहा है कि यह ओल्ड और न्यू पेंशन के बीच का रास्ता है, लेकिन इससे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर बहस शुरू हो गई है। सवाल है कि वे सब तर्क कहां गए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ देकर इसे सन् 2004 में बंद किया गया था और जिसके खिलाफ वर्तमान सरकार दस साल से चट्टान जैसी दृढ़ता दिखाती रही? यूपीएस में सरकार का सालाना खर्च 6200 करोड़ रुपए बढ़ेगा और बकाया भुगतान में अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर साल यह व्यय बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने पेंशन के मद में 2.30 लाख करोड़ और राज्यों ने 5.20 लाख करोड़ खर्च किए। भारत में सरकारी कर्मी का वेतन जीडीपी के अनुपात में दुनिया में सर्वाधिक है। आज की गवर्नेंस काफी टेक्निकल तरह से काम करती है, लिहाजा लेटरल एंट्री की योजना गवर्नेंस में गत्यात्मकता (डाइनेमिज्म) लाती, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इसे भी रोक दिया गया। कई फैसलों पर सरकार का यू-टर्न सवाल खड़े करता है। मसलन तीन किसान बिलों को वापस ले लिया गया। बजट में पेश प्रॉपर्टी गेन टैक्स/इंडेक्सेशन वापस लिया। वक्फ बिल जेपीसी भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल मुल्तवी करना, डेटा प्रोटेक्शन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल को भी वापस लेना क्या कहता है? गवर्नेंस में नीतियां गंभीर चिंतन और दूरदृष्टि से बनी होती हैं। सरकार को विचार करना होगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

ptvijayshankarmehta.com

रुपए-पैसे की तरह बच्चों को समय का प्रबंधन भी सिखाएं

धन के मामले में नासमझ, अनपढ़ और मूर्ख भी जान जाते हैं कि कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। हमारे बच्चों में हम बचपन से ही धन की समझ पैदा कर देते हैं। हम धन खर्च करते हैं परिवार पर, स्वयं पर, मौज-मस्ती में, स्वास्थ्य के लिए और कभी-कभी अकारण भी। अब यही बात बच्चों को समय के मामले में समझाई जाए। और अपनी संतानों को समय रहते समय का मूल्य समझा दीजिए। वरना धन से भी अधिक नुकसान इनको होगा। बच्चों को समझाया जाए कि कहां-कहां समय का निवेश किया जाए, बिल्कुल धन की तरह। पहला शिक्षा में, उनकी परिपक्वता बढ़ेगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा। समय को खेल में भी खर्च करें, इससे आत्मविश्वास आता है। समय का एक नियमित भाग परिवार को दिया जाए, इससे चिंता खत्म होती है। और बचपन से ही समय सेवा में भी लगाया जाए, ये भाव पैदा किया जाए। खासतौर पर जब समाजसेवा करेंगे तो खुशी का स्तर बढ़ता है। आज 40% से अधिक स्कूली छात्र निराश हैं और कॉलेज के 60% विद्यार्थी उदास हैं। इसे खत्म करने में समय का प्रबंधन उनको सिखाया जाए। उनसे छोटे-मोटे काम भी कराएं और अन्य सेवा में लगाएं। आप देखेंगे, उनके भीतर आत्म विश्वास और आनंद एक साथ उतरेगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

सुर्खियों से आगे • ऐसी घटनाएं देख-सुनकर मांएं कब तक लज्जित महसूस करती रहेंगी?

कोलकाता और बदलापुर के सवाल

प्रासंगिक

नवनीत गुर्जर

navneet@dbcorp.in

जब उसके बचपन के दिन थे। चांद में परियां रहती थीं। हवाएं किसी हाकिम की मुट्ठी या कैदखाने में बंद नहीं होती थीं। उसके हिसाब से आया-जाया करती थीं।

आजकल उसी बचपन को, वही चांद हड्डी बनकर चुभ रहा है। हवाएं शरीर पर कोड़े मार रही हैं।

कोलकाता में, बदलापुर में क्या हुआ?

ये तो दो बड़े मामले हैं...

और भी देश के कई शहरों, कस्बों में क्या हो रहा है? कुछ लोगों की लालसा ने अपने लफ्जों के हाथों तलवारें क्यों थमा दी हैं? आखिर इसे क्या नाम दिया जाए? पागलपन या हवसीपना?

बच्चियों, महिलाओं का नभ, जो सुबह नीला, सुंदर होता है, उसे दोपहर और शाम और रात तक लोग स्याह, काला करने पर क्यों तुले हुए हैं?

निश्चित ही समाज में ऐसे लोग कम ही होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे उतने भी क्यों हैं?

जिस कोख को वे तितर-बितर करने पर, तहस-नहस करने पर तुले हुए हैं, आखिर वही उनकी जन्मदात्री भी तो है! वही उनके अस्तित्व की वजह भी तो है! क्यों ऐसे लोगों के नाखून जमाने भर से तेज होते जा रहे हैं?

कोई तो बताए कि ये और कितनी रातों तक कितनी रूहों को निगलते रहेंगे? जलाते-फूंकते रहेंगे?

आखिर इनकी भूख इतनी शैतानी क्यों है?

...और आखिर इस भूख के मिटने का कोई सिरा भी है या नहीं?

इन क्रूर और पिशाची घटनाक्रमों के बाद आंखों के नीचे पानी के कुछ कतरे रख लेने भर से अब कुछ नहीं होने वाला! इस स्याह अध्याय का कोई तो समाधान खोजना ही होगा।

चाहे वो कड़े कानून के तौर पर हो!

चाहे कड़ी और त्वरित या तुरंत सजा के रूप में हो।

आखिर इस अनाचार का कोई तो अंत होना ही चाहिए।

ऐसी घटनाओं को देख-सुनकर करोड़ों मांएं, बच्चियां और लड़कियां आखिर कब तक खुद को लज्जित महसूस करती रहेंगी?

आखिर एक महिला ने पुरुष के लिए क्या नहीं किया! उम्रभर, गलती रही! बहती रही! एक नदी की तरह! उसका यह योगदान बड़ा होता है। किसी आसमान से भी बड़ा।

लेकिन इन चंद हैवानों ने उसे क्या दिया? सिवाय दु:ख के?

यह ढर्रा बदलना चाहिए...

बच्चियों, महिलाओं का नभ, जो सुबह नीला, सुंदर होता है, उसे दोपहर और शाम और रात तक लोग स्याह, काला करने पर क्यों तुले हुए हैं? समाज में ऐसे लोग कम ही होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे उतने भी क्यों हैं?

निर्भया के बाद अभया और इन दोनों के बीच के समय में जाने कितनी निर्भया, कितनी ही अभया ने वो सब कुछ झेला, जो ज्यादती की हद के पार था।

दबी-दबी सिसकियों को कोई क्यों नहीं सुनता?

वे दर्दअंगेज चीखें! वे ख्वाबों के अचानक टूटने, तहस-नहस होने की आवाज इन दानवों को क्यों सुनाई नहीं देती?

ऐसी घटनाओं से तो पेड़-पौधे तक बिलख उठते हैं। दरिया तक रो पड़ता है। ये तो आखिर हाड़-मांस के, जीते-जागते पुतले हैं। इन्हें कुछ क्यों महसूस नहीं होता?

ये पिशाच क्या हमेशा से पिशाच ही थे?

मनुष्य या मनुष्यत्व से उनका कभी कोई नाता रहा ही नहीं?

अगर हां, तो ऐसा क्यों है?

सरकारें केवल कानून बना सकती हैं। उनका पालन करवा सकती हैं, जो वे फिलहाल पूर्ण रूप से या सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं।

हर तरफ, हर मौके पर लीपापोती करना और करते रहना, सरकारों का स्वभाव बन गया है।

यह ढर्रा बदलना चाहिए।

यह रवैया सुधरना चाहिए।

जहां तक आम आदमी का सवाल है उसे चेतना होगा।

क्योंकि चेतना तो भीतर से ही आएगी। वो किसी सरकार के खीसे में नहीं पाई जाती।

इसे जागृत करना होगा।

मनुष्यत्व को अपना चैतन्य रूप दिखाना होगा।

दूरदृष्टि • महामारी के बावजूद विकासशील देशों ने शानदार वापसी करके विश्लेषकों को चौंकाया है...

उभरते हुए बाजार अब अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं

मार्केट

रुचिर शर्मा

ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक

breakoutnations@gmail.com

ये 2000 के दशक की बात है, जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक व्यापक इकोनॉमिक-बूम उनके बाजारों में अरबों डॉलर की बाढ़ ला रहा था। तब उस ऐतिहासिक पल को 'राईज ऑफ द रेस्ट' यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सूची से शेष रह गई 'अन्य' विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का उदय बताया गया था। आज फिर उभरते बाजारों से वैसी ही प्रेरक कहानी सामने आ रही है, लेकिन कम ही विश्लेषकों का ध्यान इस तरफ गया है। विदेशी निवेशकों को तो भनक तक नहीं लगी है।

पिछले दशक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई थी, लेकिन अब वे पुनर्निमाण के दौर से गुजर रही हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष ग्रोथ की बढ़त दर्ज करने में मशगूल हैं। अमेरिका तक को चुनौती दी जा रही है। ऐसा गत 15 वर्षों में नहीं देखा गया था। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अनुपात- जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका से अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है- पिछले पांच वर्षों में 48 प्रतिशत से अगले पांच वर्षों में 88 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। यह 2000 के दशक में उभरती दुनिया के पीक के अनुरूप होगा।

यह उभरता हुआ उछाल पिछली बार के बूम से कई अहम मामलों में अलग है। 2000 के दशक में उभरती दुनिया को चीन के तेजी से बढ़ते कदमों, कमोडिटी की कीमतों में भारी उछाल और पश्चिमी केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई आसान मुद्रा नीतियों के कारण उछाल मिला था। कई टिप्पणीकारों ने मान लिया था कि चीन के उदय के पीछे 'अन्य' अर्थव्यवस्थाएं भी बड़े पैमाने पर उछाल जारी रख सकती हैं, लेकिन वे बुरी तरह से निराश हुए। 2012 में ही मैंने चेतावनी दे दी थी कि अत्यधिक हड़प के चलते इन 'अन्य' अर्थव्यवस्थाओं का पतन हो सकता है। और यकीनन, अगला दशक उभरते बाजारों के लिए निराशाजनक था- वहीं वह अमेरिका के लिए शानदार रहा।

लेकिन अब कई उभरते हुए देश अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत वित्तीय स्थिति में हैं। एक अति-उत्तेजित महाशक्ति के रूप में, और विकास को गति देने के लिए रिकॉर्ड घाटे पर निर्भर रहने के कारण अमेरिका अब एक अस्थिर रास्ते पर है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बजट और चालू खाता घाटा बहुत कम है, जिससे उन्हें निवेश करने और भविष्य के विकास को आगे बढ़ाने की ज्यादा क्षमता मिलती है। यहां तक कि तुर्किये से लेकर अर्जेंटीना तक- जो देश अतीत में वित्तीय अपव्यय के लिए जाने जाते थे- वे भी पुराने चलन की आर्थिक नीतियों की ओर लौट आए हैं। उभरते देशों का भाग्य अब पूरी तरह से सबसे अमीर देश पर निर्भर नहीं करता। वर्तमान में हो रहा उभार चीन के अलावा अन्य देशों द्वारा संचालित है, जिनकी अपनी कठिनाइयां हैं, घटती आबादी से लेकर भारी कर्ज तक। बीजिंग के राष्ट्रवादी रुख और पश्चिम के साथ उसके बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों ने वैश्विक निवेशकों को डरा दिया है। अब वे चीन से बाहर निकल रहे हैं और कहीं और कारखाने स्थापित कर रहे हैं।

बदलते दौर की इकोनॉमी...

एआई बूम चिप्स (कोरिया व ताइवान) और इलेक्ट्रॉनिक्स (मलेशिया व फिलीपींस) के आपूर्तिकर्ताओं से निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। भारत का बाजार, डेटा सेंटर के लिए मलेशिया का सहयोगी माहौल और मेक्सिको की अमेरिका से निकटता विनिवेशकों को खींच रही है।

आने वाले दशक में ग्रीन टेक्नोलॉजी और उसके लिए आवश्यक कच्चे माल- जैसे कि तांबा और लिथियम- के लिए निर्यात विशेष रूप से मजबूत होने की संभावना है, जिनकी आपूर्ति मुख्य रूप से उभरते देशों द्वारा ही की जाती है। एआई बूम पहले से ही एआई-संबंधित चिप्स (कोरिया और ताइवान) और इलेक्ट्रॉनिक्स (मलेशिया और फिलीपींस) के आपूर्तिकर्ताओं से निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। कई उभरते बाजारों में निवेश भी बढ़ रहा है, जो कई खूबियों से प्रभावित है- भारत का बड़ा घरेलू बाजार, डेटा सेंटर के लिए मलेशिया का उपजाऊ वातावरण और मेक्सिको की अमेरिका से निकटता।

जैसे-जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, कॉर्पोरेट आय भी उसी के अनुरूप होती है। चीन को छोड़ दें तो वर्तमान में उभरते बाजारों में आय 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जबकि अमेरिका में यह 10 प्रतिशत ही है। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में- 2009 के बाद पहली बार- उभरते बाजारों (चीन को छोड़कर) में कॉर्पोरेशंस ने अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में आय के पूर्वानुमानों को व्यापक अंतर से पीछे छोड़ दिया है। भारत और सऊदी अरब के पास तो घरेलू निवेशकों का भी मजबूत और तेजी से बढ़ता आधार है। अमेरिका की छाया में लंबे समय तक रहने के बाद, उभरते बाजार तेजी से आकर्षक विकल्प बनते जा रहे हैं। हालांकि वे तेजी से आय वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, लेकिन वे अमेरिका की तुलना में रिकॉर्ड कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। 15 वर्षों तक, अमेरिका ने मुख्य रूप से बड़ी टेक कंपनियों द्वारा संचालित बेहतर आय वृद्धि प्रदान की थी, लेकिन यह भी बदल रहा है। अमेरिका की बड़ी टेक फर्मों की आय वृद्धि अब आने वाले वर्ष में आधे से अधिक गिरने की उम्मीद है।

ये ठीक बात है कि सभी उभरते हुए देशों को एक पांत में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में उन्हें औसतन एक दशक तक अच्छा करना होगा और वैश्विक व्यापार, डॉलर, आर्थिक सुधार, नए राजनीतिक नेतृत्व आदि के अनुकूल ट्रेंड्स से अपने लिए मजबूती प्राप्त करना होगी। याद करें कि अभी हाल ही तक अनेक टिप्पणीकार चेतावनी दे रहे थे कि महामारी के बाद उभरती हुई दुनिया और कमजोर हो जाएगी। उनसे कम ही उम्मीदें की जा रही थीं। उलटे इस बात का डर था कि उभरते बाजार वैश्विक निवेशकों की पसंद नहीं रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की है। टिप्पणीकारों को अब इसका संज्ञान लेना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आपकी राय

– डॉ. आशीष द्विवेदी, लेखक और वक्ता, सागर (मप्र)

पुलिस की तत्परता से ही दुष्कर्म जैसी घटनाएं रुकेंगी

इस माह की 21 तारीख को हफ्ता भर ही गुजरा है। उस दिन इस अखबार के मुख पृष्ठ पर तीन खबरें नुमाया थीं। प्रमुख खबर अजमेर की थी, जिसमें 32 साल पुराने ब्लैकमेल कांड का फैसला आया था। यहां एक साथ छह दरिंदों ने कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। विडंबना देखिए, इन दोषियों को 32 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी खबर कोलकाता की है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर के चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में संजीदगी दिखाते हुए स्वत: उसे संज्ञान में ले लिया। इस विषय पर कोर्ट ने पुलिस के रवैए को संदिग्ध बताया है। तीसरी सदमे में डालने वाली खबर बदलापुर से आई। जहां एक स्कूल में चार साल की मासूम बच्चियों को भी हैवानों ने अपना शिकार बना लिया। दुर्भाग्य देखिए कि इतने नृशंस घटनाक्रम पर भी पुलिस ने तीन दिन बाद केस दर्ज किया। यह अति की इंतिहा नहीं तो और क्या है? समाज में पुलिसिंग इसलिए होती है कि दुर्जन उससे कांपें और सज्जन सुरक्षित महसूस करें। उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था का मजबूती से पालन कर पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाए न कि स्वयं ही उनका उत्पीड़न शुरू कर दे। इस समय वर्दी की शुचिता और विश्वसनीयता दोनों पर ही अनगिनत प्रश्नों के अंबार हैं। जब तक हमारी पुलिसिंग दुरुस्त नहीं होगी ऐसी घटनाएं भला कैसे रुकेंगी?

आप भी अपनी राय editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं।

पुरस्कृत तस्वीर: किसी की जेल, किसी का मनोरंजन!

'थाइलैंड के एक चिड़ियाघर में पानी के अंदर करतब दिखाता हाथी और दर्शक बनकर मनोरंजन करते लोग...' पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से जानवरों को बंधक बनाकर रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन थाइलैंड में यह आम है। छायाकार ने तस्वीर में जानबूझकर हाथी के साथ दर्शक बने लोगों पर फोकस किया है। फोटो जर्नलिज्म श्रेणी में इस तस्वीर के लिए Adam Oswell को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था।

विश्लेषण • रोजगार का सवाल राजनीति पर छा जाएगा

6 साल में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करने की बड़ी चुनौती

रोजगार

अभय कुमार दुबे

अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर

abhaydubey@aud.ac.in

हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और राज्य में बेरोजगारी के बेतहाशा बढ़े हुए आंकड़े वहां की बहसों के केंद्र में आ चुके हैं। बेरोजगारी के मुद्दे ने लोकसभा चुनावों को भी काफी प्रभावित किया था। ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में यह प्रश्न राजनीति के दायरे में सर्वाधिक चर्चित रहने वाला है। जाहिर है कि सरकारें कभी यह नहीं मानेंगी कि उनके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं सरकारों के आलोचक उन्हें चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते रहेंगे। जो भी हो, आईएमएफ की उप प्रबंध-निदेशक गीता गोपीनाथ ने हाल ही में दिल्ली में भाषण देते हुए कहा है कि 2030 तक भारत को कम से कम 6 करोड़ अतिरिक्त रोजगार तो पैदा करने ही होंगे। कुछ अर्थशास्त्री तो इस अवधि में 10 करोड़ रोजगारों की जरूरत पर बल दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यवस्था और सरकार को संकट का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में देश के तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (विजय महाजन, अरुण कुमार और संतोष मेहरोत्रा) ने बेरोजगारी की असलियत एक सरलता से समझ में आ सकने वाले परिप्रेक्ष्य के तहत पेश की है। विजय महाजन ने बताया है कि देश की 1 अरब 44 करोड़ आबादी में से केवल 52 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरह के श्रमिकों के रूप में भागीदारी कर रहे हैं। इनमें से 47 करोड़ के पास काम है, लेकिन 5 करोड़ लोग काम की तलाश में हैं। रोजगार के तलबगारों की इस संख्या में हर साल तकरीबन एक करोड़ की बढ़ोतरी हो जाती है। ये तथ्य बताते हैं कि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर) दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कम है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में रोजगारशुदा नागरिकों के तौर पर उनकी भागीदारी और घटी हुई दिखती है।

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जिन्हें रोजगार मिला हुआ भी है, राष्ट्रीय औसत के मुताबिक उनकी आमदनी भी उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत नहीं करती। केवल 4 करोड़ रोजगारशुदा ऐसे हैं, जिन्हें नियमित वेतनभोगी की श्रेणी में रखा जा सकता है। बाकी सभी वर्किंग पुअर या गरीब श्रमजीवी की श्रेणी में आते हैं। इनकी हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों की औसत आमदनी 3,915 रु. है। अस्थायी श्रमिकों की कमाई का औसत 7,254 रु. है। स्वरोजगार से कमाई करने वाले 13,339 रुपए ही औसतन कमाते हैं। जो नियमित वेतनभोगी की आकर्षक प्रतीत होने वाली श्रेणी में आते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा औसतन 20,049 रु. कमाते हैं। इन वेतनभोगियों में दो से ढाई फीसदी ही सरकारी क्षेत्र में हैं।

अर्थशास्त्री अरुण कुमार के मुताबिक चार तरह के बेरोजगार हैं। एक वे जिनके पास तलाशने के बावजूद रोजगार नहीं है। दूसरे वे जिन्हें हफ्ते में 24 घंटे से भी कम काम मिलता है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 8 फीसदी है, और हफ्ते में 36 घंटे से भी कम का रोजगार पाने वाले करीब 16 फीसदी हैं। तीसरे वे जिन्हें रोजगारशुदा तो मान लिया जाता है, पर वास्तव में रोजगार उनके पास होता नहीं है। इनमें वे मजदूर और किसान आते हैं, जो खेत पर या दुकान पर काम करने जाते हैं पर उन्हें बेकार बैठना पड़ता है। चौथे वे हैं जिन्होंने लगातार नाकामी से निराश होकर रोजगार तलाश करना बंद कर दिया है।

हमारी इकोनॉमी 30-40 लाख रोजगार हर साल पैदा कर सकती है। 6 साल के समय में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने की चुनौती किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो यह और मुश्किल है।

अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने बजट में किए जाने वाले इस दावे का खंडन किया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश से रोजगार बढ़ सकता है। वे कहते हैं कि सरकारी निवेश में विशुद्ध बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है। पहले राज्य सरकारें ऐसा निवेश करती थीं, और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की भी निवेश में भागीदारी होती थी। अब राज्यों को मिलने वाले 17 टैक्स जीएसटी में समा गए हैं। स्वरोजगार के लिए चलाई गई मुद्रा स्कीम के 65 फीसदी कर्ज 27,000 रुपए वाले हैं। इससे व्यक्ति ठेला या रेहड़ी ही खरीद सकता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • पति या पत्नी का रोल निभाने के अलावा खुद से भी पूछें कि मैं कौन हूं?

रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने के लिए कोशिश जरूरी है

रिलेशनशिप

रश्मि बंसल

लेखिका और स्पीकर

mail@rashmibansal.in

सास, बहू और नागिन वाले सीरियल्स का जमाना गया, अब लोग देख रहे हैं 'के-ड्रामा'। यानी कोरिया में बने हल्के-फुल्के धारावाहिक। इनमें सबसे लोकप्रिय है रोमांस, जहां किसी गरीब लड़के या लड़की का एक रईस इंसान के साथ चक्कर चल जाता है। उलट-पुलट, हंसी-मजाक और कुछ कारनामों के बाद उनका होता है मधुर मिलन। साधारण सीरियल यहां खत्म हो जाता है, लेकिन हाल ही में मैंने एक अलग सीरीज देखी। नाम है 'क्वीन ऑफ टीयर्स', जिसमें कपल का तलाक हो जाता है। उनकी भी एक प्रेम कहानी थी, मगर तीन साल बाद वो एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे, कि हां और ना में बात होने लगी। यहां तक कि अलग-अलग कमरों में रहने लगे थे। कई कपल्स एक ही बेड पर लेटे हुए अपनी अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। एक पार्टनर सोचता है- 'इससे कुछ कहना ही बेकार, झगड़ा होता है। बेहतर मैं चुप रहूं'। दूसरा सोचता है, 'अरे ये तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है'। और इस तरह शुरू होती है एक ऐसी साइकिल, जो रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है।

पुराने जमाने में लोग निभा भी लेते थे, क्योंकि आस-पास सब निभा रहे थे। नई पीढ़ी को मंजूर नहीं। अजनबियों की तरह रहने से बेहतर अलग हो जाएं। और हो जाता है तलाक। मेरी एक सहेली डायवॉर्स लॉयर है, वो किसी पार्टी में जाती है तो चार लोग उसे कोने में ले जाकर वहीं अपनी दुख भरी कहानी उड़ेलने लगते हैं। भाई, जिस तरह की कहानियां वो सुनाती है, मैं हिल जाती हूं। कुछ ऐसे मामले हैं, जहां मानसिक या शारीरिक यातना इतनी है कि तलाक जरूरी है। लेकिन कई हास्यास्पद भी हैं।

हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आपके पति आपको फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं देते, तो इसे 'क्रूरता' नहीं माना जाएगा। असल बात ये थी कि डिलीवरी के बाद पत्नी को बीपी हो गया, इस वजह से मना किया था। पति का ये भी कहना था कि अमेरिका में वही घर के सारे काम करता है। पत्नी सिर्फ टीवी देखती है और रिश्तेदारों से फोन पर बात करती है। ये एक नया ट्रेंड-सा दिखने लगा है। दूसरी ओर ऐसे भी मिस्टर हैं जो अपनी मिसेज को बिल्कुल आजादी नहीं देते। पैसे के मामले में इनकी मुट्ठी बंद रहती है। पत्नी की कमाई को भी वो कंट्रोल में ले लेते हैं।

बात ये है कि हर इंसान अपने अस्तित्व का प्यासा है। एक पति या पत्नी का रोल निभाने के अलावा मैं कौन हूं? क्या हम दोस्त हैं, जो एक-दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं? हफ्ते-महीने-साल हो गए, आंखों में आंखें डालकर आपने मुझसे कोई दिल में छुपी बात कही हो।

तो हो जाए हर महीने एक शाम, सिर्फ एक-दूसरे के नाम। थोड़ा एफर्ट इसमें डालिए, ये नहीं कि कुछ भी खा लिए। एक बार पत्नी प्लान करे, एक बार पति; सिर्फ ले लें उस डेट की अनुमति। सोचो उसे क्या पसंद है, कुछ ऐसा जो सालों से बंद है। अगर बिल्कुल समझ न आए, तो उसके दोस्तों से आइडिया पाएं।

जमी हुई बर्फ पिघलानी है, एक छोटी सी आशा लानी है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी बहता है। ऐसे रिश्ते में ही प्रेम रहता है। प्रेम के घर में सब पनपते हैं, कोई गैर-नहीं सब अपने हैं। पहली डेट के बाद मुझे ईमेल करें, कैसा लगा? तहे दिल से लिखें!

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

काहिरा वार्ता

शांति की आशा

काहिरा वार्ता से युद्धरत गाजा में शांति की आशा पैदा हुई है। गाजा में लगातार जारी युद्ध के दौरान वार्ताकार इस सप्ताहान्त गाजा में एकत्र हुए। उनका उद्देश्य युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए वार्ता करना था। यह वार्ता महत्वपूर्ण समय पर हो रही है क्योंकि हमास और इस्राइल के बीच टकराव दसवें महीने में प्रवेश कर गया है। वर्तमान समय में जारी युद्ध के बावजूद उम्मीद है कि निकट भविष्य में शांति स्थापना संभव है, हालांकि अनेक बाधायें बनी हुई हैं। युद्ध के कारण गाजा खंडहरों में बदल गया है और असाधारण मानवीय संकट पैदा हुआ है। इस टकराव के कारण गाजा की पूरी जनसंख्या कम से कम एक बार विस्थापित हुई है और स्थाई शांति लाने के लिए अब तक युद्धविराम प्रयास विफल हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय अंततः वार्ता कराने में सफल हुआ है ताकि वर्तमान समय में जारी हिंसा समाप्त हो सके। हिंसा की छाया में हो रही काहिरा वार्ता टकराव समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। लेकिन वार्ता इस तथ्य से जटिल हो जाती है कि हमास ने एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा भेजने के बावजूद कहा है कि वह सीधे वार्ता में भाग नहीं लेगा। इसके बजाय उम्मीद है कि हमास प्रतिनिधिमंडल मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा और वार्ता की प्रगति पर जानकारी प्राप्त करेगा। हमास लगातार गाजा से इस्राइली सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग कर रहा है जिसमें गाजा-मिस्र सीमा पर स्थित 'फिलाडेल्फी कारीडोर' भी शामिल है। यह चर्चा में विवाद का प्रमुख विषय है। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू का अपना दृष्टिकोण है और वे सीमाओं से सैनिकों की वापसी के पक्ष में नहीं हैं।

वर्तमान वार्ता का आधार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 31 मार्च को पेश एक योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्वीकार किया है। इस योजना में तीन-चरणों वाली प्रक्रिया शामिल है जिसकी शुरुआत पूर्ण युद्धविराम से होगी। इसके दौरान इस्राइली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में इस्राइली बंधकों की वापसी होगी। योजना पर हमास नेतृत्व की शुरुआती सहमति के बाद, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने कुछ आपत्तियां प्रकट की हैं। वे गाजा-मिस्र सीमा पर इस्राइली सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं। उनका तर्क है कि यह हमास को पुनः हथियारबंद होने से रोकने के लिए जरूरी है। अमेरिका, इस्राइल और हमास के बीच खाई पाटने के लिए नए प्रस्ताव तलाश रहा है। वार्ता की सफलता इस बात पर निर्भर है कि अमेरिका समझौता स्वीकार करने के लिए नेतनयाहू पर दबाव डालने में सफल होता है या नहीं। इस बीच गाजा में युद्ध जारी है। इस्राइली हवाई हमलों तथा तोपखाने की गोलाबारी में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है और हाल में दर्जनों सिविलियनों के हताहत होने की खबरें आई हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस्राइली सैनिक कार्रवाई तेज होने के बाद डेर-अल-बालेह व खान यूनिस जैसे क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन की खबरें दी हैं। गाजा में मानवीय संकट गंभीर बना हुआ है तथा रोज सुरक्षा की तलाश में दर्जनों परिवार पलायन कर रहे हैं। इस्राइल व गाजा के निवासी रक्तपात समाप्त करने के पक्ष में हैं। इस्राइल में जारी विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग बाकी बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने का आह्वान कर रहे हैं। इस्राइल और हमास के बीच गाजा में शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है। आने वाले दिन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि इस क्षेत्र में स्थाई रूप से युद्धविराम लागू हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति

पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को उच्च वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। लेकिन जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।

बी. के. झा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अर्थशास्त्रियों के बीच चर्चा में आमतौर से कहा जाता है, 'जब छः अर्थशास्त्री किसी विषय पर चर्चा के लिए एकत्र होते हैं तो उनके बीच सात दृष्टिकोण सामने आते हैं।' यह कहावत अक्सर आर्थिक विमर्श में आने वाले विचारों की विविधता को अभिव्यक्त करती है। हालांकि, अर्थशास्त्री आमतौर से जीडीपी, मुद्रास्फीति व अवमूल्यन दरों की बात करते हैं, पर उनके अनुमान अक्सर असली दुनिया की राजनीतिक जटिलताओं तथा सामाजिक परिवर्तनों का अति-सरलीकरण कर देते हैं। वास्तव में अधिकतम तार्किक आर्थिक पूर्वानुमान भी राजनीतिक यथार्थ की अभूतपूर्व परिवर्तनशील प्रकृति और व्यापक सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के कारण गलत हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, अन्य बड़े वित्तीय संस्थानों के अर्थशास्त्रियों तथा यहां तक कि सरकार की सेवा करने वाले प्रमुख विशेषज्ञ भारत की 'प्रगति गाथा' के बारे में अलग-अलग नतीजे निकालते हैं।

नवीनतम दो अनुमानों में नरेन्द्र मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वैंकट सुब्रमणियन और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष-आईएमएफ के भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक का कहना है कि भारत वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अर्नेस्ट एंड यंग ने अनुमान लगाया है कि भारत 2047 तक 26 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसे देखते हुए सुब्रमणियन का 55 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का अनुमान ज्यादा आशावादी लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील प्रकृति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि कौन सा अनुमान यथार्थवादी है क्योंकि यहां अनेक सामाजिक-आर्थिक कारण तथा राजनीतिक शक्तियां एकसाथ काम कर सकती हैं। सुब्रमणियन ने अपनी नई पुस्तक 'इंडिया 100: इन्विजनिंग टूमारोज इकोनोमिक पावरहाउस' में एक आशावादी अनुमान लगाया है। हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित 'एसोचैम' के आयोजन में इसे जारी किया। पुस्तक में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। महत्वाकांक्षी होने के बावजूद सुब्रमणियन का तर्क भारतीय अर्थव्यव्था के मार्ग तथा उच्च वृद्धि दर बनाए रखने वाली नीतियों के समग्र विश्लेषण पर आधारित है।

भारत में ऐतिहासिक मुद्रास्फीति दरों, मुद्रा के अवमूल्यन तथा हालिया आर्थिक नीतियों को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी अनुमान के पीछे छिपे तर्क तलाशना कठिन नहीं है। उन्होंने उचित ही जोर दिया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को 8 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा लगभग 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर बनाए रखनी होगी।

ऐतिहासिक रूप से डालर की तुलना में भारतीय रुपये की अवमूल्यन दर 3 से 3.5 प्रतिशत के बीच बनी हुई है जिसका कारण भारत की उच्च मुद्रास्फीति दर है। सुब्रमणियन का अनुमान है कि 2016 का मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखते हुए भारत की मुद्रास्फीति औसतन 7 प्रतिशत रहेगी जिससे अवमूल्यन दर अधिक होगी। लेकिन मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थायित्व को देखते हुए भारत की मुद्रास्फीति दर घट कर लगभग 5 प्रतिशत पर आ गई है, जबकि कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया को आर्थिक झटके लगे हैं। हालांकि, निवेश दूना होने के 'नियम 72' के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति के समक्ष कुछ सीमायें हैं। सुब्रमणियन के अनुसार, यदि भारत की वास्तविक वृद्धि दर 7 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत पर बनी रहे तो रुपये में यह वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत होगी। 3 प्रतिशत के ऐतिहासिक अवमूल्यन दर को देखते हुए डालर के अनुसार वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत होगी और इससे अर्थव्यवस्था का आकार हर आठ साल में दूना हो जाएगा। इससे 2047 तक भारत की जीडीपी 26 ट्रिलियन डालर होगी।

लेकिन सुब्रमणियन का तर्क है कि बेहतर मुद्रास्फीति लक्ष्य को देखते हुए मुद्रास्फीति तथा अवमूल्यन दरों में कमी आएगी और इससे भारतवर्ष रुपये में 13 प्रतिशत तथा डालर में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था हर 6 साल में दूनी होगी और वह 2047 तक 55 ट्रिलियन डालर की हो जाएगी। अनेक अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों के अनुसार ये अनुमान यथार्थ से परे लगते हैं क्योंकि राजनीतिक यथार्थ को देखते हुए अगले बीस साल के मैक्रोइकोनोमिक परिदृश्य का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। इसमें राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण संचालक शक्ति की भूमिका अदा करेगा, लेकिन यदि भारत की वर्तमान स्थिर गठबंधन सरकार अपनी शक्ति खो देती है तो पूरी आर्थिक यात्रा का मार्ग कठिन हो जाएगा। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इससे असहमत हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पुस्तक प्रस्तुतीकरण आयोजन में इस तथ्य पर जोर दिया कि भारत में वर्तमान स्थिर राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह लक्ष्य यथार्थवादी लगता है। उन्होंने जोर दिया कि गठबंधन राजनीति में भी साहसी निर्णय लेना आर्थिक सुधार जारी रखने का प्रमुख तत्व है। गोयल ने राजनीतिक स्थायित्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी-भाजपा की प्रभुत्वकारी स्थिति बनी हुई है और इससे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन का परिवेश बनता है।

उन्होंने संकेत किया कि पिछले आम चुनाव में भाजपा की जिन सीटों पर पराजय हुई, वह 30,000 वोट से कम थी। इससे स्पष्ट होता है कि उसका मजबूत जनाधार बना हुआ है। गोयल के अनुसार यह राजनीतिक परिदृश्य अगले दो दशकों और उसके बाद तक साहसी आर्थिक सुधार बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह स्वीकार किया जाता है कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मजबूत आर्थिक नीतियां जरूरी हैं। इनमें खासकर औपचारीकरण, खोज व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं। भारत का अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, पर वह औपचारिक क्षेत्र की तुलना में कम उत्पादक है। डिजिटल ढांचे के माध्यम और नियामक सुधारों द्वारा औपचारीकरण को बढ़ावा देना उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही उद्यमिता एवं खोज का बहुत महत्व है। 2014 के बाद से भारत में नई फर्मों के गठन में तेजी आई है। इससे देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र वाला देश बन गया है। उद्यमिता से न केवल नई फर्मों में उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि इससे नई फर्मों को खोज का प्रोत्साहन मिलता है। इससे समग्र आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। सुब्रमणियन के दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ 'नैतिक संपदा सृजन' है। उनके विचार से यह बड़े और समृद्ध मध्य वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन तथा व्यापक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इस अवधारणा का खंडन किया है कि संपदा सृजन और रोजगार परस्पर विरोधी शक्तियां हैं। उनका तर्क है कि संपदा सृजन से काफी रोजगार सृजन होता है, उच्च वेतन देने की संभावना बनती है तथा समग्र आर्थिक कल्याण में योगदान मिलता है। नैतिक संपदा सृजन अतीत में 'क्रोनी कैपिटलिज्म' की प्रतिक्रिया से पैदा हुआ है जो आर्थिक वृद्धि रोकने तथा व्यवस्थागत अक्षमता को जन्म देने का काम करता था। एक पारदर्शी और न्यायोचित बिजनेस परिवेश प्रोत्साहित कर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि संपदा सृजन का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचे।

इससे सामाजिक व आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ अर्थशास्त्री 55 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जटिल वैश्विक व घरेलू आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए काल्पनिक मान सकते हैं। लेकिन भारत की अंतर्निहित आर्थिक शक्ति तथा दृढ़ता को देखते हुए स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद भारत की आर्थिक प्रगति का लक्ष्य यथार्थ लगता है। घरेलू निवेश एवं निर्यात को प्रोत्साहन जैसी उचित नीतियों को आगे बढ़ाने से भारत अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर आगे बढ़ सकता है। वर्तमान समय में भारत नए आर्थिक युग के प्रवेश द्वार पर है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं।

मलित बस्तियों में किशोरियों का संघर्षमय जीवन

"सरकारी पहलों के बावजूद, युवा लड़कियां। अक्सर शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है और घरेलू ज़िम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं।"

हर्षाली नीलकंठ जलके
(लेखिका जयपुर में जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं)

जयपुर की झुग्गी बस्ती बाबा रामदेव नगर की संकरी गलियों में, 12 वर्षीय पूजा (बदला हुआ नाम) अपने तीन वर्षीय भाई को गोद में लिए हुए है, जबकि उसकी माँ शारदा पास में ही खाना बना रही है। पूजा अपनी माँ के कहने पर पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए इधर-उधर भागती है। इसके विपरीत, उसका 8 वर्षीय भाई बिना किसी बाधा के खेलता रहता है। दृश्य तब मार्मिक हो जाता है जब पूजा की एक सहेली स्कूल से लौटती है। स्कूल के बारे में बात करते हुए पूजा की आंखें चमक उठती हैं, जिससे उसकी शिक्षा के लिए लालसा का पता चलता है। लेकिन जब पूछा जाता है कि पूजा स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो शारदा बीच में बोलती है, अगर वह स्कूल जाती है, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? पूजा के सपने उसकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।

बाबा रामदेव नगर में रहने वाले कई परिवारों में शारदा और उनके पति, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, 500 से ज़्यादा लोगों की झुग्गी बस्ती में रहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बहुलता वाले इस गांव में लोहार (लोहार), जोगी, कालबेलिया और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। ये परिवार राजस्थान के सुदूर ग्रामीण इलाकों से शहर में बेहतर रोजगार के अवसरों की उम्मीद में पलायन कर आए हैं। कुछ परिवार स्थायी रूप से बस गए हैं, जबकि अन्य काम की उपलब्धता के आधार पर मौसमी तौर पर पलायन करते हैं।

हालांकि, पलायन की प्रक्रिया और इसके साथ आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का सबसे ज्यादा असर बच्चों, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। गुजारा करने के संघर्ष के कारण अक्सर परिवार शिक्षा जैसे दीर्घकालिक निवेशों की तुलना में तत्काल जीवनयापन को प्राथमिकता देते हैं। ऐसी स्थितियों में, लड़कियों को सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। घर पर आर्थिक तनाव लड़कों की तुलना में लड़कियों को ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे न केवल उनकी शिक्षा बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी बाधित होता है। इस झुग्गी में पूजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है- 14 वर्षीय आशा (बदला हुआ नाम), चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी। उसके माता-पिता स्क्रैप डीलर के रूप में काम करते हैं, इसलिए आशा को अपने भाई-बहनों की देखभाल और घर का काम संभालना पड़ता है। जिन दिनों उसकी माँ काम नहीं कर पाती, आशा आगे आती है।

सीखने की तीव्र इच्छा के बावजूद आशा ने पांचवीं कक्षा के बाद से कक्षा के अंदर का दृश्य नहीं देखा है। झुग्गी-झोपड़ी की कई लड़कियों की तरह उसकी शिक्षा भी रुक गई क्योंकि उसने घर की ज़िम्मेदारियां संभाल लीं। एक बुज़ुर्ग निवासी कांति सवाल करती हैं, अगर लड़की स्कूल जाएगी, तो घर और छोटे भाई-बहनों की देखभाल कौन करेगा? फिर भी, वह इस बात पर चुप रहती है कि ये ज़िम्मेदारियाँ लड़कों पर क्यों नहीं डाली जातीं। आठ साल से झुग्गी-झोपड़ी में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश मिश्रा बताते हैं, बाबा रामदेव नगर जैसी शहरी झुग्गियों में लड़कियों की शिक्षा के बारे में अभी भी जागरूकता की कमी है। आर्थिक चुनौतियों और शिक्षा के महत्व के बारे में सामाजिक चेतना की कमी के कारण माता-पिता स्कूली शिक्षा की तुलना में आय को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अक्सर बच्चे बाल श्रम में धकेल दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन बाबा रामदेव नगर में लड़कियों के स्कूल से दूर रहने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इंडियास्पेंड की रिपोर्ट एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है: 2021-22 में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर 1.35 प्रतिशत थी, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़ा बढ़कर 12.25 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट न केवल नीति कार्यान्वयन बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की तरह ही महत्व दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए संघर्ष किशोर लड़कियों के लिए सबसे अधिक स्पष्ट है, खासकर बाबा रामदेव नगर जैसे शहरी गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में। हालांक कुछ शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की बाधाएं कम होने लगी हैं, लेकिन इस झुग्गी बस्ती की लड़कियाँ सीखने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना जारी रखती हैं।

बाबा रामदेव नगर में, पूजा और आशा जैसी लड़कियों के लिए शिक्षा की खोज में कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयां और जड़ जमाए हुए सामाजिक मानदंड दीर्घकालिक शिक्षा की तुलना में तत्काल अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कई लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती हैं। सरकारी पहलों के बावजूद, बाल श्रम और लड़कियों द्वारा असमान रूप से उठाए जाने वाले घरेलू उत्तरदायित्व जैसे कारकों के कारण शैक्षिक प्राप्ति में अंतर बहुत बड़ा है।

गरीबी के चक्र को तोड़ने तथा इन युवा लड़कियों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आप की बात

टिकट की मारामारी

सत्ता में बार-बार अने वाली राजनीतिक पार्टी में टिकट की मारा-मारी आरम्भ हो जाती है। ऐसा ही सदैव कांग्रेस में रहा है। जब से देश में कांग्रेस कमजोर हुई है तब से कांग्रेस में टिकट की मारा-मारी कम हो गई है। भाजपा में भी टिकट की उठापटक 2024 के चुनाव में देखी ही गई, वर्तमान विधानसभा चुनावों में भी सामने आ रही है। आरोप है कि जिन जमीनी कार्यकर्ताओं ने जिंदगी का बहुमूल्य समय पार्टी की सेवा में लगाया, उनके टिकट काट दिए गए और दलबदलुओं को टिकट मिल गए। जम्मू-कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही टिकट बंटवारे की हलचल तेज हो गई है। दूसरे दलों से पार्टी में आने वालों को टिकट देने का विरोध भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में भाजपा नेता विनोद रैना कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि उनकी राय पूरी तरह सुनी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद असंतोष जारी है। भाजपा पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और उसने अनेक मुस्लिमों को भी टिकट दिए हैं। ऐसे में भाजपा को लोकसभा चुनाव परिणाम से भी उचित सबक लेना चाहिए जहां दलबदलुओं को टिकट देने से उसे कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

अमेरिका में चुनाव

जब तक जो बाइडेन चुनवी मैदान से नहीं हटे थे तब तक रिपब्लिकन ट्रम्प का ग्राफ ऊपर के ओर अग्रसर था, मगर जैसे ही कमला हैरिस का नाम सामने आया तबसे ट्रम्प न सिर्फ पीछे चल रहे हैं बल्कि कई रिपब्लिकन शासित राज्यों में भी कमला हैरिस बराबरी की टक्कर देने में कामयाब हुई हैं। शायद इसी वजह से ट्रम्प के इन दिनों पसीने छूट रहे हैं। भले ही अपने द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की मेहरबानी पर अपराध के मामलों से उन्हें अदालती छूट मिल गयी है मगर जनता की अदालत से उनका बचना फ्लिहाल नामुमकिन लग रहा है। संभवतः कमला हैरिस से डर के कारण ट्रम्प ने 10 सितम्बर को आयोजित होने वाली टीवी बहस में भाग नहीं लेने की घोषणा की है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रम्प ने नेटवर्क को पक्षपाती बता कर इस बहस से पल्ला झाड़ा है। यही ट्रंप जो बाइडेन को बार-बार बहस की चुनौती दे रहे थे क्योंकि पहली बहस में बाइडेन का प्रदर्शन बहुत खराब था। लेकिन बाइडेन के स्थान पर कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने से ट्रंप की सारी रणनीति विफल हो गई है। कमला हैरिस ने देश के मध्य वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ ही अमीर वर्ग को भी आकर्षित करते हुए रिकार्डतोड़ फड एकत्र किया है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

जम्मू कश्मीर चुनाव

जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पूरे भारत ही नहीं समूचे विश्व की निगाहें लगी हुई है। अनुच्छेद 370 हटाने पर देश भर में खून की नदियां बहने की धमकी देने वाले अलगाववादी कश्मीरी नेता भी इस चुनाव में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने का आश्वासन देने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करके अपनी असलियत दिखा दी है। पता नहीं क्यों इन दलों को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 बहाल करने का वायदा मतदाताओं को लुभाने वाला सिद्ध होगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो अमन चैन कायम हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि धारा 370 बहाल करने की बात करना मतदाताओं को अपने विरुद्ध करना सिद्ध होगा। वास्तव में अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ्रेंस को कश्मीर पर अपनी खोई हुकूमत की पीड़ा सता रही है और यही कष्ट महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को भी है। विडंबना है कि कांग्रेस अनुच्छेद 370, कश्मीर का अलग झंडा व अलग संविधान बहाल करने वाली परिवारवादी पार्टियों के साथ मिल गई है। आशा है कि कश्मीर की जनता अपने प्रदेश को फिर अंधेरे युग में ले जाने का प्रयास करने वाली इन शक्तियों को पूरी तरह खारिज कर देगी।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

योगी आदित्यनाथ का संदेश

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन जोधपुर के नरेश महाराजा जसवंत सिंह के सेनापति राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नही हो सकता। यह तब होगा जब हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से सबक लेने का आवाहन करते हुए कहा कि ऐसी गलती हमारे देश मे नही होनी चाहिए। अपने देश के वीरों पर गर्व करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस देश मे वीर दुर्गादास जैसे योद्धा पैदा होते है, उस देश का कोई बाल बांका नही कर सकता। लोगों में वीरवर दुर्गादास के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा का भाव है, यही हमारी असली ताकत है। योगी के संदेश को गलत ढंग से देखने वाले विपक्षी नेताओं की जितनी निन्दा की जाए वह कम होगी। योगी और मोदी अपने हिंदुत्व को छिपाते नहीं हैं, इसलिए दुनिया में हिंदुओं पर कहीं भी हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ उनका मुखर होना प्रेरणादायक है।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 165

ऋण देने में आसानी

भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रायोगिक परियोजना के बाद आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर एक नया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अथवा यूएलआई जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण बढ़ाया जाएगा, खासकर कृषि और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) क्षेत्र में। एक बार क्रियान्वयन होने के बाद इसमें इतनी क्षमता है कि यह ऋण क्षेत्र के परिदृश्य को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की तरह बदलकर रख दे। यूपीआई से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया। हाल ही में 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज' विषय पर आयोजित आरबीआई@90 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात को रेखांकित किया कि यूएलआई प्लेटफॉर्म विभिन्न डेटा सेवा प्रदाताओं से कर्जदाताओं तक डिजिटल सूचना का अबाध और सहमति आधारित प्रवाह सुनिश्चित करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यूएलआई ढांचा विभिन्न स्रोतों से हासिल सूचनाओं तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे कर्जदाताओं को संभावित कर्जदारों की ऋण पात्रता के बारे में सही सूचना मिल सकेगी।

यह उम्मीद भी है कि ऋण मंजूरी और वितरण में लगने वाले समय में कमी आएगी। ऋण की अबाध आपूर्ति और बिना गहन दस्तावेजीकरण के सहजता से काम होने से कर्जदारों और कर्जदाताओं दोनों को लाभ होगा। शासन की गुणवत्ता में सुधार करने की एक कोशिश में भारत ने अपनी डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना (डीपीआई) का सही उपयोग किया है। इसमें जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन के साथ यूपीआई भी शामिल है। यूएलआई देश में डीपीआई के सफर में सबसे नया हिस्सेदार बनने को तैयार है। छोटी कंपनियों द्वारा निजी निवेश को बढ़ाने तथा आम घरेलू खपत को गति देने के लिए भारत को एक विकसित ऋण बाजार की आवश्यकता है। बीते सालों के दौरान ऋण की मांग में निरंतर इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए 2021 और 2022 को मिलाकर देखें तो न्यू टु क्रेडिट (एनटीसी यानी नया ऋण लेने वाले) लोगों की संख्या 6.6 करोड़ रही। इसमें से 67 फीसदी लोग ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों से थे। इसके बावजूद आम परिवारों और एमसएमई को ऋण की उपलब्धता सीमित बनी रही।

ऋण की मांग और आपूर्ति में लगातार अंतर बना रहा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, मसलन कर्जदारों का ऋण जोखिम प्रोफाइल, जोखिम आकलन के लिए अपर्याप्त आंकड़े, सेवा की ऊंची लागत, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग निजी खपत के लिए कम मूल्य का कर्ज लेते हैं। ईवाई द्वारा गत वर्ष जारी एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि देश में एमएसएमई ऋण की पहुंच, खुदरा ऋण की पहुंच और क्रेडिट कार्ड की पहुंच क्रमशः 14 फीसदी, 11 फीसदी और चार फीसदी है। इस संबंध में यूएलआई कर्जदाताओं को उपभोक्ताओं के तमाम वित्तीय और गैर वित्तीय आंकड़े मुहैया कराएगा और डिजिटल ढंग से कर्ज देना संभव होगा। पूरी तरह पारंपरिक ऋण और आय वक्तव्यों पर विचार करने के बजाय कर्जदाताओं को अतिरिक्त आंकड़ों और उन्नत एलगोरिद्म तक पहुंच कराई जाएगी जिससे जोखिम का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए भौतिक परिसंपत्ति स्वामित्व, जमीन के रिकॉर्ड, जियोलोकेशन टैगिंग और डिजिटल छाप की ट्रैकिंग से संभावित कर्जदार की ऋण पात्रता का संकेत मिल सकता है।

कुल मिलाकर डिजिटल ऋण उद्योग मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण कुल वितरण में अच्छी खासी हिस्सेदारी रहेगी। परंतु इसके साथ ही बैंकिंग तंत्र के भीतर आंतरिक समायोजन करना होगा ताकि इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सके। उदाहरण के लिए बैंकिंग तंत्र में ऋण और जमा वृद्धि के बीच भारी अंतर है। जमा वृद्धि कुछ समय से ऋण वृद्धि से पीछे चल रही है। बैंकों को जमा जुटाने की जरूरत है तभी वे मजबूत ऋण वृद्धि बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक को भी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण व्यवहार पर नजर रखनी होगी। गत वर्ष उसने ऋण वृद्धि में नियंत्रण रखने के लिए कुछ क्षेत्रों के ऋण में जोखिम भार को बढ़ाया था।

अजय मोहंती

कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार की दरकार

सरकार को बाजार के अनुकूल होना चाहिए न कि कारोबारों के। उसे सभी कंपनियों के साथ तटस्थ रिश्ते रखते हुए काम करना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई

आजाद भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो नीतिगत बदलाव के मोर्चे पर वह दो बड़े चरणों से गुजर चुकी है। पहले की चर्चा इन दिनों ज्यादा नहीं होती और वह है अप्रैल 1951 में योजनागत विकास की शुरुआत, जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। दूसरा जुलाई 1991 में शुरू किया गया आर्थिक उदारीकरण था, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है। इन दोनों की बदौलत वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी आई। परंतु दोनों में सरकार की जो भूमिका सोची गई थी, वह काफी अलग है। इन दोनों बदलावों के प्रभाव को अर्थव्यवस्था की वृद्धि, निवेश और व्यापारिक रुझान में देखा जा सकता है। वृद्धि का एक अपेक्षाकृत धीमा चरण 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के अंत तक भी रहा, जब सूखा, नई कृषि वृद्धि नीति और राजनीतिक उथलपुथल से भरा एक दशक सामने था।

1951-52 में उठाए गए कदम के कारण आए बदलाव कुछ कम लग सकते हैं मगर ये बहुत अहम थे क्योंकि आजादी के पहले की एक सदी में 0.5 फीसदी रहने वाली औसत वार्षिक वृद्धि दर इसके कारण नौ गुना बढ़ गई। 1951 से 1965 के बीच आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया, खास तौर पर भारी उद्योग में। यद्यपि इस दौरान निजी निवेश भी बढ़ा। निर्यात उत्पादन के जरिये होने वाली वृद्धि संभव नहीं थी क्योंकि वैश्विक व्यापार के मूल्य में वृद्धि 60 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही शुरू हुई।

उच्च वृद्धि का चरण 1980 से शुरू हुआ लेकिन नीतिगत क्षेत्र में सार्वजनिक से निजी निवेश की ओर सफर जुलाई 1991 में उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। निवेश और विदेशी व्यापार में सरकारी नियंत्रण कम करने के अलावा एक बड़ा बदलाव था बैंकिंग और म्युचुअल फंड में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना। उदारीकरण से पहले के रुख को देखें तो यह वित्तीय उदारीकरण औद्योगिक निवेश को लाइसेंसमुक्त करने की तुलना में ज्यादा बड़ा बदलाव रहा। उदाहरण के लिए हमने गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नई पूंजी में भारी इजाफा देखा और यह 1981-82 में करीब-करीब 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गई।

निर्यातोन्मुखी वृद्धि की ओर बदलाव कम दिखता है। 1951 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी थी। पहले परिवर्तनकारी चरण में 1980 तक यह गिरकर 0.4 फीसदी रह गया था। परंतु उसके बाद से ही इसमें स्थिर गति से वृद्धि हुई और 2003 के बाद से आठ वर्षों तक उच्च वृद्धि के दौर के साथ भारत ने वैश्विक विनिर्माण निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर ली है। अब यह 1.8 फीसदी है यानी 1951 के स्तर से कुछ कम। वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1990 के 0.6 फीसदी से बढ़कर 2023 में 4.3 फीसदी हो गई।

सवाल यह है कि अगर हमें 2047 तक विकसित देश बनना है तो सरकार और कारोबार के रिश्तों में क्या बदलाव लाना होगा? सबसे स्पष्ट बदलाव है सरकार और निजी कारोबारी क्षेत्र के बीच रिश्ते को चुनिंदा कंपनियों को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के बजाय ऐसी साझेदारी बनाना, जहां सरकार कारोबार नहीं बाजार के अनुरूप है एवं सभी कंपनियों के साथ उसके संबंध एकदम निरपेक्ष हैं। यह सांठगांठ और भ्रष्टाचार से बचने में ही कारगर नीति नहीं है बल्कि इसलिए भी सही है क्योंकि राजनेता और अफसरशाह तकनीक, उत्पादों, प्रक्रियाओं, बाजार विकास आदि की उतनी जानकारी नहीं रखते, जितनी कंपनियों के अधिकारियों को होती है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजना में प्राथमिकता वाली तकनीकों के वास्तविक प्रदर्शन और कड़ी अफसरशाही जांच की आवश्यकता होती है। यह इस बात का उदाहरण है कि किन चीजों में बदलाव की जरूरत है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी तथा व्यापार कर नीतियां तय करते समय उत्पादकों के हितों को पूरी तरह दरकिनार करना सरकार को बाजार के अनुकूल निष्पक्ष कारक बनाने की दिशा में अहम कदम होग। अगर पूरी तरह निष्पक्षता कठिन है तो कम से कम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विशिष्ट उत्पादकों का हित नियम के बजाय अपवाद हो। सबसे अहम नीतिगत पहल यह होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा आयोग की क्षमता और उसका प्रभाव बढ़ाया जा सके।

प्रभावी प्रतिस्पर्धा नीति का महत्त्व निजी कारोबारी क्षेत्र के प्रबंधन पर उसके संभावित प्रभाव में निहित है क्योंकि इस क्षेत्र में अब भी परिवारों का दबदबा है। मगर स्वामित्व मसला ही नहीं है। मसला तो पेशेवर प्रबंधन है। परिवार द्वारा संभाले जा रहे उद्यम से पेशेवर प्रबंधन वाले उद्यम तक सफर आसान नहीं है। इस दौरान प्रतिस्पर्धा होती है और संस्थागत अंशधारकों द्वारा अंशधारकों के हितों को मजबूती से सामने रखा जाता है। कंपनियों को भी सरकार का पसंदीदा साझेदार बनने पर जोर देने के बजाय देसी-विदेशी साझेदारों की तुलना में अपने उत्पाद और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए।

भारत को विकसित या उच्च आय वाला विकासशील देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में इजाफा जरूरी है। परंतु देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी काफी हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मोटे तौर पर दायित्व की तरह देखती है और उनका विनिवेश करके निजीकरण करना चाहती है। इन कंपनियों में से कई तकनीकी विकास में अग्रणी रही हैं और उन्होंने तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं का वर्ग तैयार किया है जिन्हें निजी क्षेत्र ने हथिया लिया। सरकार को सरकारी उपक्रमों की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख रखना चाहिए।

कारोबारी प्रशासन की जो नीति कंपनियों की स्वतंत्रता बढ़ाती हो उसे राजनीतिक रूप से आकर्षक नहीं माना जाएगा क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं मिलेगा। किंतु इसके जरिये वृद्धि और रोजगार सृजन में होने वाले इजाफे का स्वागत किया जाएगा। बहरहाल ऐसी सरकार को आसानी से राजनीतिक स्वीकार्यता मिलेगी जो गैर कॉरपोरेट निजी क्षेत्र की मदद करती नजर आती हो, आय में भारी असमानता कम करने वाली हो और क्षेत्रीय असमानता एवं जाति संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हो। मुक्त बाजार वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह सही है। ऐसे में वह संदेश भी समझने की आवश्यकता है जो पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति वाले अध्याय में लिखा गया था- किसी भी समय किसी देश की आर्थिक स्थिति व्यापक सामाजिक माहौल से बनती है। इसके साथ ही आर्थिक योजना निर्माण को एक व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका लक्ष्य न केवल संसाधनों का विकास है बल्कि मानव क्षमताओं का विकास और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत ढांचा बनाना भी है।

बुनियादी ढांचे के लिए सामूहिक कराधान व्यवस्था

देश में बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को नए ढंग से परिभाषित कर सकने वाले कदम के रूप में सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इस क्षेत्र के लिए सामूहिक कराधान व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए। दुनिया के कई बड़े और आर्थिक रूप से समृद्ध देश पहले ही इसे अपना चुके हैं।

बिस्कुट, जूते और स्टील के पाइप बनाने वाली एक कंपनी इन सभी कारोबारों को मूल कंपनी की अलग-अलग शाखाओं के रूप में चला सकती है और कराधान के नजरिये से वह अपने मुनाफों और घाटों को समेकित करके एकल करयोग्य मूल्य पर पहुंच सकती हैं। अब बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी पर विचार कीजिए। मध्यम आकार की किसी भी कंपनी में 20 से 30 विशेष उद्देश्य वाली कंपनियां (एसपीवी) होंगी, जबकि बड़ी कंपनियों में एक समय पर 50 से अधिक ऐसी कंपनियां हो सकती हैं। इन्हें एसपीवी कहा जाता है क्योंकि वे किसी अलग परियोजना का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के डेवलपर विभिन्न प्रकार के एसपीवी में काम करती हैं। ये कई प्रकार के अनुबंधों के तहत काम करती हैं जिनमें साधारण निर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ कहीं अधिक जटिल रियायती समझौते, खासकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किए गए समझौते शामिल होते हैं।

ऐसी रियायतें या अनुबंध काफी जटिल साबित हो सकते हैं क्योंकि रियायत देने वाले प्राधिकार, वित्तीय मदद करने वाले और नियामक इस बात पर जोर दे सकते हैं कि हर परियोजना को एक अलग विधिक संस्था बनाया जाए, जिसका अलग नकदी प्रवाह, ऋण देनदारी आदि हों। दिक्कत यह है कि प्रत्येक एसपीवी के अलग विधिक संस्था होने के कारण उनमें से हरेक को अलग- अलग आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। इतना ही नहीं बुनियादी ढांचा कंपनियां पोर्टफोलियो पद्धति के साथ काम करना पसंद करती हैं तथा वे लंबी अवधि के दौरान अलग-अलग परियोजनाओं के मुनाफे और नुकसान को संतुलित करके देखती हैं ताकि उन्हें कुल मिलाकर एक स्वीकार्य प्रतिफल मिल सके। परंतु एकल एसपीवी दर्जा उन्हें ऐसा कराधान नहीं अपनाने देता।

इस व्यवस्था से कई नियामकीय और वित्तीय उद्देश्य तो पूरे हुए मगर अनजाने में यह दोधारी तलवार बन गई। इससे व्यावसायिक अकुशलता उत्पन्न हो रही है और पूंजी के भारी इस्तेमाल वाले क्षेत्र में विकास बाधित हो रहा है। बिजली, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों को ग्रुप होल्डिंग कंपनी के तहत हर उपक्रम के लिए अलग-अलग एसपीवी बनानी पड़ती है। इससे परिचालन जटिलता बढ़ती है और वे कानूनी भूल-भुलैया में फंस जाती हैं। जटिलताओं में उलझने के कारण व्यय बढ़ता है और हर एसपीवी के लिए कर रिटर्न दाखिल करना होता है।

बुनियादी ढांचा
विनायक चटर्जी

कई बार प्रतिकूल सामाजिक, नियामकीय या राजनीतिक मसलों के कारण परियोजनाएं लंबे समय तक रुकी रहती हैं। ऐसी परियोजनाओं के कारण लागत डूबती है और कॉरपोरेट समूहों को अधिक कार्यशील पूंजी डालने की आवश्यकता होती है। एक कारोबार में होने वाले नुकसान को दूसरे कारोबार के मुनाफे से पटा पाने की अक्षमता कर संबंधी मुश्किलें और विसंगतियां पैदा करती है। एक एसपीवी की वित्तीय कठिनाइयां या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां समूचे समूह की क्रेडिट रेटिंग पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में और रकम जुटाना मुश्किल होता है।

आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो एसपीवी कुछ और नहीं बल्कि एक ही मूल कंपनी के हिस्से हैं। बस, कुछ जरूरतों के कारण वे अलग-अलग विधिक ढांचे में चलती हैं। ऐसे में कारोबार एक मजबूत सामूहिक कर व्यवस्था पेश करके साझा प्रबंधकीय नियंत्रण के लाभ ले सकते हैं।

प्रस्तावित सामूहिक कराधान व्यवस्था का लक्ष्य है पूरी तरह या बहुलांश स्वामित्व वाली कंपनियों के समूह को समेकित कर रिटर्न दाखिल करने की इजाजत देकर इन समस्याओं को हल करना और कर उद्देश्यों के लिए उन्हें एकल इकाई मानना। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मूल कंपनी पर ही समेकित कर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी होगी। मूल कंपनी के साथ समेकित सभी भारतीय अनुषंगी कंपनियों को इस रिटर्न में शामिल किया जाएगा। इससे निरंतरता और व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सकेगी।

उचित लेखा मानकों के हिसाब से भारतीय संस्थानों के लिए तैयार किए गए समेकित खाते, कर की गणना के आधार के रूप में काम करेंगे। इनमें आयकर प्रावधानों के अनुरूप जरूरी बदलाव किए जाएंगे। कर रिटर्न के उद्देश्य में समूहों के बीच लेनदेन समाप्त हो जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया आसान होगी और विवादों की आशंका घट जाएगी। कर योग्य आय या नुकसान का आकलन समूह की हर कंपनी के लिए समेकित ढंग से होगा और उसे एक साथ मिलाकर समूह के समग्र लाभ या हानि का आकलन होगा।

प्रस्तावित योजना के तहत कर दरों को तार्किक बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि समेकित समूह कराधान दर को 22 फीसदी तथा उपकर एवं अधिभार के साथ लागू किया जाएगा। यह आयकर अधिनियम की धारा 115 बीबीए के तहत मौजूदा रियायती कर व्यवस्था के अनुरूप ही होगी। इसके साथ ही समेकन के जरिये बेहतर लाभ दिए जाएंगे। प्रस्तावित पुनर्निर्धारण में समेकित सामूहिक कर प्रणाली में बदलाव के दौरान आगे लाए गए घाटे और न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पर भी विचार किया जाना चाहिए। नुकसान को मूल कंपनी के साथ शेष पात्र अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और क्रेडिट को एकबारगी जाने दिया जा सकता है। नुकसान की भरपाई और उसे आगे बढ़ाने के बारे में मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। इससे मौजूदा कर सिद्धांतों के साथ निरंतरता बनी रहेगी। इस कर सुधार के संभावित लाभ केवल प्रशासनिक किफायत से कहीं आगे जाते हैं। देश की कर नीति को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन व्यवहार के साथ जोड़कर सरकार इस क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटा सकेगी।

आलोचक कह सकते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में ऐसा अहम बदलाव सरकार को राजस्व में नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु सुधार समर्थक कहेंगे कि इसके दीर्घकालिक लाभ होंगे, जिसमें निवेश में इजाफा, कारोबारी सुगमता में सुधार और अधोसंरचना विकास में गति आदि शामिल हैं। ये लाभ राजस्व पर कुछ समय तक पड़ने वाली चोट पर भारी रहेंगे।

यह माना जा सकता है कि यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है और तमाम अंशधारक उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय नजरिये से देखें तो आठ में से छह बड़ी अर्थव्यवस्थाएं (भारत और चीन को छोड़कर), जी-7 के छह सदस्य, जी-20 के 10 सदस्य पहले ही सामूहिक कराधान को अपना चुके हैं। ऐसे में इस सुझाव को बेहतरीन वैश्विक व्यवहार के रूप में प्रगतिशील कर सुधार के रूप में अपनाया जा सकता है।

यह स्पष्ट है कि ऐसे सामूहिक कराधान आने वाले समय में समृद्ध और विकसित देश बनने की राह आसान कर सकता है क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के कठिन क्षेत्र में निजी पूंजी की आमद आसान करेगा।

(लेखक बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ हैं। वह इन्फ्राविजन फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी हैं। लेख में धीरेन शाह का भी योगदान)

आपका पक्ष

ई-कामर्स और खुदरा व्यापार में संतुलन स्थापित हो

लेख 'प्रतिस्पर्धा बढ़ाए ई-कॉमर्स नीति' खुदरा व्यापार पर ई-कॉमर्स के ऑनलाइन व्यापार और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा करता है। विषय को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ई-कॉमर्स छोटे और मध्यम व्यापारियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां जिनके टर्नओवर हजारों करोड़ रुपये के हैं, उनकी करदेयता उनकी अकाउंटिंग नीति के कारण हमेशा शून्य रहती है और उनके कर योग्य घाटे भी हजारों करोड़ रुपये के रहते हैं जो वर्ष दर वर्ष कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। वहीं छोटे और मध्यम उद्योग अपनी कर योग्य आय पर लगभग 20 प्रतिशत आयकर देते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां अपने घाटे के साथ बड़ी कंपनियों में मर्ज होती हैं तो इस प्रकार उनके घाटे कभी खत्म नहीं होते तथा वह कभी आयकर नहीं देते। इसी कर-देयता से बची हुई ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को भारी छूट देने की स्थिति में होती हैं। पूंजी के हिसाब से इनमें भारी विदेशी निवेश होता है जबकि व्यापारी बैंक ऋण पर निर्भर रहते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां कैश का व्यापार वह भी एडवांस में लेकर करती हैं। इन्हीं बिंदुओं पर सरकार को नीति बनानी चाहिए कि ई-कॉमर्स को कैश बर्न खर्च में नहीं स्वीकार होने चाहिए और मर्ज होने वाली कंपनियों का नुकसान सैट ऑफ नहीं होना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

ई-कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए खुदरा व्यापारियों को बढ़ावा देने की जरूरत है

बाल्यावस्था से ही बच्चों की प्रतिभा को पहचानें

खेलों इंडिया कार्यक्रम से खेलों को प्रोत्साहन तो मिला है लेकिन बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाना होगा। बढ़ चढ़ कर बातें और दावे करने के बजाय ठोस धरातल पर कार्य करना जरूरी है। बाल्यकाल से ही बच्चों की अभिरुचि और स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप उन्हें नियमित प्रशिक्षण देना श्रेयस्कर सिद्ध होगा।

दिव्यांश जैन, मुंबई

सरकारी सुविधाएं बढ़ें और हस्तक्षेप घटे

ओलिंपिक जैसे खेलों में पदक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि खेलों में सरकारी सुविधाएं बढ़ाकर और सरकारी हस्तक्षेप घटाए जाएं। खेल संघों में राजनीति हटाकर उन्हें समर्पित व्यक्तियों के नियंत्रण में देकर पूरे देश से प्रतिभाओं का चुनाव किया जाए। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करके उन्हें 'हराओ और जीतो' का महामंत्र देकर ही भारत अपने पदकों की संख्या को बढ़ा सकता है।

मनीषा पांडे, अंबाला

बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा

ओलिंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए एथलीटों को मानसिक और शारीरिक तैयारी के लिए प्रशिक्षण व विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करें। सरकार को स्कूलों और कॉलेजों में खेल कार्यक्रम को बढ़ावा देकर युवा प्रतिभा की पहचान तथा उसका विकास करना चाहिए। एथलीटों के प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के लिए इसके बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। भारत को अंतर-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए जैसे कि विश्व कप और एशियाई खेलों में।

सौरभ यादव, अंबेडकर नगर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा (बाएं) ने मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 28 अगस्त 2024

भारत-US साथ-साथ

पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर दिखी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अगर सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ हुई उनकी फोन वार्ता पर गौर करें तो हाल की यूक्रेन यात्रा की सार्थकता ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आती है। यूक्रेन यात्रा ने उन गलतफहमियों को भी खत्म कर दिया है, जो रूस यात्रा के बाद खास तौर पर पश्चिमी हलकों में दिखाई देने लगी थीं।

उठ रहे थे सवाल | पीएम मोदी की रूस यात्रा की टाइमिंग को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठाए गए थे। एक तो वह यात्रा अमेरिका में नैटो देशों की प्रस्तावित बैठक के ठीक पहले हुई थी, दूसरे वह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई उनकी पहली विदेश यात्रा होने की वजह से भी अहम मानी गई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी तब पीएम मोदी की रूस यात्रा पर खुले रूप में नाखुशी जताई थी।

बाइडन-मोदी की फोन पर बात

दोनों को एक जैसा सुझाव | इसके बरक्स सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की पहल पर हुई फोन वार्ता इस बात का साफ संकेत है कि जो भी गलतफहमियां रही हों, वे पूरी तरह मिट चुकी हैं। हालांकि भारत पहले दिन से अपने इस रुख पर अडिग रहा है कि वह बातचीत के जरिए जल्द से जल्द शांति स्थापित करने के पक्ष में है। पीएम मोदी ने रूस में राष्ट्रपति पूतिन से भी कहा था कि युद्ध के मैदान से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता, और यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी सुझाव दिया कि जल्द शांति स्थापित करने के लिए वह रूस से बातचीत करें।

बांग्लादेश का जिक्र | दोनों नेताओं की फोन वार्ता में बांग्लादेश का जिक्र आना कई लिहाज से अहम है। पड़ोस का यह मुल्क जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, उसे लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों देशों का अपनी चिंताएं साझा करना मायने रखता है। पीएम मोदी की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मसला उठाना जाहिर करता है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बावजूद इस मामले में भारत की चिंता दूर नहीं हुई है। जिस तरह से तथ्यों के विपरीत जाकर बांग्लादेश के कुछ नेता बाढ़ के लिए भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी बताता है कि वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाले तत्व अब भी सक्रिय हैं।

टाइमिंग है अहम | यह फोन वार्ता ऐसे समय हुई है, जब कुछ ही दिनों बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान मोदी और बाइडन मिलने वाले हैं। उसी बीच, क्वॉड देशों की बैठक भी प्रस्तावित है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की। कुल मिलाकर, इस बातचीत ने दोनों देशों के रिश्तों की सहजता को रेखांकित किया है।

ऑफबीट

गाने और बदलाव

सौरभ श्रीवास्तव

कुछ रोज पहले दोस्त के साथ कार से कहीं जा रहा था। बारिश हो रही थी, रेडियो पर 70 के दशक गाना बज रहा था। सब बहुत ही सुकून देने वाला था। मैंने रेडियो का स्टेशन बदला और 'RRR' फिल्म का गाना 'नाचो नाचो' बजने लगा। गाने की गति तेज थी तो मजा लेने के लिए मैंने रेडियो की आवाज बढ़ा थी। दोस्त ने घूमकर मुझे ऐसे घूरा, जैसे मैंने उसकी पूरी दुनिया ही लूट ली हो। बोला, 'तुम्हें ये शोर वाले गाने ही क्यों पसंद आते हैं?' 'अरे यार! ऑस्कर मिला है इस गाने को।' खैर, दोस्त का मूड न खराब हो इसलिए वापस रेडियो पर पुराना स्टेशन लगा दिया।

बात तो बहुत सामान्य-सी है, पर ऐसा क्यों है कि हम पुराने गानों को ही मधुर मानते हैं और नए संगीत को शोर? ऐसा क्या है जो हमें नए और पाश्चात्य संगीत का आनंद लेने से रोकता है? पहले दोनों तरह के संगीत के बीच के मोटे फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। पुराने गानों में गायक या गायिका की आवाज प्रमुख होती थी, संगीत उस आवाज की संगत करता था, इसलिए हम पुराने गानों के बोल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अर्थ का मजा लेते हुए लय पर बहने के लिए दिमाग को आजाद छोड़ देते हैं। दिमाग को आजाद छोड़ देना ही हमें आनंद का अनुभव करवाता है। अब नए गानों पर आइए। इन गानों में रिद्म, बीट्स, म्यूजिक आदि प्रमुखता से सुनाई देते हैं। गायक की आवाज सेकेंडरी या गौण होती है। गाने का यह फॉर्मेट 70-80 के दशक या उसके पहले पैदा हुए लोगों के दिमाग में बनी मधुर संगीत की अवधारणा के सामने चुनौती पेश करता है, जबकि नई पीढ़ी ऐसे संगीत का लुत्फ लेती है और उस पर थिरकती है। नई पीढ़ी के युवाओं को पुराने गाने नहीं भाते, उन्हें ये गाने सुस्त लगते हैं। समस्या संगीत की नहीं, हमारे दिमाग की है। वह कुछ भी नया सीखने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। नया सीखने के लिए पुरानी मान्यताओं को भुलाना होता है। पुरानी चीजों की बारीकियां समझने में जो समय लगाया, जो मेहनत की, क्या वह बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुरानी चीजें आपके संदर्भ के दायरे को बड़ा बनाती हैं। संदर्भ का दायरा बड़ा होगा तो आप चीजों को अलग तरह से देख-समझ सकेंगे।

बात यह है ही नहीं कि कौन-सा संगीत बेहतर है, नया या पुराना? मसअला यह है कि आपमें अपने दिमाग को पुरानी मान्यताओं से आजाद करने की कितनी क्षमता है। हमें अभ्यास भी इसी चीज का करना है, पुराने अनुभव वाले खाने में नए के लिए जगह बनाना। एक बार यह कर लिया तो 'डिजीज ऑफ चेंज' का इलाज हो जाएगा।

एकदा

गुरु की सीख

छत्रपति शिवाजी के गुरु थे गुरु समर्थ रामदास। वह भिक्षा में प्राप्त भोजन ही करते थे। एक बार वह भिक्षा मांगते हुए शिवाजी के महल में गए। शिवाजी अपने गुरु की आवाज पहचानकर नंगे पांव दौड़े-दौड़े बाहर आए और कहा, 'गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं। भिक्षा मांग कर आप हमें लज्जित न करें।' रामदास ने कहा, 'शिवा, आज मैं गुरु नहीं, भिक्षुक के नाते आया हूं।' शिवाजी ने एक कागज पर कुछ लिखकर गुरु के कमंडल में डाल दिया। गुरु ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, 'सारा राज्य गुरुदेव को अर्पित है।' उन्होंने कागज को फाड़ कर फेंक दिया और उल्टे पैर लौटने लगे। शिवाजी ने कहा, 'गुरुदेव, क्या मुझसे कोई भूल हुई है?' गुरुदेव ने कहा, 'शिवा! भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैं तुम्हारा गुरु होकर भी तुम्हारे अंदर से तुम्हारे अहंकार को नहीं निकाल पाया कि तुम राजा नहीं, एक सेवक हो।' शिवाजी ने कहा, 'यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं तन मन धन से जनता की सेवा करता हूं। अपने को राजा समझता ही नहीं।' गुरु रामदास ने कहा, 'शिवा! जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उसे तुम मुझे दे रहे हो, यह अहंकार नहीं तो और क्या है। मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? मुझे तो दो मुट्ठी दाना ही काफी है।' गुरुदेव ने आगे कहा, 'वत्स! यह राजपाट, धन दौलत, सब जनता की मेहनत का फल है। इस पर सबसे पहले उनका अधिकार है। तुम एक समर्थवान सेवक मात्र हो। एक सेवक का दूसरे की चीज को दान देना राजधर्म नहीं है। उसकी रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है।' शिवाजी गुरुदेव की भावना को समझ गए और उनसे क्षमा मांग कर बोले, 'गुरुदेव अब कभी भूल नहीं होगी।'

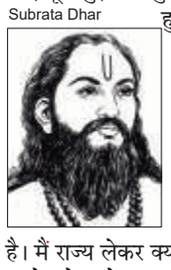

Subrata Dhar

संकलन : **ललित गर्ग**

महाराष्ट्र में लाडली बहना और UPS जैसी योजनाओं के ज़रिये जनता को लुभाने की तैयारी में BJP

फ्रंटफुट पर कैसे आई महायुति सरकार

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र में लोकलुभावन घोषणाओं की बौछार से तीन निष्कर्ष उभरते हैं। पहला, BJP ने लोकसभा चुनाव से सबक ले लिया लगता है। दूसरा यह कि पार्टी अब कांग्रेसनीत विपक्ष के चुनावी फंदों में फंसने के पूर्व ही उन्हें ध्वस्त कर रही है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को BJP और उनके मित्र दलों की काट के लिए नए नैरेटिव खोजने पड़ेंगे। संविधान, आरक्षण और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के संकट में होने का जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव में चला था, उसके विधानसभा चुनाव में कारगर होने की उम्मीद कम है।

घोषणाओं की भरमार | इन निष्कर्षों का सार समझने के लिए विपक्ष के वोट बैंक पर धावा बोलने वाली घोषणाओं पर सरसरी निगाह डालना जरूरी है। पिछले महीने भर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एटमी वेग से कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करना, असम और मध्य प्रदेश जैसी 'लाड़ली बहना' योजना पर तीव्र गति से अमल करना, किसानों को 24 घंटे बिजली मुहैया करना, महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी को 29 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की गारंटी देना, मेडिसिटी, मैंग्रोव पार्क, केमिकल हब, डिजिटल यूनिवर्सिटी से जुड़े कदम उठाना शामिल हैं।

महिलाओं पर फोकस | कुछ विशिष्ट तबकों के लिए अलग से योजनाएं जारी की गई हैं, जैसे आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, डॉ. बाबा साहब आंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के पिछड़े वर्ग के 763 छात्रों को 100% छात्रवृत्ति प्रदान करना, मुंबई की 228 झोपड़-पट्टियों के पुनर्वास को गति देना, 'लखपति दीदी' योजना लाना और गरीब वृद्धों के लिए वरिष्ठ नागरिक विकास महामंडल का गठन करना। 'लखपति दीदी' योजना के तहत सालाना दो लाख रुपये आय वाली महिलाओं को उद्यम के लिए एक लाख रुपये का कर्ज बिना ब्याज दिया जाता है।

पेंशन पर पॉलिटिक्स | UPS के चलते कांग्रेस की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हवा हो गई है। विडंबना यह है कि पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस के जमाने में, 2004 में ही बंद की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही वही इसे दोबारा लागू करने की मांग करने लगी। इसी के चलते कांग्रेस ने हिमाचल और राजस्थान विधानसभा चुनावों में वैसा वादा भी किया था, लेकिन राज्यों की माली हालत को देखते हुए इस वचन को पूरा करना संभव नहीं हुआ। अभी जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में अगले कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने हैं। UPS आने से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विपक्ष का दांव अब नहीं चलेगा।

चुनावी दांव
- कांग्रेस से पेंशन का मुद्दा छिना
- महिलाओं को साधने का प्रयास
- इंफ्रा पर जमकर हो रहा खर्च

लाड़ली बहना योजना | BJP ने 'लाड़की बहिण' (लाड़ली बहना) योजना से बेहद गरीब तबके की महिलाओं को साधने की कोशिश की है। अभी तक दो महीने की किस्त के तीन हजार रुपये दिए जा चुके हैं। कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होने थे, लेकिन 'लाड़ली बहना' की चार किस्तें जमा होने तक रुकने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र इलेक्शन अब नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं।

जीत की गारंटी | 'लाड़ली बहना' का श्रेय मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले यह योजना असम में कांग्रेस से BJP में आए हिमंता बिश्व सरमा ने शुरू की और चुनाव जीत गए। उनकी सफलता देखकर शिवराज सिंह चौहान ने इसे लागू किया और वह भी जीत गए। अब बारी महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो कह दिया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह योजना की राशि हर महीने तीन हजार रुपये कर देंगे।

सीएम कौन | और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे महाराष्ट्र बहुत आंदोलित रहा, मसलन - मराठों को ओबीसी से अलग आरक्षण, अनुसूचित जातियों के आरक्षण को उप-श्रेणियों में बांटने पर रोक। BJP ने विपक्ष से ये मुद्दे भी छीन लिए हैं। BJP का गठबंधन महायुति कहलाता है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन महाविकास आघाड़ी। दोनों ओर तीन-तीन पार्टियां हैं, लेकिन किसी के पास भविष्य के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है।

किसका फायदा | लोकसभा चुनाव के नतीजे BJP के लिए निराशाजनक रहे। उसे कुल 48 सीटों में से केवल 10 पर जीत मिली। पिछली बार यह संख्या 23 थी। कांग्रेस को फायदा हुआ और पार्टी एक से 13 सीटों पर पहुंच गई। शिवसेना का शिंदे गुट 7 पर, जबकि उद्धव गुट 9 पर रहा। शरद पवार ने भी 7 जीतकर 2 सीटों की बढ़त हासिल की। अजित पवार कहीं के नहीं रहे। अब विधानसभा चुनाव में इन लोकलुभावन घोषणाओं का अजित को कितना लाभ मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर, शिंदे अपने पैर कुछ जमा सकते हैं, जबकि BJP सबसे अधिक फायदे में रह सकती है। कांग्रेस और मित्र दल आकर्षक मुद्दों के अभाव में परेशानी महसूस कर सकते हैं।

गोलियों का गड़बड़झाला

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते 150 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर रोक लगाई है। ये दवाएं मरीजों में तरह-तरह के साइड इफेक्ट्स पैदा कर रही थीं। पिछले तकरीबन 7-8 बरसों से सरकार ने सैकड़ों FDC बैन की हैं, फिर भी यह कारोबार रुक नहीं रहा है। जानते हैं FDC के पूरे गोरखधंधे के बारे में...

क्या है FDC

Fixed dose combination यानी कॉकटेल दवाएं। FDC वे दवाएं होती हैं जिन्हें दो या दो से अधिक दवाओं को तय हिसाब से आपस में मिलाकर बनाया जाता है। इस समय बड़े लेवल पर ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं।

बड़े बैन

पिछले हफ्ते जो दवाएं बैन की गईं, उनमें प्रमुख नाम और उनके साइड इफेक्ट्स

मेफेनामिक एसिड + पैरासिटामोल इंजेक्शन

साइड इफेक्ट्स
- गैस्ट्रिक ब्लीडिंग
- लीवर डैमेज
- किडनी फेल्योर

सेट्रीजिन Hcl + पैरासिटामोल + फेनिलफ्रीन Hcl

साइड इफेक्ट्स
- उच्च रक्तचाप
- लीवर डैमेज

लेवोसेट्रीजीन + फेनिलफ्रीन Hcl + पैरासिटामोल

साइड इफेक्ट्स
- उच्च रक्तचाप और हृदय गति बढ़ना
- लीवर डैमेज

पैरासिटामोल + क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फेनिल प्रोपेनोलामाइन

साइड इफेक्ट्स
- उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं
- लीवर डैमेज
- गैस्ट्रिक ब्लीडिंग

कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 Mg + पैरासिटामोल 300 Mg

साइड इफेक्ट्स
- लीवर डैमेज
- पेट में अल्सर और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग

दवाएं अब तक कुल बैन 917+

2016, 2018 और 2024 में सबसे अधिक दवाओं पर प्रतिबंध लगे

बैन की वजह

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया कि
- इनका इस्तेमाल खतरनाक।
- कोई औचित्य नहीं।
- वैज्ञानिक प्रमाण नहीं।

चलन में कैसे

FDC इतनी ज्यादा मात्रा में चलन में क्यों हैं? विशेषज्ञों ने ये कारण बताए...
- **झोला छाप डॉक्टर:** ये लोग ऐसी दवाएं बहुत देते हैं।
- **कमीशनबाजी:** डॉक्टरों को FDC लिखने पर भारी लाभ।
- **मशरूम कंपनियां:** दवा कंपनी खोलने के लचर नियम।
- **चीन की चाल:** चीन से आता है सस्ता माल।
- **देसी चालबाजी:** केंद्र की जगह कंपनियां राज्यों से लेती हैं लाइसेंस।

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स : अर्जुन सिंह

काला कारोबार

जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का वर्ष 2020 का एक शोध बताता है...

- भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक एंटीबायोटिक FDC दवाएं बिकती हैं।
- **2020 में एंटीबायोटिक FDC की बाजार हिस्सेदारी 37% थी।**
- 2020 में बिकी 395 एंटीबायोटिक FDC में से 278 अस्वीकृत या प्रतिबंधित।
- **2018 और 2019 में प्रतिबंधित 39 फॉर्मूलेशन 2020 में भी बाजार में बने रहे।**
- 2020 में बेची गई 4.5 बिलियन यूनिट्स में से 700 मिलियन से अधिक अस्वीकृत थीं।

"विदेशों में तो FDC पूरी तरह से बैन हैं। न तो अमेरिका और न ही यूरोप इन्हें इस्तेमाल करता है। ये दवाएं सिर्फ भारत में बेची जाती हैं तो इसके पीछे कहीं न कहीं नियम-कानून में मिली हुई ढील है।"
-डॉ. अंशुमान कुमार, सीनियर सर्जन

दवा की डोज प्रति किग्रा वजन के हिसाब से ही दी जाए। जो FDC सरकार ने बैन की हैं, सबसे पहले डॉक्टरों को उन्हें प्रिस्क्राइब करना बंद करना होगा।
-डॉ. संजय तेवतिया, सीनियर डॉक्टर

10 वर्षों में जन धन योजना से देश को क्या मिला

अखिलेश झा

प्रधानमंत्री जन धन योजना विकसित भारत के लक्ष्य का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। आज जब यह योजना अपना एक दशक पूरा कर रही है। आज हर घर का एक बैंक खाता है, जिसमें 53 करोड़ से भी अधिक जन धन योजना के तहत खोले गए हैं। वित्तीय समावेशन की यह गाथा विश्व की सबसे सफल और गाथा है। ये खाते सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं, विकास के अवसर घर-घर तक पहुंचाते हैं और खुशहाली के द्वार जन-जन के लिए खोलते हैं।

जमाराशि चार गुना | मार्च, 2015 में जहां जन धन खातों में औसत जमाराशि 1,065 रुपये थी, मई 2024 में वह बढ़कर 4,398 रुपये हो गई। दस साल में बैंक की औसत जमाराशि का चार गुना हो जाना, उस पूरी व्यवस्था की सफलता की कहानी कहता है जो इस वित्तीय समावेशन की मुहिम से संभव हुआ है। दो दिन पहले तक जन धन खातों में कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये जमा थे।

बैंकों का भी ख्याल | यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि खाताधारकों और बैंकों के हितों का ध्यान रखा गया। बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई, ताकि खाताधारकों को बिना हिचक के लोन मुहैया कराएं। खाताधारकों को दस हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। उन्हें डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी गई। अब तक 36 करोड़ से भी अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जीवन-बीमा एवं दुर्घटना-बीमा की सुविधाएं जन धन खातों के माध्यम से दी गईं। इन्हीं खातों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पेंशन की योजना से भी जोड़ा गया।

वित्तीय समावेशन | प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक साथ कई लक्ष्यों को साध लिया है। वित्तीय समावेशन में भी उन क्षेत्रों को अधिक वरीयता दी गई, जो पारंपरिक रूप से सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार रहे हैं। लगभग 56 प्रतिशत बैंक खाते महिलाओं के खुले हैं। इस पहल ने महिलाओं को न सिर्फ पहचान दी और घर के बाहर अवसर दिए, बल्कि उन्हें लखपति बनाना शुरू कर दिया है। आज एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इसे बहुत जल्द तीन करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी काम चल रहा है। महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार सशक्त होगा और अंततः देश और तेज गति से सशक्त होगा।

AI Image

कॉमन रूम

रोजगार के मौके | प्रधानमंत्री जन धन योजना का डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि महिलाएं ही बैंकिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने का माध्यम बनें। बैंक-सखी के रूप में वे बैंकों की सुविधाएं देश के कोने-कोने तक पहुंचा रही हैं और इसी क्रम में वे अपने लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

ग्रामीण क्रांति | इस योजना के तहत दो तिहाई खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। अब इस नेटवर्क के माध्यम से किसानों से लेकर बुनकरों, हस्तशिल्पियों, कामगारों- सब को अपना सामान देश में कहीं भी बेचने और आसानी से उसका भुगतान प्राप्त करने में मदद मिल रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 13 हजार करोड़ से भी अधिक लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हुए, उसमें जन धन खाता धारकों की तादाद भी अहम थी।

करप्शन में कमी | पिछले दस सालों में सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों के खाते में सीधा पहुंचाने में भी जो सफलता मिली है, उसका सबसे बड़ा कारक जन धन योजना ही है। इस अवधि में लगभग 38.50 लाख करोड़ रुपये लोगों के बैंक खातों में सीधे पहुंचाए गए भारत सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत। इससे भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगा ही, लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये के लीकेज को भी रोकने में सरकार समर्थ रही।

विकास के अवसर | जन धन योजना विकसित भारत के प्रण को साकार करने की दिशा में, गांवों की गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने के लक्ष्य में और सबको विकास के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में उठाया गया सबसे सक्षम और सुनियोजित कदम है, इसमें कोई संदेह नहीं।

(लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

उसने जीवन की लौ बुझने नहीं दी, हम भी वही करें

हरीश बड़थ्वाल

पति के असमय गुजर जाने पर सभी आशंकित थे कि वह महिला मामूली आमदनी से तीन बच्चों का गुजारा कैसे करेगी। पति की कम आमदनी के चलते वह बुझी-बुझी रहती। समय का खेल देखें, चंद दिनों में अच्छी नौकरी मिल गई, घर में जरूरी सुविधाएं जुट गईं, उस महिला के हाव-भाव-चाल खिल गए। उसके शब्दों में हौसला झलकने लगा और व्यवहार में आत्मविश्वास। ऐसा नहीं कि पति के प्रति उसका बेरुखी का रिकॉर्ड हो, बल्कि दांपत्य कर्तव्य निभाने में उसकी मिसाल दी जाती थी। पत्नी को समझ आ गया था कि उसे पति की अनुपस्थिति में जीवन की लौ को बुझने नहीं देना। जीने की ललक बहुत दमदार होती है। वार से बच गया अधमरा तिलचट्टा निष्प्राण हो जाने का स्वांग रचेगा और मौका पाकर सरपट ओने-कोने में ओझल हो जाएगा। आड़ी-तिरछी अखंडित चट्टानों के बीच पनपते, धीमे-धीमे भारी भरकम आकार ले चुके पीपल के पेड़ आपने भी देखे होंगे। बयान न कर सकने वाली दुष्कर परिस्थितियों के बावजूद गिरते-उठते अनेक मरियल से शख्स बुलंदियों तक पहुंचे। लीक पर न चलने पर उन्होंने घोर तिरस्कार और अपमान झेले। ऊबड़खाबड़ रास्तों पर चलकर ही नई सोच मिलती है।

चुनौतियों से कतराने वाले ताउम्र वहीं ठहरे रहते हैं। एक तबका उनका है, जो परिजन के विरह में हमेशा के लिए गुमसुमी में चले गए और तमाम सांसारिक खुशियों से वंचित रहे। डिप्रेशन की पकड़ ऐसी होती है, जिससे छूटना सरल नहीं। इसीलिए डिप्रेशन के पनपते ही इसे कुचल देना चाहिए।

डिप्रेशन के मामले उनमें ज्यादा मिलते हैं, जिन्होंने अपने सरोकार न्यूक्लियर परिवार तक सीमित रखे। नतीजतन, बाहर कुछ भी बेहतरीन दिखना उन्हें बंद हो गया। सोशल मीडिया के जरिए या इने-गिने पिछलग्गुओं के सामने अपने जीवनसाथी या संतान के गुणगान अलापते रहना उन्होंने प्रमुख एजेंडा बना लिया। इस बिरादरी वाले हर किसी को हेय मानकर उनसे औपचारिक से ज्यादा संवाद नहीं रखते। यह भी धारणा बना लेते हैं कि दुनिया खुदगर्जों से सराबोर है, यह भी कि मेरे परिजन, मेरे सहकर्मी, मेरे समाज वाले घटिया स्तर के हैं। वैसे भी नश्वर, मायावी संसार में कुछ भी सार्थक किया जाना संभव नहीं। नश्वर संसार नहीं, हमारा जीवन है। संसार तो तब भी चल रहा था जब हम न थे, तब भी चलता रहेगा जब हम न रहेंगे। जन्म और मृत्यु के बीच की छोटी-सी यात्रा का नाम ही जीवन है।

मृत्यु सत्य है, यह ज्ञान सभी को है, प्रश्न इस कड़वे सत्य को गले उतारने का है। 'मैं' और 'मेरा' के जाल में हम इतना जकड़ जाते हैं कि स्वयं के बिना संसार की कल्पना करने में अक्षम हो जाते हैं। स्वयं और परिजनों की मृत्यु की कल्पना भयावह होती है, इसीलिए मनुष्य इस विचार से कतराता है। धारणा यह रहती है कि आज जो जैसा है, वैसा ही चलता रहेगा, जबकि कालचक्र का अपना दस्तूर है। जिसने खुले मन से सदाशयताओं और सरोकारों का दायरा घर-परिवार तक सीमित नहीं रखा, परिजन से अंतिम जुदाई की पीड़ा उसे नहीं तोड़ सकी। वियोग की पीड़ा की तीव्रता ज्यादा नहीं टिकती। हालांकि हर कोई सदमे से जल्द नहीं उबर पाता। सदमे से बाहर निकलना पर्याप्त धैर्य मांगता है, तभी हम नई सुबह के लिए सुसज्जित हो सकते हैं।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 28 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दीपक सोने का हो या मिट्टी का मूल्य उसका नहीं होता, मूल्य होता है उसकी लौ का जिसे कोई अंधेरा, अंधेरे के तरकश का कोई तीर ऐसा नहीं जो बुझा सके
-विष्णु प्रभाकर

योगी की नसीहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हुईं गलतियां भारत में नहीं होनी चाहिए। आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के सिलसिले में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तभी मजबूत होगा 'जब हम सब एकजुट रहेंगे।' दुर्गादास राठौर एक राजपूत सरदार थे, जिन्हें सत्रहवीं शताब्दी में मारवाड़ पर मुगलों के कब्जे की कोशिशों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने आगाह करते हुए कहा, 'बंटेंगे तो कटेंगे।' 'एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।' पिछले दिनों बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ इस कदर हिंसक प्रदर्शन हुए कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश भी छोड़ना पड़ गया। हालांकि इसके बाद भी पड़ोसी देश में हिंसा की घटनाएं जारी रहीं जिनमें हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय पर लक्षित हमले किए गए। इस घटनाक्रम के बाद भारत में भी कुछ विपक्षी नेताओं ने इस तरह के बयान दिए कि भारत में भी ऐसा कुछ घट सकता है। सरकार को सचेत रहना चाहिए। दरअसल, भू-राजनीतिक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि तमाम देशों के परस्पर समीकरण बिगड़ रहे हैं। इसके चलते देशों के बीच तनाव चरम पर हैं, और तनावों व टकरावों के चलते विश्व के एक हिस्से में दो देश रूस-यूक्रेन युद्धरत हैं, तो इस्राइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध चल रहा है। दोनों क्षेत्रों में हालात इस कदर खराब हैं कि जब-तब विश्व युद्ध का अंदेशा होने लगता है। हालात में यह खराबी किसी एक या दो देश तक सीमित रहने जैसा घटनाक्रम नहीं होता। वैश्विक आर्थिक हालात पर भी असर डालता है। देशों के बीच खेमेबाजी बढ़ाता है। बड़ी ताकतें देशों के बीच टकराव पैदा करके स्वार्थ साधने की ताक में रहती है। भारत के लिए तो और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थितियां शांतिपूर्ण नहीं रह गई हैं। ले-दे के बांग्लादेश ही बचा था जहां की सरकार के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण थे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी। लेकिन युवाओं को गुमराह करके जनता की एकजुटता को तार-तार कर दिया गया। एकजुटता से ही ऐसे मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है।

शांति की पहल

दुनिया के सभी मानवतावादी, शांतिप्रेमी और युद्धविरोधियों की निगाहें इस्राइल-फिलिस्तीन और रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की ओर लगी हुई हैं। वर्तमान में दोनों क्षेत्र युद्धग्रस्त हैं और हाल की घटनाओं से यह नहीं लगता कि आने वाले दिनों में यहां स्थिरता और शांति कायम हो सकती है। पिछले रविवार से इस्राइल और फिलिस्तीन समर्थक लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बड़े संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। दोनों युद्धरत पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए। विडंबना यह है कि ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता हो रही है। रविवार को इस्राइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं से खतरे की आशंका में उसके ठिकानों पर हवाई हमले किए जिसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर ड्रोन से हमले किए। अभी इस बात का ठीक से पता नहीं चल पाया है कि इन हमलों से दोनों पक्षों को जान-माल का कितना नुकसान हुआ। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आग भड़काने वाली कार्रवाइयां पश्चिमी एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं हैं। रविवार की घटना से दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की कोशिशों को झटका लगा है, लेकिन पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका आशान्वित हैं कि आगामी कुछ दिनों में युद्धविराम के लिए होने वाली वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। वार्ता में शामिल अधिकारियों का विश्वास है कि युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के जिन मुद्दों पर मतभेद हैं उन्हें सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। वास्तव में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जरूरी हो गया है कि इस्राइल पर युद्धविराम के लिए दबाव डालना चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूक्रेन से वापसी से मात्र 72 घंटे के बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करके शांति के प्रयासों को एक सिरे से नकार दिया। माना जा रहा है कि रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला है। प्रधानमंत्री मोदी जब 'शांति दूत' बनकर यूक्रेन जाने वाले थे उसी समय अनुमान लगाया जा चुका था कि इस यात्रा का क्या हश्र होगा। लेकिन भारत शांतिप्रेमी देश है। जाहिर है शांति के पक्ष में यात्रा का जोखिम उठाना अपरिहार्य था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर जो बाइडन से बात करके शांति के लिए नई पहल की है। अब आगे देखना है कि इस पहल के क्या नतीजे सामने आते हैं।

कहानी/पुष्पेश कुमार पुष्प

समय-समय की बात है

सड़क के फुटपाथ पर एक मां अपने बच्चे के साथ बैठी अमीरों के बच्चों को स्कूल जाते एकटक निहार रही थी। वही वे बच्चे फुटपाथ पर लगे ठेले-खोमचे से तरह-तरह के व्यंजन खरीदकर खा रहे थे, तो कुछ महंगे चॉकलेट का लुत्फ उठा रहे थे। अपनी मां के साथ बैठा बच्चा उन बच्चों की ओर लालायित निगाहों से देख रहा था। तभी उसके बेटे ने उन बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा - मां! हमारी रातें यूं ही फुटपाथ पर क्यों गुजरती है? मैं क्यों नहीं अपने घर में सोता? मां उदास स्वर में बोली-बेटा!

तू भी एक दिन अपने घर में आराम से सोएगा। एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। इन बच्चों की तरह मैं क्यों नहीं अंगेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं जाता? मैं गरीबों के स्कूल में क्यों पढ़ता हूं? बच्चा फिर अपनी मां से प्रश्न किया। समय आने दे तू भी इन बच्चों की तरह अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने जाएगा। मां बच्चे को पुचकारते हुए बोली।

ये बच्चे कितने अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं! तरह-तरह के व्यंजन और महंगे चॉकलेट खाते हैं। एसी बस में बैठकर स्कूल जाते हैं। मैं क्यों नहीं इनकी तरह अच्छे - अच्छे कपड़े पहनता, न इनकी तरह महंगे चॉकलेट खाता हूं और न चाट-पकौड़े? मैं तो फटे-पुराने कपड़ों में पैदल ही स्कूल जाता हूं। ऐसा क्यों मां? बच्चा उदास स्वर में बोला मां बोली-एक दिन तू भी उनकी तरह अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेगा। महंगे-महंगे चॉकलेट खाएगा और बस से स्कूल जाएगा। बस! समय का इंतजार करो। लेकिन मां! वह समय कब आएगा, बताओ न मां! बेटा व्याकुल होकर बोला। उस बच्चे की मां स्वयं से प्रश्न करने लगी कि आखिर वह समय कब आएगा! कभी गरीबों की किस्मत बदली है क्या? क्या कभी गरीबों के सपने पूरे हुए हैं? गरीबों का तो अभाव और कष्टों से पुराना नाता रहा है।

मां मुस्कुराकर बोली-बेटा! वह समय कब आएगा, यह तो ईश्वर ही जानता है। विश्वास पर ही तो दुनिया टिकी है। इतना सुनते ही बच्चा मां से लिपट गया और मां प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ फेरने लगी।

संघर्ष बने स्थायी चरित्र

बांग्लादेश में हिन्दू

अवधेश कुमार

पहली बार है जब बांग्लादेश में हिन्दुओं और उनके धर्मस्थलों पर हुए हमलों के विरुद्ध पूरी दुनिया में आक्रोश देखा गया है। स्वयं बांग्लादेश में भी भारी संख्या में हिन्दू सड़कों पर उतरेंगे, इसकी भी कल्पना नहीं थी। इसी का परिणाम हुआ कि बांग्लादेश की वर्तमान गठित अंतरिम सरकार की ओर से औपचारिक रूप से हिन्दुओं से माफी मांगी गई तथा कहा गया,'हम आपकी हर हाल में रक्षा करेंगे।' बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लग रहा था जैसे हिन्दुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा हो । स्त्री-पुरुष-बच्चे-जवान-वयस्क-बुजुर्ग सबको सड़क पर प्रदर्शन करते, नारा लगाते, वक्तव्य देते देखकर लग रहा था कि उनके अंदर संघर्ष करने और अपना अधिकार पाने का जज्बा बना हुआ है। प्रदर्शन में महिलाएं भी नेतृत्व करती दिखीं।

सच यही है कि अगर बांग्लादेश के हिन्दुओं ने साहस न दिखाया होता तो उनको विश्व का समर्थन नहीं मिलता। वहां की तस्वीरें और वीडियो किसी को भी उद्वेलित करती हैं। भारत में भी अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए जो चल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन नारी शक्ति के नेतृत्व में दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक 16 अगस्त को हुआ। भारत के बाहर अमेरिका-इंग्लैंड-फ्रांस-कनाडा और अन्य अनेक देशों में हिन्दुओं ने सड़क पर उतर कर बांग्लादेश के हिन्दुओं के साथ एकता दर्शाई तथा अपने-अपने देश से मांग की कि वहां शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद शासन चलाने वालों पर दबाव बढ़ाया जाए। इसका प्रभाव भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने हिन्दुओं पर हमले रोकने की मांग की तो अमेरिका और कुछ अन्य देशों का भी ऐसा ही बयान आया।

हालांकि भारत ने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर यहां आने के बाद से ही अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रखा। संसद में दिए बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिन्दुओं पर हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'हम वहां की अथॉरिटी के संपर्क में हैं।' बयान में निश्चयात्मक भाव था कि गैर-मुस्लिमों विशेषकर हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों आदि पर हमलों को रोकने के लिए भारत जो कुछ संभव है, करेगा। मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बधाई में ही हिन्दुओं पर हमलों का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार उन्हें रोकेगी। वैसे मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों जगह हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों यहां तक कि ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा पर भारत ने हमेशा स्पष्ट रुख अपनाया। मोदी सरकार ने 2019 में ही तीन पड़ोसी देशों

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना को आधार बना कर ही नागरिकता संशोधन कानून बनाए जो इसके प्रति वर्तमान भारत की प्रतिबद्धता दर्शाति है। हालांकि सीमा के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी हिन्दू भारत में प्रवेश करने के लिए भी पहुंच गए। इससे संकेत मिला कि आगे स्थिति बिगड़ी तो भारत को इसके संबंध में स्पष्ट नीति और तैयारी रखनी पड़ेगी।

बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट डेली स्टार के अनुसार 2022 में भारत के इस पड़ोसी देश की आबादी साढ़े सोलह करोड़ से कुछ ज्यादा थी जिसमें 7.95 प्रतिशत हिन्दू थे। वैसे संख्या के हिसाब से देखें तो हिन्दू एक करोड़, 31 लाख (13.1 मिलियन) हैं। इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं। धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन, संपत्तियों पर कब्जा आदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में समान रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल में भी हिन्दू लगातार धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा के शिकार रहे। इन देशों में एक पूरा ढांचा मजहबी कट्टरवाद का है जिनके लिए गैर-इस्लामिक काफिर हैं, और उनको इस्लाम के अंदर लाना या न आने पर प्रताड़ित करना मजहबी अपना दायित्व समझते हैं। बांग्लादेश के हिन्दुओं ने जैसा प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वहां गठित अंतरिम सरकार को भी इसकी कल्पना नहीं रही होगी। आखिर, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे होगा, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। इसे मरता क्या न करता का परिणाम कहा जाए क्योंकि हिन्दुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के पास कोई चारा नहीं बचा था। दूसरी ओर, पिछले 10 वर्षों में भारत के चरित्र में आए परिवर्तन तथा दुनिया भर में इसके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। इस स्थिति ने ही विश्व भर के हिन्दुओं और इनसे जुड़े समुदायों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मबल पैदा किया है। ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के हिन्दू समुदाय ने कहीं भी हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं दिया है। यही स्थिति अन्य जगह भी है। अनुभव बताता है कि जो भी समाज अपनी सुरक्षा के लिए उठकर खड़ा नहीं होता, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। यह कमजोरी अगर दूर हुई है तो इसे भविष्य की दृष्टि से हिन्दुओं के लिए अच्छा संकेत और संदेश माना जाना चाहिए।

बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता और इसके आधार पर भेदभाव और हिंसा खत्म करने के लिए लंबे संघर्ष और परिवर्तन की आवश्यकता है। वैसे भी शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जिन शक्तियों के बीच घोषित-अघोषित गठजोड़ हुआ उनमें पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी मजहबी हिंसक तत्व भी शामिल हैं किंतु अहिंसक तरीके से प्रखर होकर अपनी भावना सामूहिक तौर पर अभिव्यक्त करने का असर होता है। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सखावत हुसैन अगर सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हिंसा में अनेक स्थानों पर हिन्दुओं पर हमले हुए, उसके लिए सरकार को खेद है और इस हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ और जो मंदिर तोड़े या जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति और निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी तो अतीत को देखते हुए यह सामान्य परिवर्तन नहीं है। देखना होगा कि वाकई अंतरिम सरकार किस सीमा तक अपने वचन का पालन करती है, क्योंकि बांग्लादेश का आंतरिक ढांचा काफी हद तक कट्टरपंथियों के प्रभाव में रहा है, जिसे शेख हसीना भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाईं। किंतु हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन इसी तरह सतत अपने अंदर संघर्ष के लिए खड़े होने का चरित्र विकसित कर लें जो अभी दिखाई दिया है, तो परिवर्तन अवश्य होगा।

(लेखक के निजी विचार हैं)

बांग्लादेश के हिन्दुओं ने जैसा प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वहां गठित अंतरिम सरकार को भी इसकी कल्पना नहीं रही होगी। आखिर, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे होगा, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। इसे मरता क्या न करता का परिणाम कहा जाए क्योंकि हिन्दुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के पास कोई चारा नहीं बचा था। दूसरी ओर, पिछले 10 वर्षों में भारत के चरित्र में आए परिवर्तन तथा दुनिया भर में इसके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता

जानलेवा है मंकीपॉक्स का वायरस

- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकीपॉक्स जानलेवा है
- चिकनपॉक्स और स्मॉलपॉक्स परिवार से ही एमपॉक्स भी है जो इंसान से इंसान तक संक्रमण के जरिए फैलता है
- यह वॉयरस कांगो में 500 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। मंकीपॉक्स का बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

कार बाजार का पहिया चरमरा रहा है। अनबिकी कारों लेकर जिस बात आशंका थी, वह सामने आ गई है। डीलर्स की इन्वेट्री बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मुसीबत बनने वाली है। आटोमोबाइल डीलर एसोसएिशन (फाडा) ने कहा है कि डीलरों को फाइनेंस करने वालों को रोकना होगा। डीलर के पास अगर कार की इन्वेट्री 30 दिन से ज्यादा की है तो उसे नुकसान होना तय है इस वक्त स्टॉक 67 से 72 दिन का है।

अंशुमान तिवारी, पत्रकार@anshuman1tiwari

आसान होती विकसित भारत की राह

डिजिटलाइजेशन | सतीश सिंह

द इंडियन इकॉनमी : अ रिव्यू' रिपोर्ट, जिसे सरकार ने अंतरिम बजट पेश करने से पहले जारी किया था, में अर्थव्यवस्था के 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक भारत के विकसित देश बनने की बात कही गई है। सवाल का उठना लाजिम है कि क्या सचमुच यह मुमकिन है, क्योंकि अभी भी भारत विकासशील देश है, और कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करना, गरीबी का खात्मा, आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाना, शिक्षा के स्तर में इजाफा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना आदि शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में नॉमिनल जीडीपी के 7 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि भारत की जीडीपी 2030 तक 7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। एस एंड पी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट-'न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक'-में कहा है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। 'द इंडियन इकॉनमी : अ रिव्यू' की रिपोर्ट और एस एंड पी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 प्रतिशत से अधिक की दर से आगे बढ़ सकती है। ऐसा होता है तो 2030 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का हो जाएगा। पुनश्चः 'द इंडियन इकॉनमी : अ रिव्यू' रिपोर्ट के अनुसार भी वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 8.2 प्रतिशत रही।

उल्लेखनीय है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। हमारे देश ने आजादी के सौवें वर्ष यानी 2047 में विकसित देश बनने का सपना देखा है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण, कृषि यंत्रीकरण, यातायात व सुचारु संचार-व्यवस्था, अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव विकास संबंधी सरोकारों को भी प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि विकसित देश बनने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की आपूर्ति, आत्मनिर्भरता आदि मानकों पर भी हमें खरा उतरना होगा।

बीते महीने दुनिया की नजर फिर भारत की ओर उठी, जब जर्मनी के डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर विस्सिंग ने भारत में एक सब्जी विक्रेता को यूपीआई से भुगतान किया था। भारत डिजिटल भुगतान की दिशा में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अन्य देशों में यूपीआई जैसी कोई भुगतान व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में फेडनाऊ नाम से भुगतान सुविधा है, लेकिन इसकी प्रणाली अलग है। भारत सरकार ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में विकसित यूपीआई की तकनीक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों को उपलब्ध कराई है। वैसे तमाम तरह की चुनौतियों के बीच यह कोई अकेला चमकदार पहलू नहीं है।

देश में जनधन खातों की कुल संख्या 52 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इनमें 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, और 67 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। आंकड़ा दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन की राह पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन साथ में वे थोड़ा खर्च भी करने लगे हैं क्योंकि अब अमेजन, फ्लिप्कार्ट, अजिओ, मिन्त्रा आदि गांवों में भी डिलीवरी कर रहे हैं। सरकार ने 2014 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जनधन बैंक खाते खोलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सहित कई वित्तीय सेवाओं को गरीबों के लिए सुलभ बनाना था।

2026 तक देश की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 20 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। यह 2014 में 4.00-4.5 प्रतिशत था, जो आज बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है। भारत ने तकनीक को न केवल नवाचार के लिए, बल्कि विविध क्षेत्रों में समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी अपनाया है, जिससे पिछले कुछ सालों में लोगों के जीवन, परिचालन व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र के तकनीकी स्वरूप आदि में बदलाव आया है। भारत में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में सुधार, पेयजल की आपूर्ति आदि के संदर्भ में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि की मदद से देश में समावेशी विकास को बल मिल रहा है। डिजिटलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने का काम किया है। आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और डिजिटलाइजेशन के मोर्चे पर देश के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत 2047 में विकसित देश बन सकता है।

अभ्यास | श्रीराम शर्मा आचार्य

सतत अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन को इच्छानुवर्ती बनाया जा सकता है तथा उन्हें असामान्य कार्यों को कर सकने के लिए भी सहमत किया जा सकता है। प्रतिभा-योग्यता के विकास में बुद्धि आवश्यक तो है, सर्वसमर्थ नहीं। बुद्धिमान होते हुए भी विद्यार्थी यदि पाठ याद न करे, पहलवान व्यायाम को छोड़ दे, संगीतज्ञ, क्रिकेटर अभ्यास करना छोड़ दें, चित्रकार तूलिका का प्रयोग न करे, कवि भाव संवेदनाओं को संजोना छोड़ बैठे, तो उसे प्राप्त क्षमता भी क्रमशः क्षीण होती जाएगी और अंततः लुप्त हो जाएगी, जबकि बुद्धि की दृष्टि से कम पर सतत अभ्यास में मनोयोगपूर्वक लगे व्यक्ति अपने अंदर असामान्य क्षमताएं विकसित कर लेते हैं। आत्मविश्वास की कमी एवं प्रयास का अभाव ही मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता तथा वह महत्त्वपूर्ण सफलताएं पाने से वंचित रहता है। मानवीय काया परमात्मा की विलक्षण संरचना है। सर्वसमर्थता के बीज उसके अंदर विद्यमान हैं। उसे जैसा चाहे ढलाया, बनाया जा सकता है। सामान्यतया लोग कुछ दिनों तक तो बड़े उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं पर अभीष्ट सफलता तुरंत न मिलने पर प्रयत्न छोड़ देते हैं। फलस्वरूप अपने प्रयत्नों में असफल सिद्ध होते हैं जबकि धैर्य एवं मनोयोगपूर्वक सतत अभ्यास में लगे व्यक्ति असामान्य क्षमताएं तक विकसित कर लेते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा शारीरिक-मानसिक क्षमताओं का विकास ही नहीं, रोगों का निवारण भी किया जा सकता है। मानवीय काया एवं मन में शक्ति भंडार छिपे पड़े हैं। विकास की असीम संभावनाएं हैं। निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रयास चल पड़े और उसमें धैर्य एवं क्रमबद्धता का समावेश हो जाए तो असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। पहलवान, विचारवान, कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार, वैज्ञानिक, अध्यापक कोई अकस्मात नहीं बन जाते, वरन उन्हें उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। शरीर एवं मन को निर्धारित लक्ष्य के लिए अभ्यस्त करना होता है। प्रयत्न करने पर कोई भी व्यक्ति अपने अनगढ़ शरीर एवं मन को प्रशिक्षित कर सकता है। अनगढ़ शरीर एवं मन को सुगढ़ एवं व्यवस्थित करने के लिए धैर्य के साथ सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है।

रीडर्स मेल

पेंशन का मसला अहम

पिछले चार दिनों से देश भर में एकीकृत पेंशन योजना की खूब चर्चा हो रही है। सरकार के समर्थक इसे कामगारों की जीत बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे लेकर अपना पीठ थपथपा रही है। खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड एवं महाराष्ट्र जैसे अहम राज्यों का चुनाव होने वाले हैं। क्या सरकार इस घोषणा से इन राज्यों के मतदाताओं का दिल जीत पाएगी? पेंशन का मुद्दा केवल एक भावनात्मक मुद्दा है जिसे यह सरकार उछालकर लोगों का सहानुभूति बटोरना चाह रही है। लगता नहीं है कि वो सहानुभूति उसे मिल पाएगी।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

जनता को समझना होगा

बरसात के मौसम में देश के प्रायः सभी शहरों में जल जमाव की समस्या सामान्य हो चुकी है। देश के सभी शहरों में जल निकासी व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकारी महकमे द्वारा प्रति वर्ष जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया जाता है, लेकिन ये समस्याएं बदस्तूर बढ़ती जा रही है। बरसात में मुसीबतों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। शहरों में नदी, नालों का अतिक्रमण कर घर बना लिया जा रहा है। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से सभी नदी और नालों के मुहानों पर प्लास्टिक कचरों का अंबार लगा रहता है, इन कचरों की वजह से जल निकासी अवरुद्ध होती है। सरकार और आम नागरिक को जल निकासी के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास करने होंगे अन्यथा बरसात मुसीबत खड़ी करती रहेगी।

हिमांशु शेखर, गया

कंगना को सख्त चेतावनी

मंडी लोक सभा से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में आ जाती हैं। रनौत का ताजा वक्तव्य बीजेपी नेतृत्व को नागवार गुजरा है और पार्टी ने उन्हें भविष्य में ऐसी बातें न करने की सख्त चेतावनी दी है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'जो किसान आंदोलन हुआ, वहां लाश लटक रही थी एवं वहां रेप हो रहे थे और आशंका जताई कि इन 'उपद्रवियों' की बड़ी प्लान थी। कंगना ने ऐसा बयान देकर अनावश्यक विवाद को बढ़ावा दिया है, जिसे विपक्ष और किसान संगठनों ने लपक लिया और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन चुनाव में हमेशा बड़ी भूमिका में रहे हैं। ऐसी अनावश्यक चर्चा के कारण बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिलेगी। केंद्र सरकार को इस मुद्दे को जितना जल्दी हल कर सके कर लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी दखल देते हुए इस मसले पर एक कमेटी का गठन करने का आदेश पारित किया है और सरकार से वार्ता जारी करने का निर्देश भी दिया है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

रोकना होगा गैस का उत्सर्जन

मीथेन गैस पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके प्रभाव जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत की क्षति और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। पृथ्वी पर मीथेन की बढ़ती मात्रा गर्मी बढ़ाने में बूस्टर का काम कर रही है। ये गैस गर्मी को कैद रखने में बहुत ताकतवर होती है। चिंताजनक बात यह भी है कि इंसान मंगल ग्रह पर अपना ठिकाना तलाश रहा है और वहां भी इस गैस की मौजूदगी का पता चल चुका है। मीथेन गैस के उत्सर्जन को रोकने के उपाय करने होंगे ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 14

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स -** 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स -** 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

टूटी मूर्ति पर सियासत

छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष के रूप में लिया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति उनके नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र ही नहीं सम्पूर्ण देश में शिवाजी महाराज के प्रशंसक हैं। छत्रपति शिवाजी प्रथम हिन्दू नेता थे जिन्होंने मराठों को लड़ना सिखाया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महाराष्ट्र की सभी जातियों को एक भगवा झंडे के नीचे एकत्रित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी थल सेना और जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए धर्म कोई मानदंड नहीं था। छत्रपति शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा के केन्द्र हैं। महाराष्ट्र क्योंकि उनकी जन्मस्थली ही नहीं कर्मस्थली भी रहा इसलिए उनकी महानता को जन-जन पसंद करता है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति उनका नाम लिए बिना चल ही नहीं सकती। मराठा अस्मिता उनके नाम से जुड़ी हुई है। सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर जाने से महाराष्ट्र के लोग आहत हुए हैं। प्रतिमा के गिर जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने तैयार किया था। कहा तो यही जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रतिमा टूटकर गिर गई। मालवन के राजकोट किले में स्थापित की गई इस प्रतिमा के गिरने से मराठा अस्मिता बहुत आहत हुई है।

वैसे तो इस देश में नवनिर्मित पुल भी लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज आंधी के कारण महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषियों की सात मूर्तियों में से 6 गिर गई थीं। मूर्तियां लगाने के समय बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि यह मूर्तियां न तो आंधी-तूफान में खराब होंगी और न ही इन पर बारिश का कोई असर होगा लेकिन श्रद्धालु गवाह हैं कि प्लास्टर ऑफ पैरिस और प्लास्टिक से बनी इन मूर्तियों में पहली ही बारिश में टूट-फूट हो गई थी। इस देश में प्रतिमाओं को तोड़ने, उन्हें तय स्थान से हटाने या फिर रास्ता अवरुद्ध कर रही प्रतिमाओं को हटाने को लेकर बवाल होते रहे हैं। एनसीपी शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था और इस काम में गुणवत्ता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। स्मारक बनाने के पीछे का मकसद छत्रपति शिवाजी के नाम का इस्तेमाल करना था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी भी संरचना या स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यह विश्वास होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा लेकिन प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया क्वालिटी का था। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में जुट गए हैं। ठेकेदार और स्ट्रक्चरल कंसलटैंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीडब्ल्यूडी और नेवी के अधिकारी घटना की जांच में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का कहना है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नेवी को 2.36 करोड़ रुपए दिए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी भी संरचना या स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यह विश्वास होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा लेकिन प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया क्वालिटी का था। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में जुट गए हैं। ठेकेदार और स्ट्रक्चरल कंसलटैंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पीडब्ल्यूडी और नेवी के अधिकारी घटना की जांच में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का कहना है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नेवी को 2.36 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि प्रतिमा बनाने वाले आर्टिस्ट का चयन और उसके डिजाइन की पूरी प्रक्रिया नेवी ने की थी। 2023 को प्रतिमा बनाने का आर्डर दिया गया था। यह खबर भी हवाओं में घूम रही है कि प्रतिमा में इस्तेमाल किए गए स्टील में जंग लगना शुरू हो गया था और पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नेवी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे अब यह सरकार का दायित्व है कि वह निष्पक्ष जांच करा कर जवाबदेही तय करे,अगर गुनाह हुआ है तो दोषियों को दंडित करे। महाराष्ट्र विधानसभा में भी शिवाजी महाराज स्मारक के मुद्दे पर पहले ही राजनीति होती रही है। यद्यपि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोबारा प्रतिमा लगाए जाने का आश्वासन दिया है लेकिन इस पूरे प्रकरण ने विपक्षी दलों को सरकार की घेराबंदी करने का मौका दे दिया। चुनावी राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। अब तो राजकोट किले में टूटी हुई 35 फुट की प्रतिमा की जगह 100 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई जा रही है।

एक बात तो स्पष्ट है कि प्रतिमा की गुणवत्ता खराब थी और बारिशों के चलते इसके नट-बोल्ट पहले ही जंग खा चुके थे। अब क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मराठा अस्मिता के मुद्दे पर सियासत और गर्म होने की उम्मीद है। वर्तमान राजनीति हमेशा इतिहास में झांकती है और भावनाओं को पुकार कर वोट हासिल करना चाहती है। महाराष्ट्र भी अपवाद नहीं है। शिवाजी, अम्बेडकर और बाल ठाकरे के स्मारक राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवाजी की प्रतिमा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। यद्यपि स्मारकों के लिए जो भावनाएं हैं उनसे पूरी राजनीति नहीं बदल सकती लेकिन यह वोट जुटाने के लिए असरदार जरूर है। स्मारकों को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है और यह सिलसिला महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

नारी को निर्भय और सशक्त...

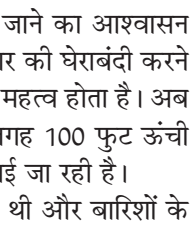

-गीता पाढा

चलो मिलकर हम सभी एक मुहिम चलाते हैं,
एक सुरक्षित समाज का निर्माण अपनी बेटियों के लिए करवाते हैं,
नारी को निर्भय और सशक्त बनाते हैं,
और वास्तव में आजादी का अमृत काल ले आते हैं..!!

भाजपा मुस्लिम का दिल जीते, मुस्लिम भाजपा का !

फिरोज बख्त अहमद

ऐसा समझा जाता है कि भाजपा और मुसलमानों के बीच 36 का आंकड़ा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये दोनों आपसी मध्यस्थता या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आज तक मेज़ के आमन-सामने नहीं बैठे। वास्तव में इन दोनों घटकों को एक-दूसरे से गलतफहमी के तहत रंजिशें हैं, जिनका निवारण किया जा सकता है और बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत जैसे लोकतंत्र में यह बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि समाज के सभी तबकों के साथ बराबरी का सुलूक किया जाता है, जिसमें धर्म, जाति, रंगभेद, अमीरी-ग़रीबी आदि के कोई मायने नहीं होते और कानून की निगाह में सभी बराबर होते हैं।

मगर जहां तक मुस्लिमों और भाजपा संबंधों की बात है, सब कुछ ठीक नहीं है। देखते हैं, मुसलमानों को भाजपा और संघ से क्या आपत्ति है। पिछले दिनों, इलेक्शन के दौरान भाजपा के कई अग्रज नेताओं द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के संबंध में कई अभद्र टिप्पणियां की गईं जैसे यह क़ौम गज़वा-ए-हिंद आदि लाएगी। भारत का मुसलमान इन लंपटवादी बातों को सुन कर ऊब चुका है, उसके कान पाक गए हैं, क्योंकि भले ही वह भाजपा को वोट न देता हो, संघ की विचारधारा पर न चलता हो, वह पक्का राष्ट्रवादी, संस्कारवादी और देशभक्त होता है, जिसका कारण है कि इस्लाम धर्म उसे

इस बात की सीख देता है, "हब्बूल वतनी, निस्फुल ईमान", अर्थात एक मुसलमान के लिए वतन से मुहब्बत ही उसका आधा ईमान है, बल्कि पूरा ही ईमान है।

भाजपा को मुस्लिम तबके से यह शिकायत है कि वे अपने अतिवादी व उग्र नेताओं के कहने में चलते हैं। ये नेता टीवी पर जाकर जिस प्रकार से मुसलमानों के ठेकेदार बन कर भारत, भाजपा और मोदी के विरुद्ध ज़हर उगलते हैं और देश में वैमनस्य फैलाते हैं और सांप्रदायिकता की आग लगाने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम कौम की भलाई में सरकार चाहे तीन तलाक को समाप्त करे, 370, 35ए का खात्मा करे, ये स्वयंभू मुस्लिम नेता अपने तबके को बहलाते, फुसलाते, भटकाते और भड़काते रहते हैं। इससे मुसलमानों को ज़बरदस्त नुक्सान हो रहा है, क्योंकि दुनिया समझती है कि जब इनके नेता ऐसे हैं तो इनकी क़ौम भी ऐसी ही होगी। एक आम मुस्लिम शहीद ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद हों, ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान हों, जाकिर नगर के कैप्टेन जावेद हों या कोई भी मुसलमान हो, सभी भारत माता के सच्चे सपूत रहे हैं।

हां, मुस्लिमों को इस बात का भी रोष है कि सरकार वक्फ बिल ला कर उनकी संपत्ति जायदाद, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, खानकाहों आदि पर कब्ज़ा करना चाह रही है जो कि पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। मुसलमान को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सरकार की सहायता से कब्जाई वक्फ बोर्ड की जमीन उसे वापिस दी जाए। भारत की लगभग 65 प्रतिशत ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड की समस्या के संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दल और विपक्षी दल शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के नेतृत्व में और जमीयत उलमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद के साथ मिलकर प्रतिनिधियों ने तेलगू देशम पार्टी, जनता दल (यू), शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेताओं के साथ बैठकें की हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ भी बैठक की है। इसका उद्देश्य विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ उनका समर्थन सुनिश्चित करना है।

दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम संगठनों ने भाजपा के सहयोगी दलों जेडी (यू) और टीडीपी से भी मुलाकात की है, जिन्होंने शुरू में संसद में विधेयक का समर्थन किया था, हालांकि जल्द ही उनके अलग-अलग विचार सार्वजनिक हो गए। इस संबंध में एआईएमपीएलबी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और विधेयक पर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित पांच साल की अवधि पर विशेष आपत्ति जताई, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है।

मौजूदा हालात में भाजपा सरकार को संघ और सरकार को समर्पित मुसलमानों पर भरोसा कर उन्हें जिम्मेदारियां देनी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए और मुस्लिमों को मिलकर भारत माता की सेवा करते हुए अखंडता और एकता के लिए जुट जाना चाहिए।

मोदी सरकार की नई पहल यूनिफाइड पेंशन स्कीम

रोहित माहेश्वरी

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) सरकार की नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्यूटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की तर्ज पर ही 10 प्रतिशत योगदान देना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का प्रावधान किया जाएगा जो नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से अलग है, जिसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी।

मोदी सरकार ने इस स्कीम को 'सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा' करार दिया है। अलग-अलग श्रेणियों में जो पेंशन बनेगी वह 'सुनिश्चित' तौर पर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को मिलेगी। पेंशन के साथ 'महंगाई राहत' को भी जोड़ा गया है। यदि राज्य सरकारें भी इस नई घोषित स्कीम से जुड़ना चाहती हैं तो कुल 90 लाख के करीब कर्मचारी इसके दायरे में होंगे।

पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में मूल अंतर ये है कि ओपीएस नॉन कॉन्ट्रीब्यूट्री थी और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूट्री है। इसमें 10 प्रतिशत कर्मचारी का भी कटेगा, ये पहले भी कटता था लेकिन वो ब्याज के साथ रिटर्न हो जाता था। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इससे पहले 'ओल्ड पेंशन स्कीम' (ओपीएस) थी, जिसमें संशोधन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'न्यू पेंशन स्कीम' (एनपीएस) बनवाई थी। यह दीगर है कि केंद्र में सत्ता बदल गई लेकिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने एनपीएस को लागू किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। वहीं इस मुद्दे को चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। असल में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं और महाराष्ट्र, झारखंड में अगले माह चुनावों की घोषणा होनी है। चुनावों के मद्देनजर ही केंद्रीय कैबिनेट ने जिस 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (यूपीएस) को स्वीकृति दी है, उससे 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।

चुनावी राजनीति के मद्देनजर ही केरल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल की सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणाएं की थीं। तब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थीं। अब भाजपा

सरकारें हैं, लिहाजा राजनीति बदल गई है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की 'महायुति सरकार' है। इधर केंद्र ने स्कीम की घोषणा की, उधर 'महायुति सरकार' ने भी स्वीकृति दे दी।

बहरहाल सवाल है कि नई पेंशन स्कीम क्यों घोषित की गई है? यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस के तत्त्व भी शामिल हैं। यह दोनों पेंशन योजनाओं के बीच का रास्ता है। पेंशन में आर्थिक सुधार किए जा सकते थे। अब राजनीति के मद्देनजर असमंजस बने रहेंगे कि यूपीएस लागू करें या ओपीएस को लागू करने के प्रयास किए जाएं। बेशक यूपीएस की घोषणा से खासकर केंद्रीय कर्मचारी गद्गद् हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ही उनके संगठनों के साथ विमर्श किया। उनके पक्ष और तर्क सुने गए।

हमारे देश में 65-70 करोड़ ही कामगार हैं। उनमें भी केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 90 लाख कर्मचारी हैं जो पेंशनधारक रहेंगे और उनकी मृत्यु के बाद पत्नी या पति को 60 फीसदी पेंशन मिलती रहेगी। यूपीएस का सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ना निश्चित है। खुद सरकार ने बताया है कि नई योजना से पहले वर्ष में ही, 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो कर्मचारी एनपीएस के दौर में 2004 में सेवानिवृत्त हुए थे उनके एरियर भुगतान के लिए भी 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

केंद्र और राज्य सरकारों के बजट में पेंशन पर खर्च करने के लिए बड़ा हिस्सा आवंटित कर रखा है। 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेंशन के लिए क्रमश: 2.3 लाख करोड़ रुपए और 5.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के पेंशन के लिए बजट को इकट्ठा कर दिया जाए तो 2023-24 में उनके राजस्व व्यय का अनुमानत: 12 फीसदी बनता है। यह छोटी पूंजी नहीं है। उप्र, केरल, हिमाचल के संदर्भ में यह पूंजी काफी ज्यादा है। बेशक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही है लेकिन यह इतनी भी नहीं है कि हम 2047 में 'विकसित भारत' का सपना साकार कर सकें।

अब यूपीएस में भारत सरकार 18.5 फीसदी का योगदान देगी, जबकि पहले यह हिस्सा 14 फीसदी का था। यह भी अतिरिक्त बोझ है। यह राशि पेंशन के तौर पर एक बहुत छोटे श्रम-बल पर खर्च की जानी है। यह अंजाम भी सरकार और देश को भुगतना पड़ेगा कि अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट सिकुड़ने लगेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से हालांकि देश पर वित्तीय भार पड़ेगा, पर इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा की रिटायर्ड व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होगा। उसे किसी के ऊपर निर्भर होने के आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

पेंशन हमारी व्यवस्था की परंपरा रही है। निस्संदेह, पूरा जीवन राजकीय सेवा में लगाने वाला कर्मचारी रिटायर होने के बाद आर्थिक असुरक्षा में घिर जाता है। वह भी तब जब देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नगण्य हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आय के साधन सीमित होने, बढ़ती उम्र की बीमारियों के दबाव तथा बच्चों की अनदेखी के चलते पूर्व कर्मियों को उपेक्षित जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है। यही वजह है कि देश में एकीकृत पेंशन योजना को सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। विपक्षी दल भी विरोध करने के बजाय कह रहे हैं कि उनकी मुहिम से ही यह पेंशन योजना अस्तित्व में आयी। यह सुखद ही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये कर्मचारी हित में सकारात्मक बदलाव संभव हुआ।

हम वरिष्ठ हैं, बूढ़े नहीं...

विजय मारू

ज्यादातर लोग एक उम्र आने के पश्चात अपने आपको बूढ़ा समझने लगते हैं और यहीं से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर दिखने लगता है। इस नकारात्मक सोच से हमें उभरना होगा। हम यह भी मानते हैं कि उम्र तो एक नम्बर है, असल जिन्दगी तो आपकी सोच, आपकी जीवनशैली पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक होकर अपना जीवन निर्वाह करें तो बढ़ती उम्र में भी हम खुशी। खुशी भगवान के द्वारा निर्धारित प्रत्येक क्षण का आनंद ले सकते हैं। हमें बढ़ती उम्र में अपने आपको वरिष्ठ बनाना और महसूस करना है। बुढ़ापे और वरिष्ठता के अंतर को बारीकी से समझना होगा तभी हम इस उलझन से निकल पायेंगे और स्वस्थ व सुखी रह सकेंगे।

हम अगर अपने को बुढ़ऊ समझने लगें तो अन्य लोगों का आधार ढूंढ़ते रहेंगे। इस मानसिकता से बाहर आकर हम अपने को वरिष्ठ समझें। दूसरों को आधार देने की हिम्मत रखें। घर पर भी हमें अपने विचार बच्चों पर जबरदस्ती अपनाने की जिद्द नहीं करनी चाहिए। इस तरुणपीढ़ी की राय हमें भी समझनी चाहिए और फिर आपसी सहमति से कोई निर्णय लेना चाहिए। शायद यहीं अंतर दर्शाता है बुढ़ापे और वरिष्ठता में। अपने ही मध्य अनेकानेक व्यक्ति मिल जाएंगे, जो 75 के पार हैं और अपने को कुछ न कुछ उपयोगी कार्य में लगा रखे हैं। अखबार में, टीवी पर व सोशल मीडिया पर हमें अक्सर

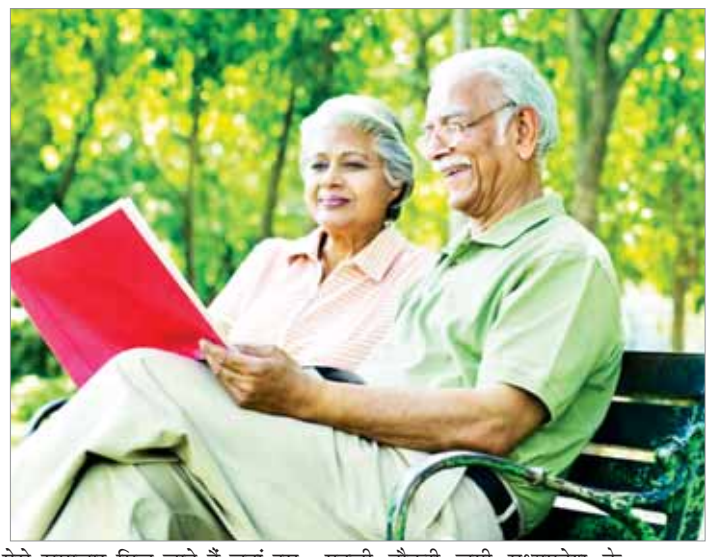

ऐसे समाचार मिल जाते हैं जहां इस 75 की उम्र को पार करके सुपर सीनियर्स बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। जिससे समाज में उनको प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे वरिष्ठजन दूसरों के लिए भी आदर्श बनते हैं। यहां मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति का आपको उदाहरण देना चाहूंगा जिनका व्यक्तित्व हमारे लिए आदर्श बन सकता है। ये हैं 89 वर्ष के श्रीअशोक पाल जी। दिल्ली के पड़ोस गाजियाबाद में जन्में अशोकजी की प्रारंभिक पढ़ाई स्थानीय सरकारी स्कूल में हुई। इसके पश्चात वे नजदीक ही स्थित रूड़की विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आजकल आई आई टी रूड़की कहा जाने लगा है, से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होकर अपना जीवन आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हुए। अशोक जी की पहली नौकरी लगी मध्यप्रदेश के सरकारी विभाग में। साढ़े तीन वर्ष तक वहां अपनी सेवा देने के बाद वो अगले साढ़े तीन वर्ष डेसू में कार्यरत रहे। इसके पश्चात 1966 में अशोक जी ने भारत सरकार की एक कन्सलटैन्सी कम्पनी, जिसका काम था जगह – जगह औद्योगिक परियोजनाएं की स्थापना करना, में अपना योगदान दिया। यहां पर 10 वर्ष तक अशोक जी ने सेवा दी और यहीं पर उनको बहुत एक्स्पोजर मिला। इसी सरकारी ईकाई में रहते हुए ये डेढ़ वर्ष तक ईरान में कार्यरत रहे। इतने वर्षों तक सार्वजनिक संस्थानों में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र की ओर अपना कदम आगे बढ़ाया। थर्मल पावर प्लांट्स की स्थापना में कार्यरत डेजीन डिजाइनिंग कम्पनी में डायरेक्टर बन कर आए। इस संस्था का पौलैंड की सरकारी कंपनी से संबंध था और इन्होंने बोकारो, दुर्गापुर व राउरकेला में कैप्टिव पावर प्लांट लगाने में सहयोग किया। 10 – 12 वर्ष इस कम्पनी में अपना योगदान देने के पश्चात इन्होंने पौलैंड सरकार के आग्रह पर एक जॉयन्ट वेन्चर कंपनी बनाई जिसके वे मैनेजिंग डायरेक्टर बने।

बाद में इस कम्पनी को इन्होंने खरीद लिया। 80 वर्ष की उम्र होने पर उन्होंने इस कंपनी का कामकाज समेट लिया। अशोक जी शुरु से ही समाज सेवा से जुड़े थे। इसी भावना ने उन्हें विद्या भारती के नजदीक ला दिया। जिससे वो कोई तीस वर्ष से जुड़े हैं। उनका विश्वास था कि शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत आवश्यक है। जिसे विद्या भारती बखूबी बहुत अच्छी तरह कर रही है। पिछले 17 वर्षों से ये विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। अशोक जी आज भी खूब प्रवास करते हैं। देश के किसी भी स्थान पर कोई बैठक हो और वो वहां पहुंच जाते हैं। भारत के 682 जिले में 12098 औपचारिक स्कूल कार्यरत है जिनमें इकत्तीस लाख से अधिक छात्र संस्कारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 54 कॉलेज व दो विश्वविद्यालय भी विद्या भारती के अंतर्गत संचालित हैं।

1998 में गाजियाबाद में ए.के.जी. इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। जिसके ये फाउंडर चेयरमैन है। इनका अपना एक ट्रस्ट भी है जो की पूरी तरह विद्या भारती को समर्पित है। 1961 में इनका विवाह हुआ और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा व एक बेटी, दोनों विदेश में रहते हैं। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हमें अपने आसपास ही कई मिल जाएंगे। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे प्रोत्साहन ले सकते है। आपको बता दूं कि बुढ़ापा जीवन की शाम में अपना अंत ढूंढता है, और वरिष्ठता जीवन की शाम में भी एक नए सवेरे का इंतजार करती है तथा युवाओं की स्फूर्ति से प्रेरित होती है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

प्रतिमा का ढह जाना

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में चंद माह पहले स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा के धराशायी होने की घटना सिर्फ इसलिए दुखद नहीं है कि यह प्रतिमा हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी थी और इससे भारतीय नौसेना की साख भी जुड़ी हुई थी, बल्कि यह इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण-कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था। यह अच्छी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने और खुद नौसेना ने भी अपने तईं इस घटना की जांच-पड़ताल के लिए टीमें गठित की हैं और इस प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कंपनी के मालिक व संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रतिमा को दुरुस्त कर पुनर्स्थापित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं।

वैसे तो पूरे देश में ही छत्रपति शिवाजी के प्रति गहरे सम्मान का भाव पाया जाता है, मगर महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के लिए वह एक प्रतीक पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है। ऐसे में, राजकोट किले की इस घटना पर राजनीतिक हंगामा खड़ा होना ही था। तब तो और, जब चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला हो और एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिव सेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्म-गौरव से प्रेरित रही हो। स्वाभाविक ही उसने तथा महाविकास अघाड़ी ने इस योजना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इसे शिवाजी के अपमान के रूप में पेश किया जाने लगा है। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि न सिर्फ विपक्ष के आरोपों की धार को वह कुंद कर सके, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को भी यह संदेश मिल सके कि वे बख्शे नहीं जाएंगे।

शिवाजी की प्रतिमा ढहने की घटना बताती है कि निर्माण-गुणवत्ता से समझौता और सियासी दबाव में जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति ने ऐसी घटनाओं की गति बढ़ाई है।

निस्संदेह, यह पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी बड़ी निर्माण योजना की कमी यूं उजागर हुई है। मई 2023 में उज्जैन के महालोक कोरिडोर में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी-तूफान में धराशायी हो गई थीं। इसी मानसून में बिहार में नए-पुराने पुलों के ढहने का सिलसिला मीडिया में सुर्खियों में रहा। कहीं नई बनी सड़कें धंस रही हैं, तो कहीं हवाई अड्डे के छज्जे टूटकर गिर जा रहे हैं। जाहिर है, इनकी वजहों को समझने के लिए किसी नजूमी की जरूरत नहीं है। निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से समझौता और राजनीतिक दबाव में जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति ने ऐसी दुर्घटनाओं की गति बढ़ाई है। इसके लिए समूचे तंत्र को अपनी कार्य-संस्कृति पर गौर करने की जरूरत है। इसके साथ ही महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के बारे में भी अब गहन विमर्श होना चाहिए। शिवाजी की प्रतिमा के तेज हवा में यूं ढह जाने से हमें सबक सीखने की जरूरत है कि हर जगह प्रतिमा लगा देने भर से पुरखों का सम्मान नहीं होता। उनके मूल्यों की शिक्षा और संस्कार के केंद्र कहीं ज्यादा दीर्घकाल तक हमारे बीच उनकी प्रासंगिकता बनाए रखेंगे। इसलिए संसाधनों का उपयोग ऐसे निर्माण में हो, जो आठ सदी बाद भी पीढ़ियों को उनकी याद दिलाए और निर्माण-कार्य में हुई चूक उसके इतिहास का हिस्सा न बन सके।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 अगस्त, 1949

युगोस्लाविया और रूस

युगोस्लाविया और रूस में पिछले कुछ महीनों से कटुता बराबर बढ़ती जा रही है। जहां तक शाब्दिक संघर्ष का ताल्लुक है, यह कटुता सीमा पर पहुंच चुकी है।... रूस ने युगोस्लाविया को जो सरकारी पत्र भेजा है, उसमें कहा गया है कि रूस युगोस्लाविया की मौजूदा सरकार को मित्र और साथी सरकार नहीं समझता, बल्कि शत्रु और विरोधी सरकार समझता है। साम्यवादी प्रचार की यह विशेषता है कि उसमें विरोधी के लिए कटु से कटु और तीखे से तीखे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। रूसी समाचारपत्रों में युगोस्लाविया के मौजूदा नेतृत्व की तीव्र भर्त्सना की जा रही है। उसे प्रतिक्रियावादी, पूंजीपतियों के हाथों बिका हुआ तथा साम्यवादी आदर्शों का द्रोही बताया जा रहा है। युगोस्लाविया के समाचारपत्र रूसी प्रचार का तुर्की-ब-तुर्की जवाब दे रहे हैं। युगोस्लाविया के प्रधान मार्शल टीटो हैं। वह किसी समय साम्यवादी जगत की पूजा और प्रशंसा के पात्र थे। किन्तु रूस के वर्तमान भाग्य विधाताओं की दृष्टि में ज्योंही वे अपराधी बने कि सारा साम्यवादी जगत उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगा। साम्यवादी देशों के संगठन कामिनफार्म से इसी कारण युगोस्लाविया को अलग कर दिया गया। रूस और उसके अनुवर्ती सभी साम्यवादी देशों ने युगोस्लाविया से व्यापारिक और आर्थिक नाता तोड़ लिया। आस्ट्रिया पर युगोस्लाविया के प्रादेशिक दावे थे। रूस कुछ समय पहले तक इन दावों की हिमायत करता था, किन्तु उसने अपना समर्थन हटा लिया। चार बड़े राष्ट्रों में इसी कारण मतभेद था, वह दूर हो गया और आस्ट्रिया के संबंध में वे एकमत पर पहुंच गये। युगोस्लाविया साम्यवादी जाति से बहिष्कृत होकर अकेला पड़ गया। ऐसी दशा में उसने पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने पिछले दिनों युगोस्लाविया को इस्पात की मिल खोलने के लिए ऐसी सामग्री बेची, जिसको बेचना उसने साम्यवादी देशों को बन्द कर रखा है; क्योंकि वह सामग्री युद्ध-कार्यों के लिए भी काम में ली जा सकती है। युगोस्लाविया अपने आन्तरिक मामलों में रूस को हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहता। रूस समझता है कि युगोस्लाविया का यह व्यवहार उसकी अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के साथ मेल नहीं खाता और वह पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध जो मोर्चा बना रहा है, उसमें इससे दरार पड़ जाती है।

उत्पीड़न के दानव का कैसे हो दमन

अनिता भटनागर जैन | पूर्व आईएएस अधिकारी

यहां स्कैन करें

दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के वाकये सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जघन्यता भी, इसलिए आवश्यक है कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस पर भी विचार किया जाए।

देश में उत्सवों और त्योहारों का दौर चल रहा है, पर बार-बार कोलकाता कांड की खबरें सुर्खियों में आ-जा रही हैं। डॉक्टरों और युवाओं की नाराजगी का दौर थम नहीं रहा है। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई बर्बरता का गहरा साया नौजवानों को सता रहा है। आक्रोश इस तरह फूटा है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी खुद संज्ञान लेकर निर्देश जारी करने पड़े हैं।

समाचार-पत्रों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की प्रचुरता हो गई है। असम में 14 वर्षीय लड़की का गैंगरेप, बदलापुर (महाराष्ट्र) में अबोध बच्चियों का त्रासद प्रकरण, अन्य स्थान पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बलात्कार और स्पेनिश पर्यटक का छत्तीसगढ़ में गैंगरेप। उधर, हेमा रिपोर्ट के बाद केरल के फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये सब घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या किसी भी उम्र की लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित हैं? स्कूल, सड़क, बस, अस्पताल, यहां तक कि कई बार अपने घर में भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं?

क्या हमारा अमृत काल आधी आबादी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के बिना साकार हो सकता है? भौतिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास तो सामाजिक विकास या सुरक्षा के बिना अधूरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक 16 मिनट में देश में एक बलात्कार होता है और प्रत्येक घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध होते हैं। प्रत्येक दिन देश में 86 बलात्कार रिपोर्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी अपराधों में बलात्कार सबसे कम रिपोर्ट होता है और 63 प्रतिशत बलात्कार तो दर्ज ही नहीं होते। 10 प्रतिशत बलात्कार अवयस्क, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं और 89 प्रतिशत मामलों में बलात्कारी जान-पहचान का व्यक्ति होता है। यह बिंदु भी विचारणीय है कि बलात्कार के आंकड़ों में वे प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें बलात्कार का प्रयास होता है या बलात्कार के उपरांत हत्या की जाती है। मतलब, महिला विरोधी कुल अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं। प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक बच्ची या महिला का पूरा जीवन है और उसका परिवार है। बहुत आक्रोश जताने के कुछ ही समय बाद शोषण की शिकार महिला को लोग भूल जाते हैं। अनेक पीड़िताएं मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो जाती हैं। एक ही तो जीवन है, जो हमेशा के लिए बोझ बन जाता है। परिवार की त्रासदी भी असहनीय हो जाती है।

निर्भया मामले के बाद शासन ने बालिकाओं के लिए बहुत प्रयास किए हैं – शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के प्रयास, गुड टच या बेड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, वूमेन पावर लाइन, चौबीस घंटे चलने वाले सहायक कॉल सेंटर, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, पिंक बूथ, जनपद स्तर पर महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रकोष्ठ इत्यादि के बावजूद बलात्कार व यौन उत्पीड़न के वाकये सुरसा के मुख की तरह बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जघन्यता भी। इसलिए आवश्यक है कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस पर भी विचार किया जाए।

बलात्कार के संदर्भ में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों के संबंध में, रेश्मा पिल्लै आदि ने युवा पुरुषों के बीच सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधानता की संकीर्णता से ग्रसित है। आज के युग में जब सबके पास मोबाइल है, तो घातक अश्लीलता भी सभी तक पहुंच रही है। समस्या और भी विकराल होती जा रही है। बाल्यकाल में दुर्व्यवहार का सामना करना, रिश्तों के बारे में नकारात्मक सोच, भावनाओं पर कमजोर नियंत्रण, मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन, यौन कुंठा या असंतोष आदि कारक विभिन्न अनुपातों में मिलकर बलात्कार की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं। महिलाओं की इच्छाओं और जरूरतों के बारे में पुरुष की गलत धारणा भी कारण हो सकती है। ऐसे पुरुष बहुत हैं, जो महिला की न को भी हां समझते हैं। हमारी अनेक फिल्में भी महिलाओं को छेड़ने और उनको घेरकर जबरन अपनी भावनाओं को थोपने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे पुरुष अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं।

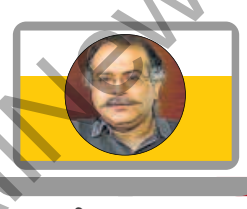

जब समाज में स्त्री को वस्तु की तरह देखा जाता है, तब हिंसा और बलात्कार की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक व नैतिक मूल्यों का पतन द्रुत गति से हो रहा है। हमारे पूर्वजों की प्राथमिकता क्रमशः ऐसी थी - समुदाय - परिवार - मैं। आज यह बिल्कुल उल्टी होती जा रही है। जब हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी पूर्ति पर ही ध्यान देंगे, तो परिणाम भयानक होंगे और इस सामाजिक अराजकता से अंततः कोई भी अछूता नहीं रहेगा। स्कूलों के बारे में विशेष रूप से सोचना होगा। जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए, तो क्या विद्योपार्जन होगा?

हमारी सोच और मानसिकता हमारे कार्यस्थल पर भी हमारे साथ जाती है। कुछ वर्ष पहले एक थाने के निरीक्षण में पुरुष प्रधान मानसिकता का दृष्टांत मुझे देखने को मिला। एक नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत पर दो दिन तक संबंधित कांस्टेबल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उत्तर था कि कदाचित वह लड़की भाग गई होगी और कुछ दिन में वापस आ जाएगी। सवाल यह है कि यदि उस कांस्टेबल की अपनी लड़की दो दिन से लापता होती, तो भी क्या उसकी यही सोच होती? नियम, कानून, व्यवस्था पर्याप्त हैं, जरूरत है संवेदनशील पुलिसिंग की।

गौर कीजिए, बलात्कार के प्रकरण में जांच की मियाद दो महीने निश्चित है, पर वास्तव में इस समय सीमा में कितनी जांच हो पाती हैं? निर्भया प्रकरण में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद फांसी होने में 12 वर्ष लग गए। पॉक्सो एक्ट के तहत एक वर्ष में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, परंतु 87 प्रतिशत मामले साल भर बाद भी लंबित रहते हैं। केवल 10 प्रतिशत मामलों का एक साल में निपटारा होता है और उनमें भी केवल 20 प्रतिशत मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाता है।

मतलब, महिला सुरक्षा के लिए अनेक स्तर पर सुधार व प्रबंध की जरूरत है। अपने परिवार, कार्यस्थल में पुरुष प्रधान संकीर्णता की सोच में बदलाव करें। पीड़िता की मदद करें। यौन उत्पीड़न करने वालों और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करें, चाहे वह हमारे रिश्तेदार या मित्र ही क्यों न हों। याद रहे, रिश्तों, दोस्ती, जाति, राजनीति, विचारधारा, चाहे जिस भी आईने से देखने की कोशिश कीजिए, बलात्कार सिर्फ बलात्कार होता है और उसका आरोपी अक्षम्य।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बलूचों का विद्रोह ही नहीं, दूसरे कई तनाव भी पाकिस्तान में

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

यहां स्कैन करें

साल 2006 में मार गिराए गए बलूच नेता नवाब अकबर शाहबाज खान बुगती की बरसी पर पिछले दो-तीन दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई हिंसक हमले हुए हैं। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आर्मी कैंप को तो निशाना बनाया ही गया है, उत्तरी बलूचिस्तान में एक बस में यात्रियों के पहचान-पत्र देखने के बाद 20 से अधिक पंजाबियों की हत्या भी की गई है। पहली बार इतनी बर्बरता के साथ हमले हो रहे हैं। उत्तरी बलूचिस्तान की घटना का संकेत इसलिए भी अधिक गहरा है, क्योंकि यह इलाका पश्तून बहुल है और यहां तालिबान से जुड़े गुटों का दबदबा रहा है। बलूच मुख्यतः मध्य, पश्चिम और निचले बलूचिस्तान में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में, बिना स्थानीय सांठ-गांठ के यहां हिंसक कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब साफ है कि अब तालिबानी पश्तून और बलूच अलगाववादियों में करीबी बढ़ने लगी है।

पंजाबियों का कत्ल निंदनीय है, पर सवाल यह है कि बलूच आखिर क्यों इस हद तक उतर आए हैं? दरअसल, वे मानते हैं कि पंजाबी उनके इलाकों में आकर बस रहे हैं, उनकी संस्कृति खत्म कर रहे हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनकी जनसांख्यिकी प्रभावित कर रहे हैं। गौरतलब है, बलूचिस्तान कभी गैस का एक भंडार हुआ करता था, लेकिन यहां से निकलने वाली गैस पंजाब, सिंध और कराची तक तो पहुंच जाती थी, पर बलूचिस्तान खुद इससे महरूम रहता था। इन्हीं सब कारणों से बलूच पंजाबियों को निशाने पर लेने लगे हैं। हालांकि, यह एकतरफा कार्रवाई नहीं है। पंजाब जाने वाले बलूच नौजवानों के साथ भी तमाम तरह के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। उन्हें सरकारी एजेंसी या अधिकारी उठा ले जाते हैं।

उत्तरी बलूचिस्तान में पहचान-पत्र देखकर हत्या करने की घटना का संकेत इसलिए भी गहरा है, क्योंकि यह इलाका पश्तून बहुल है।

बलूचिस्तान में 1947 से बाद से यह पांचवीं बड़ी बगावत है। इस विप्लव की शुरुआत वैसे तो साल 2000-01 में ही हो गई थी, पर नवाब बुगती की हत्या के बाद इसमें काफी तेजी आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन ने भी इस आंदोलन को धार दी है, क्योंकि विद्रोही उन्हीं हथियारों से लैस हैं, जो अमेरिका कभी अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता था। बलूच विद्रोहियों को पैसों की भी कमी नहीं, क्योंकि प्रवासी बलूच से उन्हें काफी मदद मिल जाती है। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि बलूच राष्ट्रवादी काफी पढ़े-लिखे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नेता अल्लाह नजर बलूच खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं और यहां नेतृत्व की भूमिका में कई उच्च शिक्षित महिलाएं भी हैं, जैसे डॉक्टर मेहरंग बलूच। इन्होंने बंदूकें इसलिए उठाईं, क्योंकि बलूचिस्तान मानव विकास के तमाम सूचकांकों में काफी नीचे है। पाकिस्तानी फौज यहां की सरकार तय करती है, जिससे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। यहां तक कि उन्हें अपना पहनावा भी नहीं पहनने दिया जाता। स्कूलों में बलूच भाषा भी नहीं पढ़ाई जाती। वैसे, यहां का एक तबका राजनीतिक गतिविधियों के सहारे भी बगावत कर रहा है। पिछले दिनों 'बलूच नेशनल गैदरिंग' के तहत मानो पूरा बलूचिस्तान ग्वादर में जमा हो गया था और अपने अधिकारों की मांग कर रहा था।

हालांकि, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान में ही तनाव नहीं है। उत्तरी हिस्से में पश्तून भी उत्तेजित हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज जो कार्रवाई करती है, उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आतंकी भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं। इसी तरह, पंजाब में राजनीतिक तनाव चरम पर है, क्योंकि इमरान खान अब भी जेल में हैं और निष्पक्ष चुनाव न होने के कारण लोगों का सरकार पर भरोसा नहीं बन सका है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हमने चंद महीने पहले बड़ा उबाल देखा था और लोग हुकूमत की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे।

उधर गिलगित-बाल्टिस्तान में भी शिया-सुन्नी के बीच तनाव बना हुआ है। कुर्रम एजेंसी में तो बीते दिनों दोनों गुटों के एक फसाद में 70-80 लोग मारे गए थे। कराची के अंदर भी जातीय तनाव बना हुआ है, जबकि सिंध में धीरे-धीरे हिंदू राष्ट्र की मुहिम रफ्तार पकड़ने लगी है। फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान का तनाव ज्यादा गहरा है, क्योंकि यहां विद्रोह को कुचलने की नीति पाकिस्तान पर भारी पड़ती दिख रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सहभागिता बिना संबंध कैसा

वह क्या है, जिसे आप परिवार कहते हैं? यह घनिष्ठता का, सहभागिता का संबंध है। अपने परिवार में पत्नी या पति के साथ आपके सहज संवाद हैं? निस्संदेह, संबंध से हमारा तात्पर्य वही है। संबंध का अर्थ है, भयमुक्त सहसंवाद। एक-दूसरे को समझने, आपस में सीधे संवाद स्थापित करने की स्वतंत्रता। स्पष्ट है, संबंध का अर्थ है दूसरे के साथ सहभागिता का होना। क्या आपके साथ ऐसा है? क्या आपकी अपनी पत्नी के साथ सहभागिता है? शायद शारीरिक दृष्टि से हो, पर उसे संबंध नहीं कहा जा सकता। आपके और आपकी पत्नी के बीच अलगाव की एक दीवार है और आपकी पत्नी उस दीवार की एक तरफ व आप दूसरी तरफ रहते हैं। आपकी अपनी दौड़ है, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और आपकी पत्नी की अपनी हैं। आप उस दीवार के पीछे रहते हैं; हां, कभी-कभी आप उस दीवार के ऊपर से झांक लेते हैं और उसे संबंध कहते हैं। यही हकीकत है न? आप इसे व्यापक बना सकते हैं, इसे कुछ सौम्य बना सकते हैं, इसका बयान करने के लिए नई शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी सच्चाई यही है कि आप दोनों अलग-थलग जीते हैं, और उस अलगाव-पसंद जीवन को आप संबंध कहते हैं।

यदि दो व्यक्तियों में वास्तविक संबंध है, यानी उनके बीच सहज संवाद है, तब उसके निहितार्थ बहुत व्यापक हो जाते हैं, फिर वहां अलगाव नहीं होता, वहां प्रेम होता है, जिम्मेदारी या दायित्व की बात नहीं होती। एक व्यक्ति, जो प्रेम करता है, दायित्व की बात नहीं करता, वह प्रेम करता है। वह अपना आनंद, अपना दुख, अपना धन दूसरे के साथ बांटता है। क्या आपके परिवार ऐसे हैं? क्या अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ आपका सीधा गहरा संबंध है? नहीं है। अतः परिवार अपने नाम या परंपरा को जारी रखने का बहाना भर है। मैं व्यापार के संसार में, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में निष्ठुरता से दूसरों का शोषण करता हूं और घर में दयालु व उदार होने की कोशिश करता हूं। कितनी विसंगति है?

संबंध वहीं खोजा जाता है, जहां परस्पर संतुष्टि, एक-दूसरे के काम आने की बात होती है। जब आप ऐसी संतुष्टि नहीं पाते, तो आप रिश्ता बदल लेते हैं। या

यदि दो व्यक्तियों में वास्तविक संबंध है, यानी उनके बीच सहज संवाद है, तब उसके निहितार्थ व्यापक हो जाते हैं, फिर वहां अलगाव नहीं होता, वहां प्रेम होता है, जिम्मेदारी या दायित्व की बात नहीं होती।

तो आप संबंध-विच्छेद कर लेते हैं या आप एक साथ बने तो रहते हैं, लेकिन तमन्नाओं की पूर्ति कहीं और खोजते हैं। अंततः यही है, संसार में हमारा संबंध; और वस्तुतः ऐसा ही है। संबंध वहीं खोजा जाता है, जहां सुरक्षा हो; जहां एक व्यक्ति के तौर पर आप सुरक्षा, तुष्टि और अज्ञान की स्थिति में रह पाएं, और यह सब सदा द्वंद्व पैदा करता है। अतः संबंध की परिणति अनिवार्यतः स्वामित्व व निंदा में होती है; सुरक्षा, सुविधा और तुष्टि की स्व-आग्रही मांग में होती है और स्वाभाविक है कि उसमें प्रेम नहीं होता।

जे कृष्णमूर्ति

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

कृष्ण की गाथा एक साधारण देहाती बच्चे की संपूर्णता से भरे मनुष्य बनने की कहानी है। इस कहानी का कोई न कोई हिस्सा हम सभी के भीतर है। कृष्ण को पूजने से भी ज्यादा जरूरी है कि हम उनसे जीना सीखें।

अनुलोम-विलोम

बिगड़े बोल

हमारे माननीय अब वाकई बड़बोले हो रहे

लोकतंत्र में सहमति-असहमति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र की यही पहचान है। मगर कोई नेता अगर किसी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है या उसके बयान बड़बोले होते हैं, तो यह राजनीति में गिरावट का ही संकेत है। भारत में आए दिन किसी न किसी राजनेता अथवा माननीय की जुबान फिसलती रहती है। किसी की गलती से फिसल जाती है, तो कोई इस तरह की बयानबाजी के लिए ही राजनीति में जाने जाते हैं। ताजा मामला अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। आंदोलन के दौरान प्रदर्शन-स्थल पर लाशें लटकती देखी गईं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था। इससे पहले भी उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी, जिसका नतीजा हवाईअड्डे पर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के रूप में निकला था। इस बार विवाद बढ़ते देख सत्तारूढ़ दल ने तुरंत उनके बयान से किनारा कर लिया और साफ कर दिया कि उन्हें इस तरह के बयान से भविष्य में बचना चाहिए।

बहरहाल, इस तरह की बदजुबानी से न केवल किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति विशेष के सम्मान अथवा गरिमा को चोट पहुंचती है, बल्कि ऐसी बातें बोलने वाले के व्यक्तित्व में छिपी कुंठा भी जाहिर होती है। मुद्दों के आधार पर तर्कों के जरिये अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं के खिलाफ बयानबाजी में तल्खी रखना या व्यंग्य का इस्तेमाल करना गलत नहीं माना जा सकता। मगर ऐसा करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जुबान गलत न हो या अभद्रता आप पर हावी न होने पाए। अफसोस की बात है कि बेबुनियाद वक्तव्यों पर विवाद उभरने और ज्यादातर मामलों में राजनेताओं द्वारा माफी मांगने के बावजूद राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में बदल जाते हैं। कई बार तो ऐसी बातें भी बोल दी जाती हैं कि बाद में किसी मौके पर यदि एक-दूसरे का सामना हो जाए, तो उस बड़बोले नेता के लिए असहज स्थिति बन जाती है। फिर भी, राजनेता सुधरने को तैयार नहीं दिखते।

किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि लंबी जुबान इंसान को बहुत छोटा बना देती है। यह विडंबना ही है कि जिन लोगों पर देश के विकास का दारोमदार है और जो अपनी फिल्मों के जरिये समाज को सकारात्मक संदेश देते रहे हैं, वही राजनीतिक बाध्यता के कारण अपनी गरिमा से समझौता करते रहते हैं। हमारे लोकतंत्र की यह तस्वीर अब बदलनी चाहिए।

जयप्रकाश नवीन, टिप्पणीकार

जो उन दिनों दिखा, वही कंगना ने कहा

खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन का इस्तेमाल उत्तर भारत की कृषक जातियों के भीतर भरी कुंठा को भुनाकर अपने को फिर से स्थापित करने के लिए किया था। और, कहीं भी जब आंदोलन को आतंकी हाईजैक कर लेते हैं, तो यह असंभव है कि आंदोलन-स्थल पर हत्या, बलात्कार, लूटपाट आदि न हों। क्या यह सच नहीं है कि इन खालिस्तानियों ने एक दलित सिख की निर्मम हत्या कर दी थी? कहा तो यह भी जाता है कि वह सिख मरते वक्त पानी के लिए तड़प रहा था, पर इन आंतकियों ने उसे एक बूंद पानी नहीं दिया। आतंकियों की पीड़ा थी कि चरणजीत सिंह चन्नी जैसा एक दलित सिख मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने जा रहा था। अपनी यह नफरत खालिस्तानियों ने एक निरीह दलित सिख की हत्या करके निकाली। इसी तरह, आंदोलन स्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। ऐसे में, कंगना रनौत ने क्या गलत कहा? हां, सच कड़वा जरूर है, इसलिए यह आपको पच नहीं रहा है। देखा जाए, तो जो जातियां अपनी कुंठा में खालिस्तानियों के हाथों इस्तेमाल हो गईं, वे अपनी गलती स्वीकार करें और भविष्य में फिर ऐसी गलती न होने पाए, यह सुनिश्चित करें। यह ठीक नहीं है कि आप अपनी मूर्खता को अपने अहंकार के कारण स्वीकार करने से बचते रहें। कंगना को मेरा पूर्ण समर्थन है।

भूपेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

साथ दे पार्टी

अपने नेताओं द्वारा पार्टी की विचारधारा के अनुरूप दिए गए बयानों से निपटने के तरीके से यही संदेश जाता है कि भाजपा चुनाव हार गई थी, विपक्ष ने उसे जबरन कुर्सी पर बिठाया है और विपक्ष की नाराजगी से सरकार की कुर्सी जा सकती है, अन्यथा कंगना रनौत के बयान पर पार्टी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती। कंगना ने यही तो कहा था कि किसान आंदोलन से बांग्लादेश जैसी परिस्थिति पैदा करने की मंशा थी। यही बात तो किसान नेताओं ने भी परोक्ष तौर पर कही थी। क्या किसान आंदोलनकारियों ने निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की थी? क्या आंदोलनकारियों ने बंगाल से आई महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था? क्या आंदोलन के क्रम में खालिस्तानी झंडे नहीं फहराए गए थे? क्या आंदोलनस्थल पर भिंडरांवाले के पोस्टर नहीं लगाए गए थे? यदि यह सब सच है, तो सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ा जा रहा है? क्या इससे सच झूठ में बदल जाएगा? कंगना के बयानों से पल्ला झाड़कर पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? उसे समझना चाहिए कि विरोधी तो वोट देते ही नहीं और जो वोट दे रहे हैं, अगर उनको भी पार्टी नाराज कर देगी, तो फिर चुनावों में सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी?

मेहरा पूरन सिंह, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
सार्थक प्रयासों के बिना स्वप्नों की पूर्ति संभव नहीं

घोटाला और जमानत

दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाले और उससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह यह प्रश्न करते हुए जमानत दे दी कि आखिर उनके विरुद्ध प्रमाण कहां हैं, उससे सीबीआइ और ईडी का कठघरे में खड़ा दिखना स्वाभाविक है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। यह ठीक है कि उसने सीबीआइ और ईडी से यह पूछा कि आखिर प्रमाण कहां हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने के. कविता को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें निर्देशित किया कि जमानत के दौरान वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की चेष्टा नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी है, लेकिन क्लीनचिट नहीं। समस्या यह है कि इस तरह के मामलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियां कुछ और ही ध्वनित करती हैं। कई बार ऐसी टिप्पणियां फैसलों का हिस्सा भी नहीं होतीं। आखिर न्यायाधीश जो कहते हैं, वह अपने फैसलों में लिखते क्यों नहीं? ध्यान रहे कि कई बार उनकी मौखिक टिप्पणियों को आधार बनाकर जमानत पाने वाले नेता और उनके समर्थक यह माहौल बनाने लगते हैं कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और जिस घपले-घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह तो हुआ ही नहीं। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है।

के. कविता और उनके पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में अंतिम फैसला आ चुका है। नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला यथाशीघ्र आए, इसके लिए जांच एजेंसियों को भी सक्रियता दिखानी होगी और अदालतों को भी। आवश्यक केवल यही नहीं कि सीबीआइ और ईडी यह स्पष्ट करें कि आखिर उन्हें बार-बार ऐसे सवालों से क्यों दो-चार होना पड़ता है कि प्रमाण कहां हैं? इसके साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना आवश्यक है कि ट्रायल शुरू होने में अनावश्यक देरी क्यों होती है? ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय ट्रायल में देरी का जो उल्लेख किया था, वही के. कविता मामले में भी किया। पता नहीं के. कविता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि प्रधानमंत्री राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं और हाल में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐसा कहा भी। राजनीतिक भ्रष्टाचार से तब तक प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता, जब तक जांच एजेंसियां और अदालतें अपना काम तत्परता से नहीं करतीं।

सही जानकारी मिले

बिहार के सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, जिससे पता चल सके कि वह जमीन उसकी है। सर्वे के संबंध में सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है। किंतु, जमीन मालिकों के समक्ष कई ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर वे भ्रम में हैं। भू-लगान की रसीद, दाखिल-खारिज, खतियान, बंटवारा एवं संयुक्त जमीन आदि को लेकर लोगों में संशय की स्थिति है। यह बात भी तेजी से प्रसारित हो रही कि अगर स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तो वह जमीन सरकार की हो जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों के निवासियों के समक्ष मूल दस्तावेजों को लेकर काफी समस्याएं हैं। दियारा क्षेत्र के रैयत भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में जानकारी देने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। इसका प्रचार-प्रसार जरूरी है, ताकि आमजन इसके प्रति जागरूक हो सकें। यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि अधिकाधिक संख्या में लोग सर्वे के लिए आगे आएं। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को भी इसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है। इसके साथ ही साइबर कैफे पर भी निगरानी की आवश्यकता है। बकाया लगान पर जुर्माना के नाम पर पैसे ऐंठने की शिकायतें भी काफी मिल रही हैं। जबकि, सरकार का साफ कहना है कि बकाया भू-लगान पर अर्थदंड का कोई प्रविधान नहीं है।

आमजन को सरकार के स्तर से भूमि सर्वेक्षण के संबंध में सही जानकारी देने की कारगर व्यवस्था की जाए, ताकि किसी स्तर पर भ्रम न रहे

पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता का समय

ए. सूर्यप्रकाश

समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े मूलभूत संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए

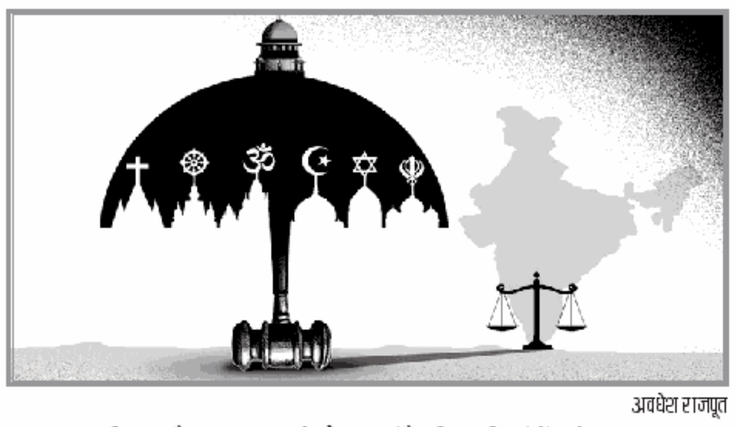

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते आए हैं। इसी कड़ी में इस बार उन्होंने 'सेक्युलर' सिविल कोड का उल्लेख किया कि संवैधानिक सिद्धांतों व उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई जाए। उनका यह रेखांकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान में जो संहिता लागू है, वह सांप्रदायिक प्रकृति की है। उनका संकेत 1955 में नेहरू सरकार के उस कानूनी सुधार की ओर था, जिसने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय को तो अपने दायरे में ले लिया, मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। हिंदू पर्सनल कानूनों में परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी। जहां यह काम तेजी से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर नेहरू सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। संविधान सभा से ही मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो दबाव बनाया, उसके आगे नेहरू सरकार ने समर्पण कर दिया। समान संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए। यह नेहरू सरकार की भूल थी और यदि देश में संवैधानिक-लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है तो इस भूल को सुधारना होगा।

मजहब के आधार पर हुए देश के रक्तरंजित विभाजन के बावजूद भारत ने पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसीलिए संभव हो सका, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं गया, क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन्होंने भारत में रहने को तरजीह दी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, वे इन उदारवादी मूल्यों को आत्मसात करें। जिन्हें अपनी मजहबी परंपराएं ज्यादा प्यारी थीं, उनके लिए सरहद पार करके नवसृजित इस्लामिक देश में जाने का विकल्प खुला हुआ था।

भारत में इसे लेकर दिखाई गई हिचक का परिणाम यह निकला कि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में नहीं आ पाई। आखिर संवैधानिक राह पर चलने वाले एक पंथनिरपेक्ष देश में मजहबी कानून कैसे प्रभावी रह गए, इसके जवाब की जड़ें 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 (तब यह अनुच्छेद 35 था) पर हुई बहस में छिपी हैं। इसके विरोध की शुरुआत बहस आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्माइल साहिब के वक्तव्य से ही हो गई। उन्होंने कहा कि पर्सनल कानूनों का पालन एक मूल अधिकार है। महबूब अली बेग साहिब बहादुर और बी. पोकर साहिब बहादुर ने उनसे सहमति जताई। बी. पोकर साहिब ने कहा, 'यूसीसी एक दमनकारी प्रविधान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' हुसैन इमाम और नजीरुद्दीन अहमद भी विरोध की इस मुहिम में शामिल हो गए। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने उसका विरोध किया।

केएम मुंशी ने उनका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्छी मेमन वर्ग में भारी असंतोष था कि उन पर शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा, 'तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां थे?' उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों से था, जो शरीयत कानून को मानने पर मजबूर थे। मुंशी ने कहा कि हम धर्म-पंथ को पर्सनल कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, 'ये मामले (विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि) धार्मिक न होकर, नितांत पंथनिरपेक्ष कानूनों के दायरे में आते हैं।' उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने अपने लिए संवैधानिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर उनसे सहमत थे। उन्होंने कहा, 'यदि कोई समुदाय स्वयं को समय के साथ बदलने के लिए तत्पर है तो वह बहुसंख्यक (हिंदू) समुदाय ही है।'

संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख डा. बीआर आंबेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने इस दावे की भी पोल खोली कि शरीयत कानून अपरिवर्तनीय होने के साथ ही पूरे भारत में एकसमान हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस में 1939 तक मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं थे। उत्तराधिकार आदि में वे हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। साथ ही, 1937 में शरीयत कानून लागू होने से पहले तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बांबे में हिंदू उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाता तो मालाबार में मुसलमान हिंदू मातृसत्तात्मक कानून का पालन करते थे। इसलिए, उन्हें मुस्लिम सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करना पड़ा।

स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भीरुता का परिचय दिया, उसकी कीमत भारत को आज भी चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसे मामलों में न्यायाधीशों ने कहा, 'जब देश के 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक पहले ही संहिताबद्ध पर्सनल कानूनों के दायरे में लाए जा चुके हैं तो शेष अन्य को इससे बाहर रखने और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने के फैसले को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं।' शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भी उतनी ही समीचीन है कि हिंदुओं के साथ-साथ सिखों, बौद्धों और जैनियों ने 'राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लिया', लेकिन कुछ अन्य समुदायों की ऐसी मंशा नहीं। वह भी तब जब संविधान पूरे भारत के लिए एक 'समान नागरिक संहिता' का निर्देश देता है। इसलिए पीएम मोदी का कहना उपयुक्त है कि समय आ गया है कि हम 'सेक्युलर कोड' यानी पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ें। हमें सुनिश्चित करना होगा कि मजहबी भावनाएं संवैधानिक मूल्यों-प्रविधानों की राह में अवरोध न बनें। जब भी मजहबी बातों और संविधान के बीच विकल्प चुनने की बारी आए तो संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ इसी प्रकार का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण से झलका। भारत के संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया ही जाना चाहिए।

(लेखक संवैधानिक मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

संकट के दौर से गुजरती भाजपा

राजीव सचान

अब विपक्ष झूठे-सच्चे विमर्श खड़ा करता है और सत्तापक्ष प्रतिक्रिया एवं सफाई देते हुए दिखता है

मोदी सरकार को अपना तीसरा कार्यकाल पूरा किए हुए अभी सौ दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी अल्पावधि में ही उसे कई फैसलों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इसके कारण उसे यू-टर्न सरकार कहा जा रहा है। सरकार के साथ भाजपा को भी यू-टर्न लेने पड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची को पार्टी ने जिस तरह वापस लिया, वह यू-टर्न ही है। इससे पार्टी की अनुशासित छवि को तो धक्का लगा ही, उसकी फजीहत भी हुई। भाजपा को यह सूची इसलिए वापस लेनी पड़ी, क्योंकि एक तो कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिए गए और दूसरे, अन्य दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बना दिया गया। इसका विरोध इतना अधिक हुआ कि भाजपा को दो घंटे के अंदर ही सूची वापस लेनी पड़ी और नई सूची में 44 के स्थान पर 16 नाम ही घोषित किए गए। हो सकता है कि शेष 28 नाम घोषित कर भाजपा असंतोष को दूर करने में समर्थ हो जाए, लेकिन इससे इतना तो पता चल ही गया कि पार्टी ने इससे कोई सबक नहीं सीखा कि उसे लोकसभा चुनावों में दूसरे दलों के नेताओं को प्रत्याशी बनाने के कैसे बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे?

जिस दिन भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के अपने प्रत्याशियों की सूची वापस ली, उसी दिन उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान से न केवल किनारा किया, बल्कि उन्हें चुप रहने की हिदायत भी दी। कंगना ने कहा था, 'उक्त आंदोलन में लाशें लटक रही थीं, दुष्कर्म हो रहे थे। कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, अन्यथा उपद्रवियों की कुछ वैसी ही योजना थी, जैसा उन्होंने बांग्लादेश में किया।' हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते कंगना का बयान मौके की नजाकत को देखते हुए भाजपा के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उक्त आंदोलन के दौरान पंजाब के दलित युवक लखबीर सिंह की हथेली काटकर सचमुच उसका शव बैरिकेड पर टांग दिया गया था। यह भी तथ्य है कि आंदोलन में शामिल होने आई एक युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया था। इसी आंदोलन में हरियाणा के एक युवक मुकेश को जलाकर मार दिया गया था और इससे तो सभी अवगत हैं कि 26 जनवरी, 2021 को ट्रैक्टर परेड के बहाने लाल किले पर धावा बोलकर किस तरह हिंसा का नंगा नाच किया गया था। इस परेड के पहले राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि ट्रैक्टर रोके गए तो 'बक्कल उतार दिए जाएंगे।' इन्हीं टिकैत ने हाल में कहा कि ट्रैक्टर परेड वाले दिन लाल किले के बजाय संसद की ओर कूच कर जाते तो उसी दिन देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो गया होता। एक तरह से राकेश टिकैत ने कंगना की बात पर मुहर लगाई। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसानों के बीच पेशेवर आंदोलनकारी भी सक्रिय थे। इसी कारण खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें आंदोलनजीवी कहा था।

नैरेटिव के मोर्चे पर लगातार मिल रही मात। प्रेट्र

कंगना के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा उन्हें पार्टी से निकाले। पता नहीं भाजपा कांग्रेस से यह क्यों नहीं पूछ सकी कि क्या उसने सलमान खुर्शीद को निकाला, जो कह रहे थे कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, वैसा ही भारत में हो सकता है। भाजपा चाहती तो आसानी से कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेती, जैसा दूसरे दल करते रहते हैं, लेकिन उसने यह भी कहा कि कंगना नीतिगत विषयों पर बोलने को न तो अधिकृत हैं और न ही उन्हें इसकी अनुमति है। भाजपा को जम्मू-कश्मीर के प्रत्याशियों की सूची वापस लेने और कंगना को हिदायत देने का काम ऐसे समय करना पड़ा, जब मोदी सरकार एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लाकर विपक्ष के हाथों से एक मुद्दा छीनने में सफल ही हुई थी।

कहना कठिन है कि कंगना को चुप कराने से भाजपा को हरियाणा में कितना लाभ होगा, लेकिन जो आसानी से कहा जा सकता है, वह यह कि भाजपा राजनीतिक रूप से कमजोर और किंकर्तव्यविमूढ़ सी दिखने लगी है। जो स्थिति पार्टी की है, वही मोदी सरकार की भी। यह सरकार केवल वक्फ अधिनियम में संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए ही राजी नहीं हुई, बल्कि उसे ब्राडकास्ट विधेयक भी वापस लेना पड़ा। लेटरल एंट्री के मामले में तो उसे सहयोगी दलों और साथ ही विपक्षी दलों के भी दबाव के आगे झुकना पड़ा। इसके लिए भी वह अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसे यह सामान्य सी जानकारी होनी ही चाहिए थी कि जब विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है और उसे नुकसान भी पहुंचा चुका है, तब लेटरल एंट्री को लेकर तो वह पक्का शोर मचाएगा। आखिर उसे यह समझ क्यों नहीं आया कि कम से कम लेटरल एंट्री पर सहयोगी दलों को तो भरोसे में लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होता?

समस्या केवल यह नहीं कि 240 लोकसभा सीटों पर सिमट जाने के कारण भाजपा और मोदी सरकार पहले जितनी सक्षम नहीं। समस्या यह भी है कि वह नैरेटिव के मोर्चे पर लगातार पिट रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना या फिर एससी-एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण पर क्या कहना चाहिए? राजनीति में नैरेटिव का बहुत महत्व होता है। पहले सत्तापक्ष कोई विमर्श खड़ा करता था और विपक्ष प्रतिक्रिया एवं सफाई देता था। अब विपक्ष एक के बाद एक विषयों पर झूठे-सच्चे विमर्श खड़ा करता है और सत्तापक्ष प्रतिक्रिया और सफाई देने की मुद्रा में दिखता है। आखिर इसे भाजपा और मोदी सरकार का संकटकाल न कहा जाए तो क्या कहा जाए?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मोक्ष का मार्ग

प्रवृत्ति और निवृत्ति कल्याण के दो प्रमुख मार्ग बताए जाते हैं। कल्याण से तात्पर्य सुख एवं अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं है। कल्याण का अर्थ है आत्मा के परम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ना है। यह ध्यान रहे कि यहां यह कहा जा रहा है मुक्ति की ओर बढ़ना न कि 'मुक्ति प्राप्त कर लेना।' मानव योनि में जन्म लेते ही कुछ कर्तव्य हमारे हिस्से आ जाते हैं। इन कर्तव्यों की पूर्ति में उत्साह एवं ऊर्जा के साथ 'प्रवृत्त' होना, अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्हें पूर्ण करना और अच्छे से उनकी पूर्ति करना, कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता न बरतना, अपने ही कल्याण को साधना है।

मां जब अपनी संतानों की उदरपूर्ति के लिए तन-मन के पूर्ण समर्पण के साथ भोजन बनाती है, तब उसे बदले में किसी भी प्रकार की प्रशंसा, पारिश्रमिक या प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं होती। वह अपना कर्म अपना दायित्व समझकर करती है। उसका उद्देश्य मात्र संतान की क्षुधा पूर्ति करना होता है। इसी प्रकार, सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म मन में किसी कामना या लालसा के बिना होने चाहिए। कर्म संपादित करते समय पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहे। कर्म के बदले में यश-धन-नाम जो कुछ भी मिले उसे पारितोषिक समझ लिया जाए। यदि एक भी ऐसा पवित्र क्षण मिल जाए, जिसमें मात्र कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होकर कर्म किया गया तो समझिए कि मोक्ष की राह मिल गई।

अब प्रश्न उठ सकता है अभी मोक्ष चाहिए ही किसे? विकारों से ग्रस्त होकर मन में जो मलिनता समाहित हो जाती है, वह उत्साहपूर्वक किए गए कर्तव्य-कर्म के वेग से थोड़ी सी भी धुल जाए तो एक पवित्रता का भाव आता है, वही परम आनंद है। वही जीवन को सार्थक करने की एक झलक है। स्मरण रहे कि अपना कल्याण साधने के प्रयास हमें ही करने होंगे और इसी देह के भीतर रहते हुए, इसी देह को साधन बनाकर करने होंगे।

ट्विंकल तोमर सिंह

खतरे में वन्यजीवों का अस्तित्व

सुधीर कुमार

वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वन्यजीव अपराधों से लगभग चार हजार पौधों व पशुओं की प्रजातियां दुष्प्रभावित हुई हैं

हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने तीसरी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट-2024 प्रकाशित की है। इससे पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2016 और 2020 में किया गया था। यह रिपोर्ट विश्वभर में वन्यजीव अपराधों की मौजूदा स्थिति और प्रवृत्तियों का एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से 'सीआईटीईएस' (वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के तहत सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों पर केंद्रित किया गया है, जिनका अवैध व्यापार लगातार बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2015-2021 की अवधि के दौरान वन्यजीव अपराध से चार हजार पौधों और जानवरों की प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। इनमें से 3250 प्रजातियों को संरक्षण के लिए पहले से ही 'सीआईटीईएस' द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। इसका अर्थ है कि उनका संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये प्रजातियां पहले से ही खतरे में थीं। इसके बावजूद, वन्यजीव अपराधों ने उनकी स्थिति को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिससे उनकी संख्या में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। इन प्रजातियों पर अवैध शिकार, तस्करी और अन्य अपराधों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चिंताजनक है कि वन्यजीव अपराध का दायरा दुनिया के 160 से भी अधिक देशों में फैल गया है। अवैध व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति पारिस्थितिकी-तंत्र की खराब सेहत, जैव विविधता के ह्रास और आमजन को प्रकृति से मिलने वाले कई सामाजिक-आर्थिक लाभों से वंचना के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2015-2021 के बीच वन्यजीवों से संबंधित जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सात वर्षों के दौरान कुल 1.3 करोड़ वस्तुएं जब्त की गईं, जिनका वजन 16 हजार टन से भी अधिक आंका गया है। इनमें गैंडा, पैंगोलिन, हाथी, मगरमच्छ, सांप और कछुआ जैसे जीव-जंतुओं के विभिन्न अंगों के अलावा देवदार, शीशम, अगरवुड और नागफनी जैसे पेड़-पौधे भी प्रमुख रूप से जब्त किए गए हैं। वन्यजीवों का अवैध व्यापार मुख्यतः भोजन, दवा, विलासिता की वस्तुओं के रूप में और उन्हें पालने के उद्देश्य से किया जाता है। वन्यजीवों के प्रति बढ़ते अपराध न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

वन्यजीव प्राकृतिक खजाने के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि मानव जीवन और पारिस्थितिकी-तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

सरकारी खजाने का हो सदुपयोग

'रेवड़ी संस्कृति का बढ़ता रोग' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगदीप सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर तार्किक ढंग से अपनी बात रखी। दशकों से प्रत्येक चुनावों में सभी राजनीतिक दल तरह-तरह के वादे करते हैं। अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। सबकी यही कोशिश होती है कि आमजन को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सहायता और मुफ्त पेशकश जैसी घोषणाओं से लुभाया जा सके। इन वादों की पूर्ति पार्टियां सत्ता में आने के बाद सरकारी खजाने से करती हैं और कई वादे तो पूरे भी नहीं हो पाते। सरकारी खजाना आम जनता की गाढ़ी कमाई से भरता है, जिसका अनुशासित रूप से व्यय करना ही सही होता है। उसका सदुपयोग किया जाना ही श्रेयस्कर है। याद रहे कि सरकारी खजाने की बंदरबांट से कभी कोई राष्ट्र उन्नति नहीं करता। उलटे ये कदम प्रतिगामी सिद्ध होते हैं। दुनिया में वेनेजुएला से लेकर श्रीलंका तक ऐसे तमाम देशों के उदाहरण हैं, जिन्होंने मुफ्तखोरी की राह पर अपनी दुर्गति कराई है। इसलिए हमारे देश में ऐसा कभी न हो, उसके लिए राजनीतिक दलों को अपना रवैया सुधारना होगा। यदि आवश्यक हो तो इस मामले में चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय भी कोई हस्तक्षेप करें तो वह उपयोगी सिद्ध होगा।

कमल कुमार, लखनऊ

जातीय जनगणना के दुष्परिणाम

लगभग समूचा विपक्ष आजकल जातीय जनगणना कराने के लिए जमीन आसमान एक करने को तैयार है। उसके बाद हर जाति का अपना नेता पैदा हो जाएगा। वह सत्ता में, नौकरी में अपनी हिस्सेदारी के साथ-साथ अपनी संख्या बढ़ाने पर भी जोर देगा, क्योंकि बंदरबांट तो संख्या के आधार पर होगा, प्रतिभा को फिर कौन पूछेगा। इसका दुष्परिणाम होगा। विभिन्न नेताओं का अपनी-अपनी जाति का वोट बैंक बनना और अंततः आपसी नफरत, मारकाट और फिर देश की बर्बादी। बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं की घुसपैठ और तेज हो जाएगी। विपक्ष तो उनका स्वागत करने को बैठा ही है। उसका सबसे मुख्य चुनावी हथकंडा ही तुष्टीकरण है। सांसदों की संख्या भी मजहब के आधार पर निश्चित करने की मांग उठेगी। संख्या में कम होने के कारण जैनियों और पारसियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मिस इंडिया के चयन में भी ध्यान रखना होगा कि उनमें भी आदिवासी, अनुसूचित एवं पिछड़ों की भी संख्या के हिसाब से भागीदारी हो। क्रिकेट टीम में भी संख्या के हिसाब से सभी धर्मों एवं जाति के हिसाब से हिस्सेदारी देनी होगी।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

मेलबाक्स

बंगाल की तानाशाह सरकार

बंगाल में हुए दुष्कर्म व हत्याकांड पर अनेक लेख छपे हैं। लेकिन अवधेश कुमार ने अपने लेख में बेहिचक सच्चाई बताई है। अब तो दुखद घटना पर काफी पर्दा उठ चुका है। बंगाल में दुष्कर्म और हत्या करने वाला, कालेज के प्रिंसिपल, कोलकाता पुलिस और बंगाल की ममता सरकार, सबने एक-दूसरे का साथ दिया। कम से कम मामले को दबाने और रफा-दफा करने में तो ऐसा हुआ ही है। लेकिन बेचारी शिकार ट्रेनी डाक्टर के परिवार का साथ इनमें से किसी ने नहीं दिया, सिवाय डाक्टर बिरादरी और बंगाल भाजपा के। ममता बनर्जी ने इसके लिए राम-वाम को दोषी ठहराया। हालांकि उस भीड़ में पकड़े गए उपद्रवियों में राम-वाम का एक भी नहीं निकला। भला हो कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसने जांच सीबीआइ को सौंप दी। वरना बंगाल पुलिस क्या करती, यह पूरा देश जानता है। बंगाल पुलिस से कलकत्ता हाई कोर्ट अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए उसने दर्जनों मामले सीबीआइ को सौंपे हैं। ममता का सड़क पर निकलना उनकी अकर्मण्यता ही दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहने, कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग न किया जाए, उसके बाद भी ममता बनर्जी का रवैया तानाशाही वाला बना हुआ है। अभी भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन से प्रहार किया जा रहा है। इससे बढ़ कर तानाशाही का उदाहरण और क्या हो सकता है?

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

सार्थक प्रयासों के बिना स्वप्नों की पूर्ति संभव नहीं

घोटाला और जमानत

दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाले और उससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह यह प्रश्न करते हुए जमानत दे दी कि आखिर उनके विरुद्ध प्रमाण कहां हैं, उससे सीबीआइ और ईडी का कठघरे में खड़ा दिखना स्वाभाविक है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। यह ठीक है कि उसने सीबीआइ और ईडी से यह पूछा कि आखिर प्रमाण कहां हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने के. कविता को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें निर्देशित किया कि जमानत के दौरान वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की चेष्टा नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी है, लेकिन क्लीनचिट नहीं। समस्या यह है कि इस तरह के मामलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियां कुछ और ही ध्वनित करती हैं। कई बार ऐसी टिप्पणियां फैसलों का हिस्सा भी नहीं होतीं। आखिर न्यायाधीश जो कहते हैं, वह अपने फैसलों में लिखते क्यों नहीं? ध्यान रहे कि कई बार उनकी मौखिक टिप्पणियों को आधार बनाकर जमानत पाने वाले नेता और उनके समर्थक यह माहौल बनाने लगते हैं कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और जिस घपले-घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह तो हुआ ही नहीं। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। के. कविता और उनके पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में अंतिम फैसला आ चुका है। नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला यथाशीघ्र आए, इसके लिए जांच एजेंसियों को भी सक्रियता दिखानी होगी और अदालतों को भी। आवश्यक केवल यही नहीं कि सीबीआइ और ईडी यह स्पष्ट करें कि आखिर उन्हें बार-बार ऐसे सवालों से क्यों दो-चार होना पड़ता है कि प्रमाण कहां हैं? इसके साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना आवश्यक है कि ट्रायल शुरू होने में अनावश्यक देरी क्यों होती है? ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय ट्रायल में देरी का जो उल्लेख किया था, वही के. कविता मामले में भी किया। पता नहीं के. कविता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि प्रधानमंत्री राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं और हाल में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐसा कहा भी। राजनीतिक भ्रष्टाचार से तब तक प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता, जब तक जांच एजेंसियां और अदालतें अपना काम तत्परता से नहीं करतीं।

प्रयोगशाला से समाधान

राज्य सरकार मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं बढ़ाने जा रही है। पूर्व से प्रत्येक जिला मुख्यालय में यह स्थापित है। अब दस जिलों के एक-एक प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला होगी। मिट्टी की जांच कर खेती करने से खाद्यान्न की गुणवत्ता-उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित नहीं होगी। फिलहाल राज्य के ज्यादातर किसान बिना मिट्टी जांचे खेती करते हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंदाज से वह खेतों में खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि अनाज का उत्पादन भी प्रभावित होता है। ऐसे अनाज में पोषण की भी कमी रहती है, जाहिर तौर पर इसे खाने वालों को भी अधूरा ही पोषण मिलता है।

मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलना किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

मिट्टी की जांच के बाद किसान सही तरीके से खेती करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण कदम होगा, किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाना। किसानों के बीच जाकर उन्हें मिट्टी जांच के फायदे समझाने होंगे। चूंकि, प्रयोगशाला जिला मुख्यालय या अनुमंडल के स्तर पर है, ऐसे में यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि किसान मित्र या किसी दूसरी व्यवस्था से किसानों के खेतों से मिट्टी के सैंपल लेकर उसे प्रयोगशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। जब इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाए तो वह किसानों तक पहुंचे और उसे विस्तार से किसानों को समझा दिया जाए कि उनके खेत की मिट्टी को किस तरीके की खाद की जरूरत है। किसानों के लिए और गांवों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इस काम में मदद ली जा सकती है। किसानों को यह बताना होगा कि कैसे विकसित देश कम जमीन में फसल लगाकर ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

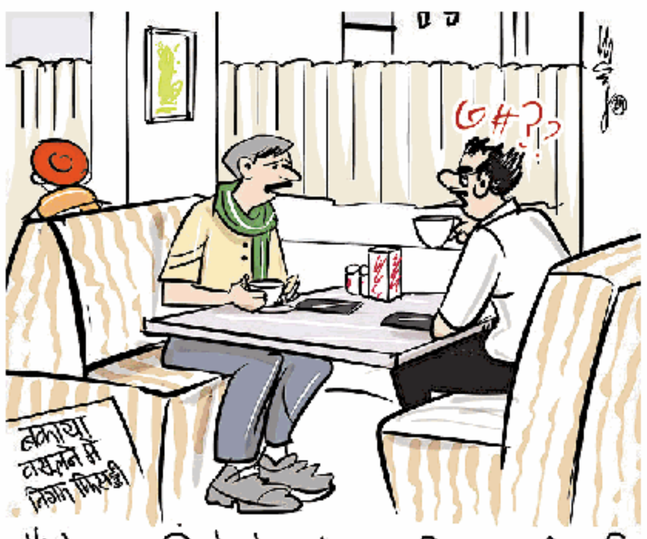

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या किसान आंदोलन में अराजकता से जुड़े कंगना रनौत के बयान से किनारा कर के भाजपा ने सही किया?

आज का सवाल

क्या जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कारगर सिद्ध हो सकता है?

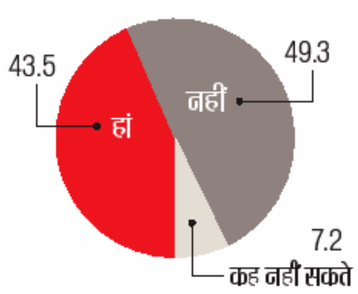

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता का समय

ए. सूर्यप्रकाश

समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े बुनियादी संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए

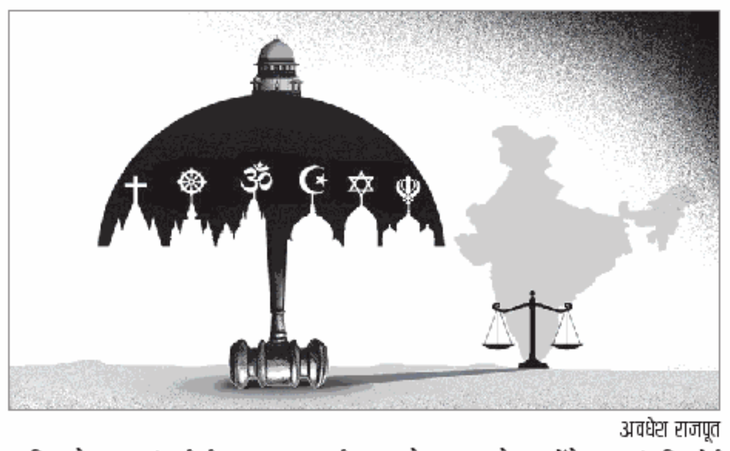

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते आए हैं। इसी कड़ी में इस बार उन्होंने 'सेक्युलर' सिविल कोड का उल्लेख किया कि संवैधानिक सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई जाए। उनका यह रेखांकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान में जो संहिता लागू है, वह सांप्रदायिक प्रकृति की है। उनका संकेत 1955 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के उस कानूनी सुधार की ओर था, जिसने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय को तो अपने दायरे में ले लिया, मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। हिंदू पर्सनल कानूनों में परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी। जहां यह काम द्रुत गति से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर नेहरू सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। संविधान सभा से ही मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो दबाव बनाया, उसके आगे नेहरू सरकार ने समर्पण कर दिया। समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए। यह नेहरू सरकार की बहुत भारी भूल थी और यदि देश में संवैधानिक-लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है तो इस भूल को सुधारना ही होगा।

मजहब के आधार पर हुए देश के रक्तरंजित विभाजन के बावजूद भारत ने पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसीलिए संभव हो सका, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं गया, क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन्होंने भारत में रहने को तरजीह दी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, वे इन उदारवादी मूल्यों को आत्मसात करें। जिन्हें अपनी मजहबी परंपराएं ज्यादा प्यारी थीं, उनके लिए सरहद पार करके नवसृजित इस्लामिक देश में जाने का विकल्प खुला हुआ था।

भारत में इसे लेकर दिखाई गई हिचक का परिणाम यह निकला कि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में नहीं आ पाई। आखिर संवैधानिक राह पर चलने वाले एक पंथनिरपेक्ष देश में मजहबी कानून कैसे प्रभावी रह गए, इसके जवाब की जड़ें 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 (तब यह अनुच्छेद 35 था) पर हुई बहस में छिपी हैं। इसके विरोध की शुरुआत बहस आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्माइल साहिब के वक्तव्य से ही हो गई। उन्होंने कहा कि पर्सनल कानूनों का पालन एक मूल अधिकार है। महबूब अली बेग साहिब बहादुर और बी. पोकर साहिब बहादुर ने उनसे सहमति जताई। बी. पोकर साहिब ने कहा, 'यूसीसी एक दमनकारी प्रविधान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' हुसैन इमाम और नजीरूद्दीन अहमद भी विरोध की इस मुहिम में शामिल हो गए। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने उसका विरोध किया।

केएम मुंशी ने उनका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्छी मेमन वर्ग में भारी असंतोष था कि उन पर शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा, 'तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां थे?' उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों से था, जो शरीयत कानून को मानने पर मजबूर थे। मुंशी ने कहा कि हम धर्म-पंथ को पर्सनल कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, 'ये मामले (विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि) धार्मिक न होकर, नितांत पंथनिरपेक्ष कानूनों के दायरे में आते हैं।' उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने अपने लिए संवैधानिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर उनसे सहमत थे। उन्होंने कहा, 'यदि कोई समुदाय स्वयं को समय के साथ बदलने के लिए तत्पर है तो वह बहुसंख्यक (हिंदू) समुदाय ही है।'

संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख डा. बीआर आंबेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने इस दावे की भी पोल खोली कि शरीयत कानून अपरिवर्तनीय होने के साथ ही पूरे भारत में एकसमान हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस में 1939 तक मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं थे। उत्तराधिकार आदि में वे हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। साथ ही, 1937 में शरीयत कानून लागू होने से पहले तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बांबे में हिंदू उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाता तो मालाबार में मुसलमान हिंदू मातृसत्तात्मक कानून का पालन करते थे। इसलिए, उन्हें मुस्लिम सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करना पड़ा।

स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भीरुता का परिचय दिया, उसकी कीमत भारत को आज भी चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसे मामलों में न्यायाधीशों ने कहा, 'जब देश के 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक पहले ही संहिताबद्ध पर्सनल कानूनों के दायरे में लाए जा चुके हैं तो शेष अन्य को इससे बाहर रखने और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने के फैसले को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं।' शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भी उतनी ही समीचीन है कि हिंदुओं के साथ-साथ सिखों, बौद्धों और जैनियों ने 'राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लिया', लेकिन कुछ अन्य समुदायों की ऐसी मंशा नहीं। वह भी तब जब संविधान पूरे भारत के लिए एक 'समान नागरिक संहिता' का निर्देश देता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कहना पूरी तरह उपयुक्त है कि समय आ गया है कि हम 'सेक्युलर कोड' यानी पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ें। इस राह में हमें सुनिश्चित करना होगा कि मजहबी भावनाएं संवैधानिक मूल्यों-प्रविधानों की राह में अवरोध न बनें। जब भी मजहबी बातों और संविधान के बीच विकल्प चुनने की बारी आए तो सदैव संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ इसी प्रकार का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण से झलका। भारत के संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया ही जाना चाहिए।

(लेखक संवैधानिक मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

संकट के दौर से गुजरती भाजपा

राजीव सचान

अब विपक्ष झूठे-सच्चे विमर्श खड़ा करता है और सत्तापक्ष प्रतिक्रिया एवं सफाई देते हुए दिखता है

नैरेटिव के मोर्चे पर लगातार मिल रही मात ● प्रेट्र

मोदी सरकार को अपना तीसरा कार्यकाल पूरा किए हुए अभी सौ दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी अल्पावधि में ही उसे कई फैसलों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इसके कारण उसे यू-टर्न सरकार कहा जा रहा है। सरकार के साथ भाजपा को भी यू-टर्न लेने पड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची को पार्टी ने जिस तरह वापस लिया, वह यू-टर्न ही है। इससे पार्टी की अनुशासित छवि को तो धक्का लगा ही, उसकी फजीहत भी हुई। भाजपा को यह सूची इसलिए वापस लेनी पड़ी, क्योंकि एक तो कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिए गए और दूसरे, अन्य दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बना दिया गया। इसका विरोध इतना अधिक हुआ कि भाजपा को दो घंटे के अंदर ही सूची वापस लेनी पड़ी और नई सूची में 44 के स्थान पर 16 नाम ही घोषित किए गए। हो सकता है कि शेष 28 नाम घोषित कर भाजपा असंतोष को दूर करने में समर्थ हो जाए, लेकिन इससे इतना तो पता चल ही गया कि पार्टी ने इससे कोई सबक नहीं सीखा कि उसे लोकसभा चुनावों में दूसरे दलों के नेताओं को प्रत्याशी बनाने के कैसे बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे?

जिस दिन भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के अपने प्रत्याशियों की सूची वापस ली, उसी दिन उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान से न केवल किनारा किया, बल्कि उन्हें चुप रहने की हिदायत भी दी। कंगना ने कहा था, 'उक्त आंदोलन में लाशें लटक रही थीं, दुष्कर्म हो रहे थे। कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, अन्यथा उपद्रवियों की कुछ वैसी ही योजना थी, जैसा उन्होंने बांग्लादेश में किया।' हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते कंगना का बयान मौके की नजाकत को देखते हुए भाजपा के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उक्त आंदोलन के दौरान पंजाब के दलित युवक लखबीर सिंह की हथेली काटकर सचमुच उसका शव बैरिकेड पर टांग दिया गया था। यह भी तथ्य है कि आंदोलन में शामिल होने आई एक युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया था। इसी आंदोलन में हरियाणा के एक युवक मुकेश को जलाकर मार दिया गया था और इससे तो सभी अवगत हैं कि 26 जनवरी, 2021 को ट्रैक्टर परेड के बहाने लाल किले पर धावा बोलकर किस तरह हिंसा का नंगा नाच किया गया था। इस परेड के पहले राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि ट्रैक्टर रोके गए तो 'बक्कल उतार दिए जाएंगे।' इन्हीं टिकैत ने हाल में कहा कि ट्रैक्टर परेड वाले दिन लाल किले के बजाय संसद की ओर कूच कर जाते तो उसी दिन देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो गया होता। एक तरह से राकेश टिकैत ने कंगना की बात पर मुहर लगाई। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसानों के बीच पेशेवर आंदोलनकारी भी सक्रिय थे। इसी कारण खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें आंदोलनजीवी कहा था।

कंगना के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा उन्हें पार्टी से निकाले। पता नहीं भाजपा कांग्रेस से यह क्यों नहीं पूछ सकी कि क्या उसने सलमान खुर्शीद को निकाला, जो कह रहे थे कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, वैसा ही भारत में हो सकता है। भाजपा चाहती तो आसानी से कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेती, जैसा दूसरे दल करते रहते हैं, लेकिन उसने यह भी कहा कि कंगना नीतिगत विषयों पर बोलने को न तो अधिकृत हैं और न ही उन्हें इसकी अनुमति है। भाजपा को जम्मू-कश्मीर के प्रत्याशियों की सूची वापस लेने और कंगना को हिदायत देने का काम ऐसे समय करना पड़ा, जब मोदी सरकार एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लाकर विपक्ष के हाथों से एक मुद्दा छीनने में सफल ही हुई थी।

कहना कठिन है कि कंगना को चुप कराने से भाजपा को हरियाणा में कितना लाभ होगा, लेकिन जो आसानी से कहा जा सकता है, वह यह कि भाजपा राजनीतिक रूप से कमजोर और किंकर्तव्यविमूढ़ सी दिखने लगी है। जो स्थिति पार्टी की है, वही मोदी सरकार की भी। यह सरकार केवल वक्फ अधिनियम में संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए ही राजी नहीं हुई, बल्कि उसे ब्राडकास्ट विधेयक भी वापस लेना पड़ा। लेटरल एंट्री के मामले में तो उसे सहयोगी दलों और साथ ही विपक्षी दलों के भी दबाव के आगे झुकना पड़ा। इसके लिए भी वह अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसे यह सामान्य सी जानकारी होनी ही चाहिए थी कि जब विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है और उसे नुकसान भी पहुंचा चुका है, तब लेटरल एंटी को लेकर तो वह पक्का शोर मचाएगा। आखिर उसे यह समझ क्यों नहीं आया कि कम से कम लेटरल एंट्री पर सहयोगी दलों को तो भरोसे में लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होता?

समस्या केवल यह नहीं कि 240 लोकसभा सीटों पर सिमट जाने के कारण भाजपा और मोदी सरकार पहले जितनी सक्षम नहीं। समस्या यह भी है कि वह नैरेटिव के मोर्चे पर लगातार पिट रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना या फिर एससी-एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण पर क्या कहना चाहिए? राजनीति में नैरेटिव का बहुत महत्व होता है। पहले सत्तापक्ष कोई विमर्श खड़ा करता था और विपक्ष प्रतिक्रिया एवं सफाई देता था। अब विपक्ष एक के बाद एक विषयों पर झूठे-सच्चे विमर्श खड़ा करता है और सत्तापक्ष प्रतिक्रिया और सफाई देने की मुद्रा में दिखता है। आखिर इसे भाजपा और मोदी सरकार का संकटकाल न कहा जाए तो क्या कहा जाए?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मोक्ष का मार्ग

प्रवृत्ति और निवृत्ति कल्याण के दो प्रमुख मार्ग बताए जाते हैं। कल्याण से तात्पर्य सुख एवं अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं है। कल्याण का अर्थ है आत्मा के परम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ना है। यह ध्यान रहे कि यहां यह कहा जा रहा है मुक्ति की ओर बढ़ना न कि 'मुक्ति प्राप्त कर लेना।' मानव योनि में जन्म लेते ही कुछ कर्तव्य हमारे हिस्से आ जाते हैं। इन कर्तव्यों की पूर्ति में उत्साह एवं ऊर्जा के साथ 'प्रवृत्त' होना, अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्हें पूर्ण करना और अच्छे से उनकी पूर्ति करना, कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता न बरतना, अपने ही कल्याण को साधना है।

मां जब अपनी संतानों की उदरपूर्ति के लिए तन-मन के पूर्ण समर्पण के साथ भोजन बनाती है, तब उसे बदले में किसी भी प्रकार की प्रशंसा, पारिश्रमिक या प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं होती। वह अपना कर्म अपना दायित्व समझकर करती है। उसका उद्देश्य मात्र संतान की क्षुधा पूर्ति करना होता है। इसी प्रकार, सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म मन में किसी कामना या लालसा के बिना होने चाहिए। कर्म संपादित करते समय पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहे। कर्म के बदले में यश-धन-नाम जो कुछ भी मिले उसे पारितोषिक समझ लिया जाए। यदि एक भी ऐसा पवित्र क्षण मिल जाए, जिसमें मात्र कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होकर कर्म किया गया तो समझिए कि मोक्ष की राह मिल गई। यही कर्तव्य कर्म निवृत्ति के मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो वास्तविक ज्ञान से परिचित कराकर मोक्ष की ओर ले जाएंगे।

अब प्रश्न उठ सकता है अभी मोक्ष चाहिए ही किसे? विकारों से ग्रस्त होकर मन में जो मलिनता समाहित हो जाती है, वह उत्साहपूर्वक किए गए कर्तव्य-कर्म के वेग से थोड़ी सी भी धुल जाए तो एक पवित्रता का भाव आता है, वही परम आनंद है। वही जीवन को सार्थक करने की एक झलक है। स्मरण रहे कि अपना कल्याण साधने के प्रयास हमें ही करने होंगे और इसी देह के भीतर रहते हुए, इसी देह को साधन बनाकर करने होंगे।

त्रिवंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

सरकारी खजाने का हो सदुपयोग

'रेवड़ी संस्कृति का बढ़ता रोग' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगदीप सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर तार्किक ढंग से अपनी बात रखी। दशकों से प्रत्येक चुनावों में सभी राजनीतिक दल तरह-तरह के वादे करते हैं। अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। सबकी यही कोशिश होती है कि आमजन को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सहायता और मुफ्त पेशकश जैसी घोषणाओं से लुभाया जा सके। इन वादों की पूर्ति पार्टियां सत्ता में आने के बाद सरकारी खजाने से करती हैं और कई वादे तो पूरे भी नहीं हो पाते। सरकारी खजाना आम जनता की गाढ़ी कमाई से भरता है, जिसका अनुशासित रूप से व्यय करना ही सही होता है। उसका सदुपयोग किया जाना ही श्रेयस्कर है। याद रहे कि सरकारी खजाने की बंदरबांट से कभी कोई राष्ट्र उन्नति नहीं करता। उलटे ये कदम प्रतिगामी सिद्ध होते हैं। दुनिया में वेनेजुएला से लेकर श्रीलंका तक ऐसे तमाम देशों के उदाहरण हैं, जिन्होंने मुफ्तखोरी की राह पर अपनी दुर्गति कराई है। इसलिए हमारे देश में ऐसा कभी न हो, उसके लिए राजनीतिक दलों को अपना रवैया सुधारना होगा। यदि आवश्यक हो तो इस मामले में चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय भी कोई हस्तक्षेप करें तो वह उपयोगी सिद्ध होगा।

कमल कुमार, लखनऊ

मुसीबत बनी बरसात

बरसात के मौसम में देश के प्रायः सभी शहरों में जल जमाव की समस्या सामान्य बात हो चुकी है। देश के सभी शहरों में जल निकासी व्यवस्था चरमरा चुकी है। संबंधित विभाग प्रति वर्ष जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने का वादा करता है, लेकिन ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। बरसात में मुसीबतों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। शहरों में नदी, नालों का अतिक्रमण कर घर बना लिए जा रहे हैं। प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग की वजह से सभी नदी और नालों के मुहानों पर प्लास्टिक कचरे का अंबार लगा रहता है, इन कचरों की वजह से जल निकासी अवरुद्ध होती है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

कानून का मोल नहीं

अवधेश कुमार का आलेख 'बंगाल में लापता कानून का शासन' पढ़ा। ममता बनर्जी की बंगाल सरकार का हाल देखकर कोई भी समझ सकता है कि सत्ता की भूख और प्रशासन की लाचारी किस कदर हावी हो चुकी है। आर. जी. कर अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ जो हुआ, वह न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इससे न केवल पुलिस तंत्र की विफलता सामने आती है, बल्कि आर. जी. कर अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार भी उजागर होता है। यह भी संभव है कि इस कुकृत्य में और भी लोग शामिल हों। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की बेचारगी को देखकर लगता है कि कानून का कोई मोल ही नहीं बचा है। जब शासन व कानून का डर नहीं होगा, तब तक कुछ लोग अपनी अनैतिक व आपराधिक मानसिकता को अंजाम देते रहेंगे। अपराध के मामले चाहे वह जो भी सरकार को आरोपित को किसी तरह रियायत नहीं देनी चाहिए। कानून का डर लोगों रहे, इसके लिए सख्ती जरूरी है।

डा. पवन कुमार, जनकपुर, गया

बदजुबान होते माननीय

लोकतंत्र में सहमति-असहमति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजनीति की यह पहचान है, लेकिन कोई नेता अगर किसी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट शब्द का प्रयोग करता है तो यह राजनीति में गिरावट का ही संकेत है। राजनीति में आए दिन किसी न किसी राजनीतिक दल के नेता, माननीयों की जुबान फिसलती रहती है, किन्हीं की गलती से फिसल जाती है तो कोई इस तरह की बयानबाजी के लिए ही राजनीति में जाने जाते हैं। ताजा मामला एक अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत का है। उन्होंने एक साक्षात्कार में किसान आंदोलन को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके तत्काल बाद भाजपा ने उनके बयान से किनारा कर लिया। साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें इस तरह के बयान से भविष्य में बचना चाहिए। इससे पहले भी कंगना ने आंदोलनकारी किसानों के बारे में टिप्पणी की थी, जिसकी परिणति हवाईअड्डे पर थप्पड़ कांड के रूप में सामने आई थी। मुद्दों के आधार पर तर्कों के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं के विरुद्ध बयानबाजी करते हुए भाषा में थोड़ी तल्खी या व्यंग्य का इस्तेमाल गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए बदजुबानी या अभद्रता हावी होने लगे तो यह गलत है। अफसोस यह कि इस मसले पर अक्सर विवाद उभरने और ज्यादातर मामलों में माफी मांगने या सफाई देने की नौबत आने के बावजूद राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप प्रत्यारोप बेलगाम बोल में बदल जाता है।

जयप्रकाश नवीन, चंडी, नालंदा

पोस्ट

कंगना रनौत रास्ते बनाना जानती हैं। फिल्मों में भी और राजनीति में भी। उन्होंने अपने बल पर अपने लिए रास्ते बनाए हैं और जो रास्ते बनाना जानते हैं, वे जीवन में कभी विफल नहीं होते। जगदीश भाटिया@jagdish

कुछ ताकतें इस समय टेलीग्राम पर शिकंजा कस रही हैं। कल किसी और प्लेटफार्म की बारी आ सकती है। विवेक रामास्वामी@VivekGRamaswamy

फेसबुक के अनुसार अमेरिका में कोविड महामारी के दौरान कंटेंट को सेंसर किया गया था। वाइडन प्रशासन ने हंटर वाइडन की स्टोरी भी दबाने का दबाव डाला था। इसके बावजूद फ्रीडम इंडेक्स में अमेरिका अव्वल देशों में और भारत 159वें पायदान पर गिना जाता है। मोनिका वर्मा@TrulyMonica

कुछ मीडिया संस्थान यह दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं। यह कुछ ऐसा ही है कि शेर के हवाले से कहा जाए कि जंगल में सभी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। ऐश्वर्या@AishwaryakiRai

रेल यात्रियों की जान लेने की सामने आ रही साजिशें डराने वाली हैं। बेहद चौकस रहने की जरूरत है। देश के ये दुश्मन बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी प्रतीत होते हैं। अरविंद चोटिया@arvindchotia

जनपथ

गिरती जाए चित्त से ममता की सरकार,
क्योंकी सुनती वो नहीं महिला की चीत्कार।
महिला की चीत्कार न सुननेवाला कोई,
सारी सेक्युलर फौज दिख रही सोई-सोई।
जब तक इज्जत खोय रहेगी लड़की मरती,
ममता जी की साख रहेगी यूं ही गिरती।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 137

****

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

सोशल मीडिया भेड़चाल की तरह है। एक व्यक्ति शोर मचाता है, तो हर कोई उसमें शामिल हो जाता है। -अर्ल स्वेटशर्ट

डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या के विरोध में छात्रों के सड़कों पर उतरने और पुलिस से झड़प के दृश्य बताते हैं कि बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक महिला के साथ हुई बर्बरता पर मुख्यमंत्री, नैतिक आधार पर त्यागपत्र भले न दें, मगर कम से कम इतना तो करें कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।

बंगाल में कुछ ठीक नहीं

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या के विरोधस्वरूप मंगलवार को छात्रों व राज्य कर्मचारी संगठनों के लोगों की भीड़ के सड़कों पर उतरने और उनकी पुलिस से झड़प के दृश्य यही जाहिर करते हैं कि दीदी के बंगाल में चीजें ठीक नहीं चल रहीं। दरअसल, बीती आठ अगस्त की रात प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई और नौ अगस्त की सुबह शव मिलने के बाद से ही देश भर में डॉक्टरों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच 13 अगस्त को अपने हाथ में ली थी। उससे पहले दस अगस्त को राज्य पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस बर्बर हत्याकांड में शुरुआत से ही एक से ज्यादा लोगों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। शीर्ष अदालत की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने बेशक जनहित में अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही हैं और चौदह दिन बाद भी यह गुत्थी सुलझ नहीं सकी है, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना उतना ही स्वाभाविक है, जितनी कि लोगों की नाराजगी। एक महिला के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर भी उठते हैं, जो खुद एक महिला हैं और राज्य के स्वास्थ्य व गृह विभाग भी उन्हीं के पास हैं। उतना ही क्षोभकारी एक तृणमूल सांसद का प्रदर्शनकारियों की तुलना पिकनिक मनाने वालों से करना भी है। ममता बनर्जी ने देश में दुष्कर्मों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खत जरूर लिखा है, लेकिन अपने ही राज्य में हुई पूरे देश की चेतना को झकझोर देने वाली वारदात पर उनकी चिर-परिचित आक्रामकता के नदारद होने पर भी सवाल हैं। तथ्य बंगाल की कहानी आप बयां करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और यौन अपराधों

से बच्चों के संरक्षण कानून (पॉक्सो) के 48 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनके त्वरित निपटान के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना पर विचार करने का आग्रह भी किया है। लेकिन, नहीं भूलना चाहिए कि अक्तूबर, 2019 में स्थापित केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पश्चिम बंगाल को जो 123 फास्ट ट्रैक अदालतें आवंटित की गई थीं, उनमें से कोई भी जून, 2023 तक शुरू नहीं हो सकी थी। इस बर्बर घटना पर मुख्यमंत्री नैतिक आधार पर त्यागपत्र भले न दें, लेकिन कम से कम दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाती तो दिखें।

रूस के 'जुकरबर्ग' और टेलीग्राम के रहस्य

टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव की प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं, लेकिन सत्ता विरोधी रवैये के चलते वह एक बार फिर मुश्किल में हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार बेशक उनके बचाव में हैं, लेकिन जब उनके एक्स से भी ज्यादा उपयोगकर्ता हों, तो वह कंटेंट पर नियंत्रण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

पॉल मोजुर
द न्यूयॉर्क टाइम्स

एक दशक से भी अधिक समय पहले, जब रूस ने पावेल डुरोव द्वारा बनाई गई फेसबुक जैसी साइट पर से विपक्षी राजनेताओं के पेज बंद करने का दबाव डाला, तो इस तकनीकी उद्यमी ने ऑनलाइन जवाब देते हुए एक हुडी पहने हुए कुत्ते की जीभ बाहर निकाले हुए एक चुटीली तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने बिना किसी खेद के लिखा, 'समूहों को ब्लॉक करने के अनुरोध पर खुफिया सेवाओं को आधिकारिक प्रतिक्रिया।'

तेरह साल बाद, डुरोव की सत्ता-विरोधी प्रवृत्ति ने उन्हें अधिकारियों के साथ मुसीबतों के एक नए दौर में पहुंचा दिया है। बीते दिनों उन्हें टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। टेलीग्राम एक ऑनलाइन संचार मंच है, जिसकी स्थापना उन्होंने 2013 में की थी, जो अब वैश्विक पहुंच बना चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डुरोव की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है' लेकिन 'कानून का पालन करने वाले मुल्क में, सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन, दोनों में स्वतंत्रता को कानूनी ढांचे के भीतर बरकरार रखा जाता है।'

डुरोव की गिरफ्तारी ने एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सेंसरशिप के बारे में चिंतित लोगों के बीच नायक बन गए हैं, खासकर तब, जब वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सामग्री की निगरानी बढ़ गई है। एक्स के मालिक एलन मस्क और एडवर्ड स्नोडेन उन लोगों में शामिल थे, जो डुरोव का बचाव करने के लिए आगे आए। इस दौरान एक्स पर हैशटैग फ्री पावेल #FreePavel छा गया। टेलीग्राम ने एक बयान में कहा कि वह यूरोपीय संघ के कानूनों का पालन करता है। कंपनी ने कहा, 'यह दावा बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है।' टेलीग्राम लंबे समय से डुरोव के सत्ता-विरोधी लोकाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कायम है। इसने टेलीग्राम को रूस, ईरान और सत्तावादी सरकारों के अधीन रहने वाले अन्य लोगों के लिए एक लोकप्रिय चैट एप बनाने में मदद की। लेकिन प्लेटफॉर्म पर निगरानी नहीं करने के डुरोव के दृष्टिकोण ने आतंकवादियों, चरमपंथियों, बंदूक तस्करों, घोटालेबाजों और ड्रग डीलरों को भी आकर्षित किया है। उनका कहना है कि गोपनीयता ऑनलाइन अभिव्यक्ति की कड़ी निगरानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक पोस्ट में, उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने शुक्राणु दाता के रूप में 12 देशों में 100 से अधिक जैविक बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन डुरोव की सबसे बड़ी प्राथमिकता टेलीग्राम है। वर्ष 2014 में उन्होंने रूस की सुरक्षा सेवाओं की बढ़ती निगरानी के बीच रूस छोड़ दिया और दुबई का रुख किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब से उन्होंने कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर एप्पल और प्रमुख सरकारों के साथ लड़ाई लड़ी है।

टेलीग्राम को 31 देशों में अस्थायी या स्थायी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। डुरोव ने एफबीआई पर एक टेलीग्राम प्रोग्रामर को काम पर रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया, ताकि अमेरिकी सरकार उपयोगकर्ताओं के डाटा तक पहुंच बना सके। एफबीआई ने इस पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। वर्ष 1984 में सोवियत संघ में जन्मे डुरोव चार साल की उम्र में ही अपने परिवार के साथ उत्तरी इटली चले गए। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद वह सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। कॉलेज में एक दोस्त ने डुरोव को फेसबुक का शुरुआती संस्करण दिखाया, जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इससे प्रेरित होकर डुरोव ने अपना खुद का संस्करण बनाने का फैसला किया। उन्होंने वीके (Vkontakte) की शुरुआत 2006 में की थी, जो कुछ ही वर्षों में रूस में छा गया। इसने क्रेमलिन का भी ध्यान आकर्षित किया, जिसने इसके उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगी।

डुरोव ने कहा कि उन्होंने 2011 के आसपास रूसी सुरक्षा बलों को अपने अपार्टमेंट के आसपास देखने के बाद टेलीग्राम का निर्माण शुरू किया था। सरकार ने अंततः उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो वे वीके के उपयोगकर्ताओं से संबंधित डाटा सौंप दें या देश छोड़कर चले जाएं। रूस से नाता तोड़ने के बाद से डुरोव टेलीग्राम इंजीनियरों से घिरे हुए घुमक्कड़ जीवन जीने लगे। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि वह हर कुछ महीनों में अपनी जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने बार्सिलोना, बाली, बर्लिन, हेलसिंकी और सैन फ्रांसिस्को में समय बिताया है, जबकि दुबई को टेलीग्राम का औपचारिक मुख्यालय बनाया है। डुरोव के पास संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की नागरिकता है। हालांकि वह निजी जेट से यात्रा करते हैं, लेकिन चीजें खरीदने से बचते हैं। वह अपने बैंक खाते में करोड़ों डॉलर और बिटकॉइन रखते हैं, ताकि आजाद रह सकें। ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया है कि उनकी कुल संपत्ति नौ अरब डॉलर से ज्यादा है।

टेलीग्राम अब दुनिया भर में एक अरब उपयोगकर्ताओं के करीब पहुंच रहा है, जो इसे एक्स से बड़ा बनाता है। जैसे-जैसे टेलीग्राम का इस्तेमाल बढ़ता गया, डुरोव द्वारा कंटेंट की निगरानी के लिए अपनाए गए हल्के-फुल्के तरीके की आलोचना होने लगी। नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कहा कि यह एप गलत सूचना, आतंकवाद के प्रचार, दक्षिणपंथी उग्रवाद, ड्रग डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हथियारों की बिक्री का अड्डा बन गया है। वर्षों तक डुरोव ने सिलिकॉन वैली के अपने साथियों की तरह सार्वजनिक जांच से काफी हद तक परहेज किया, जबकि जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई और टिकटॉक के शू च्यू को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया गया है, डुरोव और उनके इंजीनियरों ने चलते-फिरते टेलीग्राम को बनाए रखा और अपडेट करते रहे। एक बार तो उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट के बारे में अपडेट तब जारी किया, जब वे दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र में एक नाव पर सवार थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम ने कुछ सामग्री हटाई है, जैसे कि बाल यौन शोषण सामग्री या हिंसा भड़काने के उद्देश्य से किए गए पोस्ट। लेकिन अधिकारी हमेशा ही डुरोव के सहयोग की कमी से निराश रहे, जिसका खामियाजा डुरोव अब भुगत रहे हैं।

-साथ में एडम सटेरियानो। ©The New York Times 2024

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

जेम्स एलन

शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो पहले मन की रक्षा करें। शरीर को नया बनाना चाहते हैं, तो मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं।

सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे

मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है, उसके पीछे जाने-अनजाने में बोया गया विचार का बीज छिपा होता है। हम जैसा कार्य करते हैं, वैसा ही उसका परिणाम आता है। परिस्थितियों के अनुसार, हम दुख या सुख महसूस करते हैं, वह हमारे विचारों का फल ही होता है। कई बार हम निराश होते हैं और पता ही नहीं होता है कि हम क्यों निराश हैं? हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि कहीं न कहीं हमने कोई न कोई विचार जरूर बोया है। उसी के फल के परिणामस्वरूप हमें निराशा महसूस होती है। इसलिए अब हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे। साथ ही उसके परिणाम के लिए धैर्यवान रहना होगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें रोजी-रोटी के लिए हर दिन काम करना पड़ता है और वे खुश हैं। इसका मतलब है कि खुशी बाहर के रंगीन दिखावे से नहीं मिलती है। अगर किसी इन्सान के दिमाग में बुरे विचार आते हैं, तो उसके जीवन में पीड़ा आना स्वाभाविक है। वहीं, अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा सकारात्मक विचारों में लगा देते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी परछाईं की तरह आगे-पीछे घूमेगी।

विचारहीन, अज्ञानी और आलसी लोग चीज के बजाय केवल प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हैं। साथ ही वे कानून, भाग्य और संयोग की बातें करते हैं। किसी व्यक्ति को अमीर या बुद्धिजीवी बनते देखकर वे कहते हैं, 'कितने भाग्यशाली हैं।' और किसी दूसरे के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को देखकर कहते हैं कि संयोग हर मोड़ पर उसकी सहायता करता है। ऐसा कहने वाले उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं, जिनका सामना इन लोगों ने अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया है। उन्हें उन बलिदानों का कोई ज्ञान नहीं है, जो उन्होंने किए हैं, उन निडर प्रयासों का, जो उन्होंने किए हैं। वे अंधकार और हृदय के दर्द को नहीं जानते हैं। वे केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं, और इसे 'भाग्य' कहते हैं। वे कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं, बल्कि केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं, और इसे 'सौभाग्य' कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखते हैं, और उसे 'संयोग' कहते हैं। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर को नया बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच के अभ्यास द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है।

संदेह और भय पर विजय पाएं

सूत्र

मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जिसने संदेह और भय पर विजय पा ली है, उसने असफलता पर विजय पा ली है। आज अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन पानी में एक पत्थर फेंककर कई लहरें पैदा कर सकते हैं।

दूसरा पहलू

न्यूयॉर्क शहर से पांच गुना आकार का एक हिमखंड गोल-गोल घूम रहा है। यह कब रुकेगा, कोई नहीं जानता।

अंटार्कटिक के विशाल हिमखंड की गुत्थी

तीस वर्षों से भी अधिक समय तक दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिक में फंसा रहा। न्यूयॉर्क शहर से पांच गुना बड़ा व एक हजार फुट से भी अधिक गहरा यह विशाल हिमखंड अंततः वर्ष 2020 में पिघलने लगा और दक्षिण महासागर की ओर धीमी गति से बहने लगा। अब ए23ए नाम का यह हिमखंड अपनी जगह पर घूम रहा है।

रेमी तुमिन

अंटार्कटिक के पानी से निकलकर यह हिमखंड पानी के नीचे पहाड़ पर एक भंवर में फंस गया है और वहीं पर 24 दिनों में एक चक्कर घूमता है।

ए23ए 1986 के अंत में टूट गया और वेडेल सागर में नीचे चला गया, जहां यह अगले 34 वर्षों तक रहा। वर्ष 2020 में इसने खुद को मुक्त किया।

अंटार्कटिक जल से निकलकर यह हिमखंड पानी के नीचे एक पहाड़ यानी समुद्री पर्वत पर एक भंवर में फंस गया है। कल्पना कीजिए कि करीब 1,500 वर्ग मील क्षेत्रफल और एंपायर स्टेट बिल्डिंग जितनी गहराई वाला हिमखंड धीरे-धीरे, परंतु इतनी तेजी से घूम रहा है कि लगभग 24 दिनों में यह पूरी तरह से अपने सिर पर घूम सके। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण, ब्रिटेन के ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिमखंड अंटार्कटिक प्रायद्वीप से लगभग 375 मील उत्तर-पूर्व में दक्षिण ऑर्कनी द्वीप समूह के पास घूम रहा है, जो प्रतिदिन 15 डिग्री परिक्रमा के साथ ठंड बनाए रखता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में ओपन ओशन्स रिसर्च ग्रुप के प्रमुख और भौतिक महासागर विज्ञानी एलेक्स ब्रियरली ने कहा, 'यह मूल रूप से बस वहीं घूम रहा है और जब तक यह वहां रहेगा, बहुत धीरे-धीरे पिघलेगा। हम नहीं जानते कि यह वास्तव में कब इससे बाहर निकलेगा।'

ए23ए शुरू से ही इस नाटक में उलझा हुआ है, यह विशेषता इसे अपने मूल हिमखंड से मिली है। ए23ए मूलतः बेहद विशाल ए 23 हिमखंड से निकला है, जो उन तीन हिमखंडों में से एक था, जो 1986 में फिल्चनर आइस शेल्फ से टूट गए थे। टूटने के समय ए23 सोवियत संघ के अनुसंधान केंद्र का घर था, नतीजतन शोधकर्ताओं को उसे छोड़ना पड़ा। उसी वर्ष बाद में ए23ए टूटा और वेडेल सागर में नीचे चला गया, जहां यह अगले 34 वर्षों तक फंसा रहा। वर्ष 2020 में अंततः ए23ए ने खुद को मुक्त किया। यह इतना बड़ा है कि पिछले दिसंबर में डॉ. ब्रियरली और एक शोध पोत को इस हिमखंड का चक्कर लगाने में पूरा दिन लग गया। वह इसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह जमीन की तरह दिखता है। वसंत ऋतु तक ए23ए ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हुए ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने पहली बार अप्रैल में हिमखंड को घूमते हुए देखा। उन्होंने कहा कि यह हिमखंड पिघलेगा नहीं और इससे समुद्र का जलस्तर भी नहीं बढ़ेगा। डॉ. ब्रियरली ने कहा कि चाहे कुछ भी हो अंटार्कटिका के किनारे और रहस्य हमें आकर्षित करते रहेंगे। ©The New York Times 2024

आंकड़े

कोयला उत्पादन

भारत में बिजली उत्पादन में करीब 50 फीसदी कोयले का इस्तेमाल होता है। झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है।

झारखंड	26.4%
ओडिशा	25.1%
छत्तीसगढ़	18.1%
पश्चिम बंगाल	10.8%
मध्य प्रदेश	9.8%

7.3 फीसदी के साथ तेलंगाना छठे स्थान पर है। | स्रोत : cco

सत्यवती को दिए वचन की खातिर पितामह भीष्म ने परशुराम के काफी समझाने पर भी अंबा से विवाह नहीं किया, तो गुरु-शिष्य के बीच तेईस दिन भीषण युद्ध हुआ।

भीष्म ने किया गुरु परशुराम से युद्ध

अंतर्यात्रा
संकलित

पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से आठों वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें सात तो गंगा जी ने पैदा होते ही जल में बहाकर शाप से मुक्त कराए।

वसु के अंशावतार भीष्म को शांतनु ने रख लिया। एक बार भगवान परशुराम ने भीष्म से यह आग्रह किया कि तुम काशिराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो। परशुराम जी भीष्म के गुरु थे। उन्होंने कहा कि गुरुवर! 'मैंने राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है। इसलिए आपकी आज्ञा पूरी करने में असमर्थ हूं।' भीष्म ने कहा, 'मैं त्रिलोक का राज्य छोड़ सकता हूं, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता।' बहुत समझाने पर भी भीष्म नहीं माने, तो परशुराम क्रोध करने लगे। इस पर भीष्म ने कहा-आप कहते हैं, 'मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को इक्कीस बार जीत लिया था, उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या मेरे समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था।' यह सुनते ही परशुराम जी कुपित हो गए और युद्ध छिड़ गया। गुरु-शिष्य के बीच तेईस दिन तक भयानक युद्ध हुआ, तो देवताओं को बीच में आना पड़ा। देवताओं के समझाने पर युद्ध रुका। उल्लेखनीय है कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए सत्यवती को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 जुलाई, 1958

लेबनान में हस्तक्षेप के लिए प्रतिबद्ध ब्रिटेन और अमेरिका

ब्रिटेन व अमरीका लेबनान में हस्तक्षेप करने को दृढ़
तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी उठाने को तयार : श्री सेलार का बयान

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इमेनुअल सेलार ने कहा, 'यदि संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करता है, तो अमेरिका और ब्रिटेन लेबनान की मदद के लिए तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा उठाने को तैयार हैं। हम लेबनान में हस्तक्षेप करेंगे।'

पेंशन, चिंताएं और बीच का रास्ता

पेंशन योजनाओं में हमेशा विवाद रहा है। ऐसे में पहले की दोनों योजनाओं की अच्छी बातों को शामिल करती यूपीएस आशा की किरण दिखाती है।

केएस तोमर | **मुद्दा**

करीब दो वर्ष पहले प्रख्यात अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कुछ पार्टियों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की ओर बहाली के वादे को 'नैतिक रूप से गलत' और 'पाप' बताते हुए कहा था कि इससे केंद्र और राज्यों की अगली सरकारों पर देनदारी का दबाव बढ़ेगा।

पनगढ़िया के इस दृढ़ दृष्टिकोण को पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और पूर्व सीएजी राजीव महर्षि ने भी राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 में ओपीएस की ओर लौटने का फैसला करने पर कहा था कि यह वित्तीय रूप से आत्मघाती कदम होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी ओपीएस चुनने वाले राज्यों को चेतावनी दी थी कि यह भविष्य में अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा।

इसी पृष्ठभूमि में हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लेकर आई है। राज्यों के कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए भाजपा शासित राज्य इसे तत्काल या निकट भविष्य में अपना सकते हैं। 2003 में वाजपेयी सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस लागू की थी, जिसे तत्कालीन भाजपा सरकारों ने लागू किया था, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को लेकर कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यूपीएस कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे मोदी सरकार का यूटर्न बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब दबाव में हो रहा है। साथ ही मूल वेतन के 50 फीसदी के बजाय 100 फीसदी पेंशन देनी चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं ने कहा कि अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण न कर राज्यों को भी यूपीएस लागू करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ओपीएस का विकल्प अच्छा है, लेकिन हमें व्यावहारिक होना चाहिए।

यूपीएस एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी और इसे लागू करने वाला एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) शासित महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। एनडीए के शीर्ष पदाधिकारियों के अनुसार, ओपीएस और एनपीएस का मिश्रित स्वरूप है यूपीएस, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय जिम्मेदारी और सुरक्षा, दोनों प्रदान करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 से मार्च 2023 तक तीन वर्षों में 28 राज्यों की बकाया पेंशन देनदारियां 43 फीसदी से अधिक बढ़ गईं, जो चिंताजनक है, क्योंकि इससे भविष्य में आर्थिक संकट हो सकता है।

राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सराकर ने ओपीएस लागू की है, लेकिन इससे राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो गया है और वह केंद्र से आर्थिक सहायता मांग रहा है। ऐसा ही राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने किया था और केंद्र सरकार से 37,000 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था। यूपीए सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी राज्यों द्वारा ओपीएस लागू करने को बेतुका बताया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन की देनदारियां बढ़ी हैं। केंद्र सरकार का अनुमानित पेंशन बिल 2024-25 के लिए लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य सरकारों के लिए संयुक्त अनुमानित पेंशन बिल 2024-25 में लगभग 5.73 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह राज्यों के बजट के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जैसे कुछ राज्यों पर विशेष रूप से बड़ी पेंशन देनदारियां हैं।

यूपीएस कर्मचारी और सरकार, दोनों के संयुक्त पेंशन फंड में योगदान का मॉडल है। ओपीएस के विपरीत यूपीएस एक वित्त पोषित योजना है। पेंशन का बढ़ता बोझ चिंता का कारण है, क्योंकि इससे विकास और कल्याण के काम सीमित हो जाते हैं। कैग ने भी राज्यों और केंद्र सरकार को पेंशन सुधारों पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जैसे कि इन बढ़ती लागतों को प्रबंधित करने के लिए परिभाषित लाभ से परिभाषित योगदान योजनाओं में बदलाव, जो यूपीएस में परिलक्षित होता है।

edit@amarujala.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

यूएलआइ की चुनौतियों का समाधान भी जरूरी

भारतीय रिजर्व बैंक की यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआइ) डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा किसानों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन कर्ज लेना आसान हो जाएगा। यह यूपीआइ जैसा एक नया सिस्टम होगा। यह आधार कार्ड, केवाइसी, भूमि के सरकारी रिकॉर्ड, पैन नम्बर जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े जुटाएगा। इससे आवेदक के लोन लेने की क्षमता का आकलन हो सकेगा। कर्ज देने वाले दूसरे निजी ऐप और यूएलआइ में अंतर इतना होगा कि इस ऐप पर आरबीआइ का पूरी तरह से नियंत्रण होगा।

माना जा रहा है कि यूएलआइ से छोटे व्यापारियों और किसानों को बैंकों व निजी वित्तीय संस्थाओं की परंपरागत रूप से जटिल और समय लेने वाली ऋण प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकेगी। पर किसानों और छोटे व्यापारियों में डिजिटल साक्षरता की कमी होने पर उन्हें इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। विशेष रूप से सीमित कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा का पूरा उपयोग नहीं हो पाने की चुनौती आ सकती है। डिजिटल साक्षरता की कमी के चलते कर्ज की शर्तों को समझने में छोटी-सी चूक छोटे किसानों और व्यापारियों को बड़े कर्ज तले दबा सकती है। इस सुविधा के जरिए आरबीआइ कर्ज लेना आसान कर रही है तो कर्ज चुकाना आसान कैसे हो, इस पर भी मंथन किया जाना चाहिए। आरबीआइ को ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित करते समय विशेष ध्यान रखना होगा ताकि ऋण आसानी से चुकाया जा सके। बड़े व्यापारी तो योजनाबद्ध तरीके से बड़े कर्ज लेते रहते हैं। थोड़ा भुगतान करके फिर लोन ले लेते हैं। ब्याज का पैसा कम चुकाने, बार-बार कर्ज लेने और साख बनाए रखने के लिए वे ऐसा क्रमबद्ध रूप से करते रहते हैं। कई बार तो वे सरकार से कर्ज माफ भी करवा लेते हैं। छोटे किसानों और व्यापारियों की ऐसी पहुंच नहीं होने से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आरबीआइ के इस कदम का स्वागत करना चाहिए कि उसने कर्ज लेना आसान बना दिया है। लेकिन छोटे व्यापारियों को इस इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे वास्तविक जरूरतों के अनुसार ही ऋण लें। ऋण चुकाने में असमर्थ होने की स्थिति से बचना होगा।

आरबीआइ को भी इस सुविधा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा। यह सुविधा कितनी लाभदायक होगी, यह तो समय बताएगा लेकिन ऐसी प्रक्रिया तो निर्धारित होनी ही चाहिए जिसमें छोटे किसानों और व्यापारियों को नुकसान न होने पाए। यूएलआइ प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग किया गया तो यह भारत की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारतीय संसदीय प्रणाली : विकासक्रम में कुछ विकृतियां आ चुकी हैं, जिन्हें दूर करना ही होगा

लोकतंत्र पर हावी न हो राजनीति, सत्ता और बाजार

कैलाश चन्द कांण्डपाल
राज्य प्रमुख, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, झारखण्ड
@patrika.com

जागरूक मतदाता बनाने के लिए नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति विस्तृत समझ व लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का होना बहुत जरूरी है और यह बेहतर शिक्षा से ही आएगा। स्वस्थ समाज के लिए बेहतर शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। यह शिक्षा हर स्तर पर हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से 'एक देश-एक चुनाव' की बात छेड़ी और यह जताया कि उनकी सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। दूसरी ओर, जब तक इसे लागू करने की जमीन पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, देश में चुनावों का सिलसिला यों ही जारी रहेगा। इस वर्ष पहले जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव होने हैं। देश में जब-जब चुनाव की बात होती है, संसदीय प्रणाली और इसके इर्द-गिर्द विकसित होती राजनीति, सत्ता और बाजार के प्रभाव पर मंथन की जरूरत शिद्दत से महसूस की जाती है, क्योंकि आजाद भारत की 77 वर्षों की यात्रा में भारतीय संसदीय प्रणाली में ऐसे कई विचलन आ चुके हैं, विकास क्रम में जिनका आना तो स्वाभाविक है पर इन पर ध्यान देना और इनका निवारण करना भी जरूरी है।

दो विचलन उल्लेखनीय हैं। पहला विचलन चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि दूसरा विचलन राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा है और लोकतंत्र अपनाने के बाद देश में सत्ता हासिल करने वाली हर पार्टी ने इस विचलन को लाने में अपना समुचित योगदान दिया है। समय रहते इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र की विकृति का कारण बन सकते हैं। संसदीय प्रणाली में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का आशय यह है कि वह जनप्रतिनिधि स्वयं या अपने राजनीतिक दल के माध्यम से शासन व्यवस्था में अपना योगदान देगा तथा अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगा। समय के चलते प्रतिनिधि को चुनना गौण हो गया है और चुनाव प्रक्रिया में इस विचलन के लिए राजनीतिक दल और मतदाता समान रूप से जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रक्रिया में अब प्रतिनिधि का क्षेत्र विशेष से होने की आवश्यकता को अब आवश्यकता नहीं समझा जाता है क्योंकि उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण सीट जीतना हो गया है। इस चुनाव प्रक्रिया में दूसरी बात बाजार के प्रभाव की है। आज यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि चुनाव जीतना एक तरह का इवेंट मैनेजमेंट बनता जा रहा है और इस क्षेत्र में आज कई कंपनियां जोर आजमाइश कर रही हैं। लोकलुभावन नारे व प्रलोभन तैयार करना, मतदाता को आकर्षित करना और कैसे भी भीड़ जुटाकर जीत के लिए माहौल बनाना इसमें शामिल है। बाजार से लोकतांत्रिक मूल्यों को पुष्ट करने की अपेक्षा करना बेमानी है, क्योंकि बाजार का अपना चरित्र होता है, जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि होती है। इसलिए लोकतंत्र के चुनाव में बाजार का प्रवेश एक गंभीर मसला है जो कि अच्छा लक्षण नहीं है।

भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों द्वारा केन्द्र में सत्ता प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य होता है क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था में केन्द्र की तरफ शक्ति का स्पष्ट झुकाव है। केन्द्र के कई महत्त्वपूर्ण संस्थान इस सत्ता के प्रभाव में आते दिखते हैं भले ही उनमें स्वायत्तता का पुट हो। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और राजनीति में बाजार का प्रभाव, ये दोनों बातें अलग-अलग दिखती हैं पर ये मिलकर लोकतंत्र को कमजोर बनाने में भरपूर योगदान देती हैं। सत्ता के दुरुपयोग से जहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, वहीं बाजार ऐसी सत्ता को प्राप्त करने और बनाए रखने में अपना योगदान देता है।

अब सवाल यह उठता है कि बेहतर लोकतंत्र बनाए रखने के लिए आशा की किरण कहां पर है। यह पूरा प्रकरण इतना नकारात्मक भी नहीं कि इससे निजात नहीं मिल सकती। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है एक अंतराल के बाद चुनाव की प्रक्रिया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतदाता जागरूक होंगे तो राजनीतिक दल भी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं अपनाने के लिए मजबूर होंगे। न्यायपालिका और मीडिया की भी विचलन को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

निष्कर्ष यह है कि कोई भी प्रणाली हो, समय-समय पर समीक्षा जरूरी है। विचलन को नजरअंदाज करने के दूरगामी परिणाम देश के नागरिकों को ही भुगतने होंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में देखने का संकल्प लिया है। जरूरत है कि एक नागरिक के तौर पर हम इस संकल्प को सच्ची भावना के साथ फलीभूत करने में अपने योगदान के प्रति सजग हों। इसी से हमारा देश एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बना पाएगा।

फैक्ट फ्रंट

हैरिस हॉक

हैरिस हॉक, जिसे पहले बे-विंग्ड हॉक, डस्की हॉक और कभी-कभी वुल्फ हॉक के नाम से जाना जाता था, और लैटिन अमरीका में प्यूको के नाम से जाना जाता है, एक मध्यम से बड़े आकार का शिकारी पक्षी है जो दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमरीका से लेकर चिली, मध्य अर्जेंटीना और ब्राजील तक अपनी प्रजाति को बढ़ाता है। जॉन जेम्स ऑडबोन ने अपने पक्षीविज्ञान साथी, वित्तीय समर्थक और मित्र एडवर्ड हैरिस के सम्मान में इस पक्षी को यह नाम दिया। हैरिस हॉक को समूह में शिकार करने के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य शिकारी पक्षी अक्सर अकेले शिकार करते हैं। उनकी इस सामाजिक प्रकृति का कारण है उनकी बुद्धिमत्ता।

सूचना प्रौद्योगिकी : देश की अर्थव्यवस्था को मिल रही है मजबूती

वैश्विक आइटी हब के रूप में उभरता जा रहा है भारत

कल्याण शर्मा
सूचना तकनीकी विशेषज्ञ एवं लेखक
@patrika.com

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। एक समय कृषि को ही देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ माना जाता था, परन्तु विगत कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास और नवाचार ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। तेजी से बढ़ती सूचना क्रांति ने एक नए युग की शुरुआत की है जिसने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है एवं वैश्विक पटल पर भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अपना सफर 1980 में प्रारम्भ किया था जिसे 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने नई ऊर्जा दी, जो 2024 तक आते आते वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। आज देश की तरक्की में आइटी का न केवल बहुत बड़ा योगदान है बल्कि रोजगार सृजन में भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे, नोयडा, गुरुग्राम जैसे शहर तेजी से वैश्विक आइटी हब के रूप में उभर रहे हैं।

आइटी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन की बढ़ती मांग के फलस्वरूप देश विदेश में भारतीय आइटी पेशेवर एवं विशेषज्ञों की मांग वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इससे 2028 तक लगभग 6 मिलियन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। वर्तमान में उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग ने भारत के आइटी परिदृश्य को पुनः नया आयाम, आकार और दिशा दी है।

एक अनुमान के आधार पर 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान 957 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। ब्लॉकचेन तकनीक से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण एवं वित्तीय लेनदेन में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बुनियादी ढांचे को सक्षम करने, फसल निगरानी में सुधार करने और औद्योगिक क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से स्मार्ट शहरों, कृषि और विनिर्माण को प्रभावित करने की उम्मीद है। इसी तरह 5 जी तकनीक बेहतर कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट स्पीड के कारण इंटरनेट की दुनिया में वरदान साबित हो रही है। भविष्य में स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक नवाचारों को भी नई दिशा मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर गणनाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक नई अविश्वसनीय शक्ति प्रदान का रहा है। देश में इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन्स की स्थापना की गई है। आइटी क्षेत्र को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को मजबूती के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने और ई-गवर्नेंस में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी हार्डवेयर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया गया है।

देश के सतत और समावेशी विकास के नए आयामों को अर्जित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अतुलनीय योगदान है। इससे न केवल उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आइटी के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और ई-गवर्नेंस जैसे सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाना संभव हुआ है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आई है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार किए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके परिणामस्वरूप आज देश वैश्विक आइटी हब के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है।

विरासत का आकर्षण : पराग्वे में फिर एक बार

प्लेटफॉर्म पर पहुंचा 1861 का स्टीम इंजन!

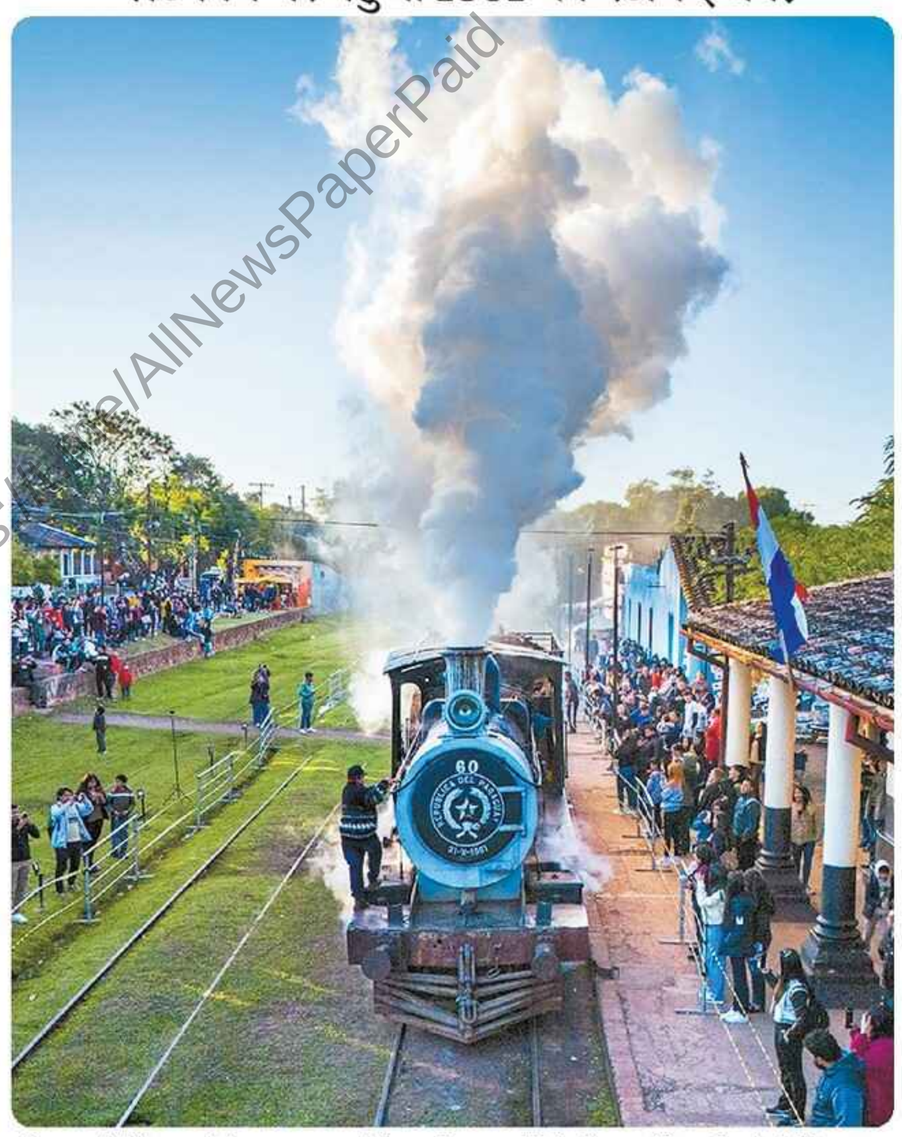

दक्षिण अमरीकी देश पराग्वे के शहर यपाकाराई में हाल ही एक प्रदर्शनी के दौरान स्कॉटिश स्टीम लोकोमोटिव 60 उर्फ 'एल इंगल' का संचालन किया गया। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस लोकोमोटिव का संचालन मूल रूप से 21 अक्टूबर 1861 को शुरू किया गया था। यपाकाराई के स्टेशन पर इस लोकोमोटिव के संचालन को शामिल करते हुए कार्यक्रमों के आयोजन का यह दूसरा साल है। गत वर्ष स्टीम लोकोमोटिव को संचालन योग्य बनाने के लिए कुछ सुधार कार्यों को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लोकोमोटिव से 500 मीटर की दूरी तय की गई थी।

प्रसंगवश

जल सहेजने के ठोस जतन करने होंगे रेगिस्तानी इलाकों में

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर किए गए दावों और हकीकत में काफी फर्क है... वर्षा जल बर्बाद हो रहा है

रेगिस्तान में पानी की कीमत यहां राजस्थान के मरु इलाकों में रहने वालों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पशुओं के साथ जुतकर पानी खींचने के दृश्य बाड़मेर-जैसलमेर में अब भी आम हैं। गर्मियों में तो दोनों जिलों के कई गांवों में सरकार को टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। जलसंकट का एक मात्र समाधान नहरी पानी नजर आता है पर वह भी बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है। ऐसे में ध्यान जलसंरक्षण के प्रयासों की तरफ ही जाता है।

एक दौर था जब रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा के लिए लोग तरसते थे। अब वह दौर है जब वर्षा जल व्यर्थ बहता नजर आता है। ऐसे में दर्द होना स्वाभाविक है। रेगिस्तानी इलाके में कभी दस में से सात साल अकाल के रहते थे लेकिन वर्ष 2001 के बाद स्थितियों में बदलाव आने लगा। वर्ष 2006 में तो कवास और मलवा की बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। हालत यह है कि बीते दशक में लूणी नदी अजमेर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर को पार करते हुए जालोर तक कई बार बही है। चिंता इस बात की है कि अथाह जलराशि धोरों को चीरते हुए कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। बरसाती पानी से गांवों में तालाब भरने से राहत जरूर मिलती है लेकिन बड़ी मात्रा में वर्षा जल बर्बाद भी हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर सरकारी स्तर पर किए गए दावे और हकीकत में काफी फर्क नजर आता है।

बरसाती पानी को सहेजने का कोई बड़ा काम इस इलाके में हुआ ही नहीं, जबकि जैसलमेर में तो पालीवालों ने वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी व्यवस्था सदियों पहले ही कर दी थी। जैसलमेर- कुलधरा के आसपास के इलाके के सारे तालाबों को इस तरह बनाया कि एक के बाद एक तालाब भरते हुए पानी का बहाव आगे तक जाता है। इसी सिस्टम के चलते बरसों तक जैसलमेर में पेयजल समस्या का हल हुआ। बाड़मेर के 108 तालाबों को इसी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा, तो ये तालाब आज भी एक के बाद एक भरते हैं और छह से बारह मास पानी रुकता है। सवाल यही है कि आज इंजीनियरिंग से भरपूर सरकारी मशीनरी के पास में ऐसी कोई योजना क्यों नहीं है? लूणी नदी के पानी को घाट या बांध बनाकर बीच रास्ते के समदड़ी, बालोतरा, जसोल, तिलवाड़ा में सालभर तक रोका क्यों नहीं जा रहा है? सरकार इसी बरसाती पानी को सहेजने पर ध्यान दे तो गर्मियों में कुछ राहत तो लोगों को मिल सकती है।

- रतन दवे
ratan.dave@in.patrika.com

अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव : कोविड जैसी घटनाएं यह सबक देती हैं कि जीवन के लिए जोखिम कितने व्यापक हो सकते हैं

सामाजिक सुरक्षा के वास्तविक उद्देश्य समझें नागरिक

कैथरीन एनी एडवर्ड्स
लेबर इकोनॉमिस्ट और इंडिपेंडेंट पॉलिसी कंसलटेंट
ब्लूमबर्ग
'द वाशिंगटन पोस्ट' से विशेष अनुबंध के तहत

सामाजिक सुरक्षा के लिए इस समय जैसे नेता की जरूरत है, वॉल्ज यथार्थ रूप से उसी प्रकार के राजनेता हैं। सामाजिक सुरक्षा बड़ा पात्रता कार्यक्रम है, फिर भी यह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मुद्दा नहीं है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी नामांकन को स्वीकार करते हुए मिनेसोटा राज्य के गवर्नर टिम वॉल्ज ने अपने सम्बोधन में राजनीति में आने से पहले की अपनी जिन्दगी के बारे में बातें कीं। उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में बताया कि किस तरह फेफड़ों के कैंसर से लम्बे समय तक जूझने के बाद उनकी पिता की मौत हुई। वॉल्ज ने कहा- 'बीमारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा उत्तरजीवी लाभों ने मदद की, इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूं।' दरअसल, वॉल्ज अक्सर ही चर्चा करते हैं कि किस तरह इस कार्यक्रम ने उन दिनों उनके परिवार को मजबूती दी और गरीबी की जगह 'सम्मान के साथ जीने की राह' मिली। उन्होंने 2018 में गवर्नर पद के लिए मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चुनावी अभियान में भाग लेने के दिनों को भी याद किया। सामाजिक सुरक्षा के लिए इस समय जैसे नेता की जरूरत है, वॉल्ज यथार्थ रूप से उसी प्रकार के राजनेता हैं। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल के साथ देश के दो सबसे बड़े पात्रता कार्यक्रमों में एक है, फिर भी यह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मुद्दा नहीं है।

एक कंजर्वेटिव ग्रुप-हैरिटेज फाउंडेशन एक व्यापक कार्ययोजना को नए रूप में लाने की अगुवाई कर रहा है जिसे प्रोजेक्ट-2025 कहा जाता है। इसे लम्बे समय से सामाजिक सुरक्षा को एक स्वैच्छिक बचत कार्यक्रम बनाने के रूप में प्रस्तावित किया गया है कि कामगार इसमें हिस्सा न लेने का चयन कर सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि लम्बी अवधि में कामगारों के लिए बेहतर स्थिति होगी कि वे अपनी आमदनी का 6.2 प्रतिशत निवेश करें जो उनकी खुद की सामाजिक सुरक्षा में जाएगा। हालांकि, वॉल्ज की कहानी यह साफ करती है कि ऐसा तर्क दोषपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है बल्कि बीमा प्रोग्राम है और बदले में संरक्षण है, डॉलर नहीं।

ईमानदारी से कहा जाए तो अधिकांश लोगों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति समझ गलत नहीं है बल्कि अधूरी है। कामगार जब अपनी आय के 6.2 प्रतिशत हिस्से का टैक्स कैप में योगदान करते हैं तो वे रिटायर होने पर अपने लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को अर्जित कर रहे हैं। इस नजरिए से, सामाजिक सुरक्षा गारंटीशुदा रिटर्न के साथ जबरन बचत की तरह है।

वॉल्ज सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आए क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई, वह 19 साल के थे। लेकिन उनकी मां और छोटे भाई को यह सुरक्षा मिली। आज यूएस में उनके जैसे 5.8 मिलियन उत्तरजीवी बीमा लाभार्थी हैं। यूएस के जनगणना ब्यूरो का अनुमान है कि सामाजिक सुरक्षा 1.3 मिलियन बच्चों और 7.5 मिलियन गैर-बुजुर्गों को गरीबी से उबारती है। तुलनात्मक रूप से, यह 1.4 मिलियन बच्चों के समान है जिन्हें पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम, जिसे फूड स्टैंम्प भी कहा जाता है, द्वारा गरीबी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

यह आश्चर्य की बात नहीं कि अमरीका के लोग सामाजिक सुरक्षा कवरेज वाले गैर-सेवानिवृत्त हिस्से पर विचार नहीं करते हैं। कुछ लोग ही सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु या विकलांग होने की आशंका पर ध्यान दे पाते हैं। पिछले दो दशकों में, दुर्भाग्य से सामूहिक मौत की दो घटनाएं देखी गईं- ओपियोइड ओवरडोज (नशीले पदार्थों की काफी अधिक मात्रा) के कारण बड़ी संख्या में मौतें और कोविड। सामाजिक सुरक्षा के 'शैडो' बाल लाभार्थी भी हैं। श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10 प्रतिशत अमरीकी बच्चे अपने दादा-दादी या नानी-नाना के साथ रहते हैं और 2021 तक 3 प्रतिशत यानी 2.3 मिलियन का पालन-पोषण इन लोगों पर ही निर्भर था। ये बच्चे आश्रित के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए तभी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं जब इन्हें उनके ग्रांड-पेरेंट्स ने गोद लिया हो। नहीं तो, वे सिर्फ ऐसे घर में रहते हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा आय का एक बड़ा स्रोत है।

भले ही टिम वॉल्ज सामाजिक सुरक्षा उत्तरजीवी लाभों के लिए अब पात्र नहीं हो सकते, पर उनकी कहानी उन लाखों माता-पिता और उनके बच्चों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है जो दुर्भाग्य से सामाजिक सुरक्षा लाभ लेने के लिए मजबूर हैं, पर वे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम मौजूद हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्र के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का महत्त्व समझना चाहिए। यदि वे नहीं समझेंगे तो उनका बचाव भी नहीं कर पाएंगे।

आपकी बात

बच्चों के साथ संवाद की कमी

बच्चों और किशोरों का व्यवहार आक्रामक होने का मुख्य कारण बच्चों के साथ संवाद की कमी और इंटरनेट पर अनर्गल सामग्री देखना है। जब बच्चे अपने आपको अकेला महसूस करते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं।

-विष्णु पटेल, उदयपुर

आज का सवाल

क्या पानी का अपव्यय रोकने के लिए पेयजल की दरों में बढ़ोतरी जैसे उपाय कारगर होंगे?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'बच्चों और किशोरों का व्यवहार आक्रामक क्यों हो रहा है?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/qet3I

इसे स्कैन करें

हम तब तक सत्य तक नहीं पहुंच सकते, जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर न दें। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते।
- बर्ट्रेंड रसेल

हादसों के शहर

महानगरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे हर आदमी को ठिकाना मयस्सर नहीं करा पाते। वहां लोगों को गुजारे का कोई जरिया भले मिल जाए, पर हर किसी को सिर पर छत नसीब नहीं हो पाती। लाखों लोग दिन भर दिहाड़ी करके, रिक्शा-रेहड़ी-ठेला खींच कर या भीख मांग कर किसी तरह गुजारे भर की आमद तो कर लेते हैं, पर रात गुजारने के लिए उन्हें फुटपाथों पर खुले आसमान या उपरिगामी पुलों के नीचे, खाली बंद दुकानों के बाहर कोई जगह तलाशनी पड़ती है। इस तरह इन्हें मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है, अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के नीचे आकर दम तोड़ देने या अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर एक बेकाबू ट्रक के चढ़ जाने की घटना इसकी ताजा कड़ी है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर स्थिति में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हादसों की खबरें कुछ-कुछ समय पर हर महानगर से मिल जाती हैं। हर घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर सोने वालों के लिए कोई सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता।

हालांकि अनियंत्रित वाहनों के सड़कों के बीच की जगहों और फुटपाथों पर चढ़ने से रोकने की गरज से बहुत सारी जगहों पर लोहे की मजबूत बाड़ लगाई जाती है, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में सड़कों पर रात में भी आवाजाही लगी रहती है। रात के वक्त शहरों की सड़कें खासकर माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए खोल दी जाती हैं। इसके अलावा, बहुत सारे युवा देर रात को शराब पीकर वाहन दौड़ाना अपनी शान समझते हैं। वाहनों के अनियंत्रित होकर फुटपाथों पर चढ़ जाने की घटनाएं अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती पाई गई हैं। हालांकि दिल्ली में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, इसके बावजूद बहुत सारे वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना कठिन बना हुआ है। देर रात को उनकी मनमानी और बढ़ जाती है। इससे यातायात व्यवस्था पर तो प्रश्नचिह्न लगता ही है, रोजी-रोजगार की तलाश में हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत रेखांकित होती है।

अनेक मौकों पर यह बात कही जाती रही है कि बढ़ते पलायन और महानगरों पर उसके बढ़ते बोझ की वजह से सरकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती है। इसके समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मगर न तो सरकारों ने रोजी-रोजगार के साधनों के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार किया, न महानगरों में सबके रहने के ठिकाने उपलब्ध कराने की व्यावहारिक पहल हो पाई। दिल्ली में रैन बसरे बनाए तो गए, मगर उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों को फुटपाथों पर सोने को मजबूर न होना पड़े। उनमें भी जरूरी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें आती रहती हैं। दरअसल, महानगरों में बेआसरा लोगों के बारे में कोई व्यावहारिक नीति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर जगह-जगह, थोड़े शुल्क के साथ भी, धर्मशाला जैसी रात गुजारने की जगहें बना दी जाएं, तो लोगों के जिंदगी जोखिम में डाल कर फुटपाथ पर सोने से काफी हद तक निजात दिलाई जा सकती है।

मिलावट का जहर

खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले आम होने की वजह से आज हालत यह है कि कुछ भी खाकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि वह सुरक्षित और सेहत के लिए फायदेमंद है। मिलावट के कारोबारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिलावटी चीजें खाकर लोग बीमार हो गए या उनकी जान ही चली गई। सामान्य दिनों की इस विडंबना के बीच हैरानी की बात यह है कि पर्व-त्योहार के मौकों को भी नहीं बख्शा जाता और सिर्फ कमाई के लिए मिलावटी या फिर खराब हो चुके खाद्य पदार्थ बेचने में कुछ लोगों को हिचक नहीं होती। कई त्योहारों के मौकों पर खबर आती है कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं और अगर कभी कोई मामला तूल पकड़ लेता है तब यह आश्वासन जरूर दिया जाता है कि इस संबंध में जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर हकीकत यह है कि कुछ दिनों के बाद सब भुला दिया जाता है और हादसे होते रहते हैं।

गौरतलब है कि वर्ष भर में आने वाले पर्व-त्योहारों के मौकों पर बहुत सारे लोग फल या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ-साथ कुट्टू के आटे का भी सेवन करते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास के दौरान कुट्टू के आटे से बना 'फलाहार' खाने से पांच गांवों के सौ से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कई लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। खबरों के मुताबिक, पीड़ित लोगों ने जहां से कुट्टू का आटा खरीदा था, वहां आटे की आपूर्ति करने वाली दो दुकानें सील कर दी गईं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मगर सवाल है कि आखिर यह कौन-सी मजबूरी है कि सरकार के संबंधित महकमे या खाद्य सुरक्षा विभाग तब तक लापरवाह बने रहते हैं, जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए। दूषित खाद्य सामग्री बेचने वालों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले में अगर अनदेखी न की जाए, तो शायद इस तरह बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर जोखिम न पैदा हो।

भय के वातावरण में जीती स्त्रियां

आज भी स्कूल-कालेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक, बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले 96 फीसद बढ़े हैं।

मोनिका शर्मा

हमारे समय का पीड़ादायी सच यह है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कुत्सित सोच का घेरा, स्कूल-कालेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। कैसी विडंबना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लाडलियां शोषण का शिकार हो रही हैं और मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जींद जिले के एक गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटनाएं हमारे समाज में स्त्री देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं। ये घटनाएं दिशाहीन सोच की ऐसी बर्बरता की बानगी हैं, जिसमें अपराधी शारीरिक शोषण के बाद स्त्री देह को क्षत-विक्षत करने से भी नहीं चूकते। हरियाणा के जींद जिले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में दस साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला, जिस पर यौन हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे।

गौरतलब है कि जींद में चौथी कक्षा की दस वर्षीय छात्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का नया भवन दिखाने के बहाने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद डरा-धमका कर उसे घर भेज दिया। बच्ची ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल उससे पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। जिससे वह काफी परेशान थी। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज परिसर में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जांच से पता चला है कि उसे बहुत बुरी तरह और बर्बरता से मारा-पीटा भी गया था। अभी इन घटनाओं का गुस्सा शांत भी न हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में करीब चार वर्ष की दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक हालात और स्त्री देह के प्रति कुत्सित सोच का पर्दाफाश करती हैं। कैसी विडंबना है कि चार वर्ष की या चौथी कक्षा की छात्रा हो या चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। कुत्सित मानसिकता के चलते एक बेटी का जीवन ही छिन गया। दूसरी बच्चियों का मन सदा के लिए भय और वेदना से भर गया।

सवाल है कि आखिर हमारे परिवेश में क्या बदला है? आज भी स्कूल-कालेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक, बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले 96 फीसद बढ़े हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक, समानता के लिए जद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन जब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है, तो भविष्य की रूपरेखा कैसी होगी? इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकने-समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारद है। बहुत से लोगों में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है। शिक्षा और सजगता के बावजूद बेटियों के शोषण के मामलों पर

लगाम नहीं लग पा रही है। मासूम बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, भय के घेरे में जीने को विवश हैं। यहां तक कि तकनीक की तरक्की से मिली सुविधाएं भी शोषण का हथियार बन रही हैं।

हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर समय, हर जगह, एक डर से जूझती हैं। सिमटी-सहमी जिंदगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर और जींद जैसी घटनाएं इस डर को और विस्तार देती हैं। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाएं तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती ही हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे तानेबाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि शोषण और दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शिथिलता भी देखने को मिलती है।

> हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर समय, हर जगह, एक डर से जूझती हैं। सिमटी-सहमी जिंदगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर और जींद जैसी घटनाएं इस डर को और विस्तार देती हैं। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाएं तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती ही हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे तानेबाने को प्रभावित करती हैं।

गौरतलब है कि करीब छह वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश में महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए 'महिला सुरक्षा प्रभाग' स्थापित किया गया। इसे समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाग है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर फोरेंसिक विज्ञान, अपराध और आपराधिक रेकार्ड के लिए एक सहायक व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। बावजूद इसके, न्यायिक शिथिलता जारी है।

बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। दुर्दांत अपराधी भी कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकट हैं, जिनमें व्यवस्था के ढुलमुल रवैए का लाभ उठाकर छूटे अपराधी फिर से बर्बर अपराध कर देते हैं। ऐसे हालात सामाजिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता के भाव को भी ठेस पहुंचाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। अकादमिक और कामकाजी मोर्चे पर स्वयं को साबित करने में जुटी बेटियों और महिलाओं के पांवों की बेड़ी बनते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2024 की रपट में पिछले वर्ष के मुकाबले आपराधिक घटनाओं में आई 0.56 फीसद की मामूली गिरावट के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में 1.1 फीसद और अपहरण की घटनाओं में 5.1 फीसद की वृद्धि हुई है। रपट में सबसे ज्यादा अपराध दर वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार शामिल हैं।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के ताजा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या हैं। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक खुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज कराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, मन-जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पाए हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

सांध्य वेला में

अंशु सिंह

बालकनी में बैठे हुए अचानक लाउडस्पीकर से निकली एक आवाज ने कौतुहल पैदा कर दिया। कोई महिला लोगों से गुहार लगा रही थी कि उसके पचहत्तर वर्षीय पिता शाम से घर नहीं लौटे हैं। वे पास के एक पार्क में टहलने गए थे। काफी देर बाद जब नहीं लौटे, तो उनके परिवार वालों ने आसपास ढूंढ़ना शुरू किया। मित्रों से पूछा। किसी को उनकी खबर नहीं थी। महिला यह भी कह रही थी कि उनके पिता को 'डिमेंशिया' यानी स्मृतिलोप नामक बीमारी है, जिस कारण कई बार वे रास्ते भूल जाते हैं। इसलिए उनके कुर्ते की जेब में घर का पता और फोन नंबर पर्ची में लिखकर रखा होता है। तिपहिया वाहन में बैठी वह महिला बीच-बीच में भावुक हो जा रही थी और उसी आवेग में अपनी बातें भी कहती जा रही थी। उसने यह भी बताया कि थाने में गुमशुदगी की रपट दर्ज करा दी गई है, फिर भी किसी को उनके पिता की खबर मिले, तो वे उनसे फोन पर जरूर संपर्क करें।

ज्यादातर लोगों को ऐसे दिनों का ध्यान होगा, जब मोहल्ले में बच्चों की गुमशुदगी को लेकर गाड़ियों से घोषणा की जाती थी। मगर किसी बुजुर्ग के गुम हो जाने की सूचना बहुत कम मामलों में रहती थी। इसी तरह के एक मामले में एक चिकित्सक का भरा-पूरा परिवार था। वक्त आने पर बेटियों की शादी हो गई, बेटों ने अपना अलग आशियाना बना लिया। कुछ समय बाद पत्नी भी गुजर गईं और वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। पहले उन्होंने बोलना कम कर दिया, फिर धीरे-धीरे वे भूलने की बीमारी की गिरफ्त में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने लोगों को पहचानना बंद कर दिया और चल बसे।

इस तरह के मामले अब अपने आसपास लोगों को देखने को मिल जा सकते हैं, जिसमें कोई बुजुर्ग स्मृतिलोप, डिमेंशिया या अल्जाइमर या भूलने की परेशानी या क्रम से बात याद नहीं रख पाने की दिक्कत से जूझ रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग आबादी के बीच इसने एक 'महामारी' का रूप ले लिया है। लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल के अनुसार, वर्ष 2050 तक एक करोड़ तिरपन लाख से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसके शिकार लोगों की याददाश्त, सोच, भाषा और व्यवहार बढ़ती उम्र के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इस मसले पर हो रहा शोध बताता है कि लोग जितनी ज्यादा उम्र तक जीते हैं, उनमें अल्जाइमर होने का जोखिम उतना ज्यादा होता है। दूसरी ओर, इस सच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत समेत दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत में साठ वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी दोगुनी होकर 34.60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इससे उन बुजुर्ग महिलाओं की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी, जो अकेली रहती हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

यों वृद्धावस्था अपने आप में एक चुनौती है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक व्याधियों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उस पर से अगर मस्तिष्क साथ देना छोड़ दे, तो उनकी स्थिति, मनःस्थिति को समझा जा सकता है। जब स्मृतिलोप जैसे रोग होते हैं, तो मस्तिष्क में काफी कुछ घटित होता है, जो जटिल माना जाता है और लक्षण के वास्तविक शुरुआत से कई वर्ष पहले से घटित होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मस्तिष्क में अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन जमा होने से वह उसकी कोशिकाओं के बीच संपर्क और संचार को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। नतीजतन, बुजुर्गों का व्यवहार, आचरण, सोच बदलने लगते हैं।

इसमें दो मत नहीं कि आज भी लोग ऐसे बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान रखने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ रहे। वे समझते हैं कि डिमेंशिया या अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के कारण उनके व्यवहार में आने वाले चिड़चिड़ेपन, नाराजगी, गुस्से को उन्हें संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करना है। छोटे बच्चे की तरह उनके साथ नरमी और सहानुभूति रखनी है, क्योंकि ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ किसी वृद्ध को भावनात्मक और मानसिक रूप से असहाय नहीं कर रही, बल्कि पूरा परिवार इस विषम और विकट परिस्थिति का सामना करने को विवश होता है।

कहते हैं कि जब हमारी खुद की मनःस्थिति अच्छी और सकारात्मक होगी, तो परिस्थिति कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। हम अपनी मजबूत अवस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर लेंगे। भारतीय समाज में ये विश्वास आज भी कायम है कि बड़े-बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करके पुण्य मिलता है। जब माता-पिता त्याग और संघर्ष के जरिये अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, हमारी छोटी-छोटी खुशियों का खयाल रख सकते हैं, तो बढ़ती उम्र में हम उनका हाथ क्यों नहीं थाम सकते? उनके साथ बातचीत का सिलसिला क्यों नहीं बनाए रख सकते? उनकी डांट या चिड़चिड़ेपन को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मस्तिष्क में होने वाले बदलावों को हम बेशक नहीं रोक सकते हों, लेकिन अपने बुजुर्ग अभिभावक को साथ में सैर पर ले जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं या कोई आसान सा खेल सकते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि संगीत सुनना भी ऐसे बुजुर्गों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो हम उनकी उदासी मिटाने के लिए अपनी सीमा में जो संभव हो, वह कर सकते हैं। उनसे अपने दिल की बातें साझा कर सकते हैं और उन्हें अहसास करा सकते हैं कि वे हमारे लिए कितने महत्त्वपूर्ण हैं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, उम्र का एक पड़ाव भर है।

दुनिया मेरे आगे

> जब हमारी मनःस्थिति अच्छी और सकारात्मक होगी, तो परिस्थिति कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। हम अपनी मजबूत अवस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर लेंगे। भारतीय समाज में ये विश्वास कायम है कि बड़े-बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करके पुण्य मिलता है।

पानी और संवेदना

जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने नल का पानी लिया, उसकी कुछ बूंदों को जमाया, इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप से उनकी जांच की और उनकी तस्वीरें लीं। बाद में उन्होंने आसपास की नदियों और झीलों से पानी लिया, उन्हें अलग-अलग बोतलों में रखा, उन पर सकारात्मक शब्दों और 'प्यार' के शब्द की पर्ची लगाई, जबकि एक अन्य बोतल को 'नफरत' के शब्दों और भावनाओं के संपर्क में रखा। दरअसल, हम पानी की तरह हैं और पानी की तरह जो गति नहीं करता, ठहरा या जड़ रहता है, वह गंध करता है। फिर भी हम इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं, चाहे हम इमोटो के प्रयोगों पर विश्वास करें या नहीं। अगर हम अनिश्चित अवधि तक गति नहीं करते हैं, तो हम स्थिर हो जाते हैं। क्या हमारे और दूसरों के शब्द हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं? अगर मैं खुद से कहता रहूं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो यह संभव है कि मैं अंत में उसे करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत, अगर मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की क्षमता हासिल कर लूंगा, भले ही शुरुआत में मेरे पास यह क्षमता न हो।

- इकबाल राजा, मधेपुरा बिहार

दोस्ती के बजाय

नेपाल से भारत की मित्रता पुरानी रही है और समय-समय पर भारत ने नेपाल को मैत्री भाव ही दिया। कैसी भी परिस्थिति रही, भारत ने सहयोग, समर्थन जारी रखा। विडंबना है कि पिछले कुछ समय से भारत की मित्रता नेपाल को रास नहीं आ रही। भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद नेपाल ने चीन से संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नई पहल की। इसके अलावा, चीनी ऐप टिकटाक पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया गया। समझ से परे लगता है कि चीन और पाकिस्तान दुनिया भर की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, उन पर नेपाल आंख मूंद कर विश्वास करता है। नेपाल को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि चीन की दोस्ती कितनी भरोसे की है। विस्तारवाद से घिरे चीन और आतंकवाद से घिरे पाकिस्तान किसी भी देश के भरोसे मंद दोस्त नहीं हो सकते। समय रहते चीन का उद्देश्य पूर्ण होने पर भरोसे के नाम पर या दोस्ती के नाम पर छल ही मिल सकता है।

- योगेश जोशी, बड़वाह

कुप्रबंधन की बरसात

'पानी और परेशानी' (संपादकीय, 22 अगस्त) पढ़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब नौ वर्ष हो गए हैं, पर सड़कों और नालियों के सुधार के मामले में आज भी इसका मामला शून्य बटा सन्नाटा ही है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली भी देश के अन्य महानगरों की तरह ही समस्याओं से ग्रस्त है। बरसात के दिनों में दिल्ली हर जगह पानी से घिर जाती है। यहां न केवल सड़कें दुर्दशा में चली जाती हैं, बल्कि नालियों का भी रखरखाव नहीं के बराबर होता है। कह सकते हैं कि राजधानी की दुर्दशा का कारण यहां की सरकार और समूचा तंत्र है। सवाल है कि आखिर दिल्ली की सरकार और उसके संबंधित महकमों की क्या जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार को राजधानी दिल्ली में आवश्यक उपाय कर हालात में सुधार करना चाहिए। अन्यथा यहां के लोगों को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

- मनमोहन राजावतराज, शाजापुर, मप्र

पर्यावरण के लिए

प्रत्येक वर्ष इस मौसम में पूरे देश में करोड़ों पौधे विशेष अभियान चलाकर सरकार द्वारा लगवाए जाते हैं, लेकिन ये पौधे कितने दिनों तक कितने सुरक्षित रह पाते हैं, यह जगजाहिर है। पौधे लगाने की खानापूर्ति तो कर दी जाती है, लेकिन उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था न होने से अधिकांश पौधे सूख जाते हैं। इससे पौधे लगाने का पर्यावरणीय उद्देश्य एक तरह से विफल ही रहता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पहल करते हुए 'एक पौधा मां के नाम' लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। यह निस्संदेह दूरदर्शितापूर्ण एवं सामाजिक सरोकार से युक्त है। पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अगर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प ले और उसकी उचित देखभाल करे, तो पर्यावरण की दृष्टि से इसका सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।

- रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

www.readwhere.com

चिंतन

बढ़ते समुद्री जल स्तर के खतरे से निपटना चुनौती

दुनिया केवल दो-दो जंग, क्षेत्रीय संघर्ष, ट्रेड वार, सीमा विवाद, विस्तारवाद, भू-राजनीतिक तनाव, वर्चस्ववाद, ऊर्जा व खाद्य आपूर्ति संकट का सामना नहीं कर रही है, बल्कि मानवीय कृत आपदा के चलते जलवायु संकट से भी जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को एक और जलवायु चेतावनी जारी करते हुए समुद्रों के बढ़ते जलस्तर को 'विश्वव्यापी आपदा' बताया है। यह गंभीर विश्वव्यापी खतरे के संकेत है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बड़ी तटीय आबादी पर जलसमाधि का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने जलवायु चेतावनी (एसओएस) में समुद्रों में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर, खासकर प्रशांत क्षेत्र के अधिक असुरक्षित द्वीपीय देशों का उल्लेख किया है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सोमवार को समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर एक रिपोर्ट जारी की है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुतारेस ने टोंगा की राजधानी से प्रशांत द्वीप समूह फोरम की बैठक में जलवायु परिवर्तन के चलते संभावित खतरे के प्रति विश्व को आगाह किया है। दरअसल, समुद्र का बढ़ता जलस्तर पूरी तरह से मानव निर्मित संकट है। अगर त्वरित ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकट जल्द ही अप्रत्याशित पैमाने पर पहुंच जाएगा, जब हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। टोंगा की राजधानी नुकु अलोफा के पास वर्ष 1990 से 2020 के बीच समुद्र का जलस्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ा है, जो वैश्विक औसत 10 सेंटीमीटर से लगभग दोगुना है। समोआ के अपिया में समुद्र का जलस्तर 31 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि फिजी के सुवा-बी में 29 सेंटीमीटर बढ़ा है। ये बढ़ते समुद्री जलस्तर दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करते हैं। भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। तटीय कटाव के कारण भारत 2050 तक लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर भूमि खो सकता है। बढ़ते समुद्री स्तरों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां पिघलती हैं और इससे महासागरों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। गर्म तापमान के कारण समुद्री जल का विस्तार होता है, जिसे थर्मल विस्तार के रूप में जाना जाता है। यह विस्तार ही मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। बढ़ते समुद्री जल स्तर के चलते तटीय कटाव, बाढ़ में वृद्धि, विस्थापन और पलायन, खारे पानी का अतिक्रमण, बुनियादी ढांचे को खतरा, पारिस्थितिकी प्रभाव, जल सुरक्षा व खाद्य उत्पादन का संकट और जैव विविधता के लिए खतरे आदि समस्याएं हो सकती हैं। इस संकट से बचने के लिए भारत को तटीय सुरक्षा, समुद्री दीवारें और तटीय क्षेत्रों में वनरोपण जैसे अनुकूलन उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को लागू करने से तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। तटीय समुदायों को ज्ञान, संसाधनों और स्थायी आजीविका विकल्पों के साथ सशक्त बनाना बढ़ते समुद्री स्तरों के प्रति उनके लचीलापन को बढ़ा सकता है। यूएन की चेतावनी को चुनौती मानते हुए भारत को बढ़ते समुद्री जलस्तर को रोकने की दिशा में त्वरित कदम उठाना चाहिए।

नशे के गिरफ्त में देश का भविष्य

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है जिसकी 65 फीसदी आबादी 40 साल तक के आयुवर्ग का है। युवा ही किसी देश के सबसे बड़े कार्यबल यानि वर्कफोर्स होते हैं जिन पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर होता है। इतिहास गवाह है कि देश और दुनिया में जितने भी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उसे युवाओं ने ही अंजाम दिया है। भारत में कालांतर में ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना दी लेकिन आज युवाओं की एक बड़ी आबादी नशे के चंगुल में फंसकर अपनी ऊर्जा गंवा रहे हैं। अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज युवाओं में बेरोजगारी से बड़ी चुनौती उनमें पनप रही नशाखोरी है जिससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है।

गौरतलब है कि राज्य के नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 'एनसीबी' के दफ्तर का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रदेश में नशीली दवा का उपयोग 1.45 फीसदी तथा गांजा का उपयोग 4.98 फीसदी किया जा रहा है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिलाशक छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य के लिए यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। अलबत्ता राज्य में एनसीबी कार्यालय खुलने से नशे के कारोबार को रोकने में मदद मिल सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ गांजा जैसे सूखे नशे के तस्करी का बड़ा कॉरिडोर है जिसके रास्ते देश के 17 राज्यों को यह मादक पदार्थ पहुंचता है जिसकी कीमत तकरीबन 600 करोड़ आंकी गई है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट 'एनडीटीडी' के मुताबिक देश के 10 वर्ष के किशोर से लेकर 75 साल के बुजुर्ग आबादी में से लगभग बीस फीसदी लोग किसी न किसी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। बहरहाल बढ़ते नशाखोरी का दुष्परिणाम परिवार और समाज को भोगना पड़ रहा है। आश्चर्यजनक तौर पर नशा करने वालों में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है जबकि नशे के कारण होने वाले घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही हो रही हैं।

बिलाशक भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया को मनवा रहे हैं लेकिन विडंबना यह भी कि पाश्चात्य संस्कृति को प्रगतिशीलता का पैमाना मानने वाले इन युवक- युवतियों के लिए नशा का सेवन उनके ' कल्चर' का अहम हिस्सा बन रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 70 फीसदी किशोर और युवा पीढ़ी अपनी आर्थिक हैसियत और उपलब्धता के लिहाज से अपने आपको किसी न किसी नशीले पदार्थ के सेवन का आदी बना लिया है। इन नशीले पदार्थों में शराब, स्मैक , हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, अफीम, चरस, गांजा,चरस, भांग, सिगरेट, तंबाकू युक्त गुटखा, खैनी, नशीली टैबलेट व सिरप आदि शामिल हैं। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट के मुताबिक देश में नशा करने वाली आबादी की पहली पसंद शराब है जबकि गांजा दूसरे नंबर पर है। आश्चर्यजनक तौर पर महानगरों से लेकर छोटे - बड़े शहरों के स्कूल - कॉलेजों के छात्र नशीले दवाओं और इंजेक्शन के गिरफ्त में है यहां तक कि यह स्लम बस्तियों में भी लोगों को उपलब्ध हो रहा है।

चिंताजनक यह कि अनेक लोग एक ही सिरींज का उपयोग इस नशीले इंजेक्शन को लेने के लिए कर रहे हैं जिससे एचआईवी के मामले बढ़ने की पूरी संभावना है। देश में नशीले दवाओं का बाजार लगातार बढ़ रहा है जिसका सबसे बड़े उपभोक्ता युवा वर्ग हैं। ड्रग वॉर डिस्टॉर्शन और वर्डोमीटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में नशीले दवाओं और इंजेक्शन का कारोबार 30 लाख करोड़ से ज्यादा का है। दूसरी ओर स्लम बस्तियों रहने वाले या कबाड़ बीनने वाले छोटे - छोटे बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वे बोनफिक्स या पंचर चिपकाने में प्रयुक्त होने वाले सुलेशन एढेसिव को नशे के तौर पर सूंघ रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अस्सी के दशक में शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की औसत आयु 28 साल थी जो अब 15 वर्ष पर आ गई है, महानगरों और शहरों में तो यह 13 वर्ष तक पहुंच चुकी है। विचारणीय है कि जिन युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य टिका है वह खुद नशे में बेसुध होकर दूसरों के कंधे का सहारा ढूंढ रहे हैं।

चिंतनीय है कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी का दुष्परिणाम उनके स्वास्थ्य के साथ - साथ परिवार और समाज में भी दृष्टिगोचर होने लगा है। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से जहां युवाओं में बड़ी तेजी से हृदय, फेफड़ों, लिवर, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे शारीरिक रोग तथा अनेक मानसिक रोगों के मामले बढ़ रहे हैं वहीं इससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक शोध के मुताबिक अनेक सड़क हादसों सहित आत्महत्या, घरेलू हिंसा, तलाक सहित लूटपाट, हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के मूल में नशाखोरी ही होती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 14 हजार सड़क दुर्घटनाएं शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों के नशाखोरी के कारण होती हैं जिसमें अधिकतर युवा चालक होते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक हत्या,लूट जैसे अपराध में नशा सेवन का मामला 73.5 फीसदी तथा दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध 87 फीसदी होता है। अलबत्ता देश में पनप रहे आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के लिए धन की व्यवस्था भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी के जरिए हो रहा है।

गौरतलब है कि भारत अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अनुशासन, आचरण, संस्कार और पाबंदियों के कारण पश्चिमी देशों के लिए सदैव उत्सुकता का विषय रहा है लेकिन आज का यंगिस्तान नशाखोरी में मदमस्त होकर वर्जनाओं और अनुशासन को तोड़ने में कोई संकोच नहीं कर रहा है। विडंबना यह कि शिक्षा के मंदिर युनिवर्सिटी, कॉलेज, हास्टल और स्कूल कैंपस में रहने वाले स्टूडेंट्स को आसानी से मादक पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं तथा यह कैंपस इनके उपभोग और कारोबार के मुख्य अड्डा बने हुए हैं।

माना कि नशा एक सामाजिक बुराई है लेकिन इसके लिए प्रमुख रूप से हमारी राजनीतिक , सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और नशीले चीजों की आसान उपलब्धता जैसे कारण जिम्मेदार हैं। आज के व्यस्ततम दिनचर्या में खासकर कामकाजी पालकों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे अपने बच्चों को समय दे सकें, उनके समस्याओं पर बात करें या फिर यह पता लगाएं कि उनके बच्चे नशाखोरी या किसी मानसिक समस्या से तो नहीं जूझ रहे हैं? लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार, संवेदनशील और सहयोगात्मक बनना होगा। यदि किशोरों और युवाओं के व्यवहार में अचानक बदलाव, आक्रामकता, सामाजिक या पारिवारिक गतिविधियों से अलगाव, बगैर अभिभावक के जानकारी के शिक्षण संस्थानों या कर्तव्य स्थल से अनुपस्थिति, पैसा चोरी या अचानक जेब खर्च के लिए ज्यादा पैसों की मांग, कार्यक्षमता और उत्साह में कमी जैसे प्रवृत्तियां दिखे तो पालकों को सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं उनके बच्चे को नशे की लत तो नहीं लग रही है? ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत मनोरोग विशेषज्ञों अथवा मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेना चाहिए।

विचारणीय यह भी है कि हर सरकार को जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्व की दरकार होती है और शराब तथा अन्य मादक पदार्थ राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्त्रोत हैं। इस तथ्य के बावजूद शराब और अन्य नशीले पदार्थों के समाज, जनस्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले नाकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर सरकारों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए अन्य स्त्रोतों पर विचार करते हुए मादक पदार्थों के व्यापार को प्रतिबंधित करने की जरूरत है आखिरकार यह देश के युवाओं से जुड़ा मसला है जिनके हाथों देश का भविष्य निर्भर है। अहम तथ्य यह भी है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग और सख्ती के बिना शराब और अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार और तस्करी को रोकना असंभव है।

यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि शराब सहित अनेक नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और सेवन को संरक्षण स्थानीय स्तर पर पुलिस महकमे द्वारा ही मिलता है। दूसरी ओर जनमानस में पुलिस प्रशासन के प्रति नकारात्मक छवि के बावजूद सुकूनदायक यह कि छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी संतोष कुमार सिंह के 'निजात अभियान' ने समाज के सामने एक अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य के राजधानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदस्थ संतोष कुमार सिंह जहां भी पदस्थ रहे उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामाजिक सरोकार के मद्देनजर इस अभियान को चलाया था जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार आम नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास कायम करने के लिए ' कम्यूनिटी पुलिसिंग' पर जोर देती रही है लिहाजा "निजात" जैसे अभियान इस दिशा में सार्थक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों को नशामुक्ति अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मादक पदार्थों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी हेतु स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस में अनिवार्य रूप से इससे संबंधित विषय शामिल किए जाएं। शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना 'एनएसएस' और एनसीसी के माध्यम से नशामुक्ति अभियान चलाने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी इन सामाजिक बुराईयों से दूर रहें।

पेरिस पैरालंपिक

योगेश कुमार गोयल

पैरालंपिक खेलों में नया इतिहास रचेगा भारत!

पेरिस ओलंपिक में छह पदक जीतने के बाद भारत के खेल प्रेमियों की निगाहें अब पेरिस पैरालंपिक खेलों पर टिक गई हैं, जो 28 अगस्त से 8 सितम्बर तक चलेंगे। पैरालंपिक में 22 अलग-अलग प्रतियोगिताओं में कुल 549 पदक स्पर्धाओं में दुनियाभर के 4 हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत को पूरी उम्मीद हैं कि पेरिस पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ी कम से कम एक दर्जन पदक जीतने में अवश्य सफल होंगे। इन उम्मीदों के हकीकत में बदलने की इसलिए भी प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक-2020 में भारत के कुल 54 खिलाड़ियों ने केवल 9 खेलों में ही हिस्सा लिया था और खेलों के उस महाकुंभ में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने में सफल हुए थे, जो भारत का पैरालंपिक में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बार भारत के 84 पैरा खिलाड़ी कुल 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो किसी भी पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है।

भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र झाझरिया तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में कम से कम 25 पदक मिलने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। यदि भारत वाकई इतने पदक जीतने में सफल हो जाता है तो यह न केवल भारत के लिए एक नया इतिहास बनेगा बल्कि भारत में इससे अन्य खिलाड़ियों का हौसला भी कई गुना बढ़ेगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत जिन तीन नई स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है, उनमें पैरा साइकलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो शामिल हैं। भारतीय पैरा एथलीटों के ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने की संभावनाएं इसलिए भी बलवती हो रही हैं क्योंकि भारतीय दल में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो पिछले पैरालंपिक में पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित कर चुके हैं। यही नहीं, जापान के कोबे में मई 2024 में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारतीय पैरा एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन कर इस उम्मीद को बढ़ा चुके हैं। पिछले दिनों सम्पन्न हुए पेरिस ओलंपिक में जहां भारत 71वें पायदान पर पहुंच गया था। वहीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा था। इस बार के पैरालंपिक में सबसे ज्यादा उम्मीदें भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनि लेखरा पर टिकी हैं। दोनों ने ही पिछले पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे और ये दोनों टोक्यो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। पेरिस पैरालंपिक में उन सभी भारतीय खिलाड़ियों को पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था या पिछले कुछ समय में अन्य पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। सुमित और अवनि के अलावा एक तीरंदाज शीतल देवी भी हैं। वहीं, बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल मुकाबले में स्वर्ण जीतने वाले कृष्णा नागर, महिलाओं की शॉट पुट में एशियन पैरा खेलों और मई महीने में ही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी भाग्यश्री जाधव, दुनियाभर में रैंकिंग में पहले पायदान पर मौजूद और पिछले पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत जीतने वाले सुहास यतिराज से भी पदक जीतने की बहुत उम्मीदें हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। इस बार भारतीय खिलाड़ियों से टोक्यो पैरालंपिक के प्रदर्शन को दोहराने या उससे भी बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारत ने अभी तक कुल 12 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया है और उनमें से टोक्यो सहित केवल 6 में ही पदक जीते हैं।

पैरालंपिक खेलों में भारत ने पहला पदक 1972 के हाईडेलबर्ग खेलों में जीता था। तब पुरुषों के 50 मीटर फ्रीस्टाइल में मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीतकर वह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं, 2016 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी होने का गौरव हासिल है। 1984 के न्यूयॉर्क पैरालंपिक में जोगिंदर सिंह बेदी ने तो तीन खेल स्पर्धाओं (भाला फैंक, चक्का फैंक और गोला फैंक) में 1 रजत और 2 कांस्य सहित एक ही पैरालंपिक में कुल तीन पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। बहरहाल, भारतीय पैरा एथलीट अंतरराष्ट्रीय पैरा स्पर्धाओं में जिस प्रकार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि हमारे खिलाड़ी पैरा खेलों के इस महाकुंभ में नया इतिहास रचने में सफल होंगे। 2023 में हांग्जो एशियाई पैरा खेलों में भारत 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदकों के साथ कुल 111 पदक जीतने में सफल हुआ था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कष्टों से भागें नहीं उनका सामना करें

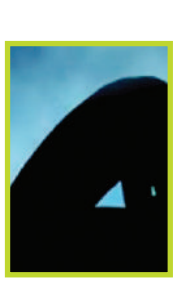

संकलित

दर्शन

हमारे रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं वे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसे- बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन समस्याओं से बचने या उनके विषय में न सोचने से अस्थायी आराम तो मिल सकता है लेकिन, अगर आप अपने कष्ट का खुलकर सामना करते हैं तो आप अपनी समस्या को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यदि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो जब तक आप अपने शत्रु की स्थिति और उसकी सैन्य क्षमता पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी और आप डर के कारण शिथिल हो जाएंगे। यदि आपको अपने शत्रु की सैन्य क्षमता और उसके हथियारों आदि के बारे में पता लग जाए तो युद्ध के समय आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसी तरह यदि आप अपनी समस्याओं से बचने के बजाय उनका सामना करेंगे तो उनसे निपटने में आपको आसानी होगी। उदाहरण के लिए आपको बुढ़ापा और मृत्यु नकारात्मक या अवांछित लगें और आप उन्हें भूलना चाहें, फिर भी ये चीजें तो आएंगी। यदि आप इनके बारे में सोचने से बचते रहें तो जिस दिन इनमें से कोई भी घट गई तो आपको असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। यदि आप बुढ़ापा, मृत्यु और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण चीजों पर सोचने में कुछ समय लगाएंगे तो इनके होने पर भी आपका मस्तिष्क स्थिर रहेगा। एक बात व्यक्ति को ध्यान में रखनी है, वह यह है कि कष्ट के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बचने की संभावना है; एक विकल्प है। कष्ट से मुक्त होने की संभावना है। कष्ट के कारण को दूर करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना संभव है। बौद्ध मतानुसार, कष्ट के मूलत तीन कारण हैं- अज्ञानता, तृष्णा और घृणा। इन्हें 'मस्तिष्क के तीन विष' कहा जाता है। बौद्ध संदर्भ में इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ हैं।

चेहरा देखकर उसके चरित्र जान गए सुकरात

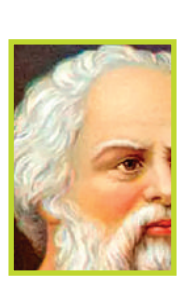

संकलित

प्रेरणा

दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठ कर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ गया। उसने देखा कि कोई भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, 'मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसके चरित्र के बारे में बता सकता हूं। बताओ तुममें से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा?' उसकी यह बात सुनकर सभी शिष्य सुकरात की ओर देखने लगे। सुकरात ने मुस्कराते हुए उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात देखने में कुरूप थे। उन्हें कुछ देर निहारने के बाद ज्योतिषी ने कहा, 'तुम्हारे चेहरे की बनावट से पता चलता है कि तुम सत्ता विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों की बनावट से लगता है कि तुम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हो।' अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर वहां बैठे शिष्यों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। ज्योतिषी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, 'तुम्हारे बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो। तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है।'उसकी ये बातें सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, लेकिन सुकरात गुस्सा होने की बजाय मुस्करा रहे थे। उन्होंने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। सुकरात के इस व्यवहार को देखकर शिष्य उन्हें आश्चर्य से देखने लगे और उनसे पूछा, 'गुरुजी, हमें आपकी यह बात समझ नहीं आई कि आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा, वो सब झूठ था?' 'नहीं शिष्यों, ज्योतिषी ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है, वे सब सच है।

अंतर्मन

आज की पाती

जनसंख्या वृद्धि समस्याओं की जड़

हमारा देश विकास और अन्य बहुत से अच्छे कामों में दुनिया भर में नंबर वन पर है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी हमारा देश दुनिया भर में एक नंबर पर पहुंच चुका है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अगर भारत सरकार और देश का आमजन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना नितांत आवश्यक है क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं।

-युवा कुमार साहू

ट्रेंड

शांतिपूर्ण समाधान

आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। रूस व यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरी अंतर्दृष्टि पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एमएसपी की गारंटी

किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, 'इंडिया' किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

समर्थन के लिए आभार

ओलंपिक के बाद गोरिया (झज्जर) लौटना एक अद्भुत एहसास है। मेरे प्रशंसकों, दोस्तों और परिवार के अटूट समर्थन के लिए आभार। गर्मजोशी भरे और अद्भुत स्वागत के लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद। यह जीत हम सभी के लिए है।

-मनु भाकर, भारतीय निशानेबाज

शिशु का विकास

बहुत सारे बच्चे इसलिए बीमार हो जाते है क्योंकि पाउडर वाले दूध का पानी उस पानी में मिला दिया जाता है जो दूषित होता है। जबकि मां के दूध में ही शिशु के विकास के लिए आवश्यक पोषण होत है।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

मुझे कुछ होने पर आईएसआई महानिदेशक जिम्मेदार: इमरान

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दोहराया कि उनकी हालत के लिए सेना और आईएसआई जिम्मेदार हैं और साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरे का अंदेशा भी जताया। पिछले साल से अदियाला जेल में बंद खान (71) ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि उसे देशभर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने को लेकर आलोचना बर्दाश्त नहीं है। खान ने जेल से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किये गए एक पोस्ट में चुनावों में धांधली के बारे में दावा दोहराया और कहा कि केवल एक वास्तविक जनादेश वाली सरकार ही मौलिक सुधारों की योजना बनाने में सक्षम होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आईएसआई मेरे कारावास से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करती है। मैं इसे फिर से कह रहा हूं: अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो सेना प्रमुख और डीजी (महानिदेशक) आईएसआई जिम्मेदार होंगे। खान की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब पाकिस्तान सरकार ने दो दिन पहले यह कहा था कि पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से संबंधित मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ मुकदमा सैन्य अदालत में चलाया जा सकता है।

ऑफ बीट

वायु प्रदूषण से लोगों में मृत्यु का जोखिम बढ़ा

भारतीय जिलों में राष्ट्रीय मानक से अधिक वायु प्रदूषण से सभी उम्र वर्ग के लोगों में मौत का जोखिम बढ़ गया है। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नवजात शिशुओं में यह जोखिम 86 प्रतिशत, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 100-120 प्रतिशत तथा वयस्कों में 13 प्रतिशत बढ़ा है। मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं समेत अन्य शोधकर्ताओं के एक दल ने 700 से अधिक जिलों में सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) संबंधी प्रदूषण के स्तर का अध्ययन किया। विश्लेषण के लिए आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (पांचवें दौर) और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) से लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन घरों में अलग रसोईघर नहीं है, वहां नवजात शिशुओं और वयस्कों में मृत्यु की आशंका अधिक होती है। 'जियोहेल्थ' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में लेखकों ने कहा कि नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, "भारत के उन जिलों में जहां पीएम 2.5 की सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) स्तर तक है, यह जोखिम क्रमशः लगभग दो गुना और दो गुना से भी अधिक है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com